Machine Translated by Google

अदृश्य महामारी: वायु प्रदूषण भारत के लिए सबसे बड़ा स्वास्थ्य खतरा क्यों है?

भारत में एयर क्वालिटी का संकट बहुत बड़ा और गहरा है; इसके वैज्ञानिक सबूत बहुत ज़्यादा हैं, और सेहत पर इसके असर को नकारा नहीं जा सकता; देश को अब साफ़ हवा को एक बुनियादी अधिकार के तौर पर मानना होगा जो सबके विकास के लिए ज़रूरी है और एक ऐसी राष्ट्रीय प्राथमिकता है जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

सुधीर कुमार शुक्ला

ए भारत में प्रदूषण अब सिर्फ़ उत्तरी मैदानों तक सीमित सर्दियों की परेशानी नहीं है। यह एक लगातार, पूरे देश में फैली पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन गई है जो हर डेमोग्राफिक ग्रुप और लगभग हर ऑर्गन सिस्टम पर असर डालती है। पूरे सिंधु-गंगा के मैदानी इलाके में, और दूसरी जगहों पर तेज़ी से बढ़ते शहरी इलाकों में, पार्टिकुलेट मैटर का खतरनाक जमाव बीमारियों के पैटर्न को बना रहा है, बच्चों के विकास को धीमा कर रहा है और चुपचाप जीवन की उम्मीद कम कर रहा है।

भारत में हवा की क्वालिटी का संकट बहुत बड़ा और गहरा है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में जिन 256 शहरों पर नज़र रखी गई, उनमें से 150 शहरों में नेशनल PM 2.5 स्टैंडर्ड पार हो गया। ज़्यादातर शहरी लोगों के लिए, खराब या खतरनाक हवा में सांस लेना अब साल का एक रेगुलर हिस्सा बन गया है। गंगा के मैदानी इलाके सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। 2025 में, दिल्ली में सीज़नल PM 2.5 का लेवल 107 –130 μg/m3 रिकॉर्ड किया गया - जो भारत की 24 घंटे की लिमिट 60 μg/m3 और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन की 15 μg/m3 की गाइडलाइन से बहुत ज़्यादा है ।

गलत इंडेक्स, पुरानी लिमिट भारत का सोशल एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) अभी भी 500 पर ही लिमिट करता है, हालांकि दिल्ली और दूसरे शहरों में रियल-टाइम प्रदूषण का लेवल अक्सर इस लिमिट से ज़्यादा हो जाता है।

यह लिमिट — जो एक दशक से भी पहले शुरू की गई थी — लोगों को परेशान करने से बचने के लिए थी और यह इस सोच पर आधारित थी कि 500 से ज़्यादा होने पर सेहत पर असर एक जैसा गंभीर होगा। इसलिए, सरकारी प्लेटफॉर्म सभी बहुत ज़्यादा प्रदूषण को एक "गंभीर" कैटेगरी में डाल देते हैं, जबकि IQAir जैसे इंटरनेशनल ट्रैकर रेगुलर तौर पर 600 से ज़्यादा और कभी-कभी 1,000 से ज़्यादा वैल्यू दिखाते हैं। एक्सपर्ट्स ने बार-बार बताया है कि भारत का AQI पुराने थ्रेशहोल्ड और इंस्ट्रूमेंट्स पर निर्भर करता है, और इस स्केल को रीकैलिब्रेशन, ऊपरी लिमिट हटाने और मॉडर्न मॉनिटरिंग की ज़रूरत है।

ज़हरीली हवा का सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। यूनिवर्सिटी ऑफ़ शिकागो के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एयर क्वालिटी लाइफ़ इंडेक्स (AQLI) के अनुसार, लगभग 46% भारतीय ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ एयर पॉल्यूशन से जीवन की उम्मीद काफ़ी कम हो जाती है। दिल्ली में, अभी PM 2.5 के संपर्क में आने से WHO के स्टैंडर्ड के हिसाब से आठ साल से ज़्यादा की ज़िंदगी का नुकसान होता है।

पूरे उत्तर भारत में यह नुकसान 3.5 से सात साल के बीच है।

मरने वालों की संख्या भी उतनी ही चिंताजनक है।

स्टेट ऑफ़ ग्लोबल एयर रिपोर्ट, 2025 के अनुसार, 2023 में, एयर पॉल्यूशन की वजह से देश भर में लगभग 20 लाख मौतें हुईं, जिनमें मुख्य रूप से कार्डियोवैस्कुलर बीमारी, स्ट्रोक, COPD और डायबिटीज़ शामिल हैं।

2000 से प्रदूषण से जुड़ी मौत की दर में 43% की बढ़ोतरी हुई है, जो लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने के कुल असर को दिखाता है।

PM 2.5 शरीर के अंदर क्या करता है? कार्डियोवैस्कुलर नुकसान: PM 2.5 के कण फेफड़ों में गहराई तक घुस जाते हैं, खून में मिल जाते हैं और सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन फैलाते हैं। भारत में कई शहरों में हुई एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ से पता चलता है कि लंबे समय तक PM 2.5 के संपर्क में रहने से हर 10 μg/m3 की बढ़ोतरी से सालाना मौत की दर में 8% की बढ़ोतरी होती है। ज़्यादा संपर्क हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एरिथमिया और इस्केमिक स्ट्रोक से जुड़ा है। एक ऐसे देश में जो पहले से ही कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों की ज़्यादा दर से जूझ रहा है, प्रदूषित हवा एक ताकतवर, अनदेखी तेज़ी लाने वाली चीज़ की तरह काम करती है।

हांफते हुए सांस: भारत में एयर पॉल्यूशन अब सर्दियों में होने वाली परेशानी नहीं है, जो सिर्फ़ उत्तरी मैदानों तक ही सीमित है। यह एक लगातार चलने वाली, देश भर में फैली पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन गई है, जो हर डेमोग्राफिक ग्रुप और लगभग हर ऑर्गन सिस्टम पर असर डालती है। सुशील कुमार वर्मा

श्वसन संबंधी बीमारी: श्वसन बीमारियाँ ज़हरीली हवा का सबसे बड़ा नतीजा हैं। लगभग 6% भारतीय बच्चे अब अस्थमा से परेशान हैं।

AIIMS के क्लिनिकल डेटा से पता चलता है कि PM 2.5 में मामूली 10 μg/m3 की बढ़ोतरी से सांस की तकलीफ के लिए बच्चों के इमरजेंसी विज़िट में 20–40% की बढ़ोतरी हो सकती है।

ज़्यादा प्रदूषण वाले बच्चों के फेफड़ों की क्षमता में 10–15% की कमी देखी गई है — यह कमी बड़े होने पर भी बनी रह सकती है। बड़ों में, COPD, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और बार-बार होने वाले सांस के इन्फेक्शन आम होते जा रहे हैं, खासकर उन लोगों में जो सड़कों, इंडस्ट्रीज़, ज़मीन और कंस्ट्रक्शन साइट्स के पास रहते हैं।

न्यूरोलॉजिकल प्रभाव: उभरते हुए साइंटिफिक सबूत बताते हैं कि एयर पॉल्यूशन फेफड़ों और दिल की तरह ही दिमाग पर भी गंभीर असर डालता है। PM 2.5 पार्टिकल्स ब्लड-ब्रेन बैरियर को पार कर सकते हैं, जिससे न्यूरोइन्फेक्शन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है। भारतीय शहरों की स्टडीज़ से पता चलता है कि बच्चों में पॉल्यूशन का असर पढ़ाई में खराब परफॉर्मेंस, याददाश्त में कमी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कमी से जुड़ा है।

इंटरनेशनल मेटा-एनालिसिस से पता चलता है कि PM 2.5 में हर 10 μg/m3 की बढ़ोतरी से डिमेंशिया का खतरा 35–49% ज़्यादा होता है । एनवायर्नमेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव्स (2024) में रिव्यू बताते हैं कि प्रदूषित हवा वैस्कुलर इंजरी और टॉक्सिक मेटल डिपॉज़िशन के ज़रिए दिमाग की उम्र बढ़ने की रफ़्तार को तेज़ करती है।

मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य: उच्च PM 2.5 के संपर्क में आने से समय से पहले जन्म, कम वज़न वाले बच्चे, मृत जन्म और नवजात शिशु की मृत्यु दर बढ़ जाती है। मुख्य सड़कों, इंडस्ट्रियल साइट्स या कचरा जलाने वाली जगहों के पास रहने वाली महिलाओं को खास तौर पर खतरा होता है। शुरुआती जीवन में इन असर के लंबे समय तक असर होते हैं, जिससे सेहत पर बुरा असर पड़ता है।

नवीनतम राज्य के अनुसार, 2023 में वायु प्रदूषण के कारण लगभग दो मिलियन मौतें हुईं

ग्लोबल एयर रिपोर्ट, मुख्य रूप से कार्डियोवैस्कुलर बीमारी, स्ट्रोक, COPD और डायबिटीज से

पीढ़ियों के बीच असमानता।

भारत में वायु प्रदूषण मौजूदा स्थिति को दिखाता है सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ। कम इनकम वाले समुदाय अक्सर एमिशन हॉटस्पॉट — बड़ी सड़कों, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, कंस्ट्रक्शन ज़ोन और ज़मीन के पास रहते हैं। इन इलाकों में रहने वाले बच्चे ज़्यादा समय बाहर बिताते हैं और इसलिए ज़्यादा एक्सपोज़्ड रहते हैं। खराब घर, साफ़ फ्यूल तक कम पहुँच और खराब हेल्थकेयर से कमज़ोरियाँ और बढ़ जाती हैं। सर्दियों में, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में अक्सर "गंभीर" या "खतरनाक" AQI लेवल (CREA, 2025) रिकॉर्ड होते हैं, जहाँ सबसे गरीब लोगों पर सबसे ज़्यादा बोझ पड़ता है।

पब्लिक चर्चा अक्सर पराली जलाने या दिवाली पर फिर से काम करने पर फोकस होती है। हालांकि ये घटनाएं प्रदूषण को बढ़ाती हैं, लेकिन ये मूल कारण नहीं हैं।

स्रोत-आबंटन अध्ययन लगातार दिखाते हैं कि वर्ष भर संरचनात्मक योगदानकर्ता - वाहनों से उत्सर्जन, औद्योगिक प्रक्रियाएं, निर्माण और विध्वंस से धूल, अनौपचारिक अपशिष्ट जलाना और घरेलू बायोमास का उपयोग - आधारभूत पीएम 2.5 के स्तर को बढ़ाते हैं।

मौसमी वजहें पहले से ही खतरनाक स्थिति को और खराब कर देती हैं।

नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) ने कुछ सुधार शुरू किए हैं, लेकिन इसके टारगेट अभी भी छोटे हैं और इसे लागू करने का तरीका कमज़ोर है। इसलिए, एक हेल्थ-सेंटर्ड, मल्टी-सेक्टोरल स्ट्रैटेजी ज़रूरी है।

अब ज़रूरी है, जिसमें ये बातें शामिल होनी चाहिए: ट्रांसपोर्ट में बदलाव: बसों, टैक्सियों, ऑटो-रिक्शा और दोपहिया वाहनों का बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक होना; डीज़ल ट्रकों से रेल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर माल ढुलाई शिफ्ट करना; असल दुनिया में एमिशन मॉनिटरिंग; और कम एमिशन वाले ज़ोन और कंजेशन प्राइसिंग शुरू करना।

औद्योगिक नियंत्रण: सख्त प्रवर्तन प्रदूषण कंट्रोल टेक्नोलॉजी और कोयला-आधारित प्रोसेस से धीरे-धीरे बदलाव।

कंस्ट्रक्शन रेगुलेशन: ज़रूरी धूल-दबाने के प्रोटोकॉल, घेरे के नियम और मशीन से सफाई।

वेस्ट-मैनेजमेंट सुधार: सोर्स पर ही अलग करना, डीसेंट्रलाइज़्ड ट्रीटमेंट, बायोमीथेनेशन और खुले में जलाने को खत्म करने के लिए साइंटिफिक लैंड रिमेडिएशन।

हेल्थ-सिस्टम इंटीग्रेशन: एक हेल्थ-सेंटर्ड फ्रेमवर्क में एयर क्वालिटी को रूटीन हेल्थकेयर में शामिल किया जाना चाहिए। रियल-टाइम AQI पर आधारित डिस्ट्रिक्ट-लेवल एडवाइजरी, स्कूल-हेल्थ प्रोग्राम में लंग-फंक्शन टेस्टिंग, और COPD और कॉग्निटिव डिक्लाइन के लिए स्क्रीनिंग।

एक बुनियादी अधिकार भारत को साफ़ हवा को एक बुनियादी अधिकार के तौर पर मानना चाहिए जो सबके विकास के लिए ज़रूरी है। वैज्ञानिक सबूत बहुत ज़्यादा हैं, और सेहत पर इसके असर को नकारा नहीं जा सकता। साफ़ हवा की रक्षा अब एक ऐसी राष्ट्रीय प्राथमिकता बन जानी चाहिए जिस पर कोई समझौता न हो — जो विज्ञान पर आधारित हो, पब्लिक हेल्थ से चले, और जिसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए।

(डॉ. सुधीर कुमार शुक्ला एक एनवायरनमेंटल साइंटिस्ट और सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट हैं। वे अभी मोबियस फाउंडेशन, नई दिल्ली में हेड-थिंक टैंक के तौर पर काम कर रहे हैं। sudheerkrshukla@gmail.com)

सार

भारत में एयर क्वालिटी का संकट बहुत बड़ा और गहरा है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में मॉनिटर किए गए 256 शहरों में से 150 शहर नेशनल PM 2.5 स्टैंडर्ड से ज़्यादा हैं। भारत का ऑफिशियल एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) अभी भी 500 पर ही है, हालांकि दिल्ली और दूसरे शहरों में रियल-टाइम प्रदूषण का लेवल अक्सर इस लिमिट से ज़्यादा हो जाता है।

ज़हरीली हवा का सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। यूनिवर्सिटी ऑफ़ शिकागो के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एयर क्वालिटी लाइफ़ इंडेक्स (AQLI) के अनुसार, लगभग 46% भारतीय ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ एयर पॉल्यूशन से उम्र काफ़ी कम हो जाती है।

नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) ने कुछ सुधार शुरू किए हैं, लेकिन इसके टारगेट अभी भी छोटे हैं और इसे लागू करने का तरीका कमज़ोर है।

इसलिए, अब एक हेल्थ-सेंटर्ड, मल्टी-सेक्टोरल स्ट्रैटेजी ज़रूरी है।

स्ट्रोक शुरू होने से पहले ही उसे रोकना: ऐसे तरीके जिनके बारे में सभी को पता होना चाहिए

Vikram Huded

ब्रेन स्ट्रोक भारत में सबसे खतरनाक पब्लिक हेल्थ चुनौतियों में से एक बना हुआ है। यह साफ़ है कि कई स्ट्रोक कभी हुए ही नहीं थे। स्ट्रोक एक लंबी, चुपचाप होने वाली प्रक्रिया की आखिरी घटना है — जिसे अब हमारे पास पता लगाने, धीमा करने और अक्सर रोकने के तरीके हैं।

स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाने वाली सबसे बड़ी वजहों में से एक दिमाग नहीं, बल्कि गर्दन है। कैरोटिड आर्टरीज़, जो दिमाग तक खून ले जाती हैं, फैटी प्लाक बनने की वजह से धीरे-धीरे पतली हो सकती हैं।

यह प्रोसेस अक्सर पूरी तरह से बिना किसी लक्षण के होता है। फिर भी जब प्लाक फट जाता है या थक्का बन जाता है, तो दिमाग में खून का बहाव अचानक रुक सकता है, जिससे पैरालिसिस हो सकता है, बोलने की शक्ति चली जाती है, या मौत भी हो सकती है।

हाल ही में, एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन, CREST-2 परीक्षण ने इस बारे में नई स्पष्टता प्रदान की कि हम कैसे जोखिम वाले लोगों को बेहतर तरीके से बचा सकता है। स्टडी में 2,400 से ज़्यादा लोगों को शामिल किया गया, जिन्हें गंभीर लेकिन बिना किसी लक्षण वाले कैरोटिड नैरोइंग की समस्या थी। सभी पार्टिसिपेंट्स को सबसे अच्छी मेडिकल थेरेपी दी गई — जिसमें ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दूसरे वैस्कुलर जोखिमों पर सख्त कंट्रोल शामिल था।

लेकिन, नतीजों से एक ज़रूरी बात पता चली: जिन लोगों ने कैरोटिड स्टेंटिंग भी करवाई थी, उनमें चार साल में स्ट्रोक या जल्दी मौत का खतरा, सिर्फ़ दवाओं से इलाज करवाने वालों के मुकाबले लगभग आधा था।

उपलब्ध टूल्स इसका मतलब यह नहीं है कि कैरोटिड बीमारी वाले हर व्यक्ति को इलाज की ज़रूरत है। हालांकि, इससे यह पक्का होता है कि गंभीर कैरोटिड सिकुड़न की शुरुआती पहचान उन लोगों को और सुरक्षा देने का मौका देती है जिन्हें सच में इसकी ज़रूरत है।

उपलब्ध सबसे सरल उपकरणों में से एक

स्ट्रोक से बचने का सबसे असरदार तरीका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज पर कंट्रोल रखना और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करना है। फाइल फोटो

हमारे लिए कैरोटिड डॉप्लर अल्ट्रासाउंड सबसे अच्छा है। यह नॉन-इनवेसिव टेस्ट साउंड वेव्स का इस्तेमाल करता है — बिना किसी रेडिएशन के — यह देखने के लिए कि प्लाक जमा हुआ है या नहीं और यह मापने के लिए कि आर्टरी कितनी सिकुड़ गई है। यह तेज़, दर्द रहित, आसानी से मिलने वाला और बहुत ही खास है।

जानकारी देने वाला। हालांकि इसे हर किसी के लिए बिना सोचे-समझे रिकमेंड नहीं किया जाता है, लेकिन यह उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है जिन्हें स्ट्रोक के कई रिस्क फैक्टर हैं। इनमें हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल, स्मोकिंग, हार्ट बीमारी, पेरिफेरल आर्टरी की बीमारी, या वैस्कुलर घटनाओं की फ़ैमिली हिस्ट्री। ऐसे रिस्क वाले 50-55 साल से ज़्यादा उम्र के बड़ों के लिए, सालाना हेल्थ चेकअप में कैरोटिड डॉप्लर स्कैन को शामिल करने से खतरनाक ब्लॉकेज का पता लगाने में मदद मिल सकती है, इससे पहले कि वे नुकसान पहुंचाएं।

बेसिक बातों पर ध्यान देना बेशक, कोई भी स्कैन बेसिक बातों की जगह नहीं ले सकता। स्ट्रोक से बचने का सबसे असरदार तरीका है ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ पर कंट्रोल रखना; स्मोकिंग छोड़ना; रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करना; और हेल्दी बॉडी वेट बनाए रखना। ये लाइफस्टाइल की बुनियाद हमारी सबसे मज़बूत सुरक्षा बनी हुई है।

साथ ही, हमें उन लक्षणों को भी याद रखना चाहिए जिनमें तुरंत मेडिकल मदद की ज़रूरत होती है। अचानक कमज़ोरी, चेहरा लटकना, बोलने में लड़खड़ाना, नज़र कमज़ोर होना, या अचानक असंतुलन होने पर हमेशा इलाज करवाना चाहिए। मेडिकल इमरजेंसी के तौर पर। ये छोटे, कुछ समय के एपिसोड — जिन्हें अक्सर वॉर्निंग स्ट्रोक कहा जाता है — गंभीर कैरोटिड बीमारी का पहला संकेत हो सकते हैं और किसी और बड़ी खतरनाक चीज़ को रोकने के लिए एक छोटा सा मौका दिखाते हैं।

जैसे-जैसे हम भारत के स्ट्रोक-तैयारी इकोसिस्टम को मज़बूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं, प्रोएक्टिव रिस्क असेसमेंट को बढ़ावा देना एक मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए। व्यक्ति के रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से गर्दन की आर्टरी का एक आसान स्कैन, एक साइलेंट खतरे को जल्दी पहचानने और डिसेबिलिटी होने के बाद ही पता चलने के बीच का अंतर हो सकता है। स्ट्रोक से बचाव न केवल मुमकिन है - बल्कि अगर हम समय पर एक्शन लें, तो यह हमारी पहुँच में है।

(डॉ. विक्रम हुडेड, नारायण हेल्थ, बेंगलुरु में इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजी प्रोग्राम के सीनियर कंसल्टेंट, डायरेक्टर और क्लिनिकल लीड हैं। vikram.huded.dr@ naranahealth.org)

दर्शकों के लिए खेलना

कर्नाटक का हेट क्राइम बिल बोलने की आज़ादी के लिए खतरा है। अच्छे इरादों से

जी ज़रूरी नहीं कि अच्छे नतीजे निकलें, और इस संदर्भ में इतिहास के इस सबक को फिर से याद करना ज़रूरी है।

कर्नाटक हेट स्पीच और हेट क्राइम (प्रिवेंशन) बिल, 2025। इसके पवित्र मकसद से बोलने की आज़ादी और व्यक्तिगत आज़ादी के खिलाफ़ अनजाने में होने वाले भयानक कामों और सरकारी ताकत के खुलेआम गलत इस्तेमाल की संभावना ज़्यादा है। इस प्रस्तावित कानून का मकसद हेट स्पीच और नफ़रत से प्रेरित कामों को रोकना और सज़ा देना है, जो अलग-अलग सुरक्षित विशेषताओं के आधार पर लोगों या ग्रुप के खिलाफ़ वैमनस्य, नफ़रत या हिंसा भड़काते हैं। आज़ाद समाजों में पब्लिक जगहों का खत्म होना वाकई परेशान करने वाला है, और सरकारें, पॉलिसी बनाने वाले और नागरिक इस बारे में सही तरह से चिंतित हैं। लोगों और समुदायों को उनके धर्म, नस्ल, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जाति और जेंडर के आधार पर पब्लिक प्लेटफॉर्म, खासकर सोशल मीडिया पर टारगेट किया जाता है। नफ़रत फैलाने वालों को कानून से एक तरह की सज़ा की गारंटी है। उन्हें अक्सर राजनीतिक ताकत और सामाजिक असर से इनाम मिलता है। साथी इंसानों के खिलाफ़ भेदभाव से शुरू होकर, हेट स्पीच को अक्सर गलत जानकारी और फेक न्यूज़ से बढ़ावा मिलता है। बोलचाल, भेदभाव और नफ़रत एक बुरा चक्र बनाते हैं, जिससे कभी-कभी ग्रुप और लोगों के खिलाफ़ हिंसा होती है। कर्नाटक में इन सबका हिस्सा बहुत ज़्यादा है, और राज्य सरकार ने सोचा होगा कि इससे निपटने के लिए एक खास कानून ही सही तरीका है।

दुनिया भर में ऐसी कोशिशें जितनी मुश्किलें हल नहीं कर रही हैं, उससे ज़्यादा खड़ी कर रही हैं। किसी भी वजह से बोलने पर रोक लगाना एक बुरा आइडिया है, और जब सरकार के किसी एजेंट को यह तय करने का अधिकार हो कि क्या अलाउड है और क्या नहीं, तो यह एक मुश्किल रास्ता है। इसका एक उदाहरण यह है कि कैसे कई पश्चिमी देशों में कानून लागू करने वाली एजेंसियां शांतिपूर्ण फ़िलिस्तीनी सपोर्ट वाली बातों को एंटी-सेमिटिक बताकर उन पर कार्रवाई करती हैं। कर्नाटक में प्रस्तावित कानून समेत ऐसे ज़्यादातर कानून जिन खासियतों को तय करने की कोशिश कर रहे हैं, वे हैं जिन्हें तय नहीं किया जा सकता, जैसे कि मेलजोल, नफ़रत, दुश्मनी और बुरी नीयत। सभी इस बात पर सहमत हैं कि किसी को भी नफ़रत या भेदभाव नहीं फैलाना चाहिए, और वे विरोधियों पर ऐसा करने का आरोप लगाते हैं। इस तय करने में ज़रूरी सब्जेक्टिविटी को देखते हुए, ताकतवर लोग ही जीतते हैं। बिल हेट स्पीच को ऐसी कोई भी बात (बोली, लिखी, दिखाई, इलेक्ट्रॉनिक) मानता है जो किसी व्यक्ति या ग्रुप के खिलाफ जानबूझकर चोट, मनमुटाव, दुश्मनी, नफ़रत या बुरी नीयत पैदा करने के लिए सबके सामने कही गई हो, जिसका कोई गलत मतलब हो। यह इतनी बड़ी और तानाशाही वाली हो कि इसके गलत इस्तेमाल का खतरा इससे हासिल होने वाले किसी भी सामाजिक फ़ायदे के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। एक आज़ाद समाज में बोलने पर कंट्रोल इसलिए होना चाहिए क्योंकि हिंसा का खतरा मंडरा रहा है, और मौजूदा कानून ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए काफ़ी हैं। कर्नाटक सरकार लोगों को खुश करने के लिए खेल रही है। और वह लोगों के साथ खेल रही है।

काल्पनिक सुरक्षा

US ग्लोबल दबदबे और अकेलेपन की कोशिश में है

टी अमेरिका ने अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट जारी किया है ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी (NSS) को एक रोड मैप बताया गया है, जो "यह पक्का करेगा कि अमेरिका आने वाले दशकों तक दुनिया का सबसे मज़बूत, सबसे अमीर, सबसे ताकतवर और सबसे सफल देश बना रहे।"

वॉशिंगटन ने विदेश नीति की पांच टॉप प्रायोरिटीज़ की पहचान की है। इनमें यह सोच शामिल है कि बड़े पैमाने पर माइग्रेशन का दौर खत्म हो गया है, बोलने की आज़ादी और धर्म की आज़ादी समेत ज़रूरी अधिकारों और आज़ादी को पहले से कहीं ज़्यादा सुरक्षित रखने की ज़रूरत है, कि "US के एटलस की तरह पूरी दुनिया को सहारा देने के दिन अब खत्म हो गए हैं", कि व्हाइट हाउस इसे दुनिया भर में शांति समझौतों को आगे बढ़ाने पर दोगुना ज़ोर देना ज़रूरी समझता है ताकि विदेशों में US का असर मज़बूत हो सके, और कि विदेश नीति में आर्थिक सुरक्षा को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। नेशनल सिक्योरिटी के आखिरी पिलर के लिए, खासकर, दूसरे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी समय के लिए मिलकर उठाए जाने वाले कदमों में बैलेंस्ड ट्रेड हासिल करने, ज़रूरी सप्लाई चेन और मटीरियल तक पहुँच पक्की करने, US अर्थव्यवस्था का रीइंडस्ट्रियलाइज़ेशन करने, अमेरिकी डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने, एनर्जी में दबदबा बनाने, और वॉल स्ट्रीट को दुनिया भर में "डायनामिक फ्री मार्केट सिस्टम और डिजिटल फाइनेंस और इनोवेशन में हमारी लीडरशिप" का फ़ायदा उठाने में मदद करने की कोशिशें शामिल होंगी।

हालांकि US की विदेश नीति की प्राथमिकताओं की बड़ी-बड़ी बातें उनके बड़े ज़ोर में कोई हैरानी की बात नहीं हैं, शायद, हमेशा रहने वाले, बिना किसी सवाल के अमेरिकी खासियत के लगातार सब-टेक्स्ट के अलावा, यह यूरोपियन साथियों के खिलाफ़ हमला है जो पूरे कॉन्टिनेंट में रीजनल स्टेबिलिटी के लिए खतरा पैदा करने वाली सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात है।

NSS न सिर्फ़ यूरोप के बारे में एक नरम रवैया अपनाता है, जो अपनी कथित आर्थिक गिरावट की वजह से "सभ्यता के खत्म होने की कड़ी संभावना" का सामना कर रहा है, बल्कि यह जर्मनी और EU देशों को भी दोषी ठहराता है, जहाँ "अस्थिर अल्पसंख्यक सरकारें" हैं, जिनके पॉलिसी एक्शन यूक्रेन में रूस के युद्ध के संदर्भ में शांति के लिए उनकी कही गई इच्छा से मेल नहीं खाते। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल ने जवाब दिया कि जर्मनी के संदर्भ में, उन्हें नहीं लगता कि "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या हमारे स्वतंत्र समाजों के संगठन के सवाल" US NSS में आते हैं और उनके देश को "बाहरी सलाह" की ज़रूरत नहीं है। जबकि NSS वॉशिंगटन द्वारा तय विदेश नीति के लक्ष्यों के लिए एक एकजुट नज़रिए की ओर US डिप्लोमैट्स को गाइड करने के लिए एक संकेत है, इसके नए वर्शन ने NATO की ताकत को लेकर चिंताओं को और बढ़ा दिया है। अगर, जैसा कि NSS कहता है, US अपने सभी साथियों को अपने इलाकों में स्थिरता की ज़िम्मेदारी लेने के लिए मजबूर करने के लिए एक "बर्डन-शेयरिंग नेटवर्क" बनाना चाहता है, तो इससे दुनिया भर में तानाशाहों की उस सोच को बढ़ावा मिल सकता है जिससे वे सत्ता की चाहत में इलाके और मानवाधिकारों के नियमों को तोड़ रहे हैं।

भारत में पढ़ाई के खर्च की कड़वी सच्चाई

ए भारत के संविधान का आर्टिकल 21A (86वां अमेंडमेंट, 2002) छह से 14 साल के बच्चों को मुफ़्त और ज़रूरी शिक्षा का अधिकार देता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 इस विज़न को तीन से 18 साल के बच्चों को कवर करने के लिए बढ़ाती है, जिससे प्री-प्राइमरी से हायर सेकेंडरी (क्लास 12) तक यूनिवर्सल एजुकेशन का लक्ष्य बढ़ाया गया है। NEP का मकसद 2030 तक सेकेंडरी लेवल तक स्कूली शिक्षा को यूनिवर्सल बनाना है। हालांकि शिक्षा मुफ़्त होनी चाहिए, फिर भी कई छात्र प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा फीस ली जाती है। इसके अलावा, कई कारणों से, कई छात्र प्राइवेट कोचिंग भी लेते हैं, जिससे पैसे का बोझ बढ़ जाता है।

मुफ़्त शिक्षा की संवैधानिक गारंटी को देखते हुए, भारत में बेसिक स्कूलिंग कितनी महंगी है? माता-पिता असल में अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कितना खर्च करते हैं — एक ज़िम्मेदारी जो, सिद्धांत रूप में, संविधान में बताई गई सरकार की है? NSS का 80वां राउंड (अप्रैल-जून 2025) सर्वे, "कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे: एजुकेशन" पर, इन सवालों को समझने के लिए लेटेस्ट डेटा देता है।

स्कूलों में एनरोलमेंट ट्रेंड्स नेशनल लेवल पर, 55.9% स्टूडेंट्स सरकारी स्कूलों में, 11.3% प्राइवेट एडेड स्कूलों में, और 31.9% प्राइवेट अनएडेड स्कूलों में एनरोल हैं। प्राइवेट स्कूलों में एनरोलमेंट ग्रामीण सेक्टर की तुलना में शहरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा है। शहरी इलाकों में कुल स्कूली बच्चों में से 51.4% प्राइवेट स्कूल में एनरोल हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह हिस्सा 24.3% है। हालांकि, प्राइवेट स्कूल एनरोलमेंट में जेंडर गैप काफ़ी कम है — लड़कों का 34% और लड़कियों का 29.5%।

ग्रामीण क्षेत्र में, बच्चों का नामांकन अधिक होता है

प्राइवेट स्कूलों की तुलना में सरकारी स्कूलों में ज़्यादा।

प्राइवेट स्कूल में एनरोलमेंट प्री-प्राइमरी में 28.1%, प्राइमरी में 25.9%, मिडिल और सेकेंडरी में 21% और हायर सेकेंडरी में 25.8% है। इसके उलट, शहरी सेक्टर में, प्राइवेट स्कूलों में एनरोल बच्चों का हिस्सा बहुत ज़्यादा है — प्री-प्राइमरी में 62.9%, प्राइमरी में 55.3%, मिडिल में 49.8%, सेकेंडरी में 44% और हायर सेकेंडरी में 42.3%। जैसे-जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ता है, शहरी इलाकों में प्राइवेट स्कूल में एनरोलमेंट कम होता जाता है।

पहले दौर की तुलना में NSS सर्वे ऑन एजुकेशन (75वां राउंड; जुलाई 2017-जून 2018) में, हमने देखा कि प्राइवेट स्कूलों में एनरोल बच्चों का हिस्सा बढ़ा है। ग्रामीण इलाकों में, प्राइमरी लेवल पर प्राइवेट स्कूलों में एनरोल बच्चों का हिस्सा 20.9% से बढ़कर 25.9% हो गया, मिडिल लेवल पर 16.7% से बढ़कर 21% हो गया, और सेकेंडरी लेवल पर 17.3% से बढ़कर 21.1% हो गया। शहरी इलाकों में, प्राइमरी लेवल पर प्राइवेट स्कूलों में एनरोल बच्चों का हिस्सा 50.5% से बढ़कर 55.3% हो गया, और मिडिल लेवल पर 41.8% से बढ़कर 49.8% हो गया। प्राइवेट स्कूलों में इस बढ़ते एनरोलमेंट की वजह से पढ़ाई का खर्च बढ़ रहा है।

सरकारी और निजी स्कूलों में नामांकन यह शिक्षा के खर्च से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है।

वाचस्पति शुक्ल
सरदार पटेल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।
आर्थिक और सामाजिक अनुसंधान संस्थान
(एसपीआईएसआर),
अहमदाबाद, गुजरात

Santosh Kumar
थोड़ा सा
is Assistant Professor at IRMA, 'Tribhuvan' सहकारी विश्वविद्यालय, Gujarat

का अंत
एनएसएस 80वां
गोल सर्वेक्षण,
पर
'विस्तृत
मॉड्यूलर
सर्वे:
शिक्षा', में असमानताएँ
बढ़ रही हैं

तक पहुंच
गुणवत्ता की
शिक्षा

सर्वे में पूछा गया कि क्या स्टूडेंट्स को कोई कोर्स फीस देनी पड़ती है। ग्रामीण इलाकों में, 25.3% सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स और 98.2% प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स ने कोर्स फीस देने की बात कही। शहरी इलाकों में, 34.7% सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स और 98% प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स ने कोर्स फीस देने की बात कही।

सर्वे से पता चलता है कि सरकारी स्कूलों में हर एकेडमिक साल की फीस के लिए, गांव के स्कूलों में फीस ₹823 (प्री-प्राइमरी) से ₹7,308 (हायर सेकेंडरी) तक है, जबकि शहर के स्कूलों में फीस ₹1,630 (प्री-प्राइमरी) से ₹7,704 (हायर सेकेंडरी) तक है। प्राइवेट स्कूलों में, गांव के स्कूलों में फीस ₹17,988 (प्री-प्राइमरी) से शुरू होती है और ₹33,567 (हायर सेकेंडरी) तक जाती है, जबकि शहर के स्कूलों में फीस ₹26,188 (प्री-प्राइमरी) से ₹49,075 (हायर सेकेंडरी) तक है।

जब इन आंकड़ों को मासिक में बदला जाता है अगर तुलना करें, तो प्राइवेट स्कूलिंग का फाइनेंशियल बोझ और भी साफ़ हो जाता है। गांव के इलाकों में, प्राइवेट स्कूलिंग पर महीने का खर्च प्री-प्राइमरी के लिए ₹1,499 से लेकर हायर सेकेंडरी के लिए ₹2,797 तक है। शहरी इलाकों में, ये आंकड़े काफ़ी बढ़कर ₹2,182 से ₹4,089 हो जाते हैं। जब हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे (HCES) 2023-24 सर्वे के मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर (MPCE) से तुलना की जाती है, तो यह साफ़ है कि प्री-प्राइमरी लेवल पर प्राइवेट स्कूलिंग का खर्च लगभग सबसे गरीब 5% घरों की महीने की इनकम के बराबर है, जबकि हायर सेकेंडरी लेवल पर खर्च तीसरे इनकम डेसिल में घरों के MPCE के बराबर है। यह साफ़ अंतर उस फाइनेंशियल दबाव को दिखाता है जिसका सामना कई परिवार अच्छी क्वालिटी की शिक्षा पाने में करते हैं।

निजी ट्यूशन का प्रभाव और लागत सर्वेक्षण में इस बारे में जानकारी एकत्र की गई कि क्या कोई छात्र चालू शैक्षणिक वर्ष के दौरान निजी कोचिंग ले रहा था या ले चुका था। इस सर्वेक्षण में, निजी कोचिंग की जानकारी अलग से एकत्र की गई थी न कि स्कूली शिक्षा पर होने वाले खर्च के घटक के रूप में। सर्वेक्षण में पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 25.5% बच्चे और शहरी क्षेत्रों में 30.7% बच्चे निजी कोचिंग लेते हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निजी ट्यूशन लेने वाले छात्रों का अनुपात बढ़ता है क्योंकि हम शिक्षा के निम्न से उच्च स्तर की ओर बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्री-प्राइमरी में 10.7%, प्राइमरी में 21.6%, मिडिल में 29.1%, सेकेंडरी में 36.7% और हायर सेकेंडरी में 33.1% है। शहरी क्षेत्रों में यह प्री-प्राइमरी में 13.6%, प्राइमरी में 26.6%, मिडिल में 31%, सेकेंडरी में 40.2% और हायर सेकेंडरी में 44.6% है।

प्राइवेट कोचिंग पर औसत खर्च

इस एकेडमिक साल में हर स्टूडेंट पर खर्च शहरी सेक्टर में ग्रामीण सेक्टर के मुकाबले ज़्यादा है। शहरी इलाकों में यह ₹13,026 और ग्रामीण इलाकों में ₹7,066 है। जैसे-जैसे हम शिक्षा के निचले लेवल से ऊंचे लेवल की ओर बढ़ते हैं, प्राइवेट कोचिंग पर औसत खर्च बढ़ता जाता है। ग्रामीण इलाकों में, यह प्री-प्राइमरी के लिए ₹3,980, प्राइमरी के लिए ₹4,825, मिडिल के लिए ₹6,043, सेकेंडरी के लिए ₹8,616 और हायर सेकेंडरी के लिए ₹13,803 है। शहरी इलाकों में, यह प्री-प्राइमरी के लिए ₹5,815, प्राइमरी के लिए ₹7,947 है।

मिडिल के लिए ₹10,765, सेकेंडरी के लिए ₹16,415, और हायर सेकेंडरी के लिए ₹22,394।

रिसर्च से पता चलता है कि घर की ज़्यादा इनकम, बेहतर पढ़े-लिखे माता-पिता और शहर में रहने का प्राइवेट ट्यूशन की ज़्यादा डिमांड से गहरा संबंध है। स्टडीज़ में यह भी देखा गया है कि स्टूडेंट्स के सीखने के नतीजों पर प्राइवेट ट्यूशन का पॉज़िटिव और अहम असर होता है।

इसलिए, जो माता-पिता पढ़ाई को बहुत महत्व देते हैं और जिनके पास पैसे होते हैं, वे अपने बच्चों के लिए प्राइवेट ट्यूशन में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए, प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स में प्राइवेट ट्यूशन लेने का झुकाव खास तौर पर ज़्यादा होता है। हालांकि प्राइवेट स्कूलिंग में फीस काफी ज़्यादा होती है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में कई टीचरों को कम पैसे मिलते हैं और वे अक्सर काबिल भी नहीं होते, जिससे स्टूडेंट्स पढ़ाई में मदद के लिए प्राइवेट ट्यूशन पर निर्भर हो जाते हैं।

इसके अलावा, कुछ जानकारों का कहना है कि प्राइवेट ट्यूशन भी परिवारों के बीच इज़्ज़त का सिंबल बन गया है।

सरकारी पैसे से चलने वाले स्कूलों को मज़बूत करें। NSS के 80वें राउंड के सर्वे के नतीजे भारत में पढ़ाई के खर्च की कड़वी सच्चाई दिखाते हैं। मुफ़्त शिक्षा की संवैधानिक गारंटी के बावजूद, बहुत सारे स्टूडेंट (गांव में 24.3% और शहर में 51.4%) प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा फ़ीस लगती है। प्राइवेट ट्यूशन से घर के खर्च पर और बोझ पड़ने से, कई परिवारों के लिए, खासकर कम इनकम वाले परिवारों के लिए, पढ़ाई करना मुश्किल होता जा रहा है।

यह ट्रेंड न सिर्फ़ अच्छी शिक्षा तक पहुँच में असमानता को बढ़ा रहा है, बल्कि बेसिक और सबके लिए शिक्षा के सिद्धांत के लिए भी खतरा बन रहा है। जैसे-जैसे सरकारी स्कूलों में एडमिशन कम हो रहे हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के बच्चों को प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम में धकेला जा रहा है, अक्सर इसकी कीमत पर उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे का बोझ उठाना पड़ता है।

इसके अलावा, प्राइवेट ट्यूशन का बढ़ता चलन सीखने में असमानता को बढ़ा रहा है, जहाँ अमीर लोगों को ज़रूरतमंद परिवारों के मुकाबले ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसलिए, सरकारी पैसे से चलने वाले स्कूलों में सीखने की क्वालिटी को मज़बूत करके इस ट्रेंड को रोका जा सकता है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए तुरंत सुधार। सरकारी स्कूलों की क्वालिटी और पहुँच को मज़बूत करना यह पक्का करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि शिक्षा एक अधिकार बनी रहे, न कि खास अधिकार। द जर्नल ऑफ़ डेवलपमेंट स्टडीज़ में छपी इकोनॉमिस्ट अंकुश अग्रवाल, पारुल गुप्ता और देबाशीष मंडल की 2024 की एक स्टडी में पाया गया है कि प्राइवेट ट्यूशन का स्कूल की क्वालिटी इंडिकेटर्स से नेगेटिव कनेक्शन है। इसका मतलब है कि 'बेहतर' स्कूलों के स्टूडेंट ट्यूशन पर कम डिपेंड करते हैं।

इस तरह, सीखने की क्वालिटी को मज़बूत करने से अलग-अलग सोशियो-इकोनॉमिक बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के बीच बढ़ते अंतर को कम करने में मदद मिलेगी। सिर्फ़ इन कोशिशों से ही हम भारत में सभी बच्चों के लिए सही मायने में बराबर और सबको साथ लेकर चलने वाली शिक्षा पाने की तरफ बढ़ सकते हैं।

मद्रास हाई कोर्ट को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए

ए उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सभी नियुक्तियाँ कोर्ट द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए कॉलेजियम, जिसमें मुख्य हाई कोर्ट के जस्टिस और दो सबसे सीनियर जज। यह रिकमेंडेशन फिर राज्य सरकार को भेजी जाती है। बदले में, राज्य सरकार ऑब्जेक्शन उठा सकती है और क्लैरिफिकेशन मांग सकती है। अगर कॉलेजियम अपनी पसंद दोहराता है या क्लैरिफिकेशन देता है, तो सरकार उस फैसले को मानने के लिए बाउंड है।

स्पष्टीकरण मांगा गया 9 नवंबर, 2025 को मद्रास हाई कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्ट में प्रमोशन के लिए छह डिस्ट्रिक्ट जजों के नामों की सिफारिश की। राज्य सरकार ने उम्मीदवारों की मेरिट या सूटेबिलिटी पर कोई आपत्ति नहीं जताई, बल्कि एक बुनियादी प्रोसेस से जुड़ी चिंता, यानी कॉलेजियम के गठन पर स्पष्टीकरण मांगा।

जस्टिस जे. निशा बानू, जो कभी मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच में महिला वकीलों के एसोसिएशन की हेड थीं, उन्हें 5 अक्टूबर, 2016 को हाई कोर्ट बेंच में प्रमोट किया गया था। बेंच पर नौ साल से ज़्यादा के करियर में, जस्टिस निशा बानू अब सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं और हाई कोर्ट की दूसरी सबसे सीनियर जज हैं। वह अब मद्रास हाई कोर्ट में 'कॉलेजियम जज' हैं।

लेकिन, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने 14 अक्टूबर, 2025 को एक नोटिस जारी किया, जिसमें जस्टिस निशा बानू का केरल हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया और उन्हें सीनियरिटी में नौवें स्थान पर रखा गया, जिसके कारण पता नहीं हैं।

लेकिन सच तो यह है कि जस्टिस निशा बानू ने जॉइन नहीं किया। माना कि हर लॉर्डशिप मद्रास हाई कोर्ट का हिस्सा हैं और वह कॉलेजियम जज बनी हुई हैं। इसलिए, राज्य सरकार ने कॉलेजियम जज जस्टिस निशा बानू को शामिल न करने और अगले सबसे सीनियर जज जस्टिस एमएस रमेश को शामिल करने पर सफाई मांगी थी।

राज्य सरकार ने इस बात पर सफाई मांगी कि इस बदलाव के लिए कानूनी अधिकार क्या है और क्या यह सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्देश या संवैधानिक सिद्धांत से सपोर्टेड है।

जीएम अकबरअली
एक पूर्व न्यायाधीश हैं,
मद्रास उच्च न्यायालय

हाई कोर्ट को यह साफ़ करना चाहिए कि क्या

हाल ही में न्यायिक नियुक्तियों के मामले में कॉलेजियम की सिफारिशें संविधान और संविधान के अनुसार थीं।

प्रक्रिया ज्ञापन

इन चिंताओं को साफ़ करने के बजाय, कॉलेजियम ने राज्य द्वारा पहले उठाए गए कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के मुख्य मुद्दे को साफ़ किए बिना, और खाली जगहों को भरने के लिए नौ और वकीलों की सिफारिश कर दी।

संवैधानिक लोकतंत्र का सार है सिर्फ़ लिखे हुए टेक्स्ट में ही नहीं, बल्कि इसके इंस्टीट्यूशन की ईमानदारी में भी। ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस — जिसे सुप्रीम कोर्ट के अपने ज्यूरिस्प्रूडेंस ने कॉलेजियम सिस्टम के ज़रिए सुरक्षित रखा है — उस ईमानदारी के दिल में है। क्या कॉलेजियम यह मान रहा है कि जस्टिस निशा बानू मद्रास हाई कोर्ट का हिस्सा नहीं हैं या उसने आगे बढ़ने के लिए किसी अधिकार के साथ इस मुद्दे को पहले ही साफ़ कर दिया है? जो भी हो, राज्य को सफ़ाई का हक़ है।

मेमोरेंडम ऑफ़ प्रोसीजर के मुताबिक, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में, हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस और उस हाई कोर्ट के दो सबसे सीनियर जज नामों की सिफ़ारिश करेंगे। लेकिन यहाँ मद्रास हाई कोर्ट में, एक सीनियर जज को नज़रअंदाज़ किया गया।

जब प्रोसीजर ही सब्सटेंस बन जाता है। कभी-कभी यह तर्क दिया जाता है कि प्रोसीजरल डेविएशन मामूली होते हैं — कि अच्छे कैंडिडेट्स को "टेक्निकल" वजह से मना नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्किटेक्चर में, प्रोसीजर कोई सजावट नहीं है। यह नींव है। कॉलेजियम सिस्टम खुद एक क्रिएशन है, कानून से नहीं, बल्कि ज्यूडिशियल मिसाल से और इसलिए, लेजिटिमेसी बनाए रखने के लिए ज्यूडिशियली बनाए गए नॉर्म्स का सख्ती से पालन करना चाहिए।

जब कोई जज जो एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार का इस्तेमाल करता रहता है, उसे बिना किसी रिकॉर्डेड जस्टिफिकेशन के बाहर कर दिया जाता है, और जब किसी दूसरे जज को बिना ज्यूरिस्डिक्शनल सपोर्ट के शामिल किया जाता है, तो फैसले लेने वाली संस्था पर ही सवाल उठने लगते हैं। अगर सिफारिश करने वाली बॉडी ठीक से नहीं बनी है, तो सिफारिशें खुद ही बेकार होने का खतरा है। यह सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव चूक नहीं है। यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल संकट है क्योंकि ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट्स की ईमानदारी इस अनिश्चितता के साथ नहीं रह सकती कि उन्हें करने का अधिकार किसे है और ऐसी स्थिति में जहां दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रांच अंधेरे में हो।

कॉलेजियम सिस्टम की खुद इसकी आलोचना की जाती है

पारदर्शिता की कमी, भाई-भतीजावाद, सभी वर्गों में योग्य सदस्यों का कम या गैर-प्रतिनिधित्व, राजनीतिक प्रभाव और जवाबदेही।

सुधारों की ज़रूरत मद्रास हाई कोर्ट कॉलेजियम को कानून या प्रक्रिया के संदर्भ में यह स्पष्ट करना चाहिए कि जस्टिस निशा बानू को क्यों बाहर रखा गया और जस्टिस एम.एस. रमेश को शामिल किया गया।

जब मामला ज्यूडिशियल इंडिपेंडेंस की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी पर हमला करता है, तो चुप रहना कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो, यह एक नागरिक को सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या इसके पीछे 'कोई मकसद' था।

चाहे असंतुष्ट हो या संतुष्ट, अलग-थलग हो या अलग-थलग, विचारधारा वाला हो या धार्मिक, एक जज तो जज ही होता है।

हाई कोर्ट को कुराल 541 पर ध्यान देना चाहिए,

"ओरन्धुकन नोताधु इराईपुरीन्धु यारमाट्टुम थेरन्धुसे वक्दहे मुराई (खोज करो, किसी को कोई एहसान मत दिखाओ; उस हृदय से जो न्याय को प्रिय है, परामर्श करो, फिर कार्य करो; यही वह नियम है जिसे अधिकार अनुमोदित करता है")।

इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को कॉलेजियम सिस्टम पर फिर से विचार करना चाहिए और उन सुधारों को बनाना चाहिए जिनकी लंबे समय से मांग की जा रही है, और कम्पोजीशन के साफ़ नियम, पब्लिश किए गए कारण, और ज़रूरी डिस्क्लोज़र पक्का करना चाहिए।

सवाल यह नहीं है कि ये छह जिले जज या नौ वकील योग्य उम्मीदवार हैं, हालांकि नौ वकीलों का चुनाव राजनीतिक पसंद या विचारधारा के हिसाब से सही लगता है। सवाल यह है कि क्या पदोन्नति के लिए उनकी सिफारिशों का तरीका भारत के संविधान के आर्टिकल 217 और मेमोरेंडम ऑफ़ प्रोसीजर के मुताबिक है, जिसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के दो सबसे सीनियर जज हाई कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करेंगे।

एक बार जब कॉलेजियम का गठन संदिग्ध हो जाता है, तो सिफारिशें भी संदिग्ध हो जाती हैं और संविधान की दो शाखाओं, न्यायपालिका और राज्य सरकार के बीच निश्चित रूप से एक संवैधानिक संकट पैदा हो जाता है।

द टर्सटूदएडिटर

संसद, बहसें

संसद में वंदे मातरम 'मुद्दे' और चुनाव सुधारों पर बहस का एकमात्र नतीजा कटु, विवादित और बेइज्जत करने वाली बहसें ही लगती हैं। राजनीतिक गलियारे के दोनों तरफ से।

चर्चा के मुद्दों पर कोई क्लैरिटी नहीं थी और सिर्फ़ कीमती समय बर्बाद हुआ। क्योंकि दोनों पक्ष अपनी बात पर अड़े रहे। इस पर बातचीत अटक गई। सरकारी खजाने पर होने वाले खर्च को देखते हुए यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

V. Padmanabhan,
Bengaluru

सोशल मीडिया बैन ऑस्ट्रेलिया का 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन एक मुश्किल लेकिन सही समय पर लिया गया फैसला है और इस पर दुनिया भर का ध्यान देने की ज़रूरत है ('वर्ल्ड' पेज, 12 दिसंबर)। इसमें कोई शक नहीं है कि इसका लंबे समय के लिए एक साफ़ और प्रेरणा देने वाला नज़रिया है और यह एक फ़ायदा साबित होगा। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री का यह बड़ा फ़ैसला निश्चित रूप से मोटिवेट करेगा। दूसरे विकसित देशों को भी इस दिशा में सोचना चाहिए।

विजया सेगरा रामसाईत, कोर्टलम,
तेनकासी, तमिलनाडु

letters@thehindu.co.in
पर ईमेल किए गए पत्रों में डाक का पता होना चाहिए।

Machine Translated by Google

क्या गिरता रुपया चिंता की बात है?

मदन सबनवीस

बैंक ऑफ अमेरिका के मुख्य अर्थशास्त्री बड़ौदा

घायल बनर्जी

भागीदार और आर्थिक पीडब्ल्यूसी इंडिया में सलाहकार नेता

बातचीत

पिछले कुछ दिनों में रुपया एक्सचेंज रेट ₹90 प्रति डॉलर से नीचे आ गया है और ज़्यादातर उसी लेवल पर बना हुआ है। अब, जब पार्लियामेंट चल रही है, तो इस पर ज़्यादातर बातचीत पॉलिटिकल हो गई है।

लेकिन, पॉलिसी लेवल पर, इस गिरावट के पीछे की इकोनॉमिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। रुपया क्यों गिर रहा है? क्या यह दूसरी करेंसी से भी ज़्यादा गिर रहा है? क्या इस गिरावट से इंडियन इकोनॉमी को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? और आखिर में, क्या यह चिंता की बात है?

मदन सबनवीस और रानेन बनर्जी ने TCA शरद राघवन द्वारा मॉडरेट की गई बातचीत में इन सवालों के जवाब दिए। एडिटेड अंश:

रुपया क्यों गिर रहा है?

मदन सबनवीस: यह कई वजहों से गिर रहा है। पहली वजह यह है कि फंडामेंटल्स पक्का नेगेटिव हैं। जब मैं फंडामेंटल्स की बात करता हूं, तो मेरा मतलब है ज़्यादा ट्रेड डेसिट, शायद ज़्यादा करंट अकाउंट डेसिट, और FPIs (फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स) का मूवमेंट, जो पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव रहे हैं। ये फंडामेंटल फैक्टर्स हैं और ये हमारे फॉरेक्स रिज़र्व के नीचे आने के रूप में भी दिखते हैं।

लेकिन मुझे लगता है कि जो वजह रही है रुपये में गिरावट ज़्यादातर टैरिफ के मोर्चे पर है, जहां उम्मीद थी कि भारत और अमेरिका के बीच कोई डील होगी।

ऐसा लगता है कि यह होने वाला है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि यही वजह है कि सेंटिमेंट दूसरी तरफ मुड़ गया है।

रुपये की कीमत गिरने के इस पूरे मामले में, एक ज़रूरी वजह जो रुपये की गिरावट को कुछ हद तक कम करती है, वह है RBI (भारतीय रिज़र्व बैंक) का दखल। अब, हमने देखा है कि फ़ॉरेक्स मार्केट में RBI का दखल कम ही रहा है। ऐसा लगता है कि रुपये की गिरावट RBI की मंज़ूर लिमिट के अंदर है, हालांकि हमें पहले ही यह कह देना चाहिए कि RBI का कहना है कि वह किसी रेट का बचाव नहीं कर रहा है, बल्कि मार्केट में किसी भी ज़्यादा उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए है। इन्हीं वजहों से हमने रुपये को ₹87 से ₹88, फिर ₹89 और अब ₹90 के पार जाते देखा है।

रानेन बनर्जी: रुपया दो या तीन वजहों से गिर रहा है। सबसे बड़ी वजह है पोर्टफोलियो से लगातार हो रहा आउटगो, जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। दूसरी वजह, हमारी इंपोर्ट ग्रोथ एक्सपोर्ट ग्रोथ से ज़्यादा रही है। और इससे डॉलर की डिमांड भी बढ़ी है। करंट अकाउंट डेसिट ज़्यादा रहा है। तो मुझे लगता है कि यह डॉलर की डिमांड और सप्लाई और RBI डिमांड को पूरा करने के लिए अपने रिज़र्व से कितना रिलीज़ करता है, इस पर निर्भर करता है। तारी एग्रीमेंट पर अनिश्चितता आगे की चुनौती पैदा करती है।

और इसका असर इकॉनमी पर भी पड़ सकता है।

गेटी इमेजेज

इससे पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के कुछ सेंटिमेंट पर असर पड़ सकता है, जो इंडियन मार्केट से पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पैसे निकालने का यही मुख्य कारण है।

मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स का मुख्य नज़रिया यह है कि वैल्यूएशन ज़्यादा हैं और वे तुरंत उस कैपिटल को लगाकर दूसरी इकॉनमी में ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं।

तो, यह पोर्टफोलियो के मुनाफे पर असर डाल रहा है। और हाँ, ट्रेड के मोर्चे पर अनिश्चितता भी इस भावना को और बढ़ा रही है।

क्या गिरता रुपया अर्थव्यवस्था में कमजोरी का संकेत है?

MS: बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आप इकॉनमी की पूरी हालत देख रहे हैं, अगर आप GDP के मोर्चे पर परफॉर्मेंस देखें, तो यह काफी शानदार रहा है, जिस तरह की ग्रोथ रेट हमने साल के पहले छह महीनों में देखी है। इसलिए, मुझे नहीं लगता कि इसका असली इकॉनमी से कोई लेना-देना है। बैलेंस ऑफ़ पेमेंट्स काफी मज़बूत है। RBI गवर्नर ने यह भी बताया था कि फंड रिज़र्व 11 महीने के इंपोर्ट को कवर कर रहे हैं। इसलिए, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। यह ज़्यादातर सेंटिमेंट की वजह से है जो रुपये को नीचे ले जा रहा है।

RB: मुझे नहीं लगता कि इकॉनमी में कोई स्ट्रक्चरल बदलाव हुआ है जो रुपये पर असर डाल रहा है। फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं। हमारी ग्रोथ अच्छी हो रही है।

स्थिति ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी काफी मददगार है। रेट में कटौती की गई है।

स्केल कंसोलिडेशन हो चुका है। कैपिटल खर्च हो रहा है। सरकार अपने बनाए स्केल रोडमैप को मान रही है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि स्ट्रक्चर के हिसाब से कुछ बड़ा बदलाव हुआ है। मेरा मानना है कि स्ट्रक्चरल फैक्टर्स के बजाय, रुपये की गिरावट पर ज़्यादा कुछ समय के लिए असर डालने वाले फैक्टर्स हैं।

"

मुझे नहीं लगता कि हम ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ हमें घबराने की ज़रूरत है। शायद पिछले तीन महीनों में हम सबसे खराब परफॉर्म करने वाली करेंसी हैं। लेकिन अगर हम दो साल का समय लें, तो मुझे लगता है कि कोरियन करेंसी के अलावा, बाकी सभी इमर्जिंग मार्केट करेंसी की कीमत डॉलर के मुकाबले रुपये से कहीं ज़्यादा कम हुई है।

रानेन बनर्जी

क्या आपको लगता है कि गिरते रुपये से भारत को कोई फ़ायदा होगा?

MS: रुपये के गिरने से हमें जो एकमात्र फ़ायदा होगा, वह ज़्यादातर थ्योरेटिकल होगा। जब मैं थ्योरेटिकल कहता हूँ, तो इकोनॉमिक थ्योरी कहती है कि जब रुपया कमज़ोर होता है, तो आपके एक्सपोर्ट को दूसरे देशों के मुकाबले कॉम्पिटिटिव फ़ायदा मिलता है। एक्सपोर्ट के नज़रिए से, अगर दूसरी करेंसी कमज़ोर नहीं हो रही हैं, लेकिन रुपया कमज़ोर हो रहा है, शायद लगभग 4-5%, जैसा कि हमने इस कैलेंडर साल में देखा है, तो यह हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए एक फ़ायदा है। US ने जो ज़्यादा टैरिफ़ लगाए हैं, उन्हें रुपये के कमज़ोर होने से हमें मिलने वाली प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस से कुछ हद तक कम किया जा सकता है।

इम्पोर्ट और महंगा हो जाएगा। हम जो भी सामान इम्पोर्ट कर रहे हैं, वह 4-5% महंगा हो जाएगा। लेकिन सिर्फ़ इन्वेंशन के नज़रिए से, अगर आप CPI (कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स) के हिस्सों को देखें और इम्पोर्ट की वजह से असल में क्या असर पड़ता है, तो हमारा कैलकुलेशन दिखाता है कि लगातार 5% डेप्रिसिएशन से इन्वेंशन लगभग 0.3-0.4% बढ़ सकता है, जो असल में बहुत ज़्यादा नहीं है। और यह देखते हुए कि इंडिया में इन्वेंशन अब तक के सबसे निचले लेवल पर है, यह हमारे लिए कोई बड़ी चिंता की बात नहीं होनी चाहिए।

RB: एक्सपोर्टर्स शायद खुश हों कि उन्हें बेहतर रियलाइज़ेशन मिल रहा है। और, वे यह भी खुश हो सकते हैं कि कुछ मुश्किलों को देखते हुए, हमारे प्रोडक्ट्स थोड़े और कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। अगर आप सर्विसेज़ को देखें, तो सर्विसेज़ एक्सपोर्ट हमारी इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और यह बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसलिए जो कंपनियाँ सर्विसेज़ एक्सपोर्ट कर रही हैं, उनकी रुपये के हिसाब से बॉटम लाइन बेहतर होगी। कौन जानता है, हो सकता है वे उन फायदों में से कुछ को अपने कर्मचारियों के साथ ज़्यादा बोनस के रूप में शेयर करने को तैयार हों। और फिर इससे कंजम्पशन को और सपोर्ट मिल सकता है। तो, ऐसे कई चैनल हैं जिनसे फायदे आ सकते हैं।

लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं।

हम बड़े इम्पोर्टर हैं। और इसलिए, रुपये में किसी भी कमजोरी के दौरान, हमें ज़्यादा रुपये खर्च करने पड़ते हैं।

और जो कंपनियाँ इम्पोर्ट कर रही हैं, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ सकते हैं। और अगर डिमांड बनी रहती है, तो बहुत कम हद तक, कुछ इम्पोर्ट भी हो सकता है, लेकिन यह बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसलिए हम सच में यह नहीं कह सकते कि इससे इंडिया को फ़ायदा हो रहा है या नहीं, क्योंकि इकॉनमी के अलग-अलग हिस्सों पर अलग-अलग तरह से असर पड़ता है।

क्या रुपये का गिरना चिंता की बात है और क्या RBI को दखल देना चाहिए या इसे गिरने देना चाहिए?

MS: हर बार जब रुपया नए निचले स्तर पर पहुँचता है, तो थोड़ा अलार्म बजता है। और अगर रुपया नीचे जा रहा है और RBI की तरफ से बहुत कम दखल है, तो यह अपने आप गिरने वाला है और रुपया और गिरेगा। लेकिन अंदरूनी डायनामिक्स के हिसाब से, करेंसी कोई बड़ी चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। एक्सपोर्ट के नज़रिए से, कोई अलार्म नहीं। इनेशन के नज़रिए से, कोई अलार्म नहीं।

लेकिन मुझे लगता है कि चिंता की बात यह है कि जब हमारी करेंसी इतनी अस्थिर होती है, तो एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स दोनों के लिए बिज़नेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आम तौर पर हम रुपये के स्टेबल रहने की उम्मीद करते हैं। डॉलर के कमज़ोर होने को देखते हुए रुपये को असल में बढ़ना चाहिए। तो, उस हद तक, मुझे लगता है कि यह हमारे लिए पक्का एक रुकावट है, खासकर उन लोगों के लिए जो इनपुट इंपोर्ट करने के बिज़नेस में हैं। लेकिन यह इकॉनमी के ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को हिला नहीं पाएगा।

स्केल बैलेंस पर भी कुछ दबाव हो सकता है, लेकिन असर कितना होगा, यह समझने के लिए हमें रिवाइज़्ड बजट के आंकड़ों का इंतज़ार करना होगा। फर्टिलाइज़र इंपोर्ट के मामले में भी कुछ समस्या ज़रूर होगी। लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि इससे स्केल का हिसाब-किताब बहुत ज़्यादा बिगड़ेगा।

RB: मुझे नहीं लगता कि हम ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ हमें घबराने की ज़रूरत है। शायद पिछले तीन महीनों में हम सबसे खराब परफॉर्म करने वाली करेंसी हैं। लेकिन अगर हम दो साल का टाइम लें, तो मुझे लगता है कि कोरियन करेंसी के अलावा, बाकी सभी इमर्जिंग मार्केट करेंसी में डॉलर के मुकाबले रुपये की तुलना में शायद ज़्यादा गिरावट आई है। इसलिए, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछले छह महीनों से पहले 12 महीने से ज़्यादा समय तक हमारा एक्सचेंज रेट लगभग एक जैसा था। इसलिए मुझे नहीं लगता कि घबराने की ज़रूरत है।

पूरा इंटरव्यू सुनने के लिए कोड स्कैन करें या www.thehindu.com लिंक पर जाएं

नोटबुक

COP30 में चीन का चाय से भरा कपड़ा और भारत की किफ़ायत

पवेलियन वे जगहें हैं जहाँ देश कल्चरल डिस्प्ले लगाते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लीन एनर्जी के लिए उनके कमिटमेंट को दिखाते हैं।

जैकब कोशी

"शायद यह सिर्फ जादू है पांडा की," लियान-टोंग झोउ ने मुझे बताया हंसी, गंभीरता और हैरानी का दौर।

ब्राजील के बेलेम में COP30 क्लाइमेट वार्ता की जगह, हैंगर कन्वेंशन एंड फेयर सेंटर में चीनी पवेलियन में कुछ अजीब हो रहा था।

सालाना यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस में ये पवेलियन वे जगहें हैं जहाँ देश कल्चरल डिस्प्ले लगाते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लीन एनर्जी के लिए उनके कमिटमेंट को दिखाते हैं। ये पैनल डिस्कशन और सेमिनार के लिए भी जगह हैं, और ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्टर्स और बिज़नेसमैन को नेटवर्क बनाने के मौके देते हैं।

वे टेम्पररी एम्बेसी की तरह हैं, जहां सभी देश बातचीत के दो हफ़्ते में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं।

चीनी पवेलियन की खासियत थी लाइनें। सुश्री झोउ ने मुझे बताया कि हर दिन लोग 'गिफ्ट' के लिए एक घंटे, कभी-कभी दिन में दो या तीन बार लाइन में लगे रहते थे। इन फ्री चीज़ों में बॉबल्स, पेन, कैप, पांडा गर्लिन, मोमबत्तियाँ और सॉफ्ट टॉयज़ शामिल थे — रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले टूरिस्ट वेयर — और बाहर से देखने में ये आम थे। बड़े पांडा सॉफ्ट टॉयज़ और कॉफी मग भी थे, लेकिन ये फ्री नहीं थे और उन्हें खरीदना पड़ता था। और वे शेल्फ पर बिल्कुल भी नहीं थे।

मैंने मिस झोउ से पूछा कि क्या वह बीजिंग में अपने घर पर ऐसे ही स्टू के लिए दो घंटे इंतज़ार कर सकती हैं। उन्होंने मुझे डिप्लोमैटिक अंदाज़ में हँसाया — वह एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में काम करती थीं और सिर्फ़ पवेलियन में वॉलंटियर कर रही थीं — और उन्होंने अपना ऑफिशियल मास्क नहीं उतारा। उन्होंने बताया, "इनमें से ज़्यादातर मेटल के हैं लेकिन कुछ चाय से भी बने हैं।" मैंने पूछा, "बैग?" "नहीं, वे घुलने वाले, चाय में घुले कपड़े के और रीसायकल होने वाले होते हैं। जब आप उन्हें इस्तेमाल कर लें, तो आप उन्हें पी सकते हैं।"

दूसरे पवेलियन भी अपनी तरह के थे: फ्री कोलंबियन कोइ और ऑस्ट्रेलियन केक थे, लेकिन कोई लंबी लाइन नहीं थी। यहां, एक छोटे से रूप में, जियोपॉलिटिक्स चल रही थी। चीन मैन्युफैक्चरिंग पावरहाउस था।

दुनिया और इसके पवेलियन में हर कोई चीनी लोगों के दिए जा रहे सामान का एक टुकड़ा लेने के लिए लाइन में खड़ा था। यह अब वह देश नहीं रहा, जो कभी लोगों की सोच में प्लास्टिक के सामान और ज़हरीले पेंट से जुड़ा था। 'मेटल,' 'रीसायकल होने वाला,' और 'बहुत पसंद किया जाने वाला' यह पवेलियन की खूबसूरती थी।

COP30 में US नहीं था। यहीं पर चीन, भारत, ईरान, सऊदी अरब जैसे देशों ने — या जैसा कि उन्हें कहा जाता है, लाइक-माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज़ — बातचीत को फॉसिल फ्यूल खत्म करने से हटाकर अडैप्टेशन और गर्म होती दुनिया के खिलाफ बेहतर तरीके से तैयार होने के लिए ज़रूरी पैसे जैसी चिंताओं की ओर मोड़ दिया। यूरोपियन नज़रिए से, ये देश, फॉसिल फ्यूल को धीरे-धीरे खत्म करने की पक्की डेडलाइन तय करने से इनकार करके, तरक्की को रोक रहे हैं, हालांकि यह भी आम बात है कि चीन के रेयर अर्थ्स, सोलर सेल और बैटरी के बिना, तेल और कोयले से मुक्त धरती एक अफीम का सपना है।

चीनी पवेलियन के उलट, भारतीय पवेलियन सादा था। लाल, नारंगी और हरे रंग के बीच 'In-dia@COP30' दिखाया गया था। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर प्रोड्यूसर हो सकता है, लेकिन इसकी असल बिजली का 70% से थोड़ा ज़्यादा कोयले से आता है। कोई लाइन नहीं थी क्योंकि देने के लिए कुछ नहीं था। भारतीय डेलीगेशन के सदस्यों के दौरे को छोड़कर यह लगभग हमेशा खाली रहता था।

"ये कुर्सियाँ देख रहे हो?" मिस झोउ ने आगे कहा, और लकड़ी की बनी हुई कुर्सियों की ओर इशारा किया। "कल शाम, जब पवेलियन बंद होंगे, तो हम ये सब दे देंगे। हमने ये चीन से मंगवाई हैं।

हमने उन्हें एक लोकल NGO को दे दिया है, लेकिन अगर कोई उन्हें चाहता है तो वह उन्हें मुफ़्त में ले जा सकता है, अगर वे लाइन में लगें।"

लेकिन, अगले दिन पवेलियन में चीख-पुकार मच गई। "आग! आग! सब लोग बाहर निकलो," UN मार्शल चिल्ला रहे थे, हम सबको बाहर निकलने के रास्तों से ले जा रहे थे। अफ्रीका पवेलियन के पास शॉर्ट सर्किट से बड़े हिस्से जल गए थे। जगह को सील कर दिया गया था। और उस दिन के लिए बंद कर दिया गया था। मुझे हैरानी हुई कि क्या किसी ने उन कुर्सियों को छीन लिया था।

jacob.koshy@thehindu.co.in

सप्ताह की तस्वीर

फसल की लय

एक्स

असम के कार्बी आंगलोंग जिले के उमसुवाई गांव में पहाड़ी तिवा समुदाय के पुरुष और महिलाएं धान की कटाई कर रहे हैं। रितु राज कोंवर

FR OMTHEARCHIVES

The Hindu.

पचास साल पहले 12 दिसंबर, 1975

लोच नेस की तस्वीरें विवाद खत्म करने में नाकाम रहीं

लंदन, 11 दिसंबर: दो ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने आरोप लगाया है कि एक अमेरिकी टीम ने मशहूर लोच नेस मॉन्स्टर की जो तस्वीरें ली हैं, उनसे "कुछ भी साबित नहीं होता"। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने कहा कि वे तस्वीरें "कुछ भी साबित नहीं करतीं"।

लंदन के मशहूर नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम के सभी एक्सपर्ट साइंटिस्ट ने कल रात कहा कि जिन तस्वीरों में एक अजीब सींग वाला सिर और शंख जैसे शरीर से निकला एक बड़ा सा अंडा दिख रहा है, वे "किसी बड़े ज़िंदा जानवर के होने का सही सबूत नहीं हैं।" इस हमले ने बोस्टन के मिस्टर रॉबर्ट राइन्स की लीडरशिप में अमेरिकियों के दावों को लेकर और विवाद खड़ा कर दिया, कि उन्होंने उस मुश्किल से मिलने वाले राक्षस का पता लगा लिया है जिसने कई पीढ़ियों से साइंटिस्ट को हैरान किया है।

सौ साल पहले 12 दिसंबर, 1925

सीलोन में मोती शेरी नहीं है

अगले साल पर्ल फिशरी की कोई उम्मीद नहीं है। यह खबर "द सीलोन डेली न्यूज़" के एक प्रतिनिधि को डॉ. जोसेफ पियर्सन, मरीन बायोलॉजिस्ट और कोलंबो म्यूजियम के डायरेक्टर ने दी, जो पर्ल बैंक्स के इंस्पेक्शन से लौटे हैं।

इनलेटर

फेड ने दरें कम कीं, संकेत अगले साल एक विराम और एक कटौती

फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में भारी कटौती की
बुधवार को ब्याज दरें बढ़ाईं लेकिन उधार लेने का संकेत दिया
निकट भविष्य में लागत में और गिरावट की संभावना नहीं है
नौकरी की दिशा पर स्पष्टता का इंतज़ार है
बाजार में नरमी के संकेत, कहा जा रहा है कि
"कुछ हद तक ऊंचा बना हुआ है" और यह एक अर्थव्यवस्था है
अगले साल इसमें तेज़ी आने की उम्मीद है।
नीति निर्माताओं के अनुमानों में औसत दिखाया गया
एक चौथाई प्रतिशत की उम्मीद
अगले साल भी कटौती होगी, सितंबर की तरह ही। रॉयटर्स

हाईकोर्ट ने चुंगी चोरी का मामला खारिज किया कोचर और आईसीआईसीआई अधिकारियों के खिलाफ

बॉम्बे हाई कोर्ट ने आपराधिक
आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ और अन्य के खिलाफ कार्यवाही
MD चंदा कोचर, पूर्व डिप्टी MD डॉ.
नचिकेत मोर, कानूनी विभाग के सदस्य
वासुदेव कुलकर्णी, और पुणे शाखा प्रबंधक
असावरी पाटनकर पर कर चोरी का आरोप
पुणे शहर में सोने के आयात पर चुंगी
ICICI बैंक के खिलाफ शिकायत,
हालाँकि, न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही करें
प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी), पुणे।

रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा, लेकिन RBI घाटे पर लगाम लगा सकता है

भारतीय रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया
गुरुवार को, इसकी गिरावट और गहरी हो गई
कॉर्पोरेट डॉलर की बिक्री और 90-प्रति-डॉलर के निशान के रूप में
व्यापार समझौते की दिशा में ठोस प्रगति की कमी
अमेरिका के साथ एशिया के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले को नुकसान हुआ
करेंसी में गिरावट आई है। रुपया 5% से ज़्यादा गिर गया है।
2025 में डॉलर के मुकाबले, अमेरिका का टैरिफ 100 डॉलर प्रति बैरल तक बढ़ सकता है।
भारतीय सामानों पर 50% की बढ़ोतरी से एक्सपोर्ट पर असर पड़ा है
देश का सबसे बड़ा बाज़ार और कम हो गया
लोकल इक्विटी की अपील। RBI ने शायद दखल दिया
5 ट्रेडर्स ने कहा कि इससे ज़्यादा नुकसान से बचने में मदद मिलेगी। रॉयटर्स

नवंबर इक्विटी एमएफ नेटवर्क 21% की वृद्धि ₹29,000 करोड़.

Ashokamithran T.
MUMBAI

इक्विटी म्यूचुअल फंड में नेट इनफ्लो 21% बढ़ा
नवंबर में ₹29,911 करोड़
आंकड़ों के अनुसार, 2025
एसोसिएशन से
म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया।
संख्या ₹24,690.33 थी
अक्टूबर 2025 में करोड़।
यह पहली बार है
चार महीने जो आपसी
फंड इनफ्लो में 21% की बढ़ोतरी हुई है।

यह लगातार तीन महीने की गिरावट के बाद
आया है।
मासिक आय हैं
अभी भी 43% कम है
वार्षिक उच्चतम स्तर ₹42,702.35
जुलाई 2025 में करोड़ रुपये की
"इक्विटी योजना
योजनाएं जारी रहीं
विकास को बढ़ावा दें, समर्थन करें
लगातार इनफ्लो से। हाइब्रिड और पैसिव फंड भी

स्वस्थ ट्रैक्शन देखा,
बहु-परिसंपत्ति और आर्बिट्रेज
निधियों का एक साथ लेखा
वेंकट ने कहा, "70% से अधिक संकर श्रेणी
के प्रवाह के लिए यह समस्या है।"
चालसानी, AMFI के CEO.

मेक्सिको के 2024 टैरिफ से भारत के ऑटो एक्सपोर्ट को नुकसान हो सकता है

अप्रैल 2024 में, देश ने इम्पोर्ट होने वाले कई आइटम पर 5-50% तक का टैरिफ लगाया
नॉन-FTA पार्टनर्स से 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट; भारत में इसका असर ऑटो सेक्टर पर ज़्यादा पड़ सकता है

टीसीए शरद राघवन
नई दिल्ली

टी वह तक का है
50% स्वीकृत
मेक्सिको की सीनेट ने
बुधवार को आयात पर
भारत समेत एशियाई देशों से

अप्रैल 2024 से जगह और
भारत की कुल निर्यात तस्वीर पर इसका कोई
खास असर नहीं पड़ेगा, एक विश्लेषण में कहा
गया है।
ट्रेड डेटा से पता चलता है। हालांकि, वे जारी
रख सकते हैं
विशेष क्षेत्रों पर प्रभाव,
जैसे ऑटोमोबाइल।
सीनेट के फैसले के अनुसार, ये दरें 1
जनवरी से लागू होने की उम्मीद है।

2026, और लागू होगा
जिन देशों के साथ मेक्सिको का कोई स्वतंत्र
संबंध नहीं है
व्यापार समझौता, जिसमें भारत भी शामिल है।
हालाँकि,
मैक्सिकन पर दस्तावेज़
सरकार की वेबसाइट
दिखाएँ कि ये तारिफ हैं

नया नहीं है। अप्रैल 2024 में,
देश ने कर लगाया
5-50% तक
आयातित वस्तुओं की श्रेणी
गैर-एफटीए भागीदारों से
दो साल की अवधि।
इस दिसंबर में सीनेट का यह कदम उसी का
विस्तार है
मूल निर्णय.
भारत ने 2024-25 में मेक्सिको को 5.7 बिलियन
डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया, जो 2024-25 में 1.5
बिलियन डॉलर था।
यह उस साल के कुल एक्सपोर्ट का 1.3% है,
जैसा कि दिखाया गया है-

यह मानते हुए कि समग्र स्तर पर, उच्च टैरिफ
होंगे
कोई महत्व नहीं
भारत के पूरे एक्सपोर्ट सिनेरियो के लिए ख़तरा।

हालाँकि, न केवल
इन निर्यातों का बोलबाला रहा
कुछ सेक्टरों में, मेक्सिको आगे है
उनमें से एक प्रमुख प्राप्तकर्ता
क्षेत्रों का निर्यात, जो
इसका मतलब है कि तारिफ असर कर सकता है
उनके लिए खतरा पैदा कर सकता है।
उदाहरण के लिए, मोटर
कारें और उनके पुर्जे

भारत के मेक्सिको को एक्सपोर्ट में $1.4
बिलियन या 25% की बढ़ोतरी हुई।
इसके अलावा, मोटरसाइकिल निर्यात भारत के
निर्यात का अतिरिक्त 7% है

मेक्सिको. ये कौन सी जगहें हैं?
से ज़्यादा जोखिम वाले सेक्टर
दूसरा यह कि मेक्सिको एक है
सबसे बड़े बाजारों में से
इनमें से कई आइटम।
उदाहरण के लिए, मेक्सिको खाते
भारत के कुल ऑटो और ऑटो पार्ट एक्सपोर्ट
में मेक्सिको का हिस्सा लगभग 10% है।

भारत के मोटर-साइकिल एक्सपोर्ट का लगभग
12% हिस्सा।

'FTA वार्ता शुरू करें'
अप्रैल की प्रतिक्रिया में
2024 के टैरिफ और उसके बाद के असर

व्यापार पर, इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद
(ईईपीसी) ने लिखा

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मेक्सिको के
साथ बातचीत शुरू करने के लिए कहा

संभावित FTA.

प्रादा ने बेचने के लिए MoU पर साइन किए भारत-इटली फोरम में कोल्हापुरी

Ashokamithran T.
MUMBAI

इतालवी फैशन ब्रांड प्रादा
कोल्हापुरी चप्पलें बेचने की योजना, मेमो-रैंडम
ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए

(एमओयू) चमड़ा विकास निगमों के साथ

कर्नाटक और महाराष्ट्र, मुंबई में इंडिया-इटली
बिज़नेस फ़ोरम में

गुरुवार।

तीन और समझौता ज्ञापनों में स्टील अथॉरिटी
ऑफ इंडिया (SAI) शामिल है
इंडिया लिमिटेड (सेल) परियोजना
इतालवी धातु को सम्मानित किया गया
उपकरण निर्माता डेनियली
ग्रुप. नियोफोलिस ब्रांड्स
प्राइवेट लिमिटेड ने एक समझौता किया
कुवेरा स्पा के साथ समझौता ज्ञापन
इतालवी रिटेल फैशन फर्म के 100 स्टोर खोलें,
और
के बीच एक संयुक्त उद्यम
ऐस बास प्राइवेट लिमिटेड और के-वैन्ना ग्रुप के
बीच हुई डील

51% हिस्सेदारी है।
बातचीत में शामिल हैं
ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में,
कृषि खाद्य, कृषि प्रौद्योगिकी, खेल
टेक और टेक्सटाइल।
इतालवी प्रतिनिधिमंडल
डिप्टी के नेतृत्व में किया गया था
प्रधानमंत्री एंटोनियो ता-ज़ानी। इस मौके पर बोलते
हुए, श्री तावजानी ने कहा कि कोशिश की जाएगी

व्यापार सौदों को पूरा करें
छह महीने।

ईंधन नियमों में बदलाव व्यापार को आसान बनाना: पुरी

द हिंदू ब्यूरो
नई दिल्ली

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
नियम (2025)
आसानी प्रदान करने के लिए संशोधित
व्यवसाय और संचालन,
केंद्रीय मंत्री हरदीप
सिंह पुरी ने जानकारी दी
गुरुवार।
संशोधनों में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि
लंबे समय तक अनुदान देने का प्रावधान है
अवधि पट्टे, यानी, ऊपर

वर्तमान 20 वर्षों से 30 वर्ष तक, और अधिक
महत्वपूर्ण बात, जिसे "जीवन" तक बढ़ाया जा
सकता है

इससे संभावित पट्टेदार को लंबे समय के
लिए सोच-समझकर निवेश का फैसला लेने में
मदद मिलती है।

इसके अलावा, जो लोग इसका लाभ उठा रहे हैं
पट्टा, होगा
सभी प्रकार के कार्य करने का अधिकार
खनिज तेल संचालन
सिर्फ एक पेट्रो-लियम लीज़ के साथ।

बाज़ार

बाज़ार देखो

	गुरुवार	% परिवर्तन
सेंसेक्स	84,818	0.51
अमेरिकी डॉलर	90.32	-0.42
सोना	1,32,490	0.06
ब्रेंट तेल	60.91	-0.83

निफ्टी 50

	मूल्य	परिवर्तन
अडानी एंटर.	2277.70	66.10
अडानी पोर्ट्स.	1504.00	5.90
अपोलो अस्पताल	7009.50	-9.00
एशियन पेंट्स.	2779.40	-25.10
एक्सिस बैंक.	1272.70	-5.90
बजाज ऑटो.	9053.50	62.50
Bajaj Finserv	2065.80	0.00
बजाज फाइनेंस	1006.40	-3.90
Bharat Elec.	387.50	0.15
Bharti Airtel.	2053.20	-13.80
सिप्ला.	1512.30	21.40
कोल इंडिया	384.00	1.85
डॉ रेड्डीज लैब	1273.50	22.70
हिंदुस्तान यूनिलीवर	40.20	0.00
आयशर मोटर्स	7256.00	27.50
इटरनल लिमिटेड	290.95	7.70
Grasim Ind.	2797.80	51.00
एचसीएल टेक	1672.40	6.40
एचडीएफसी बैंक	1000.30	10.50
एचडीएफसी लाइफ.	775.20	4.15
हिंडाल्को	824.35	2.60
हिंद यूनिलीवर.	2305.60	3.90
आईसीआईसीआई बैंक	1360.00	-3.60
IntGlobeAvi.	4819.00	13.50
इंफोसिस	1598.00	13.20
आईटीसी.	402.90	-0.25
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	298.45	7.60
जेएसडब्ल्यू स्टील	1105.40	8.60
बैंक बॉक्स.	2180.20	50.70
एल एंड टी.	4003.90	12.60
एम एंड एम.	3665.20	35.20
मारुति सुजुकी	16248.00	229.00
मैक्स हेल्थकेयर.	1087.90	10.80
नेस्ले इंडिया.	1215.00	5.70
एनटीपीसी	322.60	1.00
ओएनजीसी	238.41	-0.88
पावरग्रिड कॉर्प	264.80	-0.70
रिलायंस इंडस्ट्रीज़	1545.00	8.10
एसबीआई लाइफ.	2006.90	-7.60
स्टेट बैंक	963.25	3.50
श्रीराम वित्त लिमिटेड.	847.15	9.90
सन फार्मा	1807.20	21.70
टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट	1142.10	2.00
टाटा स्टील	166.38	4.15
टीसीएस.	3191.90	2.70
टेक महिंद्रा	1568.20	17.40
टाइटन.	3844.80	-0.90
टाटा मोटर्स पी.वी.	346.65	3.25
ट्रेंट लिमिटेड	4047.50	29.20
अल्ट्राटेक सीमेंट.	11472.00	155.00
विप्रो	259.25	1.27

ब्रेक्स इंडिया, टीबीके ने समझौते पर हस्ताक्षर किए

ब्रेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और
टीबीके कंपनी लिमिटेड ने एक समझौता किया है
पूंजी और व्यावसायिक गठबंधन समझौता,

चेन्नई स्थित फर्म ने कहा
एक रिलीज़.

कच्चे तेल को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करें 'तेल स्रोत विविधीकरण'

द हिंदू ब्यूरो
नई दिल्ली

पेट्रोलियम मंत्रालय
और प्राकृतिक गैस (MoPNG)
के साथ मिलकर काम करना चाहिए
विदेश मंत्रालय (MEA) और अन्य संबंधित
सरकारी एजेंसियों ने राजनयिक संबंधों को
बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन
(MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
तेल उत्पादक देशों के साथ जुड़ाव, सुरक्षित

अनुकूल निवेश
शर्तें और पता कर और
नियामक बाधाओं का सामना करना पड़ा
विदेशों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसयू)
द्वारा, संसदीय समिति

सार्वजनिक उपक्रम (2025-
26) ने बुधवार को पेश की गई अपनी नई
रिपोर्ट में यह कहा।
ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए
कच्चे तेल के विविधीकरण के लिए
तेल स्रोत, समिति
इसके बावजूद माना गया
सक्रिय प्रयास
इस संबंध में किए गए कार्यों के बावजूद,
प्रतिबंधों, वित्तीय बाजार के उतार-चढ़ाव के
कारण चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

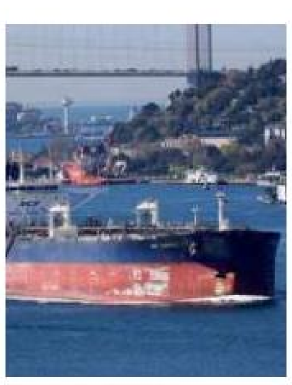

भारत लगभग 89% आयात करता है
घरेलू कच्चे तेल की ज़रूरतें।

विलंबता और विनियामक
मेजबान देशों में परिवर्तन
जहां विदेशी परियोजनाएं
स्थित हैं।

'प्रभाव ऊर्जा बिल'
"ये मुद्दे न केवल भारत के ऊर्जा आयात को
प्रभावित करते हैं
बिल में बाधा भी डालेंगे
सीपीएसयू की सुरक्षा करने की क्षमता
विदेशी अन्वेषण और
उत्पादन परिसंपत्तियों, जिससे
दीर्घकालिक ऊर्जा को सीमित करना

सुरक्षा, "यह नोट किया।
सदस्य की अध्यक्षता वाली समिति के
अनुसार
केन्द्रपारा (ओडिशा) से सांसद बैजयंत

पांडा के अनुसार, भारत अपनी घरेलू ज़रूरतों
का लगभग 89% आयात करता है
कच्चे तेल की ज़रूरतें।
इस संदर्भ में, यह देखा गया कि, "हाल ही
में वैश्विक
रूस-यूक्रेन संघर्ष और सहित घटनाएँ

मध्य में तनाव
पूर्व, ने रेखांकित किया है
भारत की भेद्यता
ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला और इसके
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भरता बढ़ रही है।"

इस प्रभाव के लिए, इसने स्रोतों के
विविधीकरण की दिशा में प्रयासों को तेज करने
की सिफारिश की

भौगोलिक और अनुबंधात्मक रूप से, हेजिंग
के रूप में जोखिम प्रबंधन प्रथाएँ

और लचीले अवधि के अनुबंध
और वैकल्पिक को बढ़ावा
दूसरे सुझावों के साथ, इम्पोर्ट रूट भी
शामिल हैं।

आईसीआईसीआई प्रू एएमसी प्री-आईपीओ दौर शुद्ध लाभ ₹4,815 करोड़। वित्त पोषण में

प्रेस ट्रस्ट भारत
नई दिल्ली

26 घरेलू
और विदेशी निवेशकों ने
में ₹4,815 करोड़ डाले गए
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट
प्रबंधन कंपनी
(AMC), ICI-CI बैंक की एक सब्सिडियरी,
ने प्री-IPO के ज़रिए
फंडिंग राउंड।
इस लेन-देन के हिस्से के रूप में,
एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने

का एक निजी प्लेसमेंट
22,240,841 इक्विटी शेयर
₹2,165 का निर्गम मूल्य
अपनी पब्लिक घोषणा के अनुसार, शेयर।

इस फंडरेज़ में अलग-अलग
तरह के लोगों ने हिस्सा लिया
निवेशकों का समूह, जिसमें शामिल हैं
ल्यूनेट कैपिटल, द एस्टेट
of late Rakesh Jhunjhunwala
और बाजार के दिग्गजों
मनीष चोकानी और मधुसूदन केला।

टाटा हिताची की कीमत में बढ़ोतरी भारत पर फोकस उच्च के बीच अमेरिकी टैरिफ, कमजोर रुपया

द हिंदू ब्यूरो
BENGALURU

हिताची कंस्ट्रक्शन मा-चिनरी कंपनी

गुरुवार को कहा गया कि नए टैरिफ
सहित वैश्विक हेड-विंड्स
ट्रम्प द्वारा पेश किया गया
प्रशासन और डी-

भारतीय रुपये की कीमत में बढ़ोतरी इसकी
बुनियाद थी
भारतीय निर्माण उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करें

बाज़ार।
टैरिफ और से जुड़ी वैश्विक अनिश्चितताओं
के बावजूद
करेंसी में उतार-चढ़ाव, Hi-tachi के
अधिकारियों ने कहा
कंपनी में तेजी बनी रही
भारत में जैसा देश था
दीर्घकालिक के रूप में स्थित
ग्रोथ इंजन की बदौलत
इंफ्रास्ट्रक्चर में तेज़ ग्रोथ, कॉस्ट-इफेक्टिव
मैन्युफैक्चरिंग, मज़बूत सप्लाई

श्रृंखला और प्रतिभा
उपलब्धता।
मासाफूमी सेनजाकी, प्रेसिडेंट,
एग्जीक्यूटिव ऑफिसर
और सीओओ, हिताची कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ने
कहा
भारत सिर्फ़ एक हाई-ग्रोथ मार्केट ही
नहीं था, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक बेस भी
था जो मदद करेगा
समूह वैश्विक नेविगेट करता है
अनिश्चितताएँ।
मीडिया में बोलते हुए
यहां गोलमेज सम्मेलन में श्री सेन-जकी ने
कहा कि भारत हिताची की वैश्विक
अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण स्थिरता
लाने वाला देश बन रहा है।
प्लेबुक.
टाटा-हिताची के साथ
संयुक्त उद्यम की शुरुआत
1982 तक, हिताची परिचालन अब योगदान
देते हैं
उच्चतम मशीन वॉल्यूम
हिताची के लिए, जो एक लीडिंग एक्सकैवेटर
मैन्युफैक्चरर है।
इस अवसर पर संदीप सिंह ने भी बात की।

प्रबंध निदेशक, टाटा
हिताची ने कहा, रुपये में गिरावट से दबाव बढ़ा

कॉम्पोनेंट इम्पोर्ट करने के लिए। हालाँकि,
उन्होंने यही कहा

टाटा हिताची के MD संदीप सिंह, डायरेक्टर तोशिकी ओनिशी के साथ
और मासाफुमी सेनजाकी, COO, हिताची कंस्ट्रक्शन मशीनरी।

मुद्रा का चलन भी था
नए एक्सपोर्ट एडवांटेज खुले। टाटा हिताची एक

टाटा और टाटा के बीच संयुक्त उद्यम
मोटर्स (40%) और जापान का
हिताची कंस्ट्रक्शन मा-चिनरी (60%).

श्री सिंह के अनुसार,
टाटा हिताची का एक्सपोर्ट
300 से लगभग दोगुना
पिछले साल 350 मशीनें
इस साल अनुमानित 500-600 यूनिट्स, जिसमें
से मजबूत मांग निकल रही है

मध्य पूर्व, अफ्रीका और
दक्षिण पूर्व एशिया.
कंपनी के प्लांट
धारवाड़ और खड़गपुर
65-80% स्थानीयकरण हासिल किया है,
महत्वपूर्ण रूप से
उन्होंने कहा कि इससे कॉस्ट
कॉम्पिटिटिवनेस मजबूत होगी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि
हालाँकि वर्तमान निर्यात पैमाना पूरी तरह से
नहीं होगा
ओसेट उच्च आयात लागत,
हिताची को स्थिरता दिख रही थी
भारत में आने वाले एक्सकेवेटर एमिशन के
बाद मार्केट में बढ़ोतरी के मौके

नियमों ने घरेलू उत्पादों को वैश्विक
उत्पादों के साथ संरेखित किया
मानकों।
श्री सिंह ने कहा कि भारत

उच्च उद्योगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण आधार
बन रहा है
कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेक्टर में टेक्नोलॉजी।
जबकि डीज़ल बना हुआ है

प्रमुख ईंधन के कारण
साइट की स्थितियों के अनुसार, इलेक्ट्रिक
सॉल्यूशन्स बढ़ रहे हैं
माइनिंग में। हिताची ने इलेक्ट्रिक डंप
ट्रक सप्लाई किए हैं
और केबल से चलने वाले बड़े
कोल इंडिया को उत्खनन मशीनें
उन्होंने विस्तार से बताया कि, "और दूसरे
ऑपरेटर्स के बीच, यह धीरे-धीरे साफ़ एनर्जी
ऑप्शन की तरफ़ बदलाव का संकेत है।"

एक प्रश्न का उत्तर देना
कौशल विकास पर, उन्होंने
टाटा हिताची के कानों ने कहा
खारागपुर और धारवाड़ के माध्यम से प्रशिक्षण

साझेदारी में केंद्र
विभिन्न आईटीआई, अन्य सहयोग, अप्रेंटिसशिप

कार्यक्रम और भारत-जापान कौशल विकास
पहल।

"ये कार्यक्रम
स्पष्ट रूप से कौशल सेट का निर्माण
और एक मजबूत टैलेंट पाइपलाइन जो इंडस्ट्री
को सपोर्ट करती है
रोजगार की मांग के साथ-साथ जरूरतें भी पूरी
होती हैं।
उसने कहा।

वित्त मंत्रालय सुव्यवस्थित भर्ती, परिणाम चक्र

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया
नई दिल्ली

वित्त मंत्रालय ने
सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से कई पहल की गई

भर्ती परीक्षाओं की समयसीमा

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी)
और उनकी घोषणा
परिणाम।
इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भर्ती
शामिल है
भारत (एसबीआई), राष्ट्रीयकृत
बैंक (एनबी) और क्षेत्रीय
ग्रामीण बैंक (आरआरबी),
वित्तीय विभाग
वित्त मंत्रालय के तहत सेवाओं के बारे में एक
रिपोर्ट में कहा गया है कि
गुरुवार को बयान जारी किया।
इसके अलावा, इन पहलों का मकसद है

द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पारदर्शिता
बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस)।

एसबीआई में भर्ती,
NBs और RRBs का एग्जाम IBPS प्रोसेस के
ज़रिए होता है, इसके अनुसार

इसमें कहा गया है कि संबंधित बैंकों के अधिकार
क्षेत्र के अनुसार।
आमतौर पर, परीक्षाएँ
आरआरबी के लिए प्रशासित हैं
एनबी और के लिए उनसे पहले
एसबीआई के नतीजे ये हैं
बाद में घोषित
इसी क्रम में, यह
कहा।
"फिर भी, एक उल्लेखनीय
एक ट्रेंड सामने आया है जिसमें नए भर्ती हुए
कैंडिडेट अक्सर बदलते रहते हैं

RRB से NB और उसके बाद SBI में। इस
माइग्रेशन की वजह से RRB में काफ़ी कमी
आई है।

बैंकों के लिए यह समस्या और परिचालन
संबंधी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं।
संज्ञान लेते हुए
उपरोक्त मुद्दे पर, इसने कहा
डीएफएस ने भर्ती परीक्षाओं की व्यापक
प्रक्रिया की समीक्षा की और

परिणाम का पैटर्न
घोषणाएँ।

भारत में AI में तेज़ी देखी जा रही है, एजेंटिक AI डिप्लॉयमेंट: नडेला

द हिंदू ब्यूरो
BENGALURU

बहुत तेज़ी है
भारत में एआई और
एजेंटिक AI एप्लिकेशन्स को डिप्लॉय
किया जा रहा है, देखा गया
सत्य नडेला, अध्यक्ष
और CEO, माइक्रोसॉफ्ट।
श्री नडेला ने कहा
यहाँ मुख्य भाषण के भाग के रूप में
बुधवार को उनका AI टूर, जो
नई दिल्ली में दो
कुछ दिन पहले भारत में $17.5 बिलियन के
इन-इन्वेस्टमेंट की घोषणा की गई थी।

डेवलपर्स से भरे दर्शकों को संबोधित
करते हुए, AI
विशेषज्ञ और टेक्नोक्रेट,
उन्होंने कहा कि भारत-

यह AI के बारे में है: माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला ने एक इवेंट के दौरान कहा
गुरुवार को बेंगलुरु, भारत में। रॉयटर्स

नंबर एक पर आओ
दुनिया में समुदाय
2030 तक GitHub के साथ।
उन्होंने कहा कि यह शानदार था
सगाई देखने के लिए और

बेंगलुरु से आने वाली परियोजनाओं का
प्रकार और
भारत. "हम बना रहे हैं
GitHub असल में एजेंट है
मुख्यालय (एक एजेंटिक प्लेटफ़ॉर्म

जो हर एजेंट को एकजुट करता है),
श्री नडेला ने कहा।
एजेंटिक AI के असर के बारे में
बताते हुए उन्होंने कहा कि
सोच में बदलाव बहुत ज़रूरी था,
डेवलपर्स के लिए भी। "हम
एक नए तरीके की भी ज़रूरत है
की सीमा के बारे में सोचो
क्लासिक एसडीएलसी (सॉफ्टवेयर
विकास जीवन चक्र),
जिसे नए सिरे से बदलना होगा,
AI-ड्रिवन SDLC.''
उन्होंने असली गोल जोड़ा
बिल्डरों को सशक्त बनाना था:
सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी
डेवलपर्स, इंजीनियरों और
संगठनों को नवाचार करने के लिए
बड़े पैमाने पर, बुद्धिमान असाइन करें
AI एजेंट्स को टास्क देना और एक्शनेबल
इनसाइट्स जेनरेट करना।

नवभारत टाइम्स • विचार

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025

> हेट स्पीच लक्षित समुदायों की गरिमा पर सीधा आघात है और यह लोकतांत्रिक ताने-बाने को कमजोर करती है।
>
> *– फ्रेडरिक एम. लॉरेंस, अमेरिकी सिविल राइट्स एक्टिविस्ट*

दुरुपयोग का डर

कर्नाटक विधानसभा में हेट स्पीच और हेट क्राइम के खिलाफ बिल पेश किया गया है। इसका मकसद है नफरत और घृणा फैलाने वाले अपराधों व बयानों को नियंत्रित करना। अक्सर कई ऐसे बयान आते रहते हैं, जिससे समाज में वैमनस्य बढ़ता है। इसे देखते हुए ऐसे कानून जरूरी लगते हैं, लेकिन इसके साथ चिंता भी है - दुरुपयोग की।

कड़ी सजा । बिल के प्रावधान बेहद कड़े हैं। पहली गलती पर एक से 7 साल की सजा और दोबारा गलती होने पर 2 से 10 साल की सजा मिल सकती है। साथ में, जुर्माना भी है। विधेयक में हेट क्राइम और हेट स्पीच को विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है और इसका दायरा बहुत बड़ा है, जिसमें सार्वजनिक बयानबाजी से लेकर ऑनलाइन निगरानी तक शामिल है।

हेट स्पीच बिल

सुप्रीम चिंता । इसमें शक नहीं कि नफरत फैलाने वाले बयान और कृत्य इस समय की एक बड़ी परेशानी हैं, जिनसे कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती खड़ी हो जाती है। सामाजिक सद्भाव को भी चोट पहुंचती है। सुप्रीम कोर्ट कई मौकों पर इस बारे में चिंता जता चुका है। 2018 में शीर्ष अदालत ने हेट क्राइम की निंदा करते हुए कहा था कि नागरिकों की जान की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। उसी साल तहसीन पूनावाला जजमेंट आया, जिसमें राज्यों के लिए कई दिशा-निर्देश थे।

आलोचना और नफरत । लेकिन, जब इतना कड़ा कानून आता है, तो उसके दुरुपयोग की आशंका भी बढ़ जाती है। भले ही बिल में अपराध की विस्तृत व्याख्या की गई हो, लेकिन असल चुनौती है इसे लागू करने में। कौन-सी बात नफरत फैलाने वाली है और कहां आलोचना की गई है - इसमें समझ का थोड़ा भी अंतर बड़ा टकराव पैदा कर सकता है। इसी तरह, असहमति के अधिकार को भी सुरक्षित रखने की जरूरत है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता । बिल में सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लैटफॉर्म को भी शामिल किया गया है। इंटरनेट पर जिस तेजी से दुष्प्रचार और वैमनस्य बढ़ाने वाले कंटेंट बढ़े हैं, उसे देखते हुए बिल उपयोगी हो सकता है, पर यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आड़े नहीं आना चाहिए। बिल को लेकर कई आशंकाएं और राजनीतिक विरोध है। कर्नाटक BJP का आरोप है कि यह बिल खास समूह को निशाना बनाने के लिए लाया जा रहा है। ऐसे में यह जरूरी है कि इस तरह का इंतजाम और निगरानी हो कि यह बिल किसी से बदला लेने का नहीं, बल्कि शांति कायम करने का टूल बने।

तिराहा

विषय 'गंभीर' है!

सुधर्मा 'परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन' के मंत्र को अक्षरशः मानती हैं, इसलिए, सोशल मीडिया जैसे 'विकार' से दूर रहती हैं। लेकिन, समय संग साम्य बैठाने को हफ्ते में एक दिन 'चीट डे' रखती हैं। संयोग से यह वही दिन था, जब वह पूछ बैठीं, 'यह 'गंभीर' का क्या विषय है?

प्रेम शंकर मिश्र

'प्रिये! इसके दो पक्ष हैं। पहला, हमारे यहां खेल हो, युद्ध हो, योजना हो, राजनीति हो, इसकी रणनीति व परिणाम अगर नुक्कड़, दफ्तर, ड्रॉइंग रूम, क्लबों और 'खलिहरों' के मानक पर खरे नहीं हैं तो विषय 'गंभीर' है। दूसरा, 'गंभीर' उस कार्य-संस्कृति का प्रतीक है जहां, आत्मश्लाघा का दंभ व हीनता का अवसाद योग्यता को खा जाता है। हनक व सनक का भेद मिट जाता है। ये तुम्हें हर कार्यस्थल पर मिलेंगे, जिनका हमेशा एक 'राणा' होता है और उसके लिए सब माफ होता है।' सुखनंदन ने समझाया।

'कोई कुर्सी पर सबसे पूछ कर फैसले लेने तो नहीं बैठा है?' सुधर्मा ने नाराजगी के साथ कहा। 'लीडर का काम उत्तरदायित्व तय करने और लेने, दोनों का होता है। कलाम साहब कहते थे - लीडर वह है जो विफलता को विनम्रता से स्वीकारे और सफलता पर और विनम्र हो जाए। सही लगने और होने में फर्क होता है, यह फर्क तभी दिखेगा जब आत्मश्लाघा का चश्मा नजर से हटेगा। लगता है तुमने दफ्तर की दीवार पर चिपका वह पोस्टर नहीं पढ़ा, 'Meeting is not me thing.', सुखनंदन ने चुटकी ली।

'तो क्या लकीर का फकीर बना रहे?' संवाद जारी था। 'नहीं लेकिन लकीर का 'गंभीर' भी न बने। विज्ञान व प्रबंधन, दोनों कहता है जो जिस विधा का मौलिक विशेषज्ञ है अगर आप उसे निखारेंगे, मौका देंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे तो वह और प्रभावी होगा। अब आप आज किसी को तैराक बनाएंगे, कल पर्वतारोही तो उसकी दक्षता बहुआयामी नहीं स्वर्गगामी हो जाएगी। दूसरे, टीम के साथ खड़े होने और व्यक्ति के साथ खड़े होने में आकाश-पाताल का अंतर है। व्यक्ति टीम नहीं होता।' 'लेकिन, कोच तो व्यक्ति होता है', सुधर्मा ने मुस्कराते हुए बात काट दी।

एकदा

संकलन : **दीनदयाल मुरारका**

साधन ज़रूरी नहीं

गंगूबाई हंगल (1913-2009) शास्त्रीय संगीत की महान गायिका थीं। उनको प्रारंभिक संगीत शिक्षा मां अंबाबाई ने ही दी, जो कर्नाटक संगीत की गायिका थीं। गंगूबाई तब धारवाड़ में रहती थीं। संगीत सीखने की उनकी लगन गहरी थी, पर घर में इतना पैसा नहीं होता था कि अच्छा तानपुरा खरीद सकें। एक बार की बात है, बरसात के दिनों में उनका पुराना तानपुरा नमी के चलते खराब होकर टूट गया। गंगूबाई बहुत दुखी हुईं, क्योंकि वही उनका अभ्यास का एकमात्र साधन था। उन्होंने मां अंबाबाई से कहा, 'अब रियाज कैसे करूं, तानपुरा ही नहीं रहा।' मां ने समझाया, 'बेटी, संगीत साधन से नहीं, साधना से निकलता है। जब तक तेरे भीतर सुर है, तानपुरा की कमी उसे रोक नहीं सकती।' उस रात गंगूबाई ने टूटे तानपुरे के तारों को अपने हाथों से जोड़ा, उन्हें लकड़ी के छोटे टुकड़ों से सहारा दिया और उसी पर अभ्यास शुरू किया। तार कभी ढीले पड़ जाते, कभी सुर निकलता, कभी टूट जाता। फिर भी वह लगातार अभ्यास करती रहीं। इस घटना का जिक्र वह अक्सर करती थीं। वह कहा करती थीं, 'अगर उस रात मैंने रियाज छोड़ दिया होता, तो संगीत की साधना का क्रम शायद कभी आगे नहीं बढ़ पाता।'

Subrata Dhar

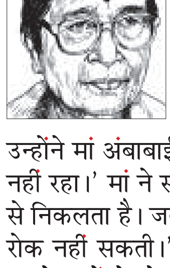

चुनावी व्यवस्था में बदलाव ज़रूरी, पर इसे भ्रष्ट बताकर नकारना ग़लत

सुधर सकता है इलेक्शन सिस्टम

क्या भारत में मतदान बस दिखावा है? क्या देश को बैलेट पेपर पर लौट जाना चाहिए? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। हकीकत में हर व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश होती है, पर इसका यह मतलब नहीं कि मौजूदा व्यवस्था पूरी तरह खराब है। भारत की चुनाव व्यवस्था में सुधार जरूरी है और हो सकता है, लेकिन इसे भ्रष्ट बताकर नकारा नहीं जा सकता।

टीके अरुण

AI Image

राजनीतिक विफलता । भारत में जब बैलेट पेपर चलते थे, तब भी कुछ राज्यों में बूथ कैप्चरिंग और फर्जी मतदान की घटनाएं होती थीं। यहां तक कि EVM के दौर में भी कई जगह स्थानीय गुंडे बूथ में घुसकर उन लोगों के नाम पर वोट डाल देते हैं, जो वोटिंग के लिए नहीं आए होते। यह वोटिंग मशीन की नहीं, राजनीतिक विफलता है।

आरोप गंभीर । राहुल गांधी वोट चोरी का जो आरोप लगा रहे हैं, उसे मजाक कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। उनका आरोप है कर्नाटक में फॉर्म 7 के जरिये बड़े पैमाने पर नाम काटे गए और इसके लिए जिनकी आईडी का इस्तेमाल हुआ, उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं थी। अब यह बात समझ से परे है कि चुनाव आयोग ने जांच को रोकने की कोशिश की और सहयोग नहीं किया।

गोपनीयता गैर जरूरी । अगर फर्जी मतदाता पंजीकृत हो रहे हैं, तो राजनीतिक पार्टियों और सामाजिक संगठनों को आपत्ति उठाने का समय मिलना चाहिए। इसके लिए उन्हें मतदाता सूची समय पर मिलनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए जिसकी मशीन से जांच हो सके। चुनाव आयोग का कहना कि यह मतदाताओं के निजता के अधिकार का उल्लंघन है, बेकार बात है। आप किसे वोट देते हैं, यह निजी मसला है, लेकिन मताधिकार सार्वजनिक है। वोटर लिस्ट इसी सार्वजनिक अधिकार का रेकॉर्ड है, इसलिए इसे गोपनीय रखने का मतलब नहीं बनता।

> **मशीन बनाम बैलेट पेपर**
> - फर्जी वोटिंग EVM नहीं, राजनीति की असफलता
> - पार्टी कार्यकर्ताओं को ज्यादा सजग रहने की जरूरत
> - वोटिंग के CCTV फुटेज को सार्वजनिक किया जाए

रेकॉर्डिंग का मसला । कई बार ऐसा हुआ है कि आखिरी घंटों में वोटिंग अचानक बहुत बढ़ गई। यह वोटिंग सही भी हो सकती है और फर्जी भी। मतदान को लेकर अगर कोई शिकायत हो और मामला कोर्ट में पहुंचे, तो फैसला आने तक रेकॉर्डिंग सुरक्षित रखनी होती है। लेकिन, मान लीजिए अगर वोटिंग के 45 दिनों बाद फ्रॉड के सबूत मिलते हैं और याचिका दायर की जाती है, तो रेकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। यही नहीं, आयोग के सदस्यों को भी मनमाने तरीके से इम्युनिटी दे दी गई है।

बेकार बहाना । CCTV फुटेज को केवल चुनावी गड़बड़ी के संभावित सबूत के रूप में ही क्यों देखा जाए? इसे तो ऐतिहासिक दस्तावेज मानना चाहिए, जिसे भविष्य के इतिहासकार यह समझने के लिए देखेंगे कि किसी इलाके में लोकतंत्र कैसे काम करता था।

अव्यावहारिक बात । यह तर्क देना कि ऐसी फुटेज का दुरुपयोग कर फर्जी विडियो बनाए जा सकते हैं, उतना ही अव्यावहारिक है जितना यह कहना कि महिलाओं को शादी-ब्याह के विडियो में न दिखाया जाए।

EVM पर चिंता । क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती? अगर चुनाव अधिकारी मिलीभगत करें, तो यह संभव है कि जिस EVM पर मतदाताओं ने मतदान किया है, उसकी जगह दूसरी मशीन रख दी जाए। ऐसी मशीन, जिसमें पहले से मनचाहे वोट दर्ज हों। इसी तरह, मिलीभगत से यह भी संभव है कि मशीनों को ऐसे प्रोग्राम किया जाए, जिससे वो कुछ और वोट दर्ज करें, जबकि वोटर ने दबाया कुछ और हो।

सतर्कता और ईमानदारी । चुनावी गड़बड़ियों से बचने की सबसे बड़ी ढाल है राजनीतिक दलों और उनके कार्यकर्ताओं की सतर्कता। साथ में चुनाव अधिकारियों की ईमानदारी भी जरूरी है। दुनिया में कहीं भी परफेक्ट लोकतंत्र बना-बनाया नहीं मिलता, उसे बनाना पड़ता है। SIR के दौरान विदेशी नागरिकों को हटाने के अभियान पर यह बुनियादी सिद्धांत लागू होना चाहिए कि आरोप साबित होने तक हर आरोपी निर्दोष माना जाता है। जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि वोटर लिस्ट में शामिल या आवेदन करने वाला कोई शख्स विदेशी नागरिक है, उसे मत देने का अधिकार मिलना चाहिए।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

महिलाओं पर हिंसा में अमीर देश भी पीछे नहीं

हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र (UN) की रिपोर्ट ने उस सच की परतें खोल दी हैं जिसे आर्थिक उन्नति की चकाचौंध में बड़ी ही सजगता से छुपा कर रखने का प्रयास किया जाता रहा है। अमूमन यह विश्वास किया जाता है कि विकसित देश महिलाओं के आत्मसम्मान और सुरक्षा को लेकर बेहद सजग हैं। परंतु यूएन की रिपोर्ट इस मिथक से पर्दा उठाती है।

ऋतु सारस्वत

घर में असुरक्षित । संयुक्त राष्ट्र के ड्रग्स और अपराध कार्यालय व UN विमिन द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक विकसित देशों में भी महिलाएं अपने घर में सुरक्षित नहीं हैं, चाहे बात अमेरिका की हो या फिर यूरोपीय देशों की। रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2024 में 50,000 महिलाओं और लड़कियों की उसके अंतरंग साथी या परिवार के सदस्य द्वारा हत्या कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक, इसकी वजह घरेलू तनाव, पितृसत्तात्मक दबाव, आर्थिक और भावनात्मक निर्भरता के साथ ही कई देशों में कमजोर कानून और धीमी न्याय प्रक्रिया भी है।

रिश्तों में हिंसा । किसी रिश्ते में हिंसा का उभरना अमूमन भावनात्मक शोषण से शुरू होता है। फिर वित्तीय शोषण और उसके बाद शारीरिक शोषण जैसे अधिक नियंत्रणकारी व्यवहारों में वह बदलता है। ऐसे में अक्सर शारीरिक शोषण की नौबत आने तक जीवन पूरी तरह उलझ चुका होता है। घर, बच्चे और वित्तीय मामले इस तरह से जुड़ जाते हैं कि इसे आसानी से छोड़ना मुश्किल हो जाता है।

पितृसत्ता की गहरी पैठ । यह सोच दुनिया भर में गहरी पैठ बनाए हुए है कि पुरुष प्रोवाइडर (प्रदाता) होते हैं और महिलाएं उनकी संपत्ति होती हैं। इसलिए विवाहित होने पर, महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने पति की आज्ञा मानें, उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करें और समान निर्णय लेने का प्रयास न करें। यदि वे इन मानदंडों का उल्लंघन करती हैं, तो दंड के तौर पर उन्हें शारीरिक हिंसा झेलनी पड़ सकती है।

कॉमन रूम

AI Image

सामाजिक समस्या । महिलाओं के खिलाफ हिंसा को अमूमन या तो व्यक्तिगत मुद्दा करार दिया जाता है या 'कुछ बुरे पुरुषों' के व्यवहार के रूप में देखा जाता है। हालांकि यह एक व्यापक, सामूहिक, सामाजिक समस्या है, जिसकी जड़ें मर्दानगी को केंद्र में रखकर बनाए गए सामाजिक मानदंडों में निहित हैं। सामाजिक रूप से निर्मित ये धारणाएं महिलाओं का ही व्यवहार निश्चित नहीं करतीं, ये पुरुषों को भी कथित मर्दाने स्वभाव को अपनाने के लिए बचपन से ही तैयार करती हैं।

मर्दानगी की पाठशाला । 'जहरीली मर्दानगी' की यह पाठशाला निरंतर इस तथ्य को स्थापित करती रहती है कि स्त्रियों पर नियंत्रण के लिए शारीरिक दंड आवश्यक है। मर्दानगी की इन सामाजिक कसौटियों पर खरा उतरने का दबाव लड़कों और पुरुषों पर होता है और यह हिंसात्मक व्यवहार को कम नहीं होने देता चाहे विकास की कितनी ही इबारतें लिखी जाएं।

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें www.speakingtree.nbt.in

AI से क्या घबराना जब विवेक और सत्य है हमारे साथ

उमा नेमाणी

आज की डिजिटल दुनिया एक नई तरह की माया पैदा कर रही है। ऐसी माया जो छूती तो नहीं, लेकिन उतनी ही वास्तविक लगती है। OpenAI के Sora जैसे उन्नत उपकरण कुछ ही सेकंड में ऐसी छवियां और विडियो बना देते हैं, जिनसे सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है। इस विषय के जानकार कहते हैं कि Sora के लॉन्च होने के केवल दो महीनों में ही X, YouTube, Facebook और Instagram पर भ्रामक विडियो की बाढ़ आ गई है। इस तेजी ने दुष्प्रचार और फर्जी सामग्री की एक नई चुनौती को जन्म दिया है। यह स्थिति हमें श्रीमद्भगवद्गीता की ओर ले जाती है, भगवान श्रीकृष्ण जहां अर्जुन को माया, विवेक और सत्य का स्वरूप समझाते हैं। गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश है- 'नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः' यानी असत्य कभी टिकता नहीं, और सत्य कभी मिटता नहीं।

AI Image

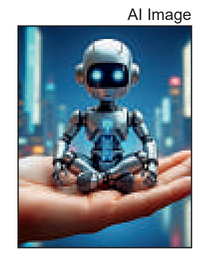

AI जनित विडियो आज हमारे विचारों, राय और भावनाओं को जिस तरह प्रभावित कर रहे हैं, यह याद दिलाता है कि आंखों से दिखाई देने वाली हर चीज सत्य नहीं होती। असली बुद्धि वह है, जिसमें मन की स्पष्टता बनी रहती है। डिजिटल दुनिया की यह चुनौती हमें अपने भीतर झांकने को भी प्रेरित करती है। बाहर चाहे कितना भी भ्रम हो, मन की स्थिरता ही वह दीपक है जो अंधकार में रास्ता दिखाती है।

यदि मन AI द्वारा रचे गए भ्रम में उलझ जाए, तो वही हमारे भीतर भय और असत्य को जन्म देगा। लेकिन यदि हम सत्य, विवेक और आत्म-जागरण पर मन को केंद्रित रखें, तो कोई भी तकनीकी छलावा हमारा मार्ग नहीं भटका सकता। आज जरूरत है विवेक, सत्यापन और अपने भीतर जागृत साक्षीभाव की। AI का युग तो आगे बढ़ेगा, लेकिन मनुष्य को सुरक्षित रखने वाली ताकत उसके अपने विवेक और सत्यबोध में ही है।

सत्य वही है जो भीतर से उजाला करे, न कि वह जो स्क्रीन पर चमकता हुआ दिखाई दे। यही गीता का संदेश है और यही इस तकनीकी युग की महत्वपूर्ण सीख भी।

कांटे की बात

> पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाया जाता है। हमने ऐसे फ्यूल की टेस्टिंग की, इसमें पाया गया कि किसी भी गाड़ी के इंजन में इस फ्यूल की वजह से खराबी नहीं आई। गाड़ियों के प्रदर्शन पर भी कोई असर नहीं हुआ।

नितिन गडकरी, सड़क, परिवहन व राजमार्ग मंत्री

सप्ताह की शख्सियत

इंडिगो संकट को इन युवाओं ने अकेले झेला

इंडिगो संकट की वजह से देशभर के एयरपोर्ट पर हजारों यात्री घंटों फंसे रहे, उनके जरूरी काम छूट गए। एयरलाइन को लेकर यात्रियों का गुस्सा कई जगह हद पार कर गया। यात्रियों का यह गुस्सा फूटा इंडिगो के फ्रंटलाइन स्टाफ पर।

भीड़ के सामने डटे रहे

चेक-इन काउंटर, बोर्डिंग गेट, सूचना डेस्क पर जो युवा कर्मचारी दिखते हैं, वही हैं जो संकट के समय यात्रियों के सवालों और गुस्से का सीधा सामना कर रहे थे। इनमें से कइयों की उम्र बमुश्किल 20-22 साल रही होगी, लेकिन सामने यात्रियों की भीड़ देखकर भी वे अपनी जगह से हटे नहीं। हालांकि टॉप मैनेजमेंट की तरफ से उनके पास न तो सही जानकारी थी और न कोई स्पष्ट निर्देश।

बोझ ग्राउंड स्टाफ पर

कुछ जगहों से खबर आई कि कर्मचारियों के साथ बदसलूकी हुई है। हालांकि इसके बाद भी किसी फ्रंटलाइन स्टाफ ने संयम नहीं छोड़ा। पायलट और फ्लाइट अटेंडेंट्स ने भी माना कि असली बोझ ग्राउंड स्टाफ पर था, खासकर शुरू में जब लोगों को पता नहीं था कि संकट की वजह क्या है। इस घटना का एक सबक यह भी है कि किसी एयरलाइन की ताकत उसके वे कर्मचारी भी हैं, जो सीधे यात्रियों के टच में होते हैं।

जनता जंक्शन

इरफ़ान

अगली सरकार किसकी? कल मिलेगा सिग्नल

हेमंत राजौरा

केरल में हो रहे लोकल बॉडी चुनाव सिर्फ पंचायतों और नगरपालिकाओं के प्रशासनिक कामकाज का आकलन भर नहीं हैं, बल्कि इन्हें 2026 विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है। पिछले तीन दशकों के पैटर्न बताते हैं कि राज्य के मतदाता स्थानीय निकाय चुनावों में ही विधानसभा चुनाव का संकेत दे देते हैं।

UDF के संगठन की परीक्षा

कांग्रेस नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) इन चुनावों को निर्णायक मोड़ के रूप में देख रहा है। यदि वह अच्छा प्रदर्शन करता है तो कांग्रेस में आत्मविश्वास लौटेगा और 2026 विधानसभा चुनावों की तैयारियों को बल मिलेगा। राज्यों में लगातार चुनौतियों से जूझ रही कांग्रेस को केरल के अच्छे नतीजे राष्ट्रीय स्तर पर भी राहत दे सकते हैं।

यदि UDF कमजोर पड़ता है तो पार्टी में पहले से मौजूद गुटबाजी और बढ़ सकती है। लंबे समय से राजनीतिक संभावनाओं की चर्चा में रहने वाले शशि थरूर जैसे नेता भविष्य को लेकर नए संकेत दे सकते हैं। कांग्रेस हाईकमान पर राज्य नेतृत्व और रणनीति बदलने का दबाव भी बढ़ेगा।

सत्तारूढ़ वाम मोर्चा (LDF) इस चुनाव को तीसरी बार सत्ता में लगातार वापसी के लक्ष्य के लिए अहम मान रहा है। पिनाराई विजयन सरकार इधर प्रशासनिक दबाव, आर्थिक चुनौतियों और राजनीतिक विवादों का सामना कर रही है। वाम मोर्चा परंपरागत रूप से पंचायतों में मजबूत संगठन के दम पर चलता रहा है। निकाय चुनाव वह मंच है, जहां उसकी जमीनी ताकत का असली आकलन होता है।

विशुद्ध राजनीति

कसौटी

अगर LDF यहां स्थिति मजबूत रखता है, तो वह 2026 विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक हवा को अपने पक्ष में मोड़ लेगा। लेकिन खराब प्रदर्शन से आगामी चुनावों में समीकरण जटिल हो सकते हैं। इसीलिए वह इन चुनावों में कैडर एकजुटता और स्थानीय संतुलन पर विशेष ध्यान दे रहा है।

केरल में BJP के लिए यह चुनाव विस्तार का मौका है। पार्टी ने हालिया वर्षों में कई जिलों में अपनी पकड़ बढ़ाई है। ईसाई समुदाय से भी संवाद बढ़ाने की उसने कोशिश तेज की है। BJP इस चुनाव में LDF सरकार के खिलाफ सबरीमला गोल्ड चोरी को प्रमुख मुद्दा बना रही है, लेकिन शोर-शराबे से दूर रहकर। पार्टी समझती है कि आक्रामक रुख अपनाने पर उसके खिलाफ 2019 की तरह धार्मिक ध्रुवीकरण हो सकता है। इसलिए उसका बूथ स्तर पर ज्यादा ध्यान है। यदि इन चुनावों में उसे अच्छी सफलता मिलती है तो विधानसभा चुनाव में वह अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी।

इतिहास क्या कहता है

केरल में लोकल बॉडी चुनावों को विधानसभा चुनाव का बैरोमीटर माना जाता है। 2020 में LDF ने 14 में से 11 जिला पंचायतें जीतीं। UDF मलप्पुरम और एर्नाकुलम तक सीमित रहा। नगर निगमों में LDF ने पांच हासिल किए, जबकि UDF को केवल कनूर निगम मिला। नगरपालिकाओं में LDF 35 पर जीता, UDF 23 पर। अगले साल विधानसभा चुनाव हुए तो LDF ने ऐतिहासिक तौर पर लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल की। 2015 निकाय चुनावों में भी LDF 549 ग्राम पंचायत और सात जिला पंचायत जीत कर आगे था। और अगले वर्ष उसने विधानसभा में सत्ता में वापसी की। ऐसे में 2025 लोकल बॉडी चुनाव UDF, LDF, BJP तीनों की शक्ति, कमजोरी, नेतृत्व और जनाधार का सबसे बड़ा परीक्षण हैं। इंतजार करिए 13 दिसंबर को इन चुनावों के नतीजों का।

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

संकट टला नहीं है

11 दिसंबर का संपादकीय 'मुआवजा मिले' पढ़कर स्पष्ट होता है कि सरकारी हस्तक्षेप के बावजूद इंडिगो संकट पूरी तरह दूर नहीं हुआ है। करीब 5,000 उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को भारी मानसिक और आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ीं। हाई कोर्ट ने कहा कि केवल रिफंड नहीं, बल्कि असुविधा का मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी पूछा कि जब इंडिगो को नए नियमों से होने वाली दिक्कतों का अंदेशा था, तो समय रहते तैयारी क्यों नहीं हुई। संकट के दौरान अन्य एयरलाइंस द्वारा टिकटों की कीमतें बढ़ा दिया जाना m भी चिंताजनक है, जिस पर सख्त निगरानी जरूरी है।

चंद्र प्रकाश शर्मा, रानी बाग

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

आर.एन.आई. नं. 510/57 © सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्सः 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु.; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

भारत-अमेरिका ट्रेड वार्ता

अमेरिका और भारत के बीच हो रही ट्रेड डील बातचीत पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। उम्मीद दिखाई दे रही है कि दोनों देश मिलकर एक निष्पक्ष और फायदेमंद बहुक्षेत्रीय व्यापार समझौता जल्द कर लेंगे। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों में बाजार पहुंच, ट्रेड बैरियर, कृषि उत्पाद, सेवाओं का व्यापार, निवेश और अन्य संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देश अपने मतभेदों को कम करते हुए ऐसे व्यवहारिक समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं जो दोनों की अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर हों। व्यापार वार्ता में भारत की कमान अब दर्पण जैन सम्भाल रहे हैं। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीयर का कहना है कि अमेरिकी किसानों की भारतीय बाजारों में पहुंच बढ़ाने को लेकर भारत ने अब तक सबसे अच्छा प्रस्ताव दिया है। खासकर ज्वार और सोया जैसी फसलों पर बाजार खोलने पर चर्चा चल रही है। भारत अमेरिकी वस्तुओं के लिए एक वैकल्पिक बाजार बन सकता है। ग्रीयर का यह बयान आने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चावल पर नए टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। उन्होंने भारत से कहा था कि वह अमेरिका में अपने चावल की डंपिंग नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी किसानों के लिए 12 अरब डॉलर की मदद का ऐलान करते हुए कहा कि भारत से सस्ता चावल आने की वजह से अमेरिका का चावल उत्पादक परेशान है और उनके दाम गिर रहे हैं। भारत ने क्या प्रस्ताव दिया है इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है लेकिन इतना तय है कि भारत कृषि उत्पादों को लेकर बहुत सतर्क है और वह अमेरिका को कोई भी अनुचित छूट देने को तैयार नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ट्रेड डील पर भारत एक सख्त वार्ताकार साबित हुआ है। अमेरिकी प्रतिनिधि स्वीकार कर रहे हैं कि भारत के कृषि क्षेत्र में खासकर राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में घुसना आसान नहीं है। भारत कुछ फसलों मांस और डेयरी उत्पादों के आयात का विरोध करता है। भारत को अपने किसानों की चिंता है। कृषि और डेयरी उत्पाद ट्रेड डील में रोड़ा बने हुए हैं। अगर अमेरिकी फसलें और दूध उत्पाद भारत आते हैं तो भारत के किसानों का क्या होगा। भारत में किसान मुद्दे पहले से ही काफी संवेदनशील बने हुए हैं। मक्का, सोयाबीन, गेहूं, कपास, चावल, गन्ना, ज्वार और केनोला जैसी फसलें वैश्विक वस्तुएं हैं और यह किसानों और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर सकती हैं। भारत को फूंक-फूंक कर कदम रखना होगा। यदि अमेरिका साझेदारी को लेकर गंभीर है तो उसे सबसे पहले भारतीय निर्यात पर लगाए गए दंडात्मक शुल्क को 50 प्रतिशत से घटाकर 20-25 प्रतिशत करना चाहिए और रूस से तेल खरीद को लेकर दबाव को कम करना चाहिए। अमेरिका भारत को कृषि निर्यात बढ़ाने के चक्कर में है जबकि भारतीय निर्यात के लिए बाजार पहुंच को लेकर अमेरिका स्पष्ट रुख नहीं अपना रहा। यह सब तब हो रहा है जब दुनिया भर में गेहूं की सप्लाई लगभग 1.10 अरब टन के करीब पहुंच गई है। ऐसे में अमेरिका भारत को अपने कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए एक बड़े बाजार के तौर पर देख रहा है। अमेरिकी कृषि विभाग (यूएसडीए) ने भी ग्लोबल अनाज सप्लाई के अपने अनुमान को बढ़ाया है। इससे सप्लाई की चिंता कम हुई है। वहीं, भारत जैसे प्रमुख बाजारों के लिए निर्यातकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने की संभावना है।

भारत और अमेरिका के अधिकारी दो अलग-अलग वार्ताएं कर रहे हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य टैरिफ से संबंधित एक ढांचागत व्यापार समझौता और एक व्यापक व्यापार समझौता तैयार करना है। फरवरी में नेतृत्व के निर्देशों के बाद, 2025 के पतझड़ तक प्रारंभिक चरण को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से बातचीत शुरू हुई। चर्चा छह दौरों से गुजर चुकी है, जिसका अंतिम उद्देश्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 191 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 500 बिलियन डॉलर करना है।

यूएसडीए की दिसंबर की 'वर्ल्ड एग्रीकल्चरल सप्लाई एंड डिमांड एस्टिमेट्स' रिपोर्ट में 2025-26 के लिए ग्लोबल गेहूं सप्लाई का अनुमान 75 लाख टन बढ़ाकर लगभग 1.10 अरब टन कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी कई बड़े निर्यात देशों में ज्यादा उत्पादन के कारण हुई है। कनाडा में उत्पादन का अनुमान 30 लाख टन बढ़कर 400 लाख टन हो गया है, जो सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। इसके बाद अर्जेंटीना, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया और रूस का नंबर आता है। यद्यपि भारत अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। भारत को नए बाजार भी मिल रहे हैं लेकिन भारत का आयात बिल तेजी से बढ़ रहा है जो चिन्ता का विषय है। आयात बिल बढ़ने के कई कारण हैं। इनमें सोने की कीमतों में तेजी, कच्चे तेल के ऊंचे दाम और इलैक्ट्रोनिक कम्पोनेंट्स के लिए निर्भरता शामिल है। यह तीनों चीजें भारत आयात करता है। इनके ट्रिपल अटैक को रुपए के कमजोर होने ने और हवा दे दी है। परिणामस्वरूप देश के व्यापार घाटे पर फिर से दबाव कायम हो गया है।

भारत और अमेरिका के अधिकारी दो अलग-अलग वार्ताएं कर रहे हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य टैरिफ से संबंधित एक ढांचागत व्यापार समझौता और एक व्यापक व्यापार समझौता तैयार करना है। फरवरी में नेतृत्व के निर्देशों के बाद, 2025 के पतझड़ तक प्रारंभिक चरण को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से बातचीत शुरू हुई। चर्चा छह दौरों से गुजर चुकी है, जिसका अंतिम उद्देश्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 191 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 500 बिलियन डॉलर करना है।

2024-25 में, अमेरिका लगातार चौथे वर्ष भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदार के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने में सफल रहा, द्विपक्षीय व्यापार 131.84 बिलियन डॉलर (86.5 बिलियन डॉलर निर्यात) तक पहुंच गया। भारत के व्यापारिक पोर्टफोलियो में अमेरिका का महत्वपूर्ण योगदान है। कुल माल निर्यात का 18 प्रतिशत, आयात का 6.22 प्रतिशत और कुल व्यापारिक वस्तुओं का 10.73 प्रतिशत। निर्यातकों ने इस समझौते के महत्व पर विशेष बल दिया है, क्योंकि भारत से अमेरिका को होने वाले व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में लगातार दो महीनों से गिरावट देखी गई है, अक्टूबर में यह गिरावट 8.58 प्रतिशत घटकर 6.3 अरब डॉलर रह गई, जिसका कारण वाशिंगटन द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ हैं। भारत रचनात्मक रूप से बातचीत कर रहा है लेकिन किसानों या छोटे उद्योगों की कीमत पर नहीं। मोदी सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह पारस्परिक और आपूर्ति श्रृंखला में साझेदारी चाहती है न कि एक तरफा रियायतें और वह रूसी कच्चे तेल को नहीं छोड़ेगी जिसे वह ऊर्जा, सुरक्षा के लिए बेहतर मानती है। देखना होगा कि ट्रेड वार्ता पर कोई खुशनुमा खबर मिलती है। इसके लिए जरूरी है कि अमेरिका भी अपने रवैये में अनुकूल बदलाव करे।

बोझ जिम्मेदारियों का

"जिम्मेदारियों का बस्ता जो कांधे पर उठाते हैं,
ऐसे लोग छुट्टियों में भी कहां चैन पाते हैं,,
घर की जरूरतें पूरी करने में जब दिन बीत जाते हैं,
तब बचपन की मासूमियत से खुद ब खुद हाथ छूट जाते हैं,,
जो लोग अक्सर खुद को जरूरत से ज्यादा व्यस्त दिखाते हैं,
ऐसे लोग जीवन के अंतिम मोड़ पर अकेले खड़े नजर आते हैं।।"

कुत्ते का ड्रामा

‘**ड्रामा**’ शब्द शायद इस माह की शुरूआत में शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद से संसद की केंद्रीय थीम रहा है, इस शब्द का प्रयोग भाजपा और कांग्रेस दोनों की ओर से काफी उदारता से किया गया।

शुरूआत के लिए, इस शीतकालीन सत्र के अपने पारंपरिक पूर्व-सत्र संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा था: “ड्रामा करने के लिए बहुत सी जगहे हैं। जिन्हें ड्रामा करना है, वे कहीं और करें। यहां डिलीवरी होनी चाहिए, ड्रामा नहीं।”

प्रधानमंत्री पर पलटवार करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद के समक्ष मौजूद मुख्य मुद्दों पर बात करने के बजाय एक बार फिर “ड्रामेबाजी” की है। उन्होंने कहा कि वास्तविकता यह है कि सरकार पिछले 11 वर्षों से लगातार “संसदीय शिष्टाचार और संसदीय प्रणाली को रौंदती रही है।” खड़गे ने कहा, “भाजपा को अब इस ध्यान-भटकाने वाले ड्रामे को खत्म कर देना चाहिए और जनता के वास्तविक मुद्दों पर संसद में बहस करनी चाहिए।”

एक अन्य स्तर पर, एक कुत्ते को लेकर भी काफी ड्रामा देखने को मिला। कांग्रेस सांसद रेनुका चौधरी जब एक कुत्ते को लेकर संसद पहुंचीं, तो एक भाजपा सदस्य ने “उचित दस्तावेज” न होने पर आपत्ति जताई। बेतुकापन किस स्तर तक पहुंचा है या इसमें कौन अधिक खराब दिखा-यह आकलन करना कठिन है, लेकिन एक बात स्पष्ट है: संसद और उसके लिए चुने गए प्रतिनिधि एक नए निचले स्तर पर पहुंच गए हैं, लेकिन इस कुत्ते-कांड का संदर्भ समझना आवश्यक है, जिस तरह यह घटनाक्रम सामने आया।

हंगामा तब शुरू हुआ जब चौधरी की कार एक कुत्ते के साथ संसद भवन परिसर में दाखिल हुई। चौधरी के अनुसार, उन्होंने एक आवारा कुत्ते को उठाया था और उसे पशु-चिकित्सक के पास ले जा रही थीं। एक कहानी यह है कि उनका चालक उन्हें संसद में उतारने के बाद कुत्ते को डॉक्टर के पास ले जाने वाला था। दूसरी कहानी यह है कि उन्होंने संसद आते समय रास्ते में एक आवारा कुत्ते को बचाया और उसे सीधे पशु-चिकित्सक के पास ले जा रही थीं। एक और कहानी यह भी है कि कार में मौजूद कुत्ता चौधरी का अपना पालतू था और उसे महज नाटकीयता के लिए संसद लाया गया और नाटकीयता आगे भी जारी रही। जब सत्तारूढ़ पार्टी ने चौधरी पर ड्रामा करने का आरोप लगाया, तो उन्होंने कहा कि सरकार को “जानवर पसंद नहीं हैं।” यहीं नहीं रुकीं, उन्होंने कहा: “इनकी समस्या क्या है? यह इतना छोटा है, क्या यह काटेगा? संसद में बैठे लोग काटते हैं, कुत्ते नहीं।” उन्होंने यह भी कहा कि सड़क से कुत्ता बचाने के खिलाफ कोई कानून नहीं है। “वाह सरकार,” उन्होंने ट्वीट किया।

दरअसल, जब उन्हें विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव की धमकी दी गई, तो उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कुत्ते की आवाज की नकल करते हुए कहा: “भौं, भौं।” मामला छोड़ने के मूड में न होते हुए भाजपा ने कहा कि चौधरी संसद का मजाक बना रही हैं और “तमाशा” कर रही हैं, और “दोषी” सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

2018 की ओर लौटें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में चौधरी की तेज हंसी का मजाक उड़ाया था। राज्यसभा में, मोदी की एक टिप्पणी पर रेनुका जोर से हंस पड़ी थीं, जिसके बाद सभापति ने संयम बरतने को कहा। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें रोका न जाए: “रामायण सीरियल के बाद, हमें इस तरह की हंसी सुनने का सौभाग्य आज ही मिला है।” भले ही प्रधानमंत्री ने रामायण के किसी चरित्र का नाम नहीं लिया, लेकिन यह स्पष्ट था कि संदर्भ रावण की बहन शूर्पणखा का था, लेकिन चौधरी कोई असहाय नायिका नहीं हैं।

उन्होंने भी नाम लेकर कटाक्ष किए हैं। अकाली दल की हरसिमरत बादल, जो उस समय केंद्रीय मंत्री थीं, को याद करें। कुछ वर्ष पहले, आरोप है कि चौधरी ने उन्हें “कचरा” कहा था। उन्होंने यह भी कहा था कि वे “भाड़ में जाएं”, और बादल की टिप्पणी को “पॉलिटिकल ड्रामा” बताकर खारिज कर दिया था।

चाहे वह कुत्ते का प्रकरण हो, शूर्पणखा-संदर्भ हो या “कचरा” टिप्पणी मूल तथ्य यही है कि संसद की मर्यादा और गरिमा गिर चुकी है, बल्कि कहना चाहिए कि गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुई है, और इसका दोष किसी एक पार्टी या एक सांसद पर नहीं डाला जा सकता, यह सामूहिक विफलता है।

उतना ही अभूतपूर्व यह भी है कि सदन के भीतर नेता-विशेष के समर्थन में नारे लगाए जाते हैं। इसे समझें तो पता चलता है कि भाजपा शासन में जब भी प्रधानमंत्री लोकसभा में प्रवेश करते हैं, “मोदी, मोदी” के नारे गूंज उठते हैं। आश्चर्य की बात है कि इन्हें रोकने के लिए सभापति की ओर से कोई निर्देश या हस्तक्षेप नहीं होता। हालात ऐसे दिखाई देते हैं कि यदि संभव होता तो सभापति भी इस मोदी समर्थक नारेबाजी में शामिल हो जाते।

मूल विषयों पर आया जाए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने उस संस्था का मजाक बना दिया है जिसे कभी अत्यंत सम्मान प्राप्त था।

यह एक संवैधानिक पवित्र स्थान था जहां मुद्दों पर चर्चा, वाद-विवाद और मतभेद होना स्वाभाविक माना जाता था। आज यह हंगामों और उसके बाद होने वाले स्थगनों तक सीमित रह गया है। अक्सर पूरा सत्र ही इस कारण व्यर्थ चला जाता है क्योंकि विपक्षी सांसद सदन को चलने नहीं देना चाहते। स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि जहां पहले यह माना जाता था कि संसद चलेगी, आज सुचारू कार्यवाही एक दिवास्वप्न बन गई है।

आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं।

उदाहरण के लिए, 21 जुलाई से 21 अगस्त 2025 के बीच हुए मानसून सत्र में निर्धारित समय का दो-तिहाई हिस्सा बाधाओं में नष्ट हुआ। इसका प्रभाव प्रश्नकाल पर भी पड़ा, जिसमें लोकसभा केवल 23% और राज्यसभा मात्र 6% निर्धारित समय तक ही काम कर सकी। कई विधेयक भी बिना चर्चा के पारित किए गए।

एकमात्र सकारात्मक पहलू बजट सत्र रहा, जिसमें लोकसभा की उत्पादकता 111% और राज्यसभा की 112% रही-और प्रश्नकाल भी अपेक्षाकृत बेहतर चला। 2024 के बजट सत्र में भी यही रूझान दिखा था, लेकिन ये हाल के वर्षों के अव्यवस्थित व्यवहार से अलग कुछ दुर्लभ अपवाद भर हैं।

उत्पादकता में गिरावट एक संरचनात्मक और बहु-सरकारी समस्या है और यह केवल भाजपा तक सीमित नहीं है। अतीत में भी उदाहरण मिलते हैं: यूपीए-2 के दौरान 15वीं लोकसभा का प्रदर्शन सबसे खराब था। निर्धारित समय का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा नष्ट हुआ, जबकि 13वीं और 14वीं लोकसभाओं की उत्पादकता क्रमश: 91% और 87% थी।

संसद चलाने की लागत अत्यंत भारी है : अनुमान के अनुसार प्रति मिनट 2.5 लाख रुपये, जो प्रतिदिन लगभग 6 करोड़ रुपये और प्रतिवर्ष 600 करोड़ रुपये बैठते हैं। तो इसका भुगतान कौन करता है? और क्या उन सांसदों को, जिन्हें जनता के मुद्दे उठाने के लिए चुना गया है, जवाबदेह नहीं ठहराया जाना चाहिए? क्या उन्हें व्यर्थ गए श्रम-घंटों के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए?

एक उदाहरण भाजपा के बैजयंत ‘जय’ पांडा ने प्रस्तुत किया था, जिन्होंने एक दशक पहले कहा था कि वे शीतकालीन सत्र में “नष्ट/व्यर्थ हुए समय” के अनुपात में अपना वेतन लौटाएंगे, क्योंकि वह सत्र 2014 के बाद के दस सत्रों में सबसे कम उत्पादक था।

यह एक तर्कसंगत और आवश्यक कदम है: हर वह श्रम-घंटा जो बाधाओं में नष्ट हो, उसके लिए सांसदों को दंडित किया जाए अर्थात उनकी वेतन से उतनी कटौती हो। जब वेतन कटेगा, तब उन्हें अनुशासन का अर्थ समझ आएगा, दूसरे शब्दों में, वेतन कटौती का मतलब होगा काम के घंटों की पुनर्स्थापना।

हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना के लिए

वर्ल्ड बैंक ने 305 मिलियन अमेरिकी डॉलर किए मंजूर

चंडीगढ़,(पंजाब केसरी): हरियाणा की पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं को एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देते हुए, वर्ल्ड बैंक ने हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (HCAPSD) के लिए 305 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता को मंजूरी प्रदान की है। यह परियोजना 2030 तक हरियाणा को प्रदूषण-मुक्त राज्य बनाने की दिशा में सरकार की प्रमुख पहल है। स्वीकृत सहायता में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का IBRD लोन तथा SA रीजनल इंटीग्रेशन मल्टी-डोनर ट्रस्ट फंड से 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान शामिल है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ल्ड बैंक द्वारा 305 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता पिछले वर्ष नवंबर में चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और वर्ल्ड बैंक प्रतिनिधियों के बीच हुई उच्च-स्तरीय बैठक के उपरांत प्राप्त हुई है। बैठक के दौरान वर्ल्ड बैंक ने हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्रियान्वयन के लिए 2,498 करोड़ रुपये के लोन का आश्वासन दिया था। परियोजना की कुल लागत 3,646 करोड़ रुपये है, जिसमें से 1,065 करोड़ रुपये का योगदान हरियाणा सरकार द्वारा और अतिरिक्त 83 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में दिया जाएगा। हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उद्देश्य परिवहन, उद्योग, कृषि, शहरी प्रबंधन और वैज्ञानिक निगरानी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में समन्वित हस्तक्षेपों के माध्यम से पूरे राज्य में वायु गुणवत्ता में मापनीय सुधार करना है। इसका क्रियान्वयन समर्पित एसपीवी ARJUN (AI for Resilient Jobs, Urban Air Quality & Next-Gen Skills Council) द्वारा किया जाएगा, जो योजना, कार्यान्वयन और वास्तविक समय निगरानी में प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करेगा।

रोजगार के अवसर और उद्योगों के विकास पर जोरः डॉ. यादव

भोपाल, (पंजाब केसरी): मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 13 दिसंबर को भोपाल और 14 दिसंबर को इंदौर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में सरकार बनने के बाद गरीब, किसान, युवा और नारी कल्याण के लिए कई उल्लेखनीय निर्णय लिए गए। राज्य में कृषि के लिए सिंचाई का रकबा दोगुना करने के उद्देश्य से जल गंगा संवर्धन अभियान और कई बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से प्रयास जारी हैं। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उद्योगों के विकास पर जोर दिया जा रहा है। हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट देश में सबसे अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सुशासन पर आधारित व्यवस्थाएं संचालित हों, इसके लिए अच्छे कार्य में सदैव साथ हैं और अगर कहीं भी कुछ गलत होगा तो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मध्यप्रदेश की धरती से नक्सलवाद के उन्मूलन की दिशा में विगत दिनों उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई है। प्रदेश में नक्सलियों का सबसे बड़ा सरेंडर बालाघाट में कराया गया है।

बस्तर अब नक्सलवाद से उभरा : शांति-विकास की लहर : सीएम विष्णु

रायपुर,जगदलपुर, आशीष शर्मा (पंजाब केसरी): छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय गुरुवार को बस्तर ओलंपिक के भव्य उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए जगदलपुर पहुंचे।

मा दंतेश्वरी एयरपोर्ट में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह बस्तरवासियों के लिए गर्व और सौभाग्य का क्षण है कि ऐसा विशाल खेल आयोजन अब बस्तर संभाग मुख्यालय की पहचान बन चुका है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष इस ओलंपिक में 1 लाख 65 हजार खिलाड़ी शामिल हुए थे, जबकि इस वर्ष भागीदारी बढ़कर 3 लाख 91 हजार तक पहुंच गई है। उन्होंने आगे कहा कि यह आंकड़ा सिर्फ खेलों की लोकप्रियता को नहीं बताता, बल्कि बस्तर के युवाओं की प्रतिभा, ऊर्जा और खेल के प्रति अदम्य उत्साह को दर्शाता है। इतनी बड़ी भागीदारी यह भी साबित करती है कि बस्तर का समाज अब पूरी मजबूती से सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ रहा है। खेल मैदानों में उमड़ रही भीड़ बताती है कि बस्तर के लोग नक्सलवाद की छाया से बाहर निकलकर शांति, विकास और प्रगति की राह चुनना चाहते हैं। बस्तर बदल रहा है और यह परिवर्तन खेल जैसे आयोजनों के माध्यम से और भी सशक्त रूप में सामने आ रहा है।

डिजिटल आजादी या बच्चों की सुरक्षा?

सोशल मीडिया न्यूनतम आयु विधेयक ने ऑस्ट्रेलिया को उन सरकारों के लिए एक परीक्षण का विषय बना दिया है, जिन्होंने युवाओं पर इसके मानसिक स्वास्थ्य प्रभाव के बारे में चिंता के बीच सोशल मीडिया पर आयु प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया है या बनाने की योजना बना रहे हैं। फ्रांस और कुछ अमेरिकी राज्यों सहित कई देशों ने माता-पिता की अनुमति के बिना नाबालिगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून पारित किए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में यह प्रतिबंध पूर्णतः लागू है। ऑस्ट्रेलिया में इस कानून का पारित होना मध्यमार्गी-वामपंथी प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ के लिए एक राजनीतिक जीत है इस प्रतिबंध का निजता के पक्षधरों और कुछ बाल अधिकार समूहों ने विरोध किया, लेकिन सर्वेक्षणों के अनुसार, 77% आबादी इसे चाहती थी। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर आना कई मायनों में खतरनाक होता है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेस की एक रिसर्च बताती है कि जो बच्चे और टीनएजर्स दिन में 3 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया पर बिताते हैं, उनमें डिप्रेशन और एंजायटी का खतरा दोगुना होता है। इस रिसर्च में एक सर्वे के हवाले से कहा गया है कि 13 से 17 साल के 46% टीनएजर्स का मानना है कि सोशल मीडिया उन्हें और बुरा महसूस कराता है। इसी तरह, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सितंबर 2024 में एक सर्वे जारी किया था। सर्वे में 44 देशों के 11, 13 और 15 साल के 2.80 लाख से ज्यादा बच्चों को शामिल किया गया था। सर्वे में शामिल 11% बच्चों ने माना था कि सोशल मीडिया के कारण उन्हें कई तरह की समस्याएं हुई हैं। अमेरिका में हुई एक स्टडी में सामने आया था कि सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताने से बच्चों का न सिर्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, बल्कि उन्हें भूख भी कम लगती है। सर्वे में शामिल 13 से 17 साल की 46% लड़कियों ने बताया था कि सोशल मीडिया ने उन्हें अपनी बॉडी को लेकर बुरा महसूस कराया है। इस सर्वे में शामिल 64% बच्चों ने बताया था कि वे रोज साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर कई ऐसे लोग भी होते हैं जो कम उम्र के बच्चों को टारगेट करते हैं और उनका इस्तेमाल अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरी करने

के लिए करते हैं या फिर उनसे पैसे ठगते हैं। सर्वे में शामिल 10 में से 6 लड़कियों ने बताया था कि सोशल मीडिया पर किसी अजनबी ने उनसे इस तरह बात की जिससे उन्हें बड़ा अजीब लगा। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह सोशल मीडिया पर एज कंट्रोल को कैसे लागू करेगी? उन्होंने कहा, 'सोशल मीडिया के कारण कुछ बच्चों में नींद की समस्या और बॉडी इमेज जैसी समस्याएं हो सकती हैं लेकिन यह ग्रामीण इलाकों में रहने वाले या विकलांग बच्चों के लिए लाइफलाइन भी हो सकता है।'16 साल से कम उम्र के बच्चे भले ही फेसबुक-इंस्टा और स्नैपचैट पर अकाउंट नहीं बना पाएंगे लेकिन फिर भी उनके पास वॉट्सऐप, डिस्कॉर्ड जैसे दूसरे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का एक्सेस होगा। रिपोर्ट कहती है कि 'यह मानना नादानी होगी कि बुलिंग ऐक्टिविटी बस एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट नहीं होगी।'ऑस्ट्रेलिया के बच्चों पर लगाए गए प्रतिबंध 'दुनिया में सबसे सख्त माने जा रहे' सोशल मीडिया बैन को चकमा देने में 13 साल की इसाबेल ने पांच मिनट से भी कम का समय लगाया।

ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर एक नया और कड़ा कदम उठाया है। अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और अन्य प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने की अनुमति नहीं होगी। इस नए कानून की घोषणा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने की। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने इस कदम को “युवा पीढ़ी की सुरक्षा के लिए दुनिया में पहला कदम” बताया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव बढ़ गया है और अब “काफी है।” नए नियमों के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के अकाउंट हटाने होंगे, वरना भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। इस कानून के लागू होते ही देशभर के कई बच्चे के फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसी साइट्स पर अकाउंट बंद हो गए।

गौरतलब है कि इंस्टाग्राम के पास अकेले 13 से 15 साल के लगभग 3.5 लाख ऑस्ट्रेलियाई यूजर्स हैं। सरकार ने स्पष्ट किया कि हर किसी को अपनी उम्र प्रमाणित नहीं करनी होगी, लेकिन जिन पर शक होगा, उन्हें अपनी उम्र साबित करनी पड़ सकती है। बच्चे बिना लॉगिन किए कुछ कंटेंट देख सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत अकाउंट नहीं बना पाएंगे। जिसके बाद देश में एक भावनात्मक बहस छिड़ गई, जिसने बिग टेक को लक्षित करने वाले सबसे कठोर नियमों में से एक के साथ दुनिया भर के न्यायालयों के लिए एक मानक स्थापित किया। स्नैपचैट समेत दस प्लेटफ़ॉर्म्स पर सरकार ने यह नियम लागू किए हैं। स्नैपचैट ने इसाबेल को एक नोटिफ़िकेशन भेजा।

इसमें लिखा था कि अगर वह यह साबित नहीं कर पाईं कि उनकी उम्र 16 साल से ज़्यादा है, तो उनका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। इसाबेल बताती हैं, "मैंने अपनी मम्मी की एक फ़ोटो ली और उसे कैमरे को दिखाया और इतने में सिस्टम क्रैक हो गया। इसके बाद स्क्रीन पर लिखा आया कि थैंक यू फॉर वेरीफाइंग योर एज"वह बताती हैं, "मैंने सुना है किसी ने ऐसा करने के लिए बियोंसे (मशहूर अमेरिकी सिंगर) का चेहरा इस्तेमाल किया था। उसे भी सिस्टम ने मान लिया था।" इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए सहारा भी बनता है। इस बारे में सबसे बड़ी चिंता तकनीकी पक्ष को लेकर भी है। आशंका जताई जा रही है कि जो बच्चे टेक्नोलॉजी को चकमा देकर खेल में माहिर होंगे वे वीपीएन का उपयोग कर अपनी उम्र गलत बताकर अकाउंट को लॉगइन कर बैन को नाकाम कर सकते हैं।

कई विशेषज्ञ कहते हैं कि ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि सोशल मीडिया कंपनियों को मजबूर किया जाए कि वे हानिकारक कंटेंट को बेहतर तरीके से नियंत्रित करें। उनका मानना है कि कंपनियों की एल्गोरिद्म की शक्ति को सीमित किया जाना चाहिए और बच्चों को इंटरनेट की असली दुनिया के लिए बेहतर तरीके से तैयार किया जाए। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आयु प्रतिबंध लागनू करने में आ रही चुनौतियों के कारण इस बात पर भी जोर देना होगा कि ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करने में माता-पिता और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका भी अहम हो जाती है। कुल मिलाकर सरकारों, शिक्षकों और तकनीकी फर्मों को ऐसे विनियमों पर सहयोग करना चाहिए जो डिजिटल जुड़ाव के साथ सुरक्षा को संतुलित करते हों।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

सुंदर, सुरक्षित और स्वच्छ होंगी दिल्ली की सड़कें: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री का सभी इंजीनियर्स को स्पष्ट संदेश, बहाने नहीं चलेंगे, एक्शन और परिणाम पर हो फोकस

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली के केदारनाथ साहनी ऑडिटोरियम में 'स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क फॉर रोड रिडेवलपमेंट' पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में सड़क निर्माण, सौंदर्यीकरण, ग्रीन कवर, ड्रेनेज, यूटिलिटी मैनेजमेंट और मेंटेनेंस के लिए एक एकीकृत और मानकीकृत ढांचा तय करना था, ताकि सभी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित हो सके। बैठक में पीडब्लूडी, एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए, दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ सीएक्यूएम, सीएसआईआर, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर तथा राहगीरी फाउंडेशन के विशेषज्ञों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया।

विशेषज्ञों ने राजधानी की अवसंरचना, यातायात प्रबंधन, शहरी डिजाइन और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। इस अवसर पर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविन्द्र इन्द्राज सिंह, डॉ. पंकज कुमार सिंह, दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

हर स्तर पर इंजीनियर्स और अधिकारियों की सक्रियता और जवाबदेही जरूरीः सीएम

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों, प्रतिनिधियों और इंजीनियरों से हर कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सुधारों और निरंतर निगरानी के महत्व पर जोर देते हुए बताया कि नालों, जल निकासी, सड़कों और फुटपाथों की समस्या केवल तभी हल होगी जब अधिकारी स्वयं अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। उन्होंने मिंटो ब्रिज और आरके पुरम अंडरपास से सम्बंधित समस्याओं का उदाहरण देते हुए बताया कि सभी विभागों के समन्वय से ही इनका तुरंत समाधान किया गया है। उन्होंने कहा कि हर स्तर पर इंजीनियरों और अधिकारियों की सक्रियता और जवाबदेही जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कचरा प्रबंधन, ओपन बर्निंग रोकने, नए बायोगैस और ग्रीन वेस्ट प्लांट लगाने, वेट वेस्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि नई बिल्डिंगों को जीरो वेस्ट, ग्रीन और सेल्फ-सस्टेनेबल बनाया जाए और वाटर हार्वेस्टिंग, मिस्ट और एंटी-स्मोग गन जैसी सुविधाएं लागू हों। उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से हर कार्य में पूर्ण निष्ठा, समर्पण और सामूहिक प्रयास की अपील की।

नौ महीनों में हुए कई प्रशासनिक सुधारः प्रवेश

दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पिछले नौ महीनों में कई प्रशासनिक सुधार किए हैं, इसके साथ साथ अधिकारियों और इंजीनियरों की सक्रियता और जिम्मेदारी भी उतनी ही अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि कई बार विभागीय अधिकारियों के बीच जिम्मेदारी तय करने में देरी होती है और तीसरी एजेंसियों के हस्तक्षेप से समय भी बर्बाद होता है। उन्होंने अधिकारियों को प्रेरित किया कि वे व्यक्तिगत और विभागीय हितों से ऊपर उठकर दिल्ली को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करें।

राष्ट्रीय राजधानी पर प्रदूषण, ठंड और फॉग का ट्रिपल अटैक, औसत एक्यूआई 282

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण, फॉग और कड़ाके की ठंड का ट्रिपल अटैक है। जहां प्रदूषण में थोड़ी राहत है वहीं फॉग की समस्या बढ़ने से रात के समय विजिबलिटी कम हो गई है। साथ ही कड़ाके की सर्दी भी परेशान करने लगी है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीपी) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में हवा की क्वालिटी खराब कैटेगरी में 288 दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के सुबह सात बजे को आंकड़ों के अनुसार, राजधानी दिल्ली के अलीपुर में एक्यूआई 309, आनंद विहार में एक्यूआई 302, अशोक विहार में 331, आया नगर में 242, बवाना में 334, बुराड़ी में 293, चांदनी चौक में 308, डीटीयू में 331, द्वारका सेक्टर 8 में 285, आईजीआई एयरपोर्ट टी3 इलाके में 211, आईटीओ में 309, जहांगीरपुरी में 341, लोधी रोड 232, मुंडका 326, नजफगढ़ में 219, पंजाबी बाग में 302, रोहिणी 339, विवेक विहार 319, सोनिया विहार 301, आरकेपुरम 309, वजीरपुर में 325 दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने गुरुवार को आसमान ज्यादातर साफ रहने और शुक्रवार और शनिवार को हल्के से मध्यम कोहरे का अनुमान लगाया है।

अशोक विहार में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पानी का छिड़काव करती गाड़ी - फोटो दयाशंकर

फॉग से दृश्यता हुई कम

दिल्ली- एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है, दृश्यता घटकर 50-200 मीटर रह गई है। 11 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 8-9 डिग्री सेल्सियस के आसपास और अधिकतम तापमान 24-25 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहेगा। दिल्ली एनसीआर शुक्रवार को भी घने कोहरे से जूझता रहेगा और सुबह-शाम के समय विजिबिलिटी बहुत कम होकर 50-200 मीटर रह जाएगी। न्यूनतम तापमान 8-9 डिग्री सेल्सियस के आस-पास बना हुआ है, जिससे राजधानी में एक और ठंडी सुबह है, जबकि अधिकतम तापमान 24-25 डिग्रई सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे दिन-रात के तापमान में 15 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का बड़ा अंतर आएगा।

प्रदूषण और तंबाकू सेवन से कैंसर पीड़ितों की संख्या बढ़ी

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : प्रदूषण की समस्या इतना विकराल रूप ले लिया है कि इसके कारण कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। आईसीएमआर-एनसीआरपी 2024 के मुताबिक, साल 2024 में देश में 15.3 लाख से ज्यादा नए कैंसर मामले दर्ज हुए थे और 2030 तक यह संख्या बढ़कर 18 लाख तक पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में प्रदूषण, जीवनशैली, तंबाकू सेवन और समय पर स्क्रीनिंग न होने की वजह से ब्रेस्ट, फेफड़े, मौखिक, कोलोरेक्टल और सर्वाइकल कैंसर ज्यादा पाए जाते हैं। ऐसे में पड़ोस-स्तर पर कैंसर केयर की व्यवस्था अब जरूरी हो गई है। ऑन्कोलॉजिस्ट, एमओसी दिल्ली डॉ. रमन नारंग ने बताया कि कैंसर के उपचार को न केवल चिकित्सकीय रूप से प्रभावी बनाने की जरूरत है, बल्कि भावनात्मक रूप से सहायक भी बनाना है। मरीजों को भीड़-भाड़ वाले अस्पतालों में भटकने या नियमित उपचार के लिए लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें अपने पड़ोस में ही पूरी तरह से ऑन्कोलॉजी को समर्पित सुविधा केंद्रों में ही जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि पारंपरिक तौर पर बड़े अस्पतालों में भीड़, लंबा इंतजार और इंफेक्शन का खतरा ज्यादा रहता है।

केंद्र वायु प्रदूषण पर भारत की बदनामी करने का ले रही जोखिमः भारद्वाज

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा एक्यूआई नापने के लिए अपना अलग नियम बनाने के कदम को जो खिमभरा बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वायु प्रदूषण पर दुनिया भर में भारत की बदनामी करने का जोखिम ले रही है। केंद्र सरकार का एक्यूआई नापने के लिए दुनिया भर के नियमों से अलग खुद का नियम बनाने का फैसला चिंताजनक है। डबल्यूएचओ और यूएस के ईपीए पैमानों को न मानकर सरकार बता रही है कि वह भारत के जानलेवा प्रदूषण को लेकर गंभीर नहीं है।

सौरभ भारद्वाज

> केंद्र सरकार का एक्यूआई नापने के लिए नियमों से अलग खुद का नियम बनाने का फैसला चिंताजनकः भारद्वाज

उन्होंने कहा कि दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत के लोग जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। इसलिए लोगों को हवा की सही गुणवत्ता जानने का हक है। लिहाजा सरकार को इस बेकार के प्रस्ताव को वापस लेकर अपनी सारी ऊर्जा प्रदूषण के स्रोत को रोकने में लगानी चाहिए, न कि आंकड़ों के फर्जीवाड़े में लगानी चाहिए। गुरुवार को सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह गंभीर चिंता की बात है कि केंद्र सरकार प्रदूषण पर दुनिया भर में भारत की बदनामी करवाने का जोखिम उठा रही है।

केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि वह हवा की गुणवत्ता नापने के लिए अपने खुद के नए नियम बनाएगी जो दुनिया भर के नियमों से अलग होंगे। यह बहुत ही चिंता वाली बात है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और दुनिया की दूसरी बड़ी वैज्ञानिक संस्थाओं के पैमानों को न मानकर सरकार यह इशारा कर रही है कि वह भारत के जानलेवा प्रदूषण को लेकर गंभीर नहीं है।

डिप्टी सीएम मौर्य के आवास से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर फ्रॉड करने वाला युवक गिरफ्तार

नई दिल्ली (पंजाब केसरी): सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की साइबर थाना पुलिस ने उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास से एक फर्जी प्रतिनिधि बनकर घुसने आए युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान नोएडा निवासी दशरथ पाल के रूप में हुई है। आरोप है कि वह दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के प्रतिनिधि बनकर उपमुख्यमंत्री से मिलने के उद्देश्य से आवास पहुंचा था। सतर्कता टीम ने दस्तावेजों की जांच के दौरान उसके मंसूबों पर संदेह होने पर उसे पकड़ लिया और तत्काल पुलिस को सौंप दिया।

> सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की साइबर थाना पुलिस ने युवक को दबोचा

सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की साइबर थाना पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। जांच के दौरान पता चला कि दशरथ पाल खुद को विभिन्न बड़े राजनीतिक पदाधिकारियों का प्रतिनिधि बताकर लगातार फ्रॉड करता रहा है। वह अब तक नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ और लखनऊ समेत कई जिलों में अलग-अलग लोगों से धोखाधड़ी कर चुका है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी पहले भी कई बार राजनीतिक पदों का झूठा प्रभाव दिखाकर लोगों को ठगने की कोशिश कर चुका है। इस बार वह दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के नाम पर अपना परिचय देकर सीधे डिप्टी सीएम से मुलाकात करना चाहता था। सतर्कता टीम के सवालों के जवाब वह संतोषजनक तरीके से नहीं दे पाया, जिसके बाद उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया।

घटना की जानकारी उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तत्काल दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को भी दी। इसके बाद यूपी पुलिस को मामले से अवगत कराया गया। सूचना पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड, अन्य ठगी के मामलों और जिन-जिन जिलों में उसने खुद को राजनीतिक प्रतिनिधि बताकर लोगों से धोखाधड़ी की है, उनकी जांच कर रही है।

दिल्ली की हलचल

डॉ. रत्नाकर साहू बने आरएमएल के नए प्रिंसिपल

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एबीवीआईएमएस) और आरएमएल अस्पताल के डॉ. रत्नाकर साहू को जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड डॉ. रत्नाकर साहू को तत्काल प्रभाव से संस्थान में प्रिंसिपल की नई जिम्मेदारी दी गई है। इस अस्पताल में वह जनरल मेडिसिन विभाग के डायरेक्टर प्रोफेसर हैं। वह इस पद पर 2009 से हैं और मेडिसिन के विशेषज्ञ हैं। सक्षम प्राधिकार की मंजूरी से, डॉ. रत्नाकर साहू को तुरंत प्रभाव से और अगले आदेश तक ऑफिसिएटिंग बेसिस पर उक्त मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में प्रिंसिपल का चार्ज सौंपा गया है।

23 करोड़ की विकास परियोजनाओं की पहल तेज

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): बवाना विधानसभा क्षेत्र में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए 23 करोड़ रुपये की नई विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने की दिशा में पहल तेज हो गई है। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सड़कों, नालों, फुटपाथों, फुट ओवर ब्रिज और जर्सी बैरियर से जुड़ी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगले पांच साल के लिए क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप व्यापक कार्ययोजना तैयार की जाए, ताकि समय पर परियोजनाओं की स्वीकृति मिल सके और विकास कार्यों में बाधा न आए। बैठक में बादली-बवाना रोड, बवाना-औचंदी रोड, औचंदी-टटेसर रोड और बवाना-कंझावला रोड पर जारी कार्यों की समीक्षा की गई। पीडब्ल्यूडी ने बताया कि जेएनवी स्कूल के पास फुटपाथ निर्माण, औचंदी गांव में नाले व फुटपाथ निर्माण, बवाना-कंझावला रोड पर जर्सी बैरियर लगाने तथा शाहबाद डेयरी में फुटओवर ब्रिज बनाने की योजनाएँ तैयार की गई हैं, जिन पर कुल 23 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है। मंत्री ने नालों की डीसिल्टिंग, सड़क मरम्मत, सिंथेटिक पेंट से सुरक्षा मार्किंग, साइनेज बोर्ड लगाने, एंटी-स्मॉग गन व वाटर स्प्रिंकलर संचालन जैसे कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी परियोजनाओं को उच्च गुणवत्ता के साथ तय समयसीमा में पूरा किया जाए ताकि जलभराव, ट्रैफिक अव्यवस्था और सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं में कमी आए। रविन्द्र इन्द्राज ने कहा कि बवाना में सड़कों, नालों और पैदल मार्गों में सुधार से क्षेत्रवासियों को बेहतर, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण मिलेगा। सरकार जनहित से जुड़े विकास कार्यों को निरंतर प्राथमिकता दे रही है।

मेट्रो में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य अभियान शुरू

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन पर महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य एवं कल्याण पर एक माह की दिल्ली मेट्रो अभियान की शुरुआत की। 10 दिसंबर 2025 से 10 जनवरी 2026 तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य मेट्रो ट्रेनों और चुनिंदा स्टेशनों पर प्रदर्शित संदेशों के माध्यम से लाखों यात्रियों तक पहुंचना है। इन संदेशों में महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के महत्व के बारे में बताना, डिजिटल विभाजन को कम करना, महिलाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता की पहुंच में सुधार करना, प्रसवोत्तर रोग निवारण एवं बाल रोग निवारण और तपेदिक के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा कि महिलाओं के स्वस्थ होने के बिना कोई भी परिवार या राष्ट्र सही मायने में प्रगति नहीं कर सकता। महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। दिल्ली मेट्रो के इस अभियान के माध्यम से हम इस संदेश को व्यापक जनसमुदाय तक पहुंचाना चाहते हैं। यह संदेश को सीधे लोगों तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने यह भी बताया कि टीबी जागरूकता, डिजिटल विभाजन को कम करने, गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम, 1994 और अन्य प्रमुख मुद्दों पर संदेश मेट्रो के डिब्बों के अंदर और बाहर दोनों जगह प्रदर्शित किए गए हैं।

नायब कोर्ट की कमी पर तीसरी बार सीपी को पत्र

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): अभियोजन शाखा में पुलिस स्टाफ यानि नायब कोर्ट की कमी को लेकर नॉर्थ-ईस्ट कड़कड़डूमा कोर्ट के मुख्य अभियोजक मसूद अहमद ने तीसरी बार दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है और तत्काल नायब कोर्ट उपलब्ध कराने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि डीसीपी के आदेश के बाद इस ब्रांच से कई नायब कोर्ट को दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया गया है, जिससे नायब कोर्ट के पद खाली हो गए हैं, जिससे सरकारी चिट्ठी-पत्री समय पर पहुंचाने और कोर्ट से जुड़े अलग-अलग कामों को सुचारू रूप से चलाने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पत्र में आगे कहा गया है कि नॉर्थ-ईस्ट की कोर्ट में नायब कोर्ट के पद काफी समय से खाली पड़े हैं, जिससे कोर्ट के कामों में काफी रुकावट आ रही है। साथ ही पहले के दो पत्रों के बाद भी कोई कार्रवाई ना होने का भी जिक्र करते हुए कहा गया है कि डीसीपी नॉर्थ-ईस्ट ने इस ऑफिस से ट्रांसफर किए गए नायब कोर्ट की जगह आज तक कोई नायब कोर्ट नहीं दिया है। जिससे कोर्ट में असंतोष फैल रहा है और कोर्ट नायब कोर्ट के ट्रांसफर के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं।

तिहाड़ में कानूनी सेवा प्राधिकरण ने किया कैदियों से संवाद

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): मानव अधिकार दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने तिहाड़ जेल का औपचारिक दौरा किया, ताकि कैदियों के लिए कानूनी सहायता सेवाओं और कल्याण कार्यक्रमों की समीक्षा की जा सके। इस दौरे का नेतृत्व सदस्य सचिव संजीव पांडे और नालसा के निदेशक कुणाल वेपा ने किया। इसके साथ नई दिल्ली जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनडीडीएलएसए) के सचिव कुमार राहुल और तिहाड़ जेल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। दौरे के दौरान टीम ने कानूनी सहायता क्लीनिक, बैरक, रसोई और चिकित्सा वार्ड का निरीक्षण किया और अंडरट्रायल कैदी, सजायाफ्ता बंदी, पैरा लीगल वॉलंटियर्स और जेल विजिटिंग एडवोकेट्स से बातचीत की, ताकि न्याय प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं को समझा जा सके। अंडरट्रायल कैदियों के अधिकारों पर एक सत्र भी आयोजित किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने कैदियों की शिकायतों का समाधान करने और न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

यौन उत्पीड़न से जुड़े डीएनए सैंपल के लिए पॉलिसी बनाने का निर्देश

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामलों में डीएनए सैंपल के ट्रांसपोर्ट में देरी को रोकने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी बनाने को कहा है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने दिल्ली पुलिस, फोरेंसिक लैब और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और गृह विभागों के बीच एक अर्जेंट और कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने को कहा। कोर्ट ने ऐसा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सीएफएसएल द्वारा जारी गाइडलाइंस के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की थीं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डीएनए सबूत पूरी सावधानी से इकट्ठा किए जाएं, वैज्ञानिक रूप से सही स्थितियों में सुरक्षित रखे जाएं और उनकी कस्टडी चेन का रिकॉर्ड सही डॉक्यूमेंटेशन के साथ रखा जाए।

डीडीए ने मांगे सीजीएचएस रिडेवलपमेंट को लेकर सुझाव

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): डीडीए ने दिल्ली की सभी कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों और फेडरेशनों के प्रतिनिधियों के साथ रिडेवलपमेंट पर एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीडीए के वाइस चेयरमैन एन. सरवन कुमार, दिल्ली नगर निगम और आरसीएस कार्यालय के अधिकारी भी शामिल रहे।दिल्ली और रोहिणी क्षेत्र की कई सोसायटियों के प्रतिनिधियों ने रिडेवलपमेंट से जुड़ी चुनौतियों और आवश्यकताओं पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए। रोहिणी फेडरेशन की ओर से प्रधान आर्य मुनि के नेतृत्व में एक टीम ने हिस्सा लिया। फेडरेशन महासचिव डॉ. एसएल सागर ने रिडेवलपमेंट के दौरान सोसायटियों के मूल चरित्र को सुरक्षित रखने की मांग रखी। कहा कि भारी खर्च को देखते हुए सोसायटियों को सदस्यता बढ़ाने की अनुमति मिलनी चाहिए, जिससे आर्थिक बोझ कम हो सके। उनके साथ फेडरेशन के वरिष्ठ उपप्रधान हर्ष जींदगर भी मौजूद रहे।बैठक के अंत में डीडीए वाइस चेयरमैन ने सभी सुझावों को सराहते हुए आश्वासन दिया कि इन्हें दिल्ली के मास्टर प्लान 2041 तैयार करते समय गंभीरता से शामिल किया जाएगा।

तंबाकू नियंत्रणः वैज्ञानिक समुदायों ने डब्ल्यूएचओ के रुख पर उठाए सवाल

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : तंबाकू उत्पादों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए विधेयक पास होने के बाद इसके उद्देश्यों को लेकर बहस छिड़ गई है। फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल (एफसीटीसी) की 11वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज (सीओपी11) तंबाकू-संबंधित हानि को कम करने की रणनीतियों पर चर्चा के दौरान फार्मिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति के 50 से अधिक स्वतंत्र विशेषज्ञों ने कहा कि डब्ल्यूएचओ की वह रणनीति, जिसमें बिना धुएं वाले तंबाकू उत्पादों को पारंपरिक सिगरेट के बराबर हानिकारक माना गया है। दुनिया को हर वर्ष धूम्रपान से होने वाली करीब 80 लाख मौतों को रोकने के अवसर से वंचित कर सकती है। सूत्रों के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन का वर्तमान तंबाकू नियंत्रण बजट लगभग एक अरब अमेरिकी डॉलर के आसपास है।

सिंगर एपी ढिल्लो के शो में लोगों के फोन चुराने वाला गिरोह पकड़ा

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): क्राइम ब्रांच ने आईजीआई स्टेडियम में सिंगर एपी ढिल्लो के शोर के दौरान लोगों के कीमती मोबाइल फोन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी (क्राइम) विक्रम सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान सलमान (35), इमरान (28), शाहरुख (32) और वसीम (25) के रूप में हुई है।

सलमान इस गिरोह का सरगना है। डीसीपी ने बताया कि आरोपी भीड़भाड़ वाले स्थान मेट्रो व रेलवे स्टेशन के अलावा बस पड़ाव, होटल व शराब के ठेकों के बाहर महंगे मोबाइल फोन पर हाथ साफ करते थे। पुलिस ने इनके पास से आठ आईफोन समेत 40 महंगे मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। डीसीपी ने बताया कि दिल्ली मोबाइल चोरी घटनाओं पर क्राइम ब्रांच की टीम भी नजर रख रही थी। इसी बीच टीम को सूचना मिली कि महंगे मोबाइल फोन चोरी करने वाला एक गिरोह सक्रिय है, जो संगीत समारोहों, मेट्रो व रेलवे स्टेशनों के अलावा अन्य व्यस्त सार्वजनिक भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लोगों को निशाना बनाता है। तुरंत इंस्पेक्टर आशीष शर्मा की देखरेख में एसआई रणजीत सिंह, गुमन सिंह, एएसआई संदीप चावला, हेड कांस्टेबल सौरव, मनीष आदि की टीम गठित की गई। टीम को पुख्ता सूचना मिली कि गिरोह के सदस्य यमुना विहार मेट्रो स्टेशन के पास आने वाला है। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंच गई। टीम ने मौके पर पहुंचकर जाल बिछाया। इसके बाद टीम ने आरोपियों को मौके पर आते ही एक कार के साथ दबोच लिया।

> पुलिस ने आठ आईफोन समेत 40 महंगे मोबाइल बरामद किए

बेटी की नाबालिग दोस्त का यौन उत्पीड़न करने वाले अधेड़ को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट ने पॉक्सो के तहत उम्रकैद की सजा काट रहे एक फरार दोषी को गिरफ्तार किया है। उसकी त्रिलोकपुरी निवासी पहचान 76 वर्षीय वाहिद खान के रूप में हुई है। सितंबर 2021 से पैरोल जम्पर बना हुआ था। डीसीपी पंकज कुमार ने बताया कि एसीपी गिरीश कौशिक की देखरेख में प्रमुख इंस्पेक्टर संदीप स्वामी ने आरोपी को पकड़ा है। वाहिद खान संजय कैंप, त्रिलोकपुरी का निवासी है और मूल रूप से आगरा, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। अधिकारी ने बताया कि यह मामला 2015 का है। मयूर विहार थाने में पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। दोषी वाहिद खान पर अपनी बेटी की 13 वर्षीय सहेली के साथ जबरन यौन उत्पीड़न करने का आरोप था। लंबी सुनवाई के बाद, 2018 में एएसजे कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। दोषी को 01 सितंबर 2021 को परोल दी गई थी, लेकिन पैरोल की अवधि समाप्त होने के बाद उसने जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया और तब से वह फरार चल रहा था।

सलमान खान के नाम के इस्तेमाल पर हाईकोर्ट सख्त, कार्रवाई का आदेश

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): फिल्म अभिनेता सलमान खान द्वारा व्यक्तित्व सुरक्षा की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तीन दिनों में कार्रवाई करने का आदेश दिया है, साथ ही बिना इजाजत मर्चेंडाइज की बिक्री पर रोक लगा दिया है। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने यह आदेश दिया है।

मामले की सुनवाई के दौरान सलमान खान की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने अजय देवगन सहित अन्य मामले में कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का हवाला दिया। इस पर कोर्ट ने संकेत दिया कि यहां भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सलमान खान को संबंधित प्लेटफॉर्म को सूचित करने का निर्देश दिया जाएगा। इसके बावजूद एक सप्ताह बाद भी आपत्ति बनी रही तो कोर्ट संयुक्त आदेश पारित करने पर विचार करेगा। बता दें कि सलमान खान की मांग है कि उनकी बिना अनुमति के उनके नाम, पहचान और आवाज का व्यावसायिक इस्तेमाल न हो। इसमें एआई से बनाए डीपफेक फोटो और वीडियो शामिल है। साथ ही नकली सामान, भ्रामक विज्ञापन, झूठे ब्रांड एंडोर्समेंट और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम एक्स और ई-कॉमर्स वेबसाइटों जैसे प्लेटफार्म पर सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाए जाते हैं।

जिन पर रोक की मांग एक्टर करते है कि सेलेब्स के अनुसार इससे उनके व्यक्तित्व अधिकारों का दुरुपयोग होता है। ऐसा ही कुछ सलमान के मामले में भी है। वह भी अपने पर्सनैलिटी, पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा चाहते है। याचिका में हाल के महीनों में देखे गए एक व्यापक ट्रेंड पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें प्रमुख फिल्मी हस्तियों और डिजिटल क्रिएटर्स ने अपनी पहचान के व्यावसायिक और गरिमापूर्ण पहलुओं की रक्षा के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है।

राष्ट्रीय
सहारा
पटना • शुक्रवार • 12 दिसम्बर • 2025
www.rashtriyasahara.com

हमारे आदर्श हमारी विरासत का आधार

राष्ट्र निर्माण केवल नीतियों, विकास योजनाओं या संस्थागत ढांचे से नहीं होता, बल्कि उस भावनात्मक और वैचारिक विरासत से होता है जिसे हम अपने आदर्शों के रूप में स्वीकार करते है। आदर्श किसी भी समाज की आत्मा होते है-वही समाज के चरित्र को दिशा देते है, उसके विचारों को आकार देते है और उसके भविष्य की रूपरेखा तय करते है। इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में यह स्पष्ट संदेश दिया कि हमारे आदर्श कोई विदेशी आक्रांता नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी असली प्रेरणा शक्ति हमारे अपने नायक, हमारे अपने पूर्वज, और हमारी अपनी गौरवशाली परंपरा है। भारत की सभ्यता सहस्त्राब्दियों से चली आ रही वीरता, त्याग और धर्मनिष्ठा की ऐसी परंपरा से भरी है जो विश्व के किसी भी देश से तुलना में कहीं अधिक समृद्ध और व्यापक है। भगवान राम का आदर्श मर्यादा का है। वे एक राजा ही नहीं, बल्कि आदर्श पुत्र, आदर्श पति और आदर्श प्रशासक के रूप में पूजे जाते है। भगवान कृष्ण ने युद्धभूमि में अर्जुन को धर्म का ज्ञान दिया, और बताया कि कर्तव्य किसी भी कठिन परिस्थिति में सर्वोपरि है। महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे वीरों ने विदेशी सत्ता के सामने न झुकने का इतिहास रचा। गुरु गोविंद सिंह ने अपने चारों पुत्रों का बलिदान कर भी धर्म और मानवता की रक्षा को सर्वोपरि रखा। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता आज भी भारतीय नारी शक्ति का प्रतीक है।

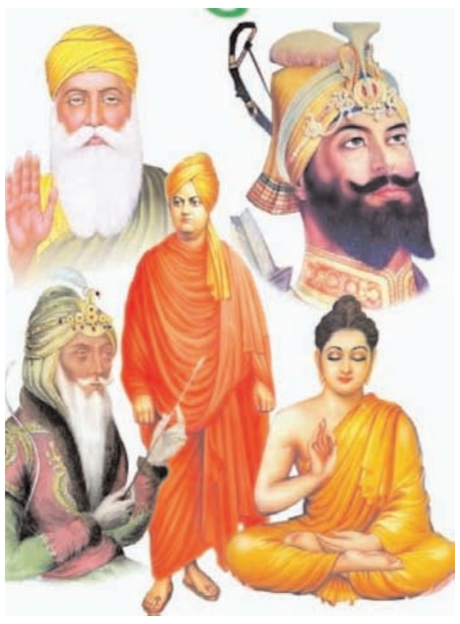

इन सभी महापुरुषों की विरासत को देखकर यह प्रश्न ही उठता है कि जब हमारे पास इतनी समृद्ध और प्रेरणादायक परंपरा है, तब हम किसी विदेशी आक्रांता को आदर्श क्यों मानें? इतिहास हमें यह सिखाता है कि विदेशी आक्रांताओं का उद्देश्य शासन, विस्तार और लूट रहा। वे किसी भी रूप में हमारे सामाजिक, आध्यात्मिक या सांस्कृतिक हितों के संवाहक नहीं थे। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह टिप्पणी केवल राजनीतिक वक्तव्य नहीं, बल्कि इतिहास और राष्ट्रचेतना की कसौटी पर एक बिल्कुल सही और समयानुकूल संदेश है। इसके साथ ही उन्होंने समाज को भाषा और क्षेत्रीय भावनाओं के आधार पर विभाजित करने के खतरों की ओर भी ध्यान दिलाया। विशेष रूप से जाट क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्रीय पहचान को समाज के बीच दूरी पैदा करने का माध्यम बनाना न केवल अविवेकपूर्ण है, बल्कि राष्ट्रहित के विरुद्ध भी है। भारत की शक्ति उसकी विविधता में है, लेकिन यह विविधता तभी सार्थक है जब वह एकता की बुनियाद पर बनी हो। विभाजन का विचार समाज को कमजोर करता है, जबकि साझा पूर्वजों और साझा गौरव की भावना हमें जोड़ती है। हमारे नायक हमारे सैनिक है।उनमें से परमवीर चक्र विजेता जनरल बिपिन रावत जैसे सेनापति राष्ट्र गौरव, साहस और कर्तव्यनिष्ठा के सर्वोच्च प्रतीक है। वे हमारी सैन्य परंपरा के उस स्वाभिमान को आगे बढ़ाते है, जिसने सदियों से इस देश की रक्षा की है। जब हमारे वीर सैनिक अपने जीवन की परवाह किए बिना सीमाओं पर डटे रहते है, तब यह स्वाभाविक है कि उनकी प्रेरणा हमारे अपने महान पूर्वजों के बलिदान और आदर्शों से ही आती है।

आज की राजनीति में आदर्शों और मूल्यों का विषय अक्सर विवादों में उलझ जाता है, जबकि वास्तव में यह आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कभी था। समाज को जोड़ने वाले आदर्श ही उसे मजबूत बनाते है। हमें यह समझना होगा कि इतिहास को विकृत कर विदेशी आक्रांताओं में नायक ढूंढने से न राष्ट्र का भला होगा और न समाज का। भारत को एकता, स्वाभिमान और अपनी सांस्कृतिक विरासत की पहचान चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि हमारे आदर्श वही हों, जिनकी जड़ें इसी मिट्टी में है। समय की मांग है कि हम अपनी नई पीढ़ी को सही इतिहास, सही प्रेरणा और सही आदर्श दें-क्योंकि राष्ट्र उन्हीं हाथों में सुरक्षित होते है जिनके दिल में अपनी विरासत के प्रति गर्व होता है।

अनमोल वचन

जहां सम्मान है वहां डर है, पर ऐसी हर जगह सम्मान नहीं है, जहां डर है, क्योंकि संभवतः डर सम्मान से ज्यादा व्यापक है।

-सुकरात

संभल के बहाने हिन्दुत्व की नई बहस

विचार

शंभूनाथ शुक्ल

उत्तर प्रदेश के संभल में पुराना मंदिर के साथ-साथ एक कुएं से भगवान की मूर्तियां मिलने का मामला पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी ऐतिहासिकता और प्रामाणिकता की जांच भी की जा रही है। अहम सवाल है क्या संभल की तरह अब भारत भर के हर कुएं में पड़ताल की लहर शुरू सकती है? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? मेरे पास गणेश जी की एक शानदार और काफी वजन वाली बहुत पुरानी एक मूर्ति थी. पीओपी के सांचे में ढली यह मूर्ति दसवीं शताब्दी की एक मूर्ति की अनुकृति थी। इसे मै मथरा म्यूजियम से लाया था. पिछले वर्ष जब फ़्लैट बदला तो वह मूर्ति गिर गई और खंडित हो गई. यह मेरे लिए आघात था क्योंकि मूर्ति मुझे बहुत प्यारी थी. मेरी श्रद्धा भी उस मूर्ति पर थी। ड्राइंग रूम में सजी यह मूर्ति हर आगंतुक के लिए आकर्षण थी। अब खंडित मूर्ति को तो घर पर रखा नहीं जा सकता इसलिए मै पड़ोस के मंदिर में उसे रखने गया। वहां पीपल के पेड़ के नीचे आस-पड़ोस के लोग खंडित मूर्तियां रख जाते थे. लेकिन पुजारी ने कहा। यह मूर्ति कहीं फेक दो, यहां मत रखो। मैने कहा, पुजारी जी और कहां रखूँ, यहां रखी रहेगी, ऐसी मूर्ति अब मिलेगी नहीं, पर पुजारी ने कहा, आप कहीं और फेंक दो। उसने पीछे बह रहे हिंडन की नहर की तरफ देख कर कहा, वहां किनारे फेंक दो. यह नहर अब एक बदबूदार नाले में बदल चुकी है।

दलदल में फंसी गणेश मूर्ति : यह मेरे लिए बहुत अपमानजनक था और दुखद भी। इतनी शानदार और दुर्लभ मूर्ति कैसे इस इस नाले-नुमा नहर में प्रवाहित कर दूं! मैने मूर्ति गाड़ी में रखी और हिंडन नदी की तरफ़ चला गया। चार किमी पर जहां ग़ाजियाबाद का सिटी फ़ॉरेस्ट है, वहां ले जाकर मैने मूर्ति फेंकने का निश्चय किया। किंतु नदी के किनारे काफ़ी दल-दल था। इसलिए मै धार तक नहीं जा सका। पूरी ताक़त से मूर्ति फेंकी फिर भी वह वज़नदार मूर्ति कुछ कदम दूर जा कर दल-दल में जा फंसी। गणेश जी की उस मूर्ति का यह हाल देख कर दुःख तो बहुत हुआ पर क्या किया जा सकता था। पहले भी हम लोग गांवों में खंडित मूर्तियां किसी नदी-नाले में प्रवाहित कर देते थे। अभी जब संभल में कुएं से मूर्तियां मिलने की खबर आई तो मुझे लगा, अरे, मूर्तियां तो हिंदू लोग कुओं में डालते ही रहे है. पहले के जमाने में मूर्तियां हम नदी में फेंक ही दिया करते थे।

कुओं में और भी अनमोल रतन : जब चापा कल और नलों के जरिए पेयजल की सप्लाई होने लगी तो कुएं पाट दिए गए। कुएं पाटने के लिए या तो यही खंडित मूर्तियां उनमें डाली जातीं अथवा मिट्टी मंगा कर उनमें भरा जाता। पहले कुएं लोगों के घरों में भी होते थे। घर की स्त्रियों के स्नान के लिए घर के आंगन में कुएं खुदवाना आम बात थी। पुरानी दिल्ली (चांदनी चौक) के घरों में कुएं मैने खद देखे है। पटियाला महाराज के सेक्रेटरी रहे दीवान जरमनी दास ने महारानी नाम से एक उपन्यास लिखा है, उसमें लिखा है, कि कैसे महाराज का एक अफ़सर रानी से मिलने के लिए कुएं के रास्ते उनके स्नानागार तक आ जाता।

घरों में कुइयां ! : अकेले संभल में नहीं भारत के हर कोने में जो भी कुएं उनमें कुछ न कुछ मिल जाएगा. अभी 20 वर्ष पहले मुझे ओडीसा में बरहम पर के समीप गोपाल पुरा पोर्ट जाना था। चिल्का झील से 25 किमी दूर इस पोर्ट के समीप केवड़ा के जंगल होते है, उन पर एक स्टोरी करनी थी। केवड़ा के जंगलों में कोबरा नाग बहुतायत में मिल जाते है, इसलिए किसी लोकल बंदे को ले जाना ज़रूरी था। कन्नौज के इत्र व्यवसायी वहीं से केवड़ा लाते है, अनेक इत्र व्यवसायियों के वहाँ पर फार्म हाउसेज भी है। मेरे एक मित्र के फार्म हाउस का मैनेजर मुझे लेने भुवनेश्वर आया। गोपाल पांडा नाम का यह व्यक्ति पहले तो मुझे हवाई अड्डे से भुवनेश्वर शहर में स्थित अपने पैतृक घर में ले गया। शाम ढल रही थी, लेकिन वहाँ के ब्राह्मण परिवार भोजन के पूर्व स्नान अवश्य करते है।

क़रीब के इतिहास को हम भूलते जा रहे : भोजन के पश्चात जब रात 9 बजे हम टैक्सी ले कर गोपालपुरा की तरफ़ चले तो मैने उससे पूछा, कि क्या घर में नगर निगम पेय जल की सप्लाई नहीं करते? तो उसने बताया, करते है लेकिन कुएं का पानी सदैव ताज़ा मिलता है। कुओं का महत्त्व भारत में खूब रहा है।

साझी विरासत को सिनमा ने नष्ट किया : अंग्रेजों ने जो हिंदू-मुस्लिम द्वेष के बीज बोये थे उन्हें बंटवारे के बाद भी नष्ट नहीं किया गया. उन बीजों से ज़हरीली फसलें पनपती ही रहीं। आपसी सद्भाव के लिए झूठी-सच्ची कहानियां रची गईं लेकिन जड़ पर प्रहार कभी नहीं हुआ. इसलिए दंगों को रोका नहीं जा सका. हर दंगे के बाद हिंदू मुस्लिम बहुल इलाक़ों से दूर होता गया और मुसलमान हिंदू क्षेत्रों से। एक-दूसरे को समझने का प्रयास कभी नहीं हुआ। ऊपर से मीडिया ने और ज़हर बोया। हिंदी सिनेमा में हर मुसलमान या तो पांच वक्त का नमाज़ी दिखाया गया या उसकी छवि एक आतंकवादी की बनाई गई।

इन दोउन राह न पाई ! : हिंदी अखबारों के लेखों में राजनीति की चटपटी खबरें रहतीं या लेखों में राजनीतिक विचार. कभी भी हिंदू-मुस्लिम की अंतरंगता और विसंगतियों को तर्कसंगत ढंग से नहीं देखा जाए। नतीजा यह है कि दोनों के मध्य इतनी दूरी पनप गई कि लोग एक दूसरे से धार्मिक चर्चा तक करने में घबराते है। या तो तुर्कों और मुग़लों की संस्कृति को महान बताओ, देश के हर खानपान, वस्त्र विन्यास, साज-सज्जा को इस्लामिक देशों से आयातित बताओ अथवा हिंदुओं के अतीत को दुनिया में सबसे अच्छा।

बाबरनामा के हवाले से बाबर : सोमवार को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबरनामा का ज़िक्र कर बड़ी शानदार बहस छेड़ दी। बाबर मध्य एशिया से आया हुआ एक तुर्क-मंगोल नस्ल का हमलावर था। इसके परिवार को बाद में मुग़ल कहा गया। क्योंकि इसकी मां मंगोल थी और बाप तुर्क. वह हिंदुस्तान में राज करने के मक़सद से नहीं आया था, बल्कि सिर्फ़ लूटपाट कर चला जाना चाहता था। समरकंद में अपने कुल-ख़ानदान ने उस पर बहुत ज़्यादतियां की थीं। उसे धन चाहिए था, ताकि काबुल में जाकर वह अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर सके। पहले तो उसने अफगानिस्तान की सीमा से सटे पंजाब के पठानों को पराजित किया फिर हिंदुस्तान की तरफ़ बढ़ा। यहां तब इब्राहिम लोदी का शासन था। हिंदुस्तान बहुत समृद्ध और ताकतवर था। 1526 में उसने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को हरा कर दिल्ली, आगरा सब को रौंद डाला।

ग़ुरु नानक ने भी बाबर को भयावह लिखा : उसके समकालीन ग़ुरु नानक ने लिखा है, खुरासान खसमाना कीआ हिंदुसतानु डराइआ ? आपै दोसु न देई करता जमु करि मुगलु चड़ाइआ ? एती मार पई करलाणे तैं की दरदु न आइआ खुरासान की सुपुर्दगी किसी और को कर के बाबर मुग़ल ने हमला करके हिन्दुस्तान को सहमा दिया हैजो लोग अपने फर्ज भुला के रंग-रलियों में पड़ जाते हैं उन्हें सजा भुगतनी ही पड़ती है, इस बारे) ईश्वर अपने ऊपर दोष नहीं आने देता।

हिंदुस्तानी मुसलमान और मुग़ल वंश : लेकिन बाबर को हिंदुस्तान की रंगत भा गई. आगरा से आगे बढ़ते हुए वह यमना के रास्ते इटावा पहुंचा। वहां उसने अपने बढ़े हुए बाल और दाढ़ी छंटवाईं और घुसल (स्नान) लिया. वहां वह लिखता है, हिंदुस्तानी (इसमें हिंदू-मुस्लिम दोनों शामिल थे) बहुत गंदे होते है. स्नान नहीं करते और बाल नहीं कटवाते। आज मुस्लिम समुदाय के लोग बाबर को अपना पुरखा मानते है।

भयादोहन की राजनीति: हिंदुस्तान में तब भी हिंदू बहुसंख्यक थे और आज भी है। मज़े की बात हिंदू तब भी किसी भी मुस्लिम शासक से नहीं डरे तो भला आज क्या डरेंगे! यह बात सत्ताधारियों ने कभी नहीं समझी. आज़ादी के पहले और उसके दौरान सिर्फ गांधी जी ही हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों के मध्य चल रही इस पारस्परिकता को समझते थे। किंतु आज़ादी मिलने के कुल पांच महीने बाद उनकी हत्या हो गई। उसके बाद कांग्रेस ने मुसलमानों को अपना सॉलिड वोट बैंक समझा और जनसंघ तथा उसी की परवर्ती भाजपा ने हिंदुओं को. इसलिए दोनों ने इन समुदायों की धार्मिकता को ही बढ़ावा दिया। यह भी संकेत किया कि उनकी रक्षक यही पार्टियाँ है. इसीलिए कुओं में मूर्तियाँ मिलने की बात के संदर्भ को कोई समझ नहीं पा रहा है।

अध्यात्म प्रेम | संत राजिंदर

प्रत्येक इंसान चाहता है कि वह औरों से प्रेम करे और दूसरे भी उससे प्रेम करें। मनोवैज्ञानिक आधार पर जब इंसान की बुनियाद जरूरतों जैसे भोजन, वस्त्र, मकान और सुरक्षा की बात की जाती है, तब उसमें प्रेम की जरूरतों को भी शामिल किया जाता है। अक्सर लोग बाहरी दुनिया में माता-पिता, भाई-बहन और रिश्तेदारों से प्रेम की उम्मीद करते हैं। जैसे-जैसे वे बड़े होते हैं तो वे अपने दोस्तों से प्रेम पाना चाहते हैं। युवा अवस्था में वे अपने जीवन साथी, बच्चों और सहकर्मियों से प्रेम पाना चाहते हैं। संत-महापुरुष हमें समझाते हैं कि इस दुनिया के सभी प्रेम अस्थायी हैं क्योंकि अक्सर देखा गया है कि समय बीतने पर रिश्तों में अनबन हो जाती है, बच्चे अपने कार्यों की वजह से दूर चले जाते हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग माता-पिता आदि धीरे-धीरे इस दुनिया से चल बसते हैं। ऐसी स्थिति में इस दुनियावी प्रेम के खोने पर हम दुःखी हो जाते हैं। इस प्रेम के खोने पर अक्सर हम दुःखों से राहत पाने के लिए परमात्मा की तरफ रुख करते हैं। प्रभु जब हमारी करुण पुकार को सुनते हैं, तब वे हमें किसी ऐसी हस्ती (सत्गुरु) के पास भेजते हैं, जो हमें बता सके कि पिता-परमेश्वर का स्थायी प्रेम हमारे अंतर में मौजूद है, जोकि दुनियावी प्रेम से कहीं ज्यादा है। हमारे सत्गुरु हमें परमात्मा के इस अनंत प्रेम से जोड़ देते हैं। युगों-युगों से आध्यात्मिक गुरु इस धरा पर आते रहे हैं, जिन्होंने हमें अनंत प्रेम को पाने का मार्ग दिखाया है। वे हमें ध्यान-अभ्यास का तरीका सिखाते हैं, जिससे हम अपने अंतर में पिता-परमेश्वर के प्रेम को पा सकते हैं। हम इन आंखों से परमात्मा को नहीं देख सकते, आध्यात्मिक सत्गुरु हमें अंतर की आंखों से परमात्मा को अनुभव करने का मार्ग दिखाते हैं। जब हम उनके बताए रूहानी रास्ते पर चलते हैं, तब हम अपने अंतर में परमात्मा के प्रेम का अनुभव करते हैं। परमात्मा का अनुभव बुद्धि के जरिए नहीं किया जा सकता। परमात्मा प्रेम है, हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते प्रेम है और परमात्मा को पाने का रास्ता भी प्रेम है। पिता-परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करने के लिए हमें मन-माया की वह सारी परतें हटानी होंगी, जो हमें उस दिव्य-प्रेम का अनुभव करने से दूर रखती हैं। जब हम आध्यात्मिक सत्गुरु के पास जाते हैं तो वे हमें परमात्मा के प्रेम का अनुभव कराते हैं।

रीडर्स मेल

यात्री शेड न होने से परेशानी

गिरीडीह-धनबाद मुख्य मार्ग एनएच 114 ए पर स्थित धनबाद जिले के टुंडी थाना अंतर्गत लोधरिया मोड़ से रोज बड़ी संख्या में लोग गिरीडीह एवं धनबाद की ओर जाने के लिए बस की प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन यहां यात्री शेड नहीं रहने के कारण यात्रियों को तेज धूप, बरसात एवं ठंड में खुले आसमान के नीचे खड़े रहना पड़ता है जिससे बुजुर्गों, महिलाओं एवं बच्चों को विशेष रूप से परेशानी होती है। यात्री शेड केवल एक छत नहीं, बल्कि एक सम्मानजनक प्रतीक्षा का स्थान होता है। इसे एक छोटी सी सुविधा समझ कर टालना लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। झारखंड परिवहन विभाग एवं स्थानीय विधायक को इस दिशा में प्राथमिकता से काम करना चाहिए एवं जल्द ही लोधरिया मोड़ पर यात्री शेड का निर्माण करवाना चाहिए। जनता को ये सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए और सरकार काफर्ज बनता है कि वह इस मामले में विचार करे।

संदीप कुमार, मधुपुर, झारखंड

letter.editorsahara@gmail.com

मुनक्का के नियमित सेवन से सौंदर्य में निखार

- मुनक्का को काली किशमिश भी कहा जाता है, जो एक तरह का सूखा हुआ अंगूर है। यह विटामिन, फाइबर, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जिसका सेवन करने से बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है
- नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, अमेरिका की फरवरी, 2022 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, किशमिश (मुनक्का) में लिपिड (वसा) कम करने के और एंटीऑक्सीडेंट्स गुण होते हैं, जो स्किन के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, त्वचा की रंगत में सुधार लाने और उम्र बढ़ने के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं

(मीडिया इनपुट्स)

दिनोंदिन राजनीतिक उथल-पुथल, नेपाल में अराजकता इस कड़ी में हालिया घटना है, से घिरा भारत लोकतंत्र का प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। अमेरिका की शह पर हसीना के देशनिकाले के बाद बांग्लादेश मुस्लिम कट्टरपंथियों की गिरफ्त में है। म्यांमार में अमेरिकी मदद से जुंटा-विरोधी विद्रोही पूर्वोत्तर भारत में अस्थिरता का खतरा मंडराए हुए हैं। पाकिस्तान नाकाम देश है, जहां सेना राजनीति पर हावी है।

ब्रह्म चेलानी, सामरिक चिंतक
@Chellaney

मानव जीवन में वेदों का महत्व

आचार्य पवन तिवारी
संस्थापक अध्यक्ष
ज्योतिष सेवा संस्थान

वेद मानव जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है। जैसे कोई इंजीनियर किसी यंत्र को बनाता है तो वह किस उपयोग के लिए बना है और उसको उपयोग में लेने की क्या रीति है उसे दूसरा कोई मनुष्य नहीं बता सकता इसी प्रकार इस संसार को किस लिए बनाया गया है इस बात की पूर्ण जानकारी ईश्वर ने हमें वेद के रूप में प्रदान की है।

जैसे बिना पढ़ाए कोई बालक विद्वान होकर दूसरों को सही रास्ता नहीं बना सकता उसी प्रकार वेद पढ़े बिना कोई भी मनुष्य इस संसार में स्वयं को और दूसरों को आनन्द में नहीं रख सकता। वेदों में व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक व्यवस्था परस्पर संबंध आदि विषयों का विस्तृत ज्ञान भरा हुआ है।

वेद की उत्पत्ति सृष्टि के आदि में मानव की प्रथम पीढ़ी को 'श्रुति के रूप में चार ऋषियों के द्वारा ईश्वर ने प्रदान की तभी से यह श्रवण परंपरा से चलती रही साथ ही ताम्र पत्रों, भोजपत्र आदि के बाद कागज के पत्रों में पुस्तक रूप में मानव समाज को उपलब्ध हुई है। वस्तुतः वेद समस्त सत्य विद्याओं का ग्रंथ या क्षेत्र के लोगों के लिए सीमित नहीं हैं। अपितु यह ज्ञान सूर्य के प्रकाश के समान समस्त सृष्टि का पोषण एवं कल्याण के लिए है।'वेद मंत्रों के तत्व को समझने के लिए हमें उपनिषद् एवं आरण्यकों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए क्योंकि प्रज्ञा शक्ति के द्वारा उपनिषद् आदि को हमें उनके भाष्य, कथा प्रसंग एवं उद्धरणों को समझने के लिए प्रदान किया है। अतः स्वाध्याय के बिना वेदों की ऋचाओं को समझना कठिन हो जाता है।

आज समाज में भ्रांति का मुख्य कारण यह है कि अधूरे अध्ययन एवं सीमित ज्ञान के कारण समाज वेदों के रहस्य से अछूता हो रहा है, अतः हमें तप स्वाध्याय एवं जिज्ञासा के साथ वेद मंत्रों को पढ़ना, पढ़ाना, समझना और समझाना होगा।

खाद्यान्न संकट से निपटना बड़ी चुनौती

21वीं सदी में भारत सहित समस्त विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती खाद्यान्नों के संकट से निबटने की होगी। वर्ष 2050 तक दुनिया की आबादी के 9.3 अरब होने उम्मीद है। इतनी बड़ी आबादी की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्तमान में होने वाले कुल वैश्विक उत्पादन की तुलना में 70 प्रतिशत अधिक खाद्यान्नों के उत्पादन की जरूरत पड़ेगी। दुनियाभर में बने युद्ध के माहौल ने कोढ़ में खाज की ही स्थिति पैदा की है। कई ध्रुवों में बंट चुकी दुनिया के देशों द्वारा खाद्यान्नों के आायात-निर्यात को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किये जाने के कारण समस्या और विकराल हुई है। इसके अलावा धरती की घटती उर्वरा शक्ति के साथ साथ जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निबटते हुए उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करना सभी देशों के लिए मुश्किलों का सबब बनने वाला है। जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक दुष्प्रभाव जिन देशों पर पड़ सकता है उसमें भारत सबसे संवेदनशील देशों वाले वर्ग में आता है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 127 देशों में 105वें क्रम पर है। जबकि 2050 तक भारत की आबादी के बढ़कर 1.7 अरब होने की संभावना है और देशवासियों की खाद्य जरूरतों को पूरा करने उसे कुल वर्तमान उत्पादन की तुलना में उत्पादन को कम से कम 32 प्रतिशत अधिक बढ़ाना होगा।

मुश्किलों की झलक हमें विगत कुछ वर्षो के दौरान स्पष्ट रूप से देखने को मिलने लगी है जब आश्चर्यजनक रूप गर्मी फरवरी-मार्च महीने में ही अपने तेवर दिखाने लगती है। बरसात के बदलते पैटर्न ने भी कृषि कार्य को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। वर्ष 2021 का ही उदाहरण लेते है। फरवरी तक जिस गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद की जा रही थी और जिसके बल पर रिकॉर्ड निर्यात की योजना बनाई जा रही थी, मई आते आते कम उत्पादन के कारण उस पर पानी फिर गया। आलम ये बना कि सरकार को गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला लेना पड़ा। गेहूं के अलावा चीनी के निर्यात को भी रोक दिया गया। यह एक दिन या एक वर्ष की बात नहीं है। आज समस्त विश्व के समक्ष बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने की बड़ी चुनौती है। दुनियाभर के नीति निर्धारक और वैज्ञानिक इस समस्या का समाधान तलाशने में अनवरत रूप से जुटे है।

जागरूकता और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के कारण खाद्यान्नों की सबसे ज्यादा मांग विकासशील और अल्पविकसित देशों से होने की उम्मीद की जा रही है। जबकि जलवायु परिवर्तन की सबसे अधिक मार भी इन्ही विकासशील देशों पर ही पड़ने की उम्मीद है। आसन्न संकट को देखते हुए दुनियाभर के नीति नियंताओं के बीच खाद्यान्न संकट से निबटने के लिए कृषि के क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकि के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि और उत्पादों के बेहतर संरक्षण को लेकर सहयोग और सामंजस्य पर सहमति तैयार करने का दौर जारी है।

जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करते हुए और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देते हुए खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि की चुनौती बड़ी है लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी अनुवांशिक रूप से संशोधित कृषि उत्पादन तकनीकि से उम्मीद जगती है। इस तकनीक से फसलों को जहां कीट, बीमारी और खरपतवार रोधी बनाए जाने में सफलता प्राप्त हुई है वहीं मौसम जनित विषमताओं को झेलने में भी आसानी हुई है। एक दशक पूर्व विकसित सब1ए प्रकार के धान का पौधा बाढ़ और सूखे दोनों प्रकार की परिस्थितियों को झेलने में सक्षम है वहीं गोल्डन राइस विटामिन ए की प्रचुरता से युक्त है। चूंकि बीजों को विकसित करने के दौरान ही उनके जीन में परिवर्तन कर उन्हें कीट और खरपतवार रोधी बना दिया जाता है इसलिए पूरे फसल चक्र के दौरान इन पर रासायनिक कीटनाशकों के छिड़काव की या तो जरूरत नहीं पड़ती या बहुत कम पड़ती है। इस पद्धति से की जाने वाली खेती में बीज रोपने के लिए खेतों की बहुत अधिक जुताई करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है जिससे पेट्रो पदार्थों की खपत और प्रदूषक गैसों के उत्सर्जन में भी कमी आती है। रसायनों के न्यून प्रयोग के कारण पर्यावरण संरक्षण और मानव स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह पारंपरिक कृषि की तुलना में अधिक प्रभावी है।

यही कारण है कि वर्ष 1996 तक दुनियाभर में जीएम फसलों का कुल रकबा जहां 17 लाख हेक्टेयर था वहीं 2019 आते आते यह बढ़कर 1 करोड़ 94 लाख हेक्टेयर तक हो गया। भारतीय किसानों ने भी बीटी कॉटन के प्रयोग से बंपर उत्पादन प्राप्त करने और देश को शुद्ध आयातक से शुद्ध निर्यातक में परिवर्तित करने में सफलता प्राप्त की है। कॉटन उत्पादकों ने बीटी बीज की मदद से उत्पादन में 22 प्रतिशत की वृद्धि और मुनाफे में 68 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की जबकि इसी दौरान रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग में 37 प्रतिशत की कमी हुई। बीटी कॉटन की सफलता से उत्साहित भारतीय कृषि विज्ञानियों ने वर्ष 2009 में ही बीटी बैंगन भी तैयार कर लिया। व्यापक परीक्षण के बाद खाद्य नियायम प्राधिकरण द्वारा इसका अनुमोदन भी किया गया लेकिन दो दशक से भी अधिक समय से किसान बीटी बैंगन के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए सरकारी हरी झंडी के इंतेजार में है। जबकि पड़ोसी देश बांग्लादेश ने 2014 में बीटी बैंगन के उत्पादन को मंजूरी दे दी और तब से वहां व्यापक रूप से इसका उत्पादन और उपभोग किया जा रहा है। सितंबर 2018 में जीईएसी की बैठक में बांग्लादेश में करीब 50 हज़ार किसानों द्वारा बीटी बैंगन उगाने की जानकारी दी गई थी। इसमें से 27 हज़ार से ज्यादा किसान ऐसे थे जिन्होंने पिछली फसल से अपने बीज बचाए थे।

इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईएफपीआरआई) और बांग्लादेश एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट (बारी) ने बांग्लादेश में बीटी बैंगन की खेती करने और न करने वाले किसानों में 2018 में एक परीक्षण किया और पाया कि बीटी बैंगन की खेती करने वाले किसानों की प्रति किलोग्राम लागत में 31 फीसदी की कमी और प्रति हेक्टेयर कमाई में 27.3 फीसदी की वृद्धि हुई। जबकि कीटनाशकों के प्रयोग में 39 फीसदी की कमी आई और बीटी बैंगन में एफएबीस कीड़े का प्रकोप केवल 1.8 फीसदी था, जबकि दूसरी किस्म के बैंगन में 33.9 फीसदी था। वर्ष 2021 फिलीपींस में भी बीटी बैंगन को मंजूरी दे दी गई। यही सूरते हाल भारतीय कृषि विज्ञानियों द्वारा विकसित सरसों की जीएम किस्म का भी है।

दो दिन पूर्व ही खबर आई कि चीन ने अपने देश में सोयाबीन और मक्का सहित 98 फसलों के जीएम प्रास्प के उत्पादन की अनुमति दे दी है। जबकि भारत में जीएम फसलों का मुद्दा खाद्यान्न आपूर्ति से ज्यादा राजनीति का मुद्दा बन चुका है। एक आधारहीन अवधारणा के बल पर यह साबित करने का अनवरत प्रयास चल रहा है कि जीएम खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। इसके अतिरिक्त इसे विदेशी बीज उत्पादकों के मुनाफे से जोड़कर देसी भावनाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है। कुछ सामाजिक संगठनों, कृषि विशेषज्ञों, कीटनाशक उत्पादकों की लॉबी आदि के दबाव में सरकार चाहते हुए भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के वाणिज्यिक उत्पादन की अनुमति नहीं दे पा रही है। जबकि लगभग 3 हजार वैज्ञानिक अध्ययनों द्वारा इन फसलों की सुरक्षा का आंकलन किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूरोपीय आयोग और रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन सहित वैश्विक स्तर के 284 संस्थान जीएम फसलों को मानव और पर्यावरण के लिए सुरक्षित मानते है। 2016 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज़, इंजीनियरिंग और मेडिसिन ने 9 सौ से अधिक प्रकाशनों की समीक्षा की, 80 वक्ताओं को सुना और जनता से 7 सौ से अधिक टिप्पणियां एकत्रित की। वे सभी एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे कि गैर जीएम फसलों की तुलना में जीएम उत्पाद मानव स्वास्थ्य के लिए कोई जोखिम पैदा नहीं करते है और न ही वे स्पष्ट रूप से किसी पर्यावरणीय समस्या का कारण बनते है। यहां तक कि भारत सरकार द्वारा भी संसद में बयान दिया जा चुका है कि जीएम सुरक्षित है।

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
• राष्ट्रीयता • कर्त्तव्य • समर्पण
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन द्वारा हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड प्रेस, मौजा-दरियापुर, पुलिस स्टेशन-शाहपुर, दानापुर, पटना से मुद्रित तथा चतुर्थ तल, सहारा इण्डिया विहार, बोरिंग रोड क्रासिंग, पटना से प्रकाशित। । स्थानीय संपादक - संजय त्रिपाठी *।
पटना कार्यालय- 3911448/417/454/422, फैक्स : 2535935,2520760 विज्ञापन-3911455/434, प्रसार- 3911451/428
वर्ष - 20, अंक 6858
आर.एन.आई. सं. -बीआईएचएचआईएन/2006/18082 Postal Reg. No. : R-10/NP-50/06-07
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु उत्तरदायी

पायनियर
नई दिल्ली, शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025

एसआईआर

अफरा-तफरी को लेकर चुनाव आयोग हुआ गंभीर

लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी व निष्पक्ष बनी रहनी चाहिए और साथ में इसके लिए मतदाताओं की विश्वसनीयता भी उतनी जरूरी है। ऐसा इसलिए कि चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी निर्णायक और अहम होती है। इस प्रक्रिया को लेकर हंगामा मचा हुआ है और प्रक्रिया की तेजी से कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं। नतीजा यह है कि निचले स्तर पर भारी दबाव दबाव इस प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों पर पड़ रहा है। कई बूथ स्तरीय अधिकारियों में अफरा-तफरी है और तनाव भी घर कर गया है। इनका कार्य मतदाता सूचियों को अपडेट करना है। पश्चिम बंगाल और कई अन्य राज्यों में कम समय में अधिक काम के दबाव के चलते कुछ बीएलओ के मरने व आत्महत्या करने के मामले सामने आए हैं। आरोप है कि उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ही नहीं बल्कि सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों द्वारा भी उन्हें परेशान किए जाने का आरोप है। हालांकि, इस अव्यवस्था के चलते ही चुनाव आयोग ने अब एसआईआर के कार्यक्रम को एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। लेकिन कहना कठिन है कि इस कदम से बीएलओ का तनाव कम करने या विभिन्न हितधारकों की आशंकाओं को दूर करने में कोई खास मदद मिल सकेगी। कहा जा रहा है कि एक माह पहले शुरू हुई राष्ट्रव्यापी एसआईआर प्रक्रिया में कई तरह की बाधाएं आ रही हैं। इस प्रक्रिया में करीब 51 करोड़ मतदाता शामिल हैं, जो तकरीबन भारतीय आबादी का एक-तिहाई से भी ज्यादा। उनकी शिनाख्त से जुड़ी जानकारी को एक निश्चित समय सीमा में प्रमाणित कर पाना आसान नहीं है। कहा जा रहा है कि निर्धारित समय-सीमा व्यावहारिक नहीं है। तीन महीने की अवधि में गणना प्रपत्रों का वितरण, उसके बाद मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन और फिर अंतिम मतदाता सूची जारी करना आसान काम नहीं है। बहुत तेजी से काम को अंजाम देने का जिम्मा अधिकारियों पर अतिरिक्त दबाव बना रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वतंत्र-निष्पक्ष चुनावों के लिए यह प्रक्रि या बेहद जरूरी है। ऐसे में अहम सवाल है कि आनन-फानन प्रक्रि या की खानापूर्ति नही हो सकती। इसके लिए इतना समय चाहिए कि उचित ढंग से अभियान को पूरा किया जा सके। यही बात बीएलओ के लिए भी लागू होती है, ताकि वे अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहराव वाले मतदाताओं का डेटा संकलित करने के लिए बूथ-स्तरीय एजेंटों के साथ मिलकर सुचारु रूप से काम कर सकें। यदि एसआईआर की प्रक्रिया किसी विवाद में उलझी रहती है तो इस अभियान का उद्देश्य ही विफल हो सकता है। बिहार की एसआईआर प्रक्रिया के घटनाक्रमों से मिले सबक को अन्य राज्यों में इस प्रक्रिया के दौरान याद रखा जाना चाहिए। निस्संदेह, स्तरहीन व संदिग्ध एसआईआर हमारे चुनावी लोकतंत्र की विश्वसनीयता को ठेस पहुंचा सकता है। उल्लेखनीय है कि विशेष गहन पुनरीक्षण की यह प्रक्रिया मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों तथा अंडमान-निकोबार, लक्ष्यद्वीप व पुडुचेरी केंद्रशासित प्रदेशों में जारी है। अधिकारियों का आरोप है कि अतिरिक्त कार्य-दबाव का उनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल रहा है। वहीं चुनाव आयोग का आरोप है कि कुछ अधिकारियों की लापरवाही के चलते प्रक्रिया की निष्पक्षता व पारदर्शिता प्रभावित हो रही है। वैसे यदि वास्तव में बीएलओ पर अतिरिक्त दबाव है तो चुनाव आयोग को इस मुद्दे का समाधान संवेदनशील ढंग से करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर मतदाता पहचान से जुड़े प्रमाणपत्रों को जुटाने में आ रही परेशानियों के चलते लोग भी बीएलओ पर दबाव बनाते हैं। कई राज्यों में बीएलओ संगठनों ने प्रदर्शन करके अधिक समय दिए जाने की मांग भी की है। अंततः मामले की गंभीरता को देखते हुए नर्वाचन आयोग ने छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए समयसीमा बढ़ा दी है।

यूपी में अवैध घुसपैठ पर कड़ा प्रहार

कांतिलाल मांडोत

उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती संख्या लंबे समय से आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सामाजिक ताने-बाने के लिए चुनौती रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस गंभीर समस्या को देखते हुए राज्य के 17 प्रमुख नगर निकायों को तुरंत प्रभाव से व्यापक सत्यापन और सूचीकरण अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। सरकार का मानना है कि अवैध रूप से भारत में घुसपैठ करने वाले लोगों की उपस्थिति न सिर्फ सुरक्षा जोखिम बढ़ाती है, बल्कि कई बार अपराध, जालसाजी, फर्जी पहचान और संसाधनों पर असमान दबाव जैसे खतरे भी उत्पन्न करती है। इसी वजह से प्रदेश स्तर पर चलाया जा रहा यह अभियान निर्णायक कदम माना जा रहा है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियां क्यों चिंता का विषय है?पिछले एक दशक में देश के कई राज्यों में अवैध प्रवासियों की संख्या तेज़ी से बढ़ी है। इनमें सबसे अधिक रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं। कई बार ये लोग फर्जी कागज़ात के सहारे नागरिक सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं और संवेदनशील क्षेत्रों में आश्रय भी बना लेते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने पहले भी रिपोर्ट दी है कि विभिन्न मामलों में अवैध घुसपैठिए आपराधिक गतिविधियों, मानव तस्करी और फर्जी दस्तावेज़ बनवाने वाले नेटवर्क से जुड़े पाए गए हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश, खासकर पश्चिमी यूपी, काशी क्षेत्र और आगरा-मथुरा बेल्ट में उनका सत्यापन बेहद आवश्यक हो गया है। सरकार का निर्णय सुरक्षा सुदृढ़ीकरण के व्यापक उद्देश्य से जुड़ा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नगर आयुक्तों, डीएम, कमिश्नर और रेंज के आईजी को स्पष्ट आदेश दिया है कि अवैध रूप से रह रहे संदिग्ध व्यक्तियों की एक संगठित सूची तैयार की जाए और उसे तत्काल पुलिस तथा खुफिया एजेंसियों के साथ साझा किया जाए। यह सूची दो चरणों में तैयार की जानी है। प्राथमिक सत्यापन जहां व्यक्ति की पहचान, निवास स्थान और दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच की जाएगी। गहन जांच एवं कार्रवाई होगी। इसमें पुलिस व खुफिया विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित व्यक्ति देश का वैध नागरिक नहीं है तो उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई हो। सरकार के अनुसार इस अभियान का उद्देश्य न केवल घुसपैठ पर रोक लगाना है, बल्कि प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को नए स्तर पर मजबूत करना भी है। सफाईकर्मी के रूप में संदिग्ध पहचान एक महत्वपूर्ण कारण है। नगर निकायों के पास मौजूद रिकॉर्ड के अनुसार, बड़ी संख्या में सफाईकर्मियों की नियुक्ति पिछले वर्षों में ठेके के माध्यम से हुई है। कई बार ठेका एजेंसियां श्रमिकों के कागजात की गहराई से जांच नहीं करतीं, जिसके चलते कुछ संदिग्ध लोग भी सफाईकर्मी के रूप में नौकरी पा जाते हैं। क्योंकि सफाईकर्मी शहर के हर इलाके में आते-

जाते हैं और कई महत्वपूर्ण स्थानों तक पहुंच रखते हैं, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों ने इस श्रेणी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई है।

आगरा में अभियान की शुरुआत 5000 सफाईकर्मियों का सत्यापन किया जा रहा है। आगरा नगर निगम ने इस सरकारी निर्देश पर सबसे तेज़ कार्रवाई करते हुए 5000 से अधिक सफाईकर्मियों की पहचान और सत्यापन प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रत्येक सफाईकर्मी का पूरा डेटा, फोटो सहित, पुलिस को सौंपा गया है। स्थानीय थानों में विशेष टीमें बनाई गई हैं जो 15 दिनों में सत्यापन प्रक्रिया पूरी करेंगी। जिन लोगों के दस्तावेजों में असंगतियां पाई जाएंगी, उनके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई होगी। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, यह कदम न सिर्फ सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक है, बल्कि शहर की प्रशासनिक पारदर्शिता को भी मजबूत करेगा। 17 नगर निकायों में एक साथ अभियान का विस्तारकिया गया है। सरकार ने जिन 17 निकायों को निर्देश भेजे हैं, उनमें लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, नोएडा, गाज़ियाबाद, आगरा, अलीगढ़, सहारनपुर समेत सभी बड़े शहर शामिल हैं। इन शहरों में प्रवासन दर अधिक है और कुछ स्थानों पर पहले भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली है। उम्मीद है कि इन नगर निकायों में अगले दो सप्ताह में सभी सफाईकर्मियों, अस्थायी मजदूरों और किराएदारों की पहचान प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। प्रक्रिया की पारदर्शिता और समयबद्धता पर विशेष जोरदिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि यह अभियान किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी तरह सुरक्षा और कानून-व्यवस्था पर केंद्रित है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति के साथ अनावश्यक दुर्व्यवहार न हो। सभी जांच निष्पक्ष और दस्तावेज़ आधारित हों। जहां भी संदेह हो, पुलिस व स्थानीय निकाय संयुक्त रूप से निर्णय लें। सरकार ने प्रत्येक निकाय को 15 दिन की समयसीमा दी है ताकि कार्रवाई तेज़ी से और प्रभावी तरीके से पूरी हो सके। अभियान के माध्यम से मिलने वाले व्यापक लाभ को गौण नही समझा जा सकता है।

आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी

अवैध घुसपैठ पर नियंत्रण के बाद संवेदनशील क्षेत्रों में संभावित आपराधिक गतिविधियों का खतरा कम होगा। नगर निकायों की कार्यप्रणाली पारदर्शी बनेगी। सभी कर्मचारियों का प्रामाणिक डेटा तैयार होने से भविष्य में फर्जी नियुक्तियों और अनियमितताओं पर लगाम लगेगी। कानून-व्यवस्था में सुधार जिन शहरों में अवैध प्रवासी अधिक संख्या में रहते हैं, वहां अपराधों में अचानक वृद्धि देखी जाती है। सत्यापन से यह प्रभाव कम होगा। राष्ट्रीय हित और सुरक्षा को बढ़ावा देना पहली प्राथमिकता है। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों के अनुरूप है, जहां देश की सीमाओं के भीतर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान स्पष्ट और प्रमाणित होनी चाहिए। स्थानीय समाज में विश्वास बढ़ेगा। नागरिकों को यह भरोसा मिलेगा कि सरकार उनके हितों और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। चुनौतियां भी कम नहीं है। हालांकि सरकार के इस कदम की व्यापक सराहना हो रही है, लेकिन चुनौतीपूर्ण पहलू भी मौजूद हैं।

कई अवैध घुसपैठिए फर्जी पहचान पत्र बना चुके हैं। कई लोग ठेका एजेंसियों के माध्यम से वर्षों से कार्यरत हैं, जिससे उनकी जांच और कठिन हो जाती है। सत्यापन के दौरान राजनीतिक और सामाजिक दबाव भी सामने आ सकते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद सरकार का रुख साफ है। कानून व्यवस्था सर्वोपरि, सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संदिग्ध रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ शुरू किया गया यह तेज़ और व्यापक अभियान प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को एक नए स्तर पर मजबूत करने वाला कदम है। अवैध घुसपैठ लंबे समय से देश की एक गंभीर समस्या रही है, जिसका समाधान तभी संभव है जब राज्य स्तर पर ठोस और नियमित सत्यापन की व्यवस्था हो। सफाईकर्मियों से लेकर अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों तक, हर व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करना न केवल कानून व्यवस्था की मजबूती के लिए आवश्यक है, बल्कि यह राष्ट्रीय हित में भी है। आगरा में 5000 सफाईकर्मियों का सत्यापन इसका प्रारंभिक नमूना है, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में माहौल अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और व्यवस्थित होगा। सरकार का यह कदम स्पष्ट संदेश देता है कि उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठ अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कानून का राज ही सर्वोच्च रहेगा।

बंगाल में उभरते हिंदू स्वरों में बदलते राजनीतिक समीकरण

ललित गर्ग

पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद पुनर्निर्माण का मुद्दा उठाना मानो एक सोए हुए राक्षस को जगाने जैसा है, क्योंकि यह केवल एक मस्जिद का प्रश्न नहीं बल्कि देश की एकता, अखंडता और सांप्रदायिक सौहार्द की कसौटी है। सदियों से चला आ रहा बाबरी विवाद भारत की सामाजिक चेतना पर गहरे जख्म छोड़ चुका है-जिसने राजनीति को उग्र बनाया, समुदायों को बाँटा और नफरत व हिंसा के बीज बोए।

पश्चिम बंगाल इन दिनों धार्मिक और राजनीतिक उफान का केंद्र बना हुआ है। बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर मुस्लिम संगठनों और राजनीतिक समूहों की सक्रियता के बीच हिन्दू धर्मगुरुओं एवं संगठनों की मोर्चाबंदी ने क्या हिंदू क्रांति का शंखनाद किया है? क्या यह आगामी विधानसभा चुनावों में हिंदू वोटों को एकत्र करने का नया एजेंडा है, या पश्चिम बंगाल में लगातार हिन्दुओं पर हो रहे हमलों, उनको कुचलने की कुचेष्टाओं एवं मुस्लिम तुष्टीकरण का माकुल जबाव है। बाबा बागेश्वर धाम-धीरेन्द्र शास्त्री सहित अनेक हिंदू धर्मगुरुओं के प्रवचनीय हस्तक्षेप, लाखों लोगों द्वारा सामूहिक गीता पाठ और संतों की हुंकार से एक नई चेतना आकार लेती दिखाई दे रही है। यह उभार महज आस्था का नहीं, बल्कि पहचान, सुरक्षा और गौरव के भावों का उभार है।

पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद पुनर्निर्माण का मुद्दा उठाना मानो एक सोए हुए राक्षस को जगाने जैसा है, क्योंकि यह केवल एक मस्जिद का प्रश्न नहीं बल्कि देश की एकता, अखंडता और सांप्रदायिक सौहार्द की कसौटी है। सदियों से चला आ रहा बाबरी विवाद भारत की सामाजिक चेतना पर गहरे जख्म छोड़ चुका है-जिसने राजनीति को उग्र बनाया, समुदायों को बाँटा और नफरत व हिंसा के बीज बोए। ऐसे समय में जब राष्ट्र विभिन्न संकटों से जूझ रहा है, इस विवाद को नए भूगोल में स्थानांतरित कर हवा देना सामाजिक सामंजस्य एवं राष्ट्रीय एकता के लिए घातक हो सकता है। सद्भाव और शांति की बुनियाद पर खड़े भारत को ऐसे मुद्दों की आवश्यकता है जो एकता को मजबूत करें, न कि पुराने घाव कुरेदकर समाज में तनाव और अविश्वास पैदा करें। अतः आवश्यक है कि नेतृत्व इस संवेदनशील विषय को विवेक, संवाद और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर संभाले, ताकि भारत का बहुलतावादी चरित्र और साझा सभ्यता सुरक्षित रह सके।

निश्चित ही बाबरी मस्जिद विवाद को हवा देकर कुछ मुस्लिम संगठनों और राजनीतिक वर्गों ने तनाव का वातावरण खड़ा किया है। इन दो समानांतर धाराओं की टकराहट ने बंगाल को विमर्श के केंद्र में ला दिया है कि क्या राज्य में हिंदू संगठित होकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी

की हिन्दू-विरोधी साजिशों एवं षडयंत्रों का अंत चाहते हैं? बंगाल परंपरा से बौद्धिक और सांस्कृतिक बहुलता का प्रदेश रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में हिंदू सामाजिक मानस में एक बदलाव दिख रहा है। ''गजवा हिंद'' के प्रलापों के प्रतिकार में ''भगवा हिंद'' का संकल्प उभर रहा है। पांच लाख से अधिक हिंदुओं द्वारा एक साथ गीता पाठ करना इसी उभार का संकेत है, जिसमें धर्म प्रदर्शन शक्ति और अस्मिता के रूप में सामने आता है। साध्वी ऋतंभरा के वक्तव्यों ने इस उभार को एक नया स्वर दिया है। उनका स्पष्ट कथन कि ''यह धरती प्रभु श्रीराम की है और श्रीराम की ही रहेगी'' बंगाल सहित पूरे देश के हिंदू मानस में गूंज रहा है। यह कथन सिर्फ आस्था की घोषणा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक अधिकार और आधिपत्य की अनुभूति का उद्घोष है। उनके भाषणों में उभरती चेतावनी है कि यदि हिंदू अपनी संस्कृति, परंपरा और मंदिरों की रक्षा के लिए नहीं उठे तो इतिहास स्वयं उनसे जवाब मांगेगा।

इस पृष्ठभूमि में बाबरी विवाद का पुनर्स्मरण राजनीति का साधन भी प्रतीत होता है। मुस्लिम संगठनों द्वारा इसकी मांगों को आगे बढ़ाना और नेताओं द्वारा इसे मुद्दा बनाना निश्चित ही सामाजिक भावना को चुनौती देता है। इसका प्रतिउत्तर धार्मिक मंचों से आया है, जहां प्रवचनों और सभाओं ने इसे हिंदू गौरव और अस्तित्व के प्रश्न के रूप में चित्रित किया है। ऐसे में यह कहना असंगत नहीं कि बंगाल की जमीन पर हिंदू पहचान की राजनीति तेजी से आकार ले रही है और हिन्दू धर्मगुरुओं के स्वर इसे वैचारिक ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। उनका यह कथन कि ''राम का नाम अनंत है, पर पुरुषार्थ के बिना सिर्फ नाम से रामराज्य नहीं आएगा'' एक सीधा संकेत है कि हिंदू समाज को संगठित, सक्रिय और आत्मनिर्भर होना होगा। इस व्यापक परिदृश्य का मुख्य केंद्रबिंदु राजनीति है। क्या यह सब आगामी विधानसभा चुनावों का संकेत है? बंगाल की राजनीति लंबे समय से मुस्लिम मतदाताओं की निर्णायक भूमिका के आसपास घूमती रही है और ममता बनर्जी ने मुस्लिम समाज के भरोसे को अपने समर्थन की नींव बनाया है। परंतु यदि हिंदू मतदाता नए सांस्कृतिक उभार से प्रेरित होकर एकजुट होते हैं, तो पहली बार बंगाल की सत्ता-समीकरण बदल सकते हैं। भाजपा और संघ परिवार का प्रयास भी इसी दिशा में है कि धार्मिक सम्मेलनों को राजनीतिक चेतना का मंच बनाकर हिंदू अस्मिता को वैचारिक शक्ति प्रदान करना। भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और धार्मिक प्रवचनीय हस्तक्षेपों द्वारा बंगाल में हिंदू एकता और पहचान को जागृत करने की रणनीति अपनाई जा रही है। इस राजनीतिक परिपाटी में बाबा बागेश्वर जैसे मंच प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं, धर्म-सम्मेलनों को राजनीतिक चेतना की पाठशाला में बदला जा रहा है। साध्वी ऋतंभरा का बंगाल में सक्रिय होना उसी रणनीति की कड़ी है, क्योंकि उनका सशक्त भाषण हिंदू भावनाओं को झकझोरता है। बंगाल जिसकी पहचान बौद्धिक विनम्रता, कविता, महात्म्य और सहिष्णुता से जुड़ी रही है, वह अब टकराव, ध्रूवीकरण और प्रतिआक्रामकता की ओर बढ़ता दिख रहा है। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में भावनात्मक आवेश बढ़ रहा है और नेताओं द्वारा इस माहौल को चुनावी लाभ के लिए साधने की त्रासद कोशिशें तेज हैं। यह परिस्थिति बंगाल के सामाजिक ताने-बाने के लिए चुनौतीपूर्ण है। फिर भी एक बात निर्विवाद है-बंगाल में एक नई चेतना, एक नई आकांक्षा जन्म ले रही है। यह पूर्ण क्रांति है या क्रांति का शंखनाद, यह कहना अभी जल्दबाजी होगा, परन्तु प्रारंभिक संकेत स्पष्ट हैं। हिंदू पहचान की राजनीति बंगाल में निर्णायक होती जा रही है, मुस्लिम वोट-बैंक की राजनीति पहली बार चुनौती में दिखाई दे रही है और ममता बनर्जी की सत्ता को सांस्कृतिक विरोध का नया मोर्चा मिला है। अब यह समय बताएगा कि यह उभार सत्ता बदलता है या सामाजिक संवाद को बदलता है। लेकिन इतना तो तय है कि बंगाल की राजनीति अब केवल विकास, योजनाओं और नेतृत्व की नहीं, बल्कि पहचान, इतिहास और प्रभुत्व की राजनीति बन चुकी है। यही कारण है कि धार्मिक मंचों की आवाज़ें चुनावी मैदान की धड़कन बन रही हैं। बंगाल अपने निर्णायक मोड़ पर खड़ा है-जहाँ राम का दावा और राम की भूमि का संकल्प राजनीति, समाज और भविष्य तीनों को प्रभावित करने वाला तत्व बन चुका है। न केवल मुस्लिम तुष्टिकरण बल्कि भ्रष्टाचार से लेकर मनमर्जी एवं तानाशाही का शासन चलाना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रक्रिया बन गयी है। ममता वोट बैंक की राजनीति के लिये कानून की धज्जियां बार-बार उड़ाती रही है। ममता बनर्जी का एकमात्र लक्ष्य मुसलमानों के वोट बैंक को बरकरार रखना रह गया है। मुद्दा चाहे रोहिंग्या मुसलामानों के अवैध प्रवेश का हो या फिर बांग्लादेशियों का या अब बाबरी मस्जिद का। इसके लिए ममता ने देश की एकता-अखंडता और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को नजरअंदाज किया है, कानून से खिलवाड़ जितना पश्चिमी बंगाल में हुआ है उतना शायद ही देश के किसी दूसरे राज्यों में हुआ हो। तृणमूल कांग्रेस हिन्दुओं को पश्चिम बंगाल में सेकेंड क्लास सिटिज़न एवं अल्पसंख्यक बनाना चाहती है। मुस्लिम तुष्टीकरण की उसकी सोच एवं नीति न केवल उनके घोषणा-पत्रों में बल्कि उनके बयानों में स्पष्ट झलकती रही है। ममता ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है, तृणमूल कांग्रेस का एकतरफा रवैया हमेशा से समाज को दो वर्गों में बांटता रहा है एवं सामाजिक असंतुलन तथा रोष का कारण रहा है। बदले हुए राजनीतिक हालात इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किसी भी एक वर्ग की अनदेखी कर कोई भी दल राजसत्ता का आनंद नहीं उठा सकता। पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है वह महज 'बागेश्वर बनाम बाबरी विवाद' नहीं है, यह सांस्कृतिक-धार्मिक पुनर्स्थापन की कोशिश बनाम राजनीतिक मुस्लिम केंद्रवाद की प्रतिस्पर्धा है।

आप की बात

एसआईआर की तारीख बढ़ाने का फैसला स्वागतयोग्य

एसआईआर की तारीख बढ़ाने का भारत निर्वाचन आयोग का फैसला काबिलेतारीफ है क्यों कि अभी भी बहुत से मतदाता ऐसे है जिनके एसआईआर फार्म भर नहीं पाए है या फिर किसी कारणवश वह अपने आवास पर नहीं हैं। बीएलओ की मेहनत रंग ला रही है। धीरे-धीरे एसआईआर का कार्य पूरा हो रहा है। कुछ लोग ही शेष है जिनका भी फार्म जल्द ही भर जाएगा। इसमें बीएलओ की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीएलओ ने पूरी ईमानदारी के साथ वार्डों के पार्षदों या फिर जिम्मेदार नागरिक के साथ आवासों पर पहुंच कर पहले फार्म का वितरण फिर एक-एक फार्म को एकत्रित करने का सफल प्रयास किया है। आयोग के इस फैसले ने जहां प्रक्रि या को लेकर संदेह था उसे सुधारने का प्रयास किया है।

अजय पाल, मोहनलाल गंज

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यात्रियों को मिलेंगी अत्याधुनिक सुविधाएं

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यात्रियों को एक अत्याधुनिक और डिजिटल-फर्स्ट अनुभव प्रदान करने जा रहा है। हर यात्री को एक तनावमुक्त, सुगम और अत्याधुनिक यात्रा अनुभव मिले। यह एयरपोर्ट भविष्य की यात्रा जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जहां तकनीक यात्रियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। एयरपोर्ट पर ऐसी आधुनिक तकनीकें लगाई जा रही हैं, जो यात्रा को तेज और सहज बनाएंगी। यात्री स्वयं ही सेल्फ बैग-ड्रॉप मशीनों के माध्यम से अपना सामान जमा कर सकेंगे, जिससे लंबी कतारों में लगने की जरूरत कम होगी। इसी तरह सेल्फ बोर्डिंग गेट्स के जरिए बोर्डिंग प्रक्रिया और अधिक तेज़ और सुविधाजनक की जा रही है। एयरपोर्ट के सभी गेट डिगी यात्रा सुविधा से लैस होंगे, जिसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के माध्यम से यात्रियों को बिना किसी दस्तावेज दिखाए तेजी से प्रवेश और बोर्डिंग की सुविधा मिलेगी।

राहुल सिंह, गाजियाबाद

ट्रैफिक पुलिस ने बढ़ा दी शहर की रफ्तार

शहर के प्रमुख चौराहा हजरतगंज, राजड्डावन, वायरलेस चौराहा और आईटी कॉलेज चौराहे के पास लगने वाले लंबा-लंबा जाम से ट्रैफिक पुलिस अफसरों ने अब निजात दिला दी है। जहां चौराहों पर आधा-आधा घंटा आगे बढ़ने के लिए इंतजार करना पड़ता था, अब वहां फर्राटा ड्डारते हुए वाहन जा रहे है। इसके लिए ट्रैफिक अफसरों ने एक योजना बनाकर चौराहों पर बैरीकैटिंग करके कुछ दूरी से टर्निंग देकर जाम से निजात दिलाया है। जिसकी अब शहर वासी प्रशंसा कर रहे है। वही अब ट्रैफिक अफसर शहर के कई उन चौराहों को चिन्हित कर रहे हैं जहां लंबा-लंबा जाम अब ड्डी लगा रहता है।

जय सैनी फर्नीचर कारोबारी
गीतापल्ली लखनऊ

रिंग रोड़ से मायापुरी कॉलोनी का सफर हो गया है दुश्वार

रिंग रोड़ से दो किलोमीटर दूर मायापुरी कॉलोनी में लोगों को चलन दूभर हो गया है। जहां हजारों की संख्या में आबादी रहती है। मायापुरी, अतरौली व जहिरापुर में रहने वाले लोग कई वर्षो से परेशानी से जूझ रहे है लेकिन नगर निगम, पार्षद और विधायक अनजान बने हुए है। जरा से बारिश में घुटने तक पानी सड़कों पर ड्डार जाता है। इलाकों में न नाली, न जल निकास, न प्रकाश की व्यवस्था और न ही सड़क। ऐसी तमाम परेशानी से जूझ रहे इन इलाकों के लोग आए दिन माननीयों के आवास पर जाकर प्रार्थना पत्र देते है लेकिन अड्डी तक परेशानी से निजात नहीं मिल सकी है।

संदीप कुमार मैटेरियल कारोबारी
मायापुरी कॉलोनी गुडम्बा लखनऊ

समस्याओं से पार पाना आसान नहीं पर समाधान तो जरूरी है

तमाम दावों के विपरीत लखनऊ के मुख्य मार्गों को छोड़ दें तो ज्यादातर इलाकों में सड़कों की हालत बिगड़ी तो सुधारने का कोई प्रयास भी नहीं हुआ। कुर्मनगर के कल्याणपुर इलाके में कालोनियों के अंदर जहां जगह-जगह सड़क पर गड्ढे हो गए हैं वहीं मरम्मत न होने की दशा में सड़कों की हालत और खराब होती जा रही है। आए दिन दुर्घटनाएं यहां आम हो गई हैं. इस बाबत जब भी पार्षदों से संपर्क की कोशिश की जाती है तो वे उपलब्ध भी नहीं होते। इसके अलावा कई क्षेत्रों में सफाई अभियान भी सरकारी तंत्र को मुंह चिढ़ा रही हैं। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि निचले स्तर पर जवाबदेह बनाने की जरूरत है। त्र्क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर भी नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और इसके लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने की भी जरीरत है। साथ पा,र्दों को लेकर भी जनता में व्याप्त असंतोष का भी हल निकालना होगा ताकि आम आदमी बोवजह की भागादौड़ी से बच सके।

लल्लन सिंहस लखनऊ

पाठकगण अपने विचार responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भेज सकते हैं।

जरूरतमंद के आवास, बीमार के उपचार की करेंगे व्यवस्थाः योगी

❖ गोरखनाथ मंदिर में लगातार दूसरे दिन सीएम योगी ने करीब 300 लोगों की सुनी समस्याएं

पायनियर समाचार सेवा। गोरखपुर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन, गुरुवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने आवास के लिए जरूरतमंद लोगों को आवास दिलाने और गंभीर बीमारियों से पीड़ितों के इलाज में भरपूर आर्थिक सहायता देने का आत्मीय संबल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार हर जरूरतमंद और पात्र व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने तथा हर

समस्या के प्रभावी निस्तारण के लिए संकल्पित है। गुरुवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 300 लोगों से मुलाकात की। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सभागार में बैठाए गए लोगो तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और एक-एक कर उनकी समस्याओं को सुना। ध्यान से बात सुनते हुए उनके प्रार्थना पत्र लिए और निस्तारण के लिए संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को संदर्भित कर निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और सन्तुष्टिपरक होना चाहिए। जनता दर्शन में एक महिला ने आवास की समस्या बताई। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाया जाएगा। इसे लेकर उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित भी किया। कहा कि सरकार की मंशा है कि हर जरूरतमंद के पास पक्का आवास हो। जनता दर्शन में एक महिला ने अपने पति की बीमारी में इलाज के लिए मदद की गुहार लगाई। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला को आश्वस्त किया कि वह अपने पति का अच्छे से इलाज कराएं, पैसे की व्यवस्था विवेकाधीन कोष से करा दी जाएगी। इलाज में आर्थिक मदद मांगने कई अन्य लोग भी आए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें भरोसा दिया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि जो भी जरूरतमंद हैं, प्रशासन उनके उच्च स्तरीय इलाज का इस्टीमेट शीघ्रता से बनवाकर उपलब्ध कराए। इस्टीमेट मिलते ही सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराएगी। जमीन कब्जा किए जाने से संबंधी शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को निर्देश दिया कि यदि कोई दबंग किसी की जमीन जबरन कब्जा कर रहा हो तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। एक महिला ने अपनी ही जमीन पर काबिज होने के संबंध में कुछ लोगों द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने की समस्या पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि महिला को उनकी जमीन पर कब्जा दिलाया जाए। जनता दर्शन में सीएम योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया।

सीएम आज करेंगे किसान पाठशाला का शुभारंभ

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

❖ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने स्थलीय निरीक्षण कर लिया तैयारियों का जायजा

❖ 12 से 29 दिसंबर तक प्रदेश भर में किया जाएगा किसान पाठशालाओं का आयोजन

प्रदेश के किसानों को नवीन तकनीक, कृषि यन्त्रों, फसलों के पैकेज आफ प्रेक्टिसेज एवं रबी प्रजातियों के बारे में अवगत कराने के लिए वर्तमान रबी मौसम की किसान पाठशाला का शुभारम्भ शुक्रवार को मुख्यमंत्री के द्वारा पद्मश्री कृषक राम सरन वर्मा के गांव दौलतपुर, बाराबंकी के खेत से किया जाएगा। सरकार किसानों के प्रति प्रतिबद्धता को निभाते हुए 'किसान की बात किसान के द्वार' की संकल्पना पर किसानों को प्रोत्साहित करेगी। विगत वर्षों में किसान पाठशाला के माध्यम से अब तक लगभग 190 लाख किसानों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

बृहस्पतिवार को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बाराबंकी में कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया और आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। उद्घाटन के अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही एवं कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख भी उपस्थित रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के प्रति अपनी कृतसंकल्पता सरकार के गठन के साथ ही निभाई जा रही है। सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को 25423 करोड़ रुपये का ऋण मोचन, 90669 करोड़ रुपये का पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ प्रत्यक्ष तौर पर उपलब्ध कराया जा चुका है। इसके साथ ही मृदा सुधार, मृदा परीक्षण, कृषि यंत्र, उर्वरक, कृषि रक्षा रसायन सहित कृषि उत्पादन के प्रसंस्करण एवं विपणन जैसी क्रियाओं के लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक स्तर पर किसानों को सहयोग कर उनके कृषि उत्पादन एवं लाभ में वृद्धि तथा आत्मसम्मान दिलाने हेतु सतत प्रयासरत है।

निर्वाचन नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन अब 31 दिसंबर को

लखनऊ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 1 जनवरी, 2026 के आधार पर प्रदेश में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की घोषित तिथियों को 15 दिन बढ़ाते हुए पुनः संशोधित तिथियां जारी कर दी गई है। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित ढंग से पूर्ण करने तथा शुद्ध मतदाता सूची को बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से 2 सप्ताह का समय और बढ़ाने का अनुरोध किया गया था, जिससे कि जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा मृतक, शिफ्टेड तथा अनुपस्थित मतदाताओं का पुनः सत्यापन कराया जा सके।

19 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति शीघ्र जारी की जाएगी: जयवीर सिंह

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

❖ वर्ष 2025-26 में ग्राम पंचायतों में वितरण के लिए वाद्य यंत्रों को उच्चस्तरीय कमेटी की देखरेख में सेट खरीदे जाएंगे

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने गुरुवार दूसरे दिन पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्यटन विभाग की परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा किया जाए। व्यवधान की स्थिति में उसका निस्तारण सुनिश्चित करते हुए कार्य को आगे बढ़ाया जाए।

वित्तीय वर्ष 2025-26 की स्वीकृत कार्ययोजना में शामिल 19 परियोजनाओं के आगणन प्रस्ताव की स्वीकृति शीघ्र जारी कर दी जाएगी। उन्होंने अब तक न शुरू की गई परियोजनाओं की भी गहन समीक्षा करते हुए कार्य की गति तेज करने के निर्देश दिए। पर्यटन मंत्री गुरुवार गोमती नगर स्थित पर्यटन भवन के सभागार में संस्कृति तथा पर्यटन विभाग की निर्माण कार्य से जुड़ी परियोजनाओं तथा विभागीय गतिविधियों की बिंदुवार समीक्षा की।

उन्होंने निर्देश दिए कि बदले परिवेश में परियोजनाओं को गुणवत्ता के साथ पूरा करके पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए, ताकि वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग का अधिकतम सहयोग सुनिश्चित हो सके और स्थानीय लोगों को अपने घर के आस-पास रोजगार मिल सके। उन्होंने पिछली बैठकों में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अधिकारी किसी कार्य में अड़गा न लगाए, बल्कि उसके समाधान के लिए हरसंभव प्रयास करे। जयवीर सिंह ने कहा कि संस्कृति विभाग द्वारा लोककला से आमजनता को जोड़ने तथा उन्हें संरक्षित रखते हुए अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए संस्कृति विभाग ने वाद्य यंत्रों का सेट क्रय करके वितरित किया था।

उसमें से अवशेष 26 सेट वाद्य यंत्र भातखंडे संगीत संस्थान को और आजमगढ़ के हरिहर पुर स्थित संगीत विद्यालय को उपलब्ध करा दिए गए है। यह वाद्य यत्र वित्तीय वर्ष 2023-24 में क्रय किए गए थे। उन्होंने शेष जिलों में वाद्य यंत्र का सेट वितरित करने के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी की देख-रेख में नए वाद्य यंत्र क्रय करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि नए वाद्य यंत्र की गुणवत्ता एवं टिकाऊपन की जांच के लिए विशेषज्ञों की भी राय ली जाए और क्रय करते समय वित्तीय अनुशासन एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में वाद्य यंत्र क्रय करने के लिए कार्यवाई शुरू कर दी गयी है। पर्यटन मंत्री ने रेडियों जयघोष की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए कार्यवाई शुरू की जाए। उन्होंने बताया कि रेडियो जयघोष की क्षमता बढ़ने से दूरस्थ स्थानों तक रेडियों जयघोष के कार्यक्रमों का श्रोताओं को लाभ मिलेगा। बैठक में यह भी बतायागया कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा रिसोर्ट होटल से समन्वय किया जा रहा है तथा उप्र लोक जनजाति संस्कृति संस्थान के माध्यम से स्थानीय रिसोर्ट-होटल से समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

नवंबर माह में जिलों के विकास खण्डों में 1,111 प्रेरणा दिवस का हुआ आयोजन

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

❖ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की पहलः हर मंगलवार मनाया जा रहा है 'प्रेरणा दिवस'

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मिशन निदेशक दीपा रंजन ने बताया कि नवंबर माह में जिलों के विकास खण्डों में 1111 प्रेरणा दिवस का आयोजन किया गया। इनमे 32,413 कैडर एवं 3164 कर्मचारियों ने भाग लिया। बैठक में 836 शिकायत एवं सुझाव प्राप्त हुए, इसमें से 754 का निस्तारण कर दिया गया। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत 9,04,250 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। इसके अलावा 63,288 ग्राम संगठन एवं 3262 संकुल स्तरीय संघ का गठन किया गया है। इनमे ग्रामीण परिवारों की 99,21,175 महिलाएं लाभान्वित हो रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की पहल व उनके कुशल मार्गदर्शन मे उत्तर प्रदेश मे महिला सशक्तिकरण व स्वालम्बन की दिशा मे क्रान्तिकारी कदम उठाये जा रहे है। स्वयं सहायता समूहो के माध्यम से महिलाओं को जोड़कर उन्हे विभिन्न गतिविधियों व क्रियाकलापो के माध्यम से न केवल स्वावलम्बी बनाया जा रहा है, बल्कि उन्हे लखपति दीदी की श्रेणी मे लाने के भरसक प्रयास किये जा रहे हैं। समूहो की दीदियो को विभिन्न विभागो से समन्वय कर उनकी आमदनी मे इजाफा किया जा रहा है। दीदियो को उनके क्रियाकलापो व गतिविधियों मे किसी प्रकार की दिक्कत या अवरोध न आने पाये, उन्हे किसी प्रकार की कठनाई न होने पाये, इस दिशा मे उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य सोच व मन्शा के अनुरूप विकास खण्ड स्तर पर प्रत्येक मंगलवार को 'प्रेरणा दिवस' का आयोजन किया जा रहा है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से मिली जानकारी के अनुसार विकासखंड स्तर पर प्रत्येक महीने के प्रथम मंगलवार को समूह सखी, द्वितीय मंगलवार को बैंक सखी, एफएलसीआरपी (वित्तीय साक्षरता सामुदायिक संसाधन व्यक्ति) एवं विद्युत सखी, तृतीय मंगलवार को अजीविका सखी एवं उद्योग सखी और चतुर्थ मंगलवार को एफएनएचडब्ल्यू सीआरपी(खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य, एवं स्वछता संसाधन व्यक्ति) की समीक्षा बैठक प्रेरणा दिवस के रूप में आयोजित की जा रही है।

युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने पाई नई सीख और प्रेरणा

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मेरा युवा भारत, लखनऊ द्वारा आयोजित अंतर जनपद युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के चौथे दिन प्रतिभागी युवाओं ने राजधानी लखनऊ का व्यापक शैक्षिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भ्रमण किया। पूरे दिन युवाओं में उत्साह और जिज्ञासा देखते ही बन रही थी।

भ्रमण के दौरान सभी प्रतिभागियों ने जनेश्वर मिश्र पार्क, अम्बेडकर स्मारक पार्क, रेजीडेंसी, बड़ा इमामबाड़ा और लखनऊ संग्रहालय जैसे प्रमुख स्थलों का अवलोकन किया। प्रत्येक स्थल पर अधिकारियों एवं विशेषज्ञों ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक महत्व और प्रशासनिक व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी, जिससे युवाओं की दृष्टि और ज्ञान में सार्थक विस्तार हुआ। युवाओं ने न केवल लखनऊ की सांस्कृतिक विरासत को नज़दीक से जाना, बल्कि आधुनिक शासन तंत्र और राज्य की विकास यात्रा को भी समझा।

प्रतिभागी युवाओं ने इस अनुभव को अत्यंत प्रेरक और ज्ञानवर्धक बताते हुए कहा कि इस प्रकार का अवसर उनके नेतृत्व कौशल, सामाजिक समझ और व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेरा युवा भारत, लखनऊ के उप निदेशक ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय एकता, सकारात्मक दृष्टिकोण, प्रशासनिक समझ और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देना है।

आप निकालेगी 'वोट बचाओ संविधान बचाओ' पदयात्राः संजय सिंह

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

❖ 21 से रामपुर, मुरादाबाद और अमरोहा जिलों से होकर गुजरेगी पदयात्रा

❖ 7500040004 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर आम आदमी पार्टी की पदयात्रा में शामिल हो सकते हैं नागरिक

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में तीन करोड़ से ज्यादा वोट काटने की तैयारी चल रही है। यह सिर्फ वोट नहीं, बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर सीधा हमला है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा था, तब हर नागरिक को समान वोट का अधिकार दिया – राष्ट्रपति का वोट भी एक और गांव के मजदूर किसान का वोट भी एक। आज वही सबसे बड़ा अधिकार भाजपा सरकार द्वारा छीना जा रहा है। इसी अन्याय और वोट चोरी के खिलाफ आम आदमी पार्टी 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक रामपुर से अमरोहा तक "वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा" निकाल रही है।

आप सांसद ने कहा कि जो भी नागरिक इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं, वे मोबाइल नंबर 7500040004 पर मिस्ड कॉल देकर इसमें शामिल हो सकते हैं। संजय सिंह ने कहा कि संविधान में दिया गया यह सबसे बड़ा मौलिक अधिकार आज जनता से छीना जा रहा है। भाजपा लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश रच रही है।

नोएडा एयरपोर्ट से पश्चिमी यूपी की अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार, हजारों नौकरियों का रास्ता खुला

पायनियर समाचार सेवा। जेवर (गौतमबुद्धनगर)

❖ परियोजना में टाटा प्रोजेक्ट्स, इंडियन ऑयल और बर्ड ग्रुप सहित 30 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों की सहभागिता

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (ठक्अ) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मजबूत नेतृत्व और दूरदर्शी सोच का श्रेष्ठ उदाहरण बनने जा रहा है। यह विश्वस्तरीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट न सिर्फ दिल्ली-एनसीआर की वैश्विक कनेक्टिविटी को नई दिशा देने वाला है, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति देने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने परियोजना की प्रगति की लगातार समीक्षा करते हुए इसके समयबद्ध निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, ताकि जिन किसानों और परिवारों ने अपनी भूमि देकर इस सपने को साकार किया है, उन्हें अधिकतम लाभ मिल सके।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के सीईओ राकेश कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर परियोजना प्रभावित परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए विशेष कार्यक्रम लागू किए गए हैं। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. (ठक्अछ) के नेतृत्व में पीपीपी मॉडल के तहत चल रही इस परियोजना में टाटा प्रोजेक्ट्स, इंडियन ऑयल और बर्ड ग्रुप सहित 30 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों की सहभागिता है। लगभग 5,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनमें न्यूनतम मजदूरी, पीएफ, ईएसआई और ग्रेच्युटी जैसे सभी सरकारी लाभ शामिल हैं। पीएएफ युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए ऑनलाइन करियर पोर्टल पर 180 से अधिक उम्मीदवारों का पंजीकरण किया जा चुका है। तीन विशेष भर्ती शिविरों में 300 से अधिक युवाओं ने प्रतिभाग किया, जिनमें से 24 युवाओं को ऑफर लेटर जारी हुए हैं। यही नहीं, कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए आईटीआई जेवर को आधुनिकीकृत किया गया है, जहां पैसेंजर हैंडलिंग और रैंप ऑपरेशंस जैसे कोर्स संचालित किए गए।

प्रयोगात्मक परीक्षकों की हो मैपिंग प्रक्रिया पूर्ण

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग ने अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा, दिसम्बर-2025 की तैयारियों को गति देते हुए समस्त जिलाधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि लेफ्टओवर/सप्लीमेंटी श्रेणी की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 15 दिसम्बर से 19 दिसम्बर तक आयोजित की जाएंगी। इसके लिए प्रेक्टिकल एक्जाम्नर मैपिंग की अनिवार्य समय-सीमा 9 दिसम्बर से 26 दिसम्बर निर्धारित की गई है, जिसे परीक्षा से पूर्व पूर्ण किया जाना है। प्रमुख सचिव ने बताया कि डीजीटी, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रेक्टिकल एक्जाम्नर मैपिंगॅ केवल उन परीक्षकों की की जाएगी जो एसआईडीएच पोर्टल पर विधिवत पंजीकृत हों। यदि किसी जनपद में पंजीकृत परीक्षकों की संख्या पर्याप्त नहीं है, तो नोडल राजकीय आईटीआई की अध्यक्षता में गठित समिति ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करेगी तथा अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेख, योग्यता तथा अनुभव की जांच कर अनुमोदन सुनिश्चित करेगी।

इस उद्देश्य से तीन सदस्यीय समिति गठित की गयी है जिसमें जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य (अध्यक्ष), नोडल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रधानाचार्य (सदस्य), तथा जनपद के अन्य राजकीय आईटीआई के प्रधानाचार्य/वरिष्ठतम कार्यदेशक (सदस्य) हैं। यह समिति डीजीटी के निर्धारित मानकों के अनुसार ही परीक्षकों का चयन सुनिश्चित करेगी ताकि प्रयोगात्मक परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हो सके।

प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम ने सभी जिलाधिकारियों को से कहा है कि अधिक से अधिक परीक्षकों को एसआईडीएच पोर्टल पर पंजीकरण के लिए प्रेरित किया जाए तथा परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार मैपिंग की प्रक्रिया निर्धारित समय में पूर्ण की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रयोगात्मक परीक्षाओं में किसी प्रकार की देरी या परीक्षकों की कमी न होने पाए, इसके लिए संबंधित नोडल प्रधानाचार्य समयबद्ध रूप से कार्यवाही करें।

नौकरी और रोजगार भाजपा के एजेंडे में नहीं हैः अखिलेश यादव

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि नौकरी और रोजगार भाजपा के एजेंडे में नहीं है। भाजपा नौजवानों और युवाओं को लगातार धोखा दे रही है। भाजपा सत्ता से हटेगी तभी नौजवानों को नौकरियां रोजगार मिलेगा।

अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों के प्रस्तावित आंदोलन को नैतिक रूप से समर्थन देते हुए कहा कि हमारा समर्थन प्रतियोगी छात्रों के साथ हमेशा रहा है और रहेगा। ये राजनीति का नहीं युवाओं के भविष्य का सवाल है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। छात्र-नौजवान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते-करते निराश और हताश हो चुके हैं। शिक्षा विभाग से लेकर प्रदेश सरकार के तमाम विभागों में बड़ी संख्या में पद खाली हैं लेकिन भाजपा सरकार भर्तियां नहीं कर रही है। बड़ी संख्या में छात्र-नौजवान लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही है। भाजपा सरकार नौजवानों से झूठे वादे करती आ रही है।

भाजपा नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर बात नहीं करती है। वह समाज को बांटने और आपस में लड़ाने के लिए नए-नए मुद्दों में उलझाए रखना चाहती है। भाजपा विवादी पार्टी है। हर जगह विवाद खोजती है। झगड़ा लगाती है। जनता के मुद्दों से ध्यान हटाने का कार्य करती है।

बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट का लोकार्पण स्वास्थ्य तंत्र को देगा नई दिशाः आनंदीबेन

❖ राज्यपाल ने केजीएमयू के क्लिनिकल हिमेटोलॉजी विभाग में स्थापित बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट का लोकार्पण

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि केजीएमयू में बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट का लोकार्पण उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य तंत्र को नई दिशा देगा और आधुनिक, उन्नत व विश्वस्तरीय चिकित्सा को और अधिक सुलभ बनाएगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह यूनिट अनगिनत परिवारों के जीवन में नई रोशनी लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट का उपचार अभी भी अत्यंत महंगा है, और कई गरीब मरीज आर्थिक

अभाव में उपचार से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में केजीएमयू की यह यूनिट प्रदेश ही नहीं, बल्कि दूर-दराज़ राज्यों के मरीजों के लिए भी जीवनदायी सहारा बनेगी।

राज्यपाल गुरुवार को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के क्लिनिकल हिमेटोलॉजी विभाग में स्थापित बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट का लोकार्पण कर रही थी। यह यूनिट आदित्य बिरला कैपिटल फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त सीएसआर सहयोग से विकसित की गई है। उन्होंने कहा कि रक्त विकार किसी जाति, वर्ग, आयु या सीमाओं में बंधे नहीं होते। ये रोग अबोध बच्चों की मुस्कान, युवाओं के सपनों और परिवारों की धैर्यशक्ति पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया और एप्लास्टिक एनीमिया जैसे गंभीर रोग समय पर उपचार न मिलने पर जीवन के लिए चुनौती बन जाते हैं, और ऐसे में अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण अंतिम आशा के रूप में सामने आता है।

राज्यपाल ने कहा कि भारत जैसे विशाल देश में प्रतिवर्ष लाखों रोगियों को प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है, परंतु सीमित सुविधाओं के कारण विशेषकर उत्तर प्रदेश में कई मरीजों को लंबी प्रतीक्षा और दूर-दराज़ की यात्रा का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में केजीएमयू लखनऊ में बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट की स्थापना प्रदेश और देश के लाखों जरूरतमंद परिवारों के लिए नई आशा लेकर आई है। राज्यपाल ने केजीएमयू की कुलपति पद्मश्री डॉ. सोनिया नित्यानंद की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से एसजीपीजीआई, डॉ. राम मनोहर लोहिया संस्थान और अब केजीएमयू में प्रत्यारोपण इकाइयों की स्थापना संभव हो सकी है।

उन्होंने आदित्य बिरला कैपिटल फाउंडेशन की अध्यक्ष राजश्री बिरला का भी आभार व्यक्त किया, जिनके सीएसआर सहयोग से हेपा-फिल्टर युक्त स्वच्छ कक्षों का विस्तार किया जा रहा है। राज्यपाल ने कैनकिड्स किड्सकैन संस्था द्वारा बच्चों के कैंसर उपचार में दी जा रही परामर्श, पोषण, औषधि सहायता और देखभाल सेवाओं की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जब विज्ञान संवेदना से जुड़ता है और संस्थाएं सेवा का संकल्प लेकर कार्य करती हैं, तभी एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है।

लोकमानस

loksatta@expressindia.com

पुतळे उभारले की झाले?

'या चिनी आक्रमणाचे काय?' हा अग्रलेख (११ डिसेंबर) वाचला. चीनने अथक मेहनतीच्या जोरावर उत्पादन, व्यापार, वैज्ञानिक व लष्करी क्षेत्रांत प्रगती केली त्यामुळे अमेरिकी निर्बंधांना धूप न घालता तो थेट अंकल सॅमलाच प्रतिआव्हान उभे करू शकला. तेवढ्याच लोकसंख्येचा (व चीनच्याच सुमारास स्वतंत्र झालेला) भारत मात्र वरील आघाड्यांवर सातत्याने निराशाजनक कामगिरी करत आहे.

मागील दशकभरापासून भारताने मुख्यतः पाकिस्तानवर लष्करी कुरघोडीचे मर्यादित लक्ष्य ठेवले पण तेही धडपणे साध्य होऊ शकले नाही. या काळात भारतीय नेतृत्व राजकीय फायद्यासाठी बहुसंख्यांच्या धार्मिक भावना गोंजारणे, भूतकालीन घटनांची निष्फळ उजळणी करणे व पूर्वीच्या राज्यकर्त्यांवर खापर फोडत दुर्बल विरोधकांना नमवणे यांतच धन्यता मानत राहिले. आज उपरोल्लेखित व त्याव्यतिरिक्त इतर अनेक आघाड्यांवर चीनच्या तुलनेत भारताची पीछेहाट होत असताना संसद व देशाचे हिरिरीचे चर्चाविषय नेहरू व बंकिमचंद्र आहेत, यावरूनच काय तो बोध घ्यावा. चीन स्वबळावर प्रचंड क्षमतेची संमीलन अणुभट्टी उभारत असताना भारत मात्र मोठमोठ्या मूर्ती व पुतळे उभारण्यात समाधानी आहे हा केवळ योगायोग नव्हे. नेते देशासाठी जी दीर्घकालीन धोरणे आखतात त्यांची बरीवाईट फळे भविष्यात अटळपणे मिळतात. त्यामुळे मोठी अंगभूत क्षमता व लोकसंख्येचा लाभांश असलेले तरुण हाताशी असूनही नेतृत्वाची दिशा भरकटल्याने भारत अग्रलेखातील चिनी आक्रमण रोखण्यात अपयशी ठरला आहे व यात लवकर बदल संभवत नाही.

■ **अरुण जोगदेव,** दापोली (रत्नागिरी)

चीनकडून स्वस्त उत्पादनाचा धडा घ्यावा

'या चिनी आक्रमणाचे काय?' हे संपादकीय वाचले. चीनने स्वस्त उत्पादनांची निर्मिती करून जागतिक बाजारपेठ जवळजवळ बळकावली आहे. इलेक्ट्रॉनिक, स्टेशनरी, कापड, गृहोपयोगी उपकरणे इत्यादी अनेक क्षेत्रांत चीनने बाजी मारली आहे.

भारताची आयात- निर्यात पाहता व्यापारातील तूट हा आपल्यापुढील गहन प्रश्न आहे. त्यामुळे दरवर्षी भारतातून मोठ्या प्रमाणात संपत्ती परदेशात जात आहे. हीच परिस्थिती कित्येक वर्षे आहे. असा देश श्रीमंत देश किंवा महाशक्ती कसा होणार? उलट देश गरीब होत चालला आहे. चीनप्रमाणे कमी खर्चात उत्पादनाची व्यवस्था उभी करणे हाच उपाय आहे. चीनने स्वस्त उत्पादन प्रक्रियेसाठी नाममात्र किमतीत जमीन, स्वस्तात वीजपुरवठा, माल वाहतूक वाढण्यासाठी रस्ते यांचा विकास केला. त्यामुळे तिथे प्रचंड उत्पादन कमी किमतीत होते. यावरून भारताने धडा घ्यावा.

■ **अरविंद जोशी,** पुणे

निर्यातक्षम उत्पादनांच्या निर्मितीवर भर हवा

'या चिनी आक्रमणाचे काय?' हा अग्रलेख वाचला. चीनच्या यशामागे काही प्रमुख कारणे आहेत. निर्यातवाढीकरता संशोधन, गुंतवणूक, कौशल्य विकास, उत्पादन आणि वितरण ही साखळी योजनापूर्वक बांधावी लागते. त्यातील परस्पर देवाणघेवाण (बॅकवर्ड आणि फॉरवर्ड लिंकेजेस) ठरल्याप्रमाणे व्हावी लागते. यासाठी नेतृत्वाकडे दूरदृष्टी असणे, नेतृत्व कर्तव्यकठोर असणे गरजेचे असते. चीनला ते करता आले. भारताला लोकशाही रचनेतदेखील हे करणे शक्य आहे, पण त्याकरता शासनाला आयात-निर्यात क्षेत्रात खासगी उद्योजकांना खुली सूट द्यावी लागेल. वरील साखळी व्यवस्थित चालली तर भारत मागे पडणे शक्य नाही. जागतिक व्यापारात कोणत्याही देशाची दीर्घकाळ मक्तेदारी चालू शकत नाही. आयात कर वाढवूनसुद्धा आपण अमेरिकेत तांदूळ ओतू शकतो. याचा अर्थ निर्यातक्षम उत्पादने देशांतर्गत गरज भागवून खूप मोठ्या प्रमाणात निर्माण करणे गरजेचे आहे. निती आयोगाने हा प्रश्न सर्व संबंधित क्षेत्रीय संघटनांशी चर्चा करून भारताला स्पर्धाक्षम करण्यात पुढाकार घेतला पाहिजे.

■ **श्रीकृष्ण फडणीस,** दादर (मुंबई)

ही तर मक्तेदारीच्या जोरावर मुजोरी

'नियामकांचे नाकर्तेपण' हे संपादकीय (९ डिसेंबर) आणि 'इंडिगोचे संकट की नियामक व्यवस्थेचे अपयश?' हा लेख (११ डिसेंबर) वाचला. वैमानिक आणि इतर एअर क्रू यांच्या कामाचे तास कमी करणारी नियमावली जाहीर केली तेव्हा त्यानुसार नियोजन करणे ही संबंधित तज्ज्ञांची जबाबदारी होती. त्याहीपेक्षा डीजीसीएनामक नियामकांचा नाकर्तेपणा अक्षम्य ठरतो. नियामक संस्था अर्धनियामक असल्याने इंडिगोला जाब विचारणे आणि दंड करणे हा त्यांचा अधिकार आहे. तसेच नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाकडे योग्य अहवालासह एअरलाइनविरुद्ध कारवाई करण्याची शिफारस करण्याचाही पर्याय होता. परंतु इंडिगोने मक्तेदारीच्या ताकदीवर नियामक आणि सरकार यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्याची मुजोरी केली.

वैमानिक व कर्मचारी आणि लाखो प्रवाशांना वेठीस धरून नफ्याचे मार्जिन कमी होऊ नये म्हणून नियामकाचे मनगट पिरगळत जणूकाही सरकारला वाकुल्या दाखविल्या. भारताच्या विकास प्रक्रियेत भांडवल केंद्रस्थानी आणि प्रभावी झाल्याने सर्व क्षेत्रांत मक्तेदारी निर्माण झाली आहे. हे मुक्त अर्थव्यवस्थेचे विकृतीकरण असून कणाहीन नियामक आणि हतबल सरकार हे वेळोवेळी निष्प्रभ सिद्ध होत आहे. विविध अपघातांत नंतर चौकशीअंती कोणाला शिक्षा झाल्याचे ऐकिवात नाही. नुकतेच गोव्यात नाइट क्लब आगीत २५ जणांनी प्राण गमावले, पण मालक परदेशी फरार झाले. भांडवलावर अधिकाधिक नफा मिळविण्यासाठी अशा मक्तेदार कंपन्या कर्मचाऱ्यांचे शोषण करतात आणि ग्राहकांना वेठीस धरतातच यासाठी स्वायत्त नियामक आणि पारदर्शक कारभार आवश्यक आहे.

■ **ॲड. वसंत नलावडे,** सातारा

तात्पुरत्या नव्हे, दीर्घकालीन योजनांची गरज

'प्रश्न बिबट्यांचा असो की श्वानांचा' हा 'अन्वयार्थ' वाचला. विधिमंडळातील सदस्यांना या प्रश्नाचे गांभीर्य वाटत नाही. आज पुण्यामध्ये बिबट्यांमुळे दहशत निर्माण झाली आहे. एक कोटीपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या या शहरास हे परवडणारे नाही. यावर तात्पुरती उपाययोजना करण्याऐवजी सरकारने त्यावर गांभीर्याने दीर्घकालीन उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. न्यायालयाने मोकाट कुत्र्यांबाबत प्रश्न विचारले आहेत. मोकाट कुत्रे आणि डुकरे यांच्यामुळे दहशत आणि रोगराई पसरते.

■ **सुदर्शन महिंद्रकर,** सोलापूर

कोण कोणाच्या अधिवासात शिरले?

'प्रश्न बिबट्यांचा असो की श्वानांचा' हा 'अन्वयार्थ' वाचला. वाट्टेल तशा उपाययोजना आखून बिबट्या आणि श्वानांचा प्रश्न सुटणार नाही. वनमंत्री म्हणतात बिबट्यांचा उपद्रव इतका वाढला आहे, तर जंगलामध्ये शेळ्या सोडल्या जाव्यात. त्यासाठी एक कोटीचा निधीही घोषित केला गेला. असे तोडगे काढण्यापेक्षा कायमस्वरूपी उपाययोजना केल्या तर बिबट्यांचे हल्ले कमी होतील. जंगल हा त्यांचा अधिवास आहे. त्यावर आपण- मानवाने केलेल्या अतिक्रमणामुळे तो आक्रसत आहे. बिबटे शहरात येतात की आपण त्यांच्या घरात शिरतो आहोत, याचाही विचार व्हावा. भटक्या श्वानांच्या विषयावरसुद्धा गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. भटक्या प्राण्यांना प्राणीमित्रांच्या घरी सोडावे, हे विधान विधिमंडळात करणे कितपत योग्य आहे? मध्यंतरी भटक्या श्वानांची नसबंदी करून त्यांना सोडून दिले जात असे. हा उपाय किती परिणामकारक ठरला, याचा विचार करावा.

■ **प्रथमेश सोलकर,** संगमेश्वर (रत्नागिरी)

नोकरी दिल्याने बिबट्यांचे हल्ले थांबतील?

'प्रश्न बिबट्यांचा असो की श्वानांचा' हा 'अन्वयार्थ' (११ डिसेंबर) वाचला. महाराष्ट्रात कोणतीही समस्या निर्माण झाली की त्यावर दीर्घकालीन उपाय केले जात नाहीत. त्यामुळे पुन्हा पुन्हा तेच प्रश्न डोके वर काढत राहतात. अर्थव्यवस्था मजबूत नसताना लाडक्या बहिणींसाठी पैसे वाटप केले जातात. माणसांना संरक्षण मिळण्यासाठी बिबट्यांचा अधिवास वाढवण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे परंतु त्याऐवजी जंगले तोडली जातात. बिबटे आणि कुत्रे यांची नसबंदी करणे हा एक उत्तम मार्ग आहे. प्राणीतज्ज्ञांशी चर्चा करून दीर्घकालीन उपाय करणे गरजेचे आहे, पण वनमंत्री गणेश नाईक बिबट्यांच्या हल्ल्यात बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबातील एकाला सरकारी नोकरी देऊ अशी घोषणा करून मोकळे झाले. नोकरी दिल्याने बिबट्यांचे हल्ले कमी होणार आहेत का?

■ **उज्ज्वला मालाडकर,** बाणेर (पुणे)

काहीच न करण्याचे दिवस

प्रत्येक वेळी स्लोअरचे उत्तर होते, 'मला खरंच काहीच न करण्यासाठी रजा घ्यायची आहे.' अखेर वाक्यांच्या आणखी काही लकेरी एकमेकांकडे भिरकावल्यानंतर 'एचआर' सहकाऱ्याने एक मध्यममार्ग काढला. म्हणाला, ''माझ्या नोकरीतील 'केआरए'चा सवाल आहे सर. रजेचे कारण म्हणून किमान 'रिक्रिएशन' इतके तरी लिहा.'' अखेर स्लोअर मोठा उसासा टाकून 'हो' म्हणाला. एचआर सहकाऱ्याचा जीव भांड्यात पडला...

लोक-लोलक

सिद्धार्थ केळकर
siddharth.kelkar
@expressindia.com

नव्या सहस्रकात स्लोअर शहाणेच्या नोकरीपश्चात आयुष्यात सुट्टीला समानार्थी शब्द म्हणून रजा या संज्ञेचा समावेश झाला, तेव्हा प्रथम त्याला रजाऐवजी वजा असे ऐकू येऊन, त्याने रजेच्या अर्जावर 'वजेचा अर्ज' असे लिहिले होते. म्हणजे त्याला रजा हा शब्दच माहीत नव्हता असे नाही; पण त्या संज्ञेचे वजन, महत्त्व (आणि बिनमहत्त्वही) इत्यादी त्याला आकळले नव्हते. पण, कार्यालयीन कामकाजातील श्रुतलेखनात रजाऐवजी वजा ऐकू आले म्हणून फार काही बिघडले नाही - तो अर्ज फाडून नवा लिहावा लागला हे सोडून. रजाऐवजी वजा ऐकू आल्याने स्लोअर शहाणेने त्याच्या स्वभावानुसार रजेचा अर्थ वजेच्या वजनानुसार समजावून घेतला, हा उलट यातील बोनस. 'काम वजा आपण, बरोबर रजा' असा अर्थ बरोबर आणि 'आपण वजा काम बरोबर रजा' हेही चूक नाही. रजा म्हणजे आपण कामातून किंवा काम आपल्यातून वजा होणे!

तर, स्लोअर शहाणेला नोकरीपश्चात रजेचा अर्थ कळला तो असा. आता पुढचा टप्पा होता, रजेचा अर्ज लिहिण्याचा. पहिला अर्ज फाडल्याने त्याने नवा अधिक काळजीपूर्वक लिहिला. नाव, पत्ता, संपर्क क्रमांक वगैरेंवर अडण्यासारखे काही नव्हते, त्यामुळे ते झटक्यात लिहून झाले. स्लोअरचे पेन अडले, ते 'रजेचे कारण' या रकान्यापाशी. म्हणजे आपल्यातून काम किंवा कामातून आपण वजा होण्यासाठीही कारण असावे लागते? लगेच त्याला प्रश्न पडला. त्याची रजेचा अर्ज लिहितानाची प्रश्नार्थक मुद्रा पाहून त्याच्याच कार्यालयातील मनुष्यबळ विकासासाठी अपेक्षिलेल्या आणि 'एचआर' अशा गोंडस नावाने सुपरिचित असलेल्या विभागातील एका सहकाऱ्याने त्याच्यापाशी येऊन त्याला समजवायला घेतले.

सहकारी : रजेला काही तरी कारण असणे हा नव्या जगाचा नियम आहे. तुम्ही कशासाठीही टाकलेले एकेक पाऊल जिथे स्मार्ट वॉच किंवा तुमचा मोबाइल फोन मोजणार आहे आणि त्याचे बरे-वाईट परिणाम सांगणार आहे, तिथे कोणतीच कृती विनाकारण करणे आता शक्य नाही.

स्लोअर : रजा घेतली, तरी काही तरी कृती करायची, असे कसे? रजा तर काम न करण्यासाठी घ्यायची ना?

सहकारी : बरोबर. कार्यालयीन काम करूच नका. ते करणे अपेक्षितही नाही. पण, ते करणार नाही, तर इतर काही तरी करणारच ना?

स्लोअर : नाही, इतरही काही करणार नाही.

सहकारी : (आश्चर्याने) असे कसे? तुम्ही सहलीला जाल, ट्रेकिंग कराल, लग्नाला जाल, इतर कुठल्या समारंभाला जाल... असे काही तरी कारण असेलच की?

स्लोअर : नाही, असे काहीच कारण नाही. मला काहीच करायचे नाही, म्हणून मला रजा घ्यायची आहे. मी तसे लिहिले तर चालणार नाही का?

सहकारी : सर, ते आपल्या धोरणात बसत नाही. रजेच्या काळात तुम्ही काहीच न करणे, हे तुम्ही रजेनंतर कामावर आल्यावर तुमच्या उत्पादकतेवर परिणाम करणारे असू शकते. त्याचा परिणाम तुमच्या कामगिरीच्या मोजमापावर, पर्यायाने बोनस आणि पगारवाढीवर आणि शिवाय सीव्हीवरही होऊच शकतो. सगळ्याच कंपन्या आता याचा गांभीर्याने विचार करतात.

स्लोअर : पण, काहीच न करण्यात गांभीर्य नाही, असे कसे म्हणता येईल?...

'एचआर'मधल्या त्या सहकाऱ्याला स्लोअरने उत्तरादाखल विचारलेला हा प्रश्न काही केल्या पचनी पडला नाही. आपण या तात्त्विक चर्चेत फार वेळ घालवला, तर आपल्या कामाचा वेळ अनुत्पादक ठरून आपल्याच बोनस आणि पगारवाढीवर गंडांतर यायचे, असा विचार करून त्याने हा संवाद तात्त्विक अंगाने पुढे न नेता, आणखी काही पद्धतींनी प्रश्न विचारून स्लोअरकडून रजेचे कारण काढून घेण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. पण, व्यर्थ! प्रत्येक वेळी स्लोअरचे उत्तर होते, 'मला खरंच काहीच न करण्यासाठी रजा घ्यायची आहे.' अखेर वाक्यांच्या आणखी काही लकेरी एकमेकांकडे भिरकावल्यानंतर 'एचआर' सहकाऱ्याने एक मध्यममार्ग काढला. म्हणाला, 'माझ्या नोकरीतील 'केआरए'चा सवाल आहे सर. रजेचे कारण म्हणून किमान 'रिक्रिएशन' इतके तरी लिहा.' स्लोअरने डोके खाजवले आणि मनात म्हणाला, 'झाले तेवढे 'मनोरंजन' खरे तर पुरेसे आहे. पण, 'रिक्रिएशन' शब्दाला किमान नवनिर्मितीची थोडी फार अर्थच्छटा आहे, तर रजेचे कारण याविषयीच काही नवनिर्मिती करता येते का, याचा विचार रजेच्या काळात करता येईल, तेव्हा हे कारण लिहायला हरकत नाही.' स्लोअर मोठा उसासा टाकून 'हो' म्हणाला. एचआर सहकाऱ्याचा जीव भांड्यात पडला.

अशा प्रकारे स्लोअरची रजा सुरू झाली. पहिल्या दिवशी स्लोअर अंथरुणातून न उठता मानेखाली दोन उशा घेऊन पडून राहिला. आहे तिथूनच डोळे, मान जेवढे वळतील, तेवढे वळवून, तो ज्या खोलीत पहुडला होता, ती खोली तो पाहू लागला. त्याने फरशा, छप्पर, पंखा, दिवे, दार, उंबरठा, कपडे वाळत घालायची दांडी, गॅलरीचे उघडे दार, कडी-कोयंडा, खिडकी, पडदा, दूरध्वनी संच, टेबल, खुर्ची, दूरचित्रवाणी संच, उशा, पांघरुणे, कपाट इत्यादी सगळे सगळे, सहलीला गेल्यावर 'साइट सीइंग' करतात, तसे पडल्या पडल्याच 'पाहून' घेतले. कोणतीही गोष्ट पाहताना त्याला सर्वांत पहिली जाणीव झाली, ती म्हणजे रोज कितीही साफसफाई केली, तरी प्रत्येक गोष्टीवर थोडी फार का होईना धूळ आहे. त्याला ती पुसावीशी वाटल्याने तो अंथरुणातून उठला आणि त्याने फडके घेऊन धूळ पुसायला सुरुवात केली. त्यासाठी प्रत्येक वस्तूजवळ जाऊन त्याने त्या वस्तूला हात लावून पाहिला. बऱ्याच वस्तूंबाबत त्याला असे लक्षात आले, की बराच काळ त्याने त्या वस्तूंना समोर दिसत असूनही प्रत्यक्ष स्पर्श केलाच नव्हता. मग त्याने स्वतःला त्या स्पर्शात सामावून घेतले, रमवून घेतले... रिक्रिएशन!

पुसापुशी झाल्यानंतर स्लोअर स्वयंपाकघरात गेला, तिथल्या वस्तू न्याहाळतच त्याने चहा केला, कपात ओतून घेऊन तो गॅलरीत गेला. मनाशी म्हणाला, 'गॅलरीतून आपण नेहमीच 'बाहेर' पाहतो. आज जरा 'आत' पाहून बघू.' आत पाहताना स्लोअरला लक्षात आले, की गॅलरी आणि त्याला लागून असलेल्या खोलीतील एकाही कोपऱ्यात आजपर्यंत आपण बसलेलो नाही. ती 'स्पेस' कशी आहे, हेच आपल्याला माहीत नाही. चहा संपवून तो सरळ प्रत्येक कोपऱ्यात जाऊन काही मिनिटे बसला. प्रत्येक कोपऱ्यातून बाकीची खोली त्याला वेगळी 'दिसली'. मग इतर खोल्यांत जाऊन त्याने याच 'पाहणी'ची उजळणी केली. सगळे 'पाहून' झाल्यावर स्लोअर मनाशी म्हणाला, 'आपल्या घरातील खोलीचा प्रत्येक कोपरा किती समृद्ध आहे! प्रत्येक कोपऱ्यातून 'वेगळे' घर दिसते.' स्लोअरने बराच काळ स्वतःला या 'वेगळ्या' विचारात सामावून घेतले, रमवून घेतले... रिक्रिएशन!

संपूर्ण घर पाहून झाल्यावर संध्याकाळी स्लोअर त्याची सदनिका असलेल्या सोसायटीच्या मुख्य प्रवेशद्वारापाशी जाऊन थांबला. संध्याकाळी सोसायटीसमोरील रस्त्यावरून जाणारी माणसं न्याहाळू, अशा कल्पनेने जिना उतरतानाच त्याच्या मनात 'घर' केले होते. मग त्याने तसेच केले. गाडीतून जाणारे, गाडीवरून जाणारे, पायी जाणारे असे बरेच जण दिसले. स्लोअरचे लक्ष त्यांच्या चेहऱ्यावर खिळले. कुणी स्वतःशी हसत, कुणी स्वतःशी बोलत, कुणी स्वतःशी लाजत, कुणी स्वतःशी वैतागत, कुणी स्वतःला गोंजारत, कुणी स्वतःला समजावत... रस्त्यावरून जातच होते. म्हणजे त्यांच्या डोळ्यांत तरी स्लोअरला तसेच दिसत होते. त्याची ही 'पाहणी' चालू असतानाच अचानक त्याचा मित्र 'क्लेव्हर' त्याच्या समोर येऊन उभा ठाकला. त्याच्या चेहऱ्यावर स्मितहास्य होते. 'अचानक इकडे कुठे,' असे स्लोअर विचारणार हे गृहीत धरून (शेवटी क्लेव्हरच तो!), हा प्रश्न यायच्या आतच क्लेव्हर म्हणाला, 'आज इकडे आलो चालत चालत... सहजच! रिक्रिएशन!' क्लेव्हरशी थोड्या फार इकडच्या तिकडच्या गप्पा झाल्या. क्लेव्हर निघतच होता, तेवढ्यात एक माणूस त्यांच्या समोरून चालत गेला. 'पाहणी'च्या मूडमध्ये असलेल्या स्लोअरने क्लेव्हरला त्याच मूडमध्ये प्रश्न केला, 'काय दिसतं तुला या माणसाच्या डोळ्यांत?' क्लेव्हर नेहमीप्रमाणे फक्त हसला आणि उत्तरला, 'शून्य!'

स्लोअरने पुढची संध्याकाळ आणि नंतर रात्रभर क्लेव्हरच्या उत्तरात स्वतःला सामावून घेतले, रमवून घेतले नाही... सकाळी उठल्यावर त्याला जाणवले, हे तर क्रिएशन! स्लोअर तडक कार्यालयात गेला. एचआर सहकाऱ्याला उरलेली रजा रद्द करायची आहे म्हणाला. एचआर सहकाऱ्याने नियमानुसार रजा रद्दचेही कारण विचारले. स्लोअर उत्तरला, 'क्रिएशन!'

ता.क. : स्लोअरने यानंतर रजा घेतलीच नाही. आयुष्यातून काम आणि कामातून तो वजा झालाच नाही. त्याच्या आयुष्यात काहीच न करण्याचे दिवस परत कधी आलेच नाहीत. ते न आल्याने 'रिक्रिएशन' होत राहिले, की नाही, हे कळायला मात्र काही मार्ग नाही!

कुतूहल

विषाणूची रोगकारक प्रथिन स्फटिके!

तंबाखूवर १८८६ साली आलेल्या एका रोगामुळे खूप नासाडी झाली. तंबाखूच्या पानांवर पिवळसर ठिपके पडत होते. त्यामुळे या रोगाला जर्मन शास्त्रज्ञांनी 'मोझाइक' असे नाव दिले. जर्मन कृषितज्ज्ञ ॲडॉल्फ मेयर यांनी एक साधा प्रयोग करून बघितला. या रोगट पानांचा रस त्यांनी निरोगी पानांत टोचला आणि निरोगी पानांतदेखील पिवळे ठिपके दिसू लागले. मग त्यांनी रोगट पानांचा रस ५५ अंश सेल्सियसपर्यंत तापवला आणि पुन्हा निरोगी पानांत टोचला. मात्र या वेळी झाड निरोगीच राहिले. त्यांनी या रोगाला जबाबदार रोगजंतूचा शोध घेण्याचा खूप प्रयत्न केला; परंतु याचे नेमके कारण ते सांगू शकले नाहीत.

वेन्डेल स्टॅन्ली

टोबॅको मोझाईक

रशियात १८९२ साली याच रोगामुळे तंबाखूची खूप नासाडी झाली. दिमित्री इवानोविच यांनी यावर संशोधन करताना 'चेंबरलँड गाळणी'तून रोगट पानांचा रस गाळून घेतला. या गाळणीची छिद्रे इतकी लहान असतात की यातून जिवाणूदेखील आरपार जाऊ शकत नाही. या गाळणीतून मिळालेला द्रव दिमित्रींनी निरोगी झाडाला टोचला. कालांतराने त्यांच्या लक्षात आले की निरोगी पानांतदेखील पिवळे ठिपके दिसताहेत. परंतु सूक्ष्मजीवाचे स्वरूप मात्र अनाकलनीयच राहिले.

पुढे डच संशोधक मार्टिनस बायजेरिंक यांनीही हा रोग जिवाणूमुळे होत नसून गाळणीतून पार होऊ शकणाऱ्या कुठल्या तरी अतिसूक्ष्म जंतूमुळे होत असावा असे मत मांडले. १९३५ साली अमेरिकन शास्त्रज्ञ वेन्डेल मेरेडिथ स्टॅन्ली (विषाणूशास्त्राचा पितामह) यांनी रोगट पानांच्या रसावर प्रक्रिया करून त्यातील अतिसूक्ष्म घटक स्फटिकांच्या रूपात वेगळे केले. ही स्फटिके निरोगी पानांत टोचली असता रोग उद्भवतो, हे त्यांनी दाखवून दिले. हा शोध क्रांतिकारी ठरला; कारण रोगास कारक सूक्ष्मजीवांचा शोध घेता घेता त्यातील निर्जीव प्रथिन स्फटिकांनीदेखील रोग निर्माण होतो हे जगाला प्रथम त्यांनी दाखवून दिले.

त्यानंतर काही काळाने असे सिद्ध झाले की, मोझाइकचा विषाणू (व्हायरस) हा प्रथिन स्फटिकांचा बनलेला असून त्यात रिबोन्यूक्लिक आम्ल म्हणजे आरएनएसुद्धा असल्याचे सिद्ध झाले. या शोधासाठी वेन्डेल स्टॅन्ली यास १९४६ सालचे नोबेल परितोषिक प्रदान करण्यात आले. १९४८ साली कॅलिफोर्निया विद्यापीठात जैवरसायन विभागात त्यांनी विषाणू प्रयोगशाळा सुरू केली. त्यालाच आता 'स्टॅन्ली हॉल' म्हणून संबोधले जाते.

विषाणू हे स्वतः प्रजननशील नसतात, परंतु सजीव पेशीत शिरकाव केल्यावर ते प्रजननक्षम होतात. यानंतर मोझाइक संरचनेमुळे आकर्षक दिसणाऱ्या अशा अनेक वनस्पती विषाणूजन्य रोगाने बाधित असल्याचे सिद्ध झाले.

– **डॉ. रंजन गर्गे**
मराठी विज्ञान परिषद
ईमेल : office@mavipa.org
संकेतस्थळ : www.mavipa.org

व्यक्तिवेध

हस्तिदंतांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर सध्या बहुतेक जगात पूर्ण बंदी आहे. आफ्रिकेतील काही देशांमध्ये रानटी हत्तींची संख्या प्रमाणाबाहेर वाढल्यास त्यांतील काहींना नाइलाजास्तव गोळ्या घालून ठार मारावे लागते. अशा प्रकारे मारलेल्या हत्तींचे दात अर्थात हस्तिदंतही आता जाळून टाकले जातात. ही खबरदारी आणि व्यापक संवेदनशीलता ज्यांच्यामुळे जगभर निर्माण झाली आणि रुजली, त्यांचे नाव इयन डग्लस-हॅमिल्टन. त्यांची मूळ ओळख हत्ती संवर्धक (कन्झर्व्हेशनिस्ट) अशी. पण त्यांना त्याऐवजी 'हत्ती संरक्षक' संबोधणे अधिक इष्ट, इतके त्यांचे मोठे कार्य आहे. त्यांनी हस्तिदंताच्या चोरट्या व्यापाराविरुद्ध जाणीव निर्माण केली नसती, तर एव्हाना अनेक देशांमधून हत्ती, त्यांच्या दातांसाठी अनियंत्रित शिकार होऊन नामशेष झाले असते. इतर काही देशांमध्ये नामशेषत्वाच्या कडेलोटापर्यंत ढकलले गेले असते. कारण हत्तींची संख्या झपाट्याने कमी होण्याच्या मुळाशी आहेत त्यांचे दात. पण त्याविषयी हत्ती काही करू शकत नाहीत! मात्र या हस्तिदंताचा व्यापार कमी करून, बंद करून आपण त्यांच्या संहाराला आवर घालू शकतो हे डग्लस-हॅमिल्टन यांनी अनेक वर्षे आफ्रिकेतील अनेक सरकारे, तसेच हस्तिदंती वस्तूंना फिजूल प्रतिष्ठा मिळवून दिलेल्या गोऱ्या धनवानांच्या गळी उतरवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचे प्रयत्न अगदी गेल्या काही वर्षांपूर्वीपर्यंत सुरू होते. याच प्रयत्नांमुळे अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा आणि चीनचे विद्यमान अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी हस्तिदंती वस्तूंच्या वापरावर जवळपास पूर्ण निर्बंध घातले. कारण हस्तिदंती वस्तूंचे सर्वांत मोठे वापरकर्ते हेच दोन देश आहेत.

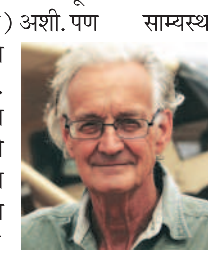

इयन डग्लस-हॅमिल्टन

इयन डग्लस-हॅमिल्टन हे मूळचे ब्रिटिश. त्यातही स्कॉटिश वंशाचे. त्यांचा जन्म १९४२मध्ये डॉर्सेट एका उमरावाच्या घराण्यात झाला. प्रथम स्कॉटलंड आणि मग ऑक्सफर्ड येथे त्यांनी जीवशास्त्र, प्राणिशास्त्राचा अभ्यास केला. त्या काळातील प्रथेप्रमाणे ते आफ्रिकेला वन्यजीवांचा अभ्यास करण्यासाठी गेले. विचार होता सिंहांच्या अभ्यासाचा, पण ओढले गेले हत्तींकडे. टान्झानियातील लेक मान्यारा नॅशनल पार्कमध्ये वयाच्या २३व्या वर्षी त्यांनी हत्तींचा अभ्यास सुरू केला. प्रत्येक हत्तीची नोंद घेऊन त्या हत्तीस स्वतंत्र क्रमांक देण्याची सुरुवातीची पद्धत होती. हत्तींचा अभ्यास करताना त्यांना मानव आणि हत्तींच्या वागणुकीतील विलक्षण साम्यस्थळांची जाणीव होऊ लागली. हत्ती परस्परांशी संवाद साधतात, त्यांना भावना असतात. मृत्यू या संकल्पनेबाबत त्यांची प्रतिक्षिप्त क्रिया असते. प्रत्येक हत्तीचा स्वभाव वेगवेगळा असतो, पण या सर्वांनी कळपाच्या शिस्तीत राहावे हे कळपाची मादी प्रमुख (मेट्रियार्क) सुनिश्चित करते, हेही डग्लस-हॅमिल्टन यांनी नोंदवून ठेवले. याच काळात त्यांची चिम्पान्झी अभ्यासक जेन गुडाल यांच्याशी भेट झाली. इयन हॅमिल्टन-डग्लस यांच्या संशोधनाने त्या खूप प्रभावित झाल्या.

पुढे १९७०च्या दशकात आफ्रिकेत सर्वत्र हत्तींच्या चोरट्या शिकारीचे पेव फुटले. त्या वेळी टान्झानिया, केनिया, युगांडा ते पार मालीपर्यंत प्रवास करून, त्या त्या देशातील सरकारांशी किंवा सशस्त्र टोळ्यांशी चर्चा करून डग्लस-हॅमिल्टन यांनी हत्तींसाठी रक्षक तुकड्या उभ्या केल्या. केनिया सरकारशी बोलून त्यांनी हस्तिदंतांचा प्रचंड साठा जाळून टाकायला लावला. त्याविषयीचे छायाचित्र आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये खूप गाजले. त्यांनी १९९३मध्ये 'सेव्ह द एलिफंट्स' ही स्वयंसेवी संस्था स्थापली. हस्तिदंतांचा व्यापार प्रतिबंधित करण्यासंबंधी आंतरराष्ट्रीय करार त्यांच्याच प्रयत्नांमुळे झाला. गतवर्षी प्रदर्शित झालेल्या 'लाइफ अमंग एलिफंट्स' या माहितीपटाने त्यांचे कार्य अधिक व्यापक जगापर्यंत पोहोचवले. त्यांचे वयाच्या ८३व्या वर्षी नुकतेच निधन झाले.

तर्कतीर्थ विचार

जिवंत प्रज्ञेच्या स्फुरणाचे प्रत्यंतर

विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात निर्माण झालेल्या तीन ग्रंथांचे स्फुरण महाराष्ट्रास लाभत आले आहे. लोकमान्य टिळकांचे 'गीतारहस्य' (१९१५), आचार्य शंकरराव जावडेकरांचे 'आधुनिक भारत' (१९३८) आणि तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशींचे 'वैदिक संस्कृतीचा विकास' (१९५१) हे ते तीन ग्रंथ होत. मराठी साहित्याच्या स्वातंत्र्यपूर्व काळावर या ग्रंथांचा जितका प्रभाव होता, तितकाच तो आजही दिसून येतो. त्या अर्थाने हे मराठी साहित्याचे अभिजात ग्रंथ ठरावेत. कालातीत विषय, उच्च कलात्मकता, असाधारण भाषिक सौंदर्य आणि कलाकृतीचे सांस्कृतिक व सामाजिक महत्त्व या अभिजाततेच्या निकषांवर आपण जेव्हा 'वैदिक संस्कृतीचा विकास' ग्रंथ अभ्यासू लागतो, तेव्हा लक्षात येते की, या ग्रंथात एका मोठ्या कालपटास वर्तमानाशी जोडत जे भाष्य केलेले आहे, ते भारतीय समाजास सांस्कृतिकदृष्ट्या निरंतर समृद्ध करणारे ठरते. म्हणून तर साहित्य अकादमीने आपल्या पहिल्या मराठी पुरस्कारासाठी या ग्रंथांची १९५५ला निवड केली होती.

हा ग्रंथ प्रकाशित झाल्यावर त्याची पहिली समीक्षा दुर्गा भागवत यांनी साप्ताहिक 'मौज'च्या १६ जानेवारी, १९५२च्या अंकात करीत म्हटले होते की, ''तर्कतीर्थांचा हा ग्रंथ एक अप्रतिम ग्रंथ आहे. कारण, या विषयातल्या विचारांची मांडणी स्वतंत्र मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवून त्यांनी केलेली आहे. जिवंत प्रज्ञेच्या स्फुरणाचे हे पुस्तक एक उत्कृष्ट प्रत्यंतर आहे. ज्या थोर विचारांनी भरलेल्या पुस्तकांची पारायणे केली जातात, त्या पुस्तकांत या पुस्तकाचा नंबर वर लागेल, यात शंका नाही.''

तर्कतीर्थांना साहित्य अकादमीने १९८९मध्ये महत्तर सदस्यत्व (फेलोशिप) बहाल केले होते, त्या वेळी प्रदान केलेल्या सन्मानपत्रात (सायटेशन) हे नमूद करण्यात आले होते की, ''वैदिक संस्कृतीचा विकास' कृति वैज्ञानिक मानवतावाद को नयी विश्व संस्कृति के अग्रदूत के रूप में स्थापित करते हुए वैदिक संस्कृति के विकास को प्रस्तुत करती है।''

या ग्रंथाची प्रशंसा करीत विद्वान थकत का नाहीत, याचा शोध घेताना लक्षात येते की, तर्कतीर्थांनी या ग्रंथाची रचनाच मुळी मोठ्या विधायक उद्देशांनी केली आहे. तो उद्देश स्पष्ट करत या ग्रंथात त्यांनी वैदिक संस्कृतीचे वैशिष्ट्य पुढीलप्रमाणे अधोरेखित केले आहे- ''जगातील सर्व धर्मांचे व संस्कृतींचे परिपालन व्हावे, त्यांचा उच्छेद (नाश) होऊ नये, स्वतःच्या विशिष्ट आध्यात्मिक प्रेरणेने त्यांचा विकास व्हावा, अशा प्रकारची असाधारण आध्यात्मिक प्रेरणा वैदिक संस्कृतीमध्ये प्रथमपासून वसत आहे. रानटी अवस्थेपासून ते उच्च अवस्थेपर्यंत पोहोचलेल्या सर्वच धार्मिक संस्थांचे त्यातील गर्ह्य (निंद्य) अनाचार वगळून वैदिक संस्कृतीने परिपालन (अंमल) केले आहे.'' (पृ. ४७०-७१)

या ग्रंथाची महत्ता ओळखून यातील विचार सर्वदूर पोहोचावेत म्हणून या ग्रंथाची इंग्रजी, हिंदी, संस्कृत भाषांतरे झाली आहेत. प्रस्तुत ग्रंथाचे इंग्रजी भाषांतर प्रकाशित झाले, तेव्हा त्याचे स्वागत करत डॉ. ग. ना. जोशी यांनी या ग्रंथाचे बलस्थान समजावत 'रविवार सकाळ'च्या १६ जून, २००२ च्या अंकातील परीक्षणात म्हटले होते की, ''वैदिकांच्या या समन्वयात्मक प्रयत्नांचा सांस्कृतिक इतिहास शास्त्रीजींच्या या ग्रंथात आहे. अखिल मानवजातीच्या, किंबहुना सर्व सजीव व निर्जीव सृष्टीच्या कल्याणाची अभिलाषा तिला आहे. तरी एकत्वाच्या भावनेला अत्युच्च महत्त्व देणारी आहे. 'एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति' या वैदिक ऋचेत भारतीयांची व्यापक सहिष्णुता म्हणजे सर्वधर्मसमभाव व सामावून घेण्याची वृत्ती यांचे मूळ आहे. या समन्वयात वैदिकांनी आपल्या देवदेवतांचे व यज्ञसंस्थेचे विसर्जन केले. अवैदिक सांख्य, योग ही तत्त्वज्ञाने आणि शैव व वैष्णव धर्मसंप्रदाय यांना वैदिकांनी महत्त्वाचे स्थान दिले. सत्याची निरंतर अन्वेषणा व त्यागाचे जीवन आणि या वृत्तीतून मिळणाऱ्या आनंदासाठी जगण्याची आकांक्षा या आध्यात्मिक प्रेरणेचे अधिष्ठान फक्त भारतीय संस्कृतीतच दिसून येते. भारतीय संस्कृतीच्या आध्यात्मिक प्रेरणांचा जरी आजच्या भारतीयांना विसर पडू लागल्याचे चित्र दिसत असले, तरी त्या प्रेरणा सर्व जगाला मार्गदर्शक ठरू शकतील इतक्या समर्थ आहेत, असे अनेक निष्कर्ष या ग्रंथात व्यक्त झालेले आहेत.''

– **डॉ. सुनीलकुमार लवटे**
drsklawate@gmail.com

खेळ मांडला महामंडळांचा...

सरकारची आर्थिक घडी व्यवस्थित असती तर विविध जातींच्या कल्याणाचा हा महामंडळांचा प्रयोग गोड मानून घेताही आला असता, पण तसेही नाही.

जातींच्या राजकारणाचा खेळ लोकशाहीसाठी तारक की मारक यावर अनेकदा चर्चा होत असते. संसदीय लोकशाहीचे पावित्र्य जपायचे असेल तर असा खेळ करणे योग्य नाही अशी विधाने राजकारणातील मंडळी नेहमी करत असतात. प्रत्यक्षात काय घडते तर नेमके विपरीत. आम्ही विकासाचे राजकारण करतो असे म्हणणारेच या खेळात तल्लीन झालेले दिसतात. याची चटक एकदा लागली की ती सुटता सुटत नाही. निवडणुकीचे राजकारण यशस्वी करायचे असेल तर सर्व काही क्षम्य म्हणून ही चूक पदरातही घालता येईल, पण जो खेळ सुरू केला तो तरी पूर्णत्वास न्यावा ना! तर तसेही नाही. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे महायुती सरकारने ऐन निवडणुकांच्या आधी घोषित केलेली विविध जातींची आर्थिक विकास महामंडळे. आता वर्ष लोटले तरी ती केवळ कागदावर असून त्यांना निधी देणार तरी कधी असा प्रश्न नागपुरात सुरू असलेल्या अधिवेशनात उपस्थित झाला व सरकारला ऐन थंडीत घाम फुटला. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिशय चतुराईने वेळ मारून नेली असली तरी हे जातींना चुचकारण्याचे राजकारण अनेक नव्या प्रश्नांना जन्म देणारे ठरते.

मुळात राज्यात आधीच असंख्य महामंडळांची गर्दी झालेली असताना व त्यातली पन्नासेक पूर्णपणे डबघाईला आलेली असताना या नव्या मंडळांची गरज काय होती? यावरचे उत्तर म्हणून त्यांच्या नावात महामंडळ असा शब्द असला तरी त्या कंपन्या म्हणून नोंदणीकृत असतील व त्यांचा कारभार त्याप्रमाणे चालेल असे जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात तो कंपनीच काय पण सध्या अस्तित्वात असलेल्या महामंडळांपेक्षाही कूर्मगतीने चालत असल्याचे सत्तारूढ पक्षाच्या आमदारांनीच बुधवारी विधानसभेत दाखवून दिले. हा सरकारला मिळालेला घरचा आहेर. यात आणखी एक पैलू दडलेला. तो म्हणजे यानिमित्ताने अजितदादांच्या वित्त खात्यावर निशाणा साधण्याचा. मराठा समाजासाठी स्थापन झालेल्या सारथीला निधीचे भरभरून दान देणारे दादा ओबीसींच्या या महामंडळांकडे मात्र साफ दुर्लक्ष करतात असा चर्चेत भाग घेणाऱ्या साऱ्या आमदारांचा सूर. तीन पक्षांची आघाडी असली की असे भांड्याला भांडे आदळणे सुरूच राहते म्हणून याकडे एकवेळ दुर्लक्ष करता येईल, पण जातींच्या उन्नतीसाठी स्थापन केलेल्या या मंडळांचे काय? निधीअभावी ती केवळ कागदी घोडेच नाचवणार काय?

दर महिन्याला १५०० रुपये मिळवणाऱ्या लाडक्या बहिणींनंतर जास्तीतजास्त लाभ पदरात कसा टाकता येईल याची काळजी सरकारला आहे ती ओबीसी या प्रवर्गाच्या बाबतीत. महायुतीतील सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपची मतपेढी असलेला प्रवर्ग हाच. लोकसभा निवडणुकीत तोच हातून गेल्याचे निकालातून स्पष्ट झाल्यानंतर या पक्षाने ज्या काही तातडीच्या उपाययोजना आखल्या त्यापैकी एक म्हणजे ही महामंडळे. तसेही भाजप जातींची समीकरणे जुळवून आणताना कायम त्यातील लहान घटकांकडे जाणीवपूर्वक लक्ष देत आला आहे. ओबीसी म्हटले की तेली,

> **राजकीय फायदा दिसून आल्याने लाडक्या बहिणींच्या मानधनात नक्की वाढ करू असे सरकारने जाहीर केलेले. म्हणजे आधीच गळती लागलेल्या तिजोरीवर आर्थिक ताण आलाच. या पार्श्वभूमीवर या ढीगभर महामंडळांच्या कागदी इमल्याचे सरकार नेमके करणार काय?**

कुणबी, माळी या मोठ्या जाती समोर येतात. मात्र, याच प्रवर्गात शेकड्याने असलेल्या पण कमी लोकसंख्येच्या लहान जातींना जवळ केले तर ते अधिक फायद्याचे हे लक्षात घेऊन या महामंडळांची आखणी करण्यात आली. निवडणुकीत यश मिळवण्यासाठी हे प्रारूप भलेही कामी आले असेल, पण आता काय? या महामंडळांना चक्क मृतावस्थेत ठेवणे म्हणजे या जातींना वाऱ्यावर सोडणे नव्हे काय? सरकारने वर्षभरापूर्वी ही घोषणा करताना प्रत्येक महामंडळाला ५० कोटी रुपये दिले जातील, यातून उद्योग, व्यवसायासाठी कर्ज वाटप केले जाईल. त्यावरचे व्याज सरकार भरेल असे जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात यापैकी चार ते पाच महामंडळांतच कर्ज वाटपाची प्रक्रिया सुरू झाली व २९ हजार लाभार्थ्यांना अवघे चार कोटी रुपये वितरित करण्यात आले. इतर ठिकाणी ना निधी मिळाला, ना लाभार्थी निश्चित झाले. या सर्व आस्थापनांचा कारभार कसा चालेल याचेही स्वरूप सरकारने घोषणा करतानाच ठरवून दिले होते. प्रत्यक्षात या प्रत्येक महामंडळाचा कागदोपत्री कारभार सुरू आहे तो अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बळावर. ना कार्यालये आहेत ना कर्मचारी. ज्या ओबीसी महामंडळाच्या पालकत्वाखाली ही मंडळे कार्यरत आहेत त्याचीच कार्यालये राज्यभर नाहीत. यावरून मते मिळवण्यासाठी आरंभलेला हा खेळ कसा अर्ध्यावर सोडला गेला, हेच स्पष्ट होते. आता हा सर्व भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आल्यावर सर्वांना निधी देऊ व प्रत्येक महामंडळावर त्या त्या जातीचे तीन अशासकीय सदस्य नियुक्त करू असे सरकार म्हणत असले तरी प्रत्यक्षात तो दिवस कधी उजाडेल याची शाश्वती कुणीही देऊ शकत नाही.

सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आधी मतांसाठी महामंडळ ही लालूच दाखवताना सरकारने प्रत्येक जातीतील एका संतांच्या नावाने पुरस्कार दिला जाईल असेही जाहीर केले होते. त्याचाही विसर आता साऱ्यांना पडलेला दिसतो. ते पुरस्काराचे सोडा पण आर्थिक सक्षमतेसाठी आवश्यक असलेल्या वित्तपुरवठ्याचे तेवढे बघा असे म्हणण्याची वेळ सरकारच्या या नाकर्तेपणामुळे या लहान जाती घटकांवर आली आहे. एकीकडे कमीतकमी प्रशासन व जास्तीत जास्त लोककल्याण अशा आकर्षक घोषणा पक्षाच्या वतीने द्यायच्या आणि दुसरीकडे मतांच्या बेगमीसाठी त्याच प्रशासनाचा फाफटपसारा वाढवत न्यायचा याला कुठले धोरण म्हणायचे? हा महामंडळांचा खेळ धोकादायक आहे हे ठाऊक असूनसुद्धा तो ठरवून खेळला गेला. आता तो अंगावर येताना दिसताच निधी न दिल्याचे खापर अजितदादांवर फोडणे कितपत योग्य? या सर्व महामंडळांचे पदसिद्ध अध्यक्ष बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे आहेत. गेले वर्षभर ते नेमके काय करत होते? निधी मिळावा म्हणून त्यांनी कोणते प्रयत्न केले? अर्थात याची उत्तरे कधी मिळणार नाहीत, पण यानिमित्ताने सरकारला महामंडळ प्रेमाचे जे भरते आले त्याचे काय? एक ना धड भाराभर चिंध्या या पद्धतीने कारभार करून राजकीय यश संपादन करता येईल, पण यातून निर्माण होणाऱ्या प्रशासकीय विस्कळीतपणाचे काय?

मराठा, समस्त ओबीसी व अनुसूचित जाती व जमातींसाठी याआधीच सारथी, महाज्योती व बार्टी यांसारख्या संस्था सुरू करण्यात आल्या. प्रारंभी स्वायत्त अशी ओळख असलेल्या या संस्थांवर नंतर हळूहळू सरकारने नियंत्रण मिळवले. तिथेही निधीची मारामार आहेच. त्याचे वाटप करताना मराठ्यांना झुकते माप मिळते. ओबीसींना नाही अशा तक्रारी सातत्याने समोर येतात. लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी का वितरित केला जात नाही असा प्रश्न वारंवार उपस्थित होतो. यातून समाज व जातीत जो दुभंग तयार होतो तो वेगळाच. सामाजिक सौहार्दाची वीण विस्कटते तेसुद्धा तेवढेच गंभीर. त्यातून शहाणपण न शिकता या नव्या महामंडळाचे घोडे पुढे दामटण्यात आले. सरकारची आर्थिक घडी व्यवस्थित असती तर विविध जातींच्या कल्याणाचा हा प्रयोग गोड मानून घेताही आला असता, पण तसेही नाही. लाडक्या बहिणींमुळे तिजोरीला गळतीच लागलेली. राजकीय फायदा दिसून आल्याने बहिणींच्या मानधनात नक्की वाढ करू असे सरकारने याच अधिवेशनात जाहीर केलेले. म्हणजे पुन्हा आर्थिक ताण आलाच. या पार्श्वभूमीवर या ढीगभर महामंडळांच्या कागदी इमल्याचे सरकार नेमके करणार काय? निधी देण्याच्या आश्वासनावर या जातींना झुलवत ठेवणार ही ओरड झाल्यावर थोडाफार निधी देऊन नुसते चुचकारत ठेवणार? हा धोकादायक खेळ राज्याला अधोगतीकडे नेणारा नाही तर आणखी काय?

लेख

निवडणूक 'विकृती' रोखण्याची गरज!

योगेंद्र यादव
स्वराज्य इंडियाचे सदस्य आणि भारत जोडो अभियानचे राष्ट्रीय संयोजक
yyadav@gmail.com

> **मतदारसंघ पुनर्रचना, एक देश, एक निवडणूक आणि मतदार यादीची विशेष सखोल फेरतपासणी हे भारताच्या निवडणूक व्यवस्थेवरचे तीन मोठे हस्तक्षेप देश-काल-पात्र ही चौकटच सत्ताधाऱ्यांच्या फायद्यासाठी वाकवू शकतात. त्यामुळे निवडणुकांची प्रामाणिकता टिकवणे हा आजचा खरा चर्चा-विषय आहे.**

''**तुम्ही 'देश,** काल आणि पात्र'बद्दल बोलत आहात.'' हे शब्द होते भारत जोडो अभियानाचे राष्ट्रीय संयोजक असलेले माझे सहकारी विजय महाजन यांचे. आम्हाला दोघांनाही वेगवेगळ्या गोष्टींना नावे देण्याची आवड आहे. फक्त विजय त्याबाबत जास्त हुशार आहे. त्या दिवशी पाटणामध्येही तसेच झाले, मी आपल्या निवडणूक प्रणालीच्या मतदारसंघ पुनर्रचना, एक राष्ट्र, एक निवडणूक तसेच मतदार याद्यांची विशेष सखोल उजळणी या संभाव्य तीन विध्वंसांमध्ये समान धागा शोधण्याचा प्रयत्न करत होतो. विजयने मला त्यांचा परस्परसंबंध समजून घेण्यास मदत केली. या तिन्ही गोष्टी निवडणुकांचा देश, काल आणि पात्र भाजपच्या कायमस्वरूपी फायद्यासाठी बदलून टाकतील.

मंगळवारी लोकसभेत आणि बुधवारी राज्यसभेत झालेल्या 'निवडणूक सुधारणां'वरील प्रस्तावित चर्चेबद्दल वाचताना मला ते संभाषण आठवले. निवडणूक सुधारणा, हा एक जुना निरागसतेच्या एका युगाची आठवण करून देणारा सुंदर शब्दप्रयोग आहे. तेव्हा आम्हाला वाटायचे की संसद सदस्यांना समजावून, लज्जित करून किंवा त्यांच्यावर दबाव टाकून नियम बदलण्यास प्रवृत्त केले जाऊ शकते. पण तेव्हापासून आतापर्यंत यमुनेतून बरेच गढूळ पाणी वाहून गेले आहे.

निवडणूक प्रणालीत 'फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट' पद्धतीतून प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाकडे बदल करण्याच्या चर्चेच्या त्या भोळ्याभाबड्या दिवसांपासून, राजकारणातील पैसा आणि गुन्हेगारीच्या दुष्परिणामांवर कायदेशीर उपाय शोधण्याच्या उत्साही काळापर्यंतचा प्रवास करून, आता आपण कढईच्या तळाशी पोहोचलो आहोतः निवडणुकीत किमान सचोटी कशी जपायची, लोकांच्या मतदानानुसारच अंतिम मतमोजणी होईल याची खात्री कशी करायची, सध्याच्या राजवटीद्वारे लादल्या गेलेल्या निवडणूक 'विकृती' कशा रोखायच्या, याची चिंता संसदेने केली पाहिजे.

ही समस्या फक्त भारताची नाही. जगभरात सगळीकडे हुकूमशाही प्रवृत्तीची सरकारे निवडणूक नियम आपल्या फायद्यासाठी पिळून घेत आहेत. २०व्या शतकातील हुकूमशहांपेक्षा २१व्या शतकातील हुकूमशहा वेगळे आहेत. आपल्याला लोकांचा पाठिंबा आहे, असे दाखवणे त्यांना भाग असते. ते निवडणुका पूर्णपणे रद्दही करू शकत नाहीत आणि पराभवाचा धोकाही पत्करू शकत नाहीत. त्यामुळे ते दोन सोपे डाव खेळतात. एक म्हणजे निवडणुका घेणाऱ्या संस्थाच ताब्यात घेणे आणि दुसरे म्हणजे निवडणुकीचे नियम अशा प्रकारे बदलणे की त्यांच्याच राजवटीला निर्णायक झुकाव मिळेल. आणि तरीही वरवर राजकीय स्पर्धा दिसत राहील. हंगेरी, तुर्की, व्हेनेझुएला, इक्वेडोर, बोलिव्हिया, केनिया, थायलंड आणि म्यानमार ही याची सध्याची उदाहरणे. यालाच तुलनात्मक राज्यशास्त्राचे अभ्यासक 'अब्युझिव्ह कॉन्स्टिट्यूशनॅलिझम', 'ऑटोक्रेटिक लिगलॅझम' किंवा 'इलेक्टोरल टिल्टिंग' असे म्हणतात. घटनात्मक, कायदेशीर आणि संस्थात्मक साधनांचा वापर करून असमान खेळपट्टी तयार करणे, असा हा खेळ आहे. तरुणाभ खैतान यांचा 'किलिंग अ कॉन्स्टिट्युशन विथ अ थाऊजंड कट्स' हा शोधनिबंध कायदा आणि राज्यसंस्थांमधील टप्प्याटप्प्याच्या बदलांमुळे भारतात पक्ष-राज्याचा संयोग कसा झाला आहे, हे दाखवून देतो.

चला, या विश्लेषणाला देश, काल आणि पात्र यांपर्यंत विस्तारण्यासाठी एका काल्पनिक कथेचा वापर करूया. कल्पना करा की, भाजपच्या कार्यालयात बसलेल्या एखाद्या व्यक्तीने २०२४ च्या निवडणुकीचा निकाल भयचकित होऊन पाहतो आहे. त्याने त्यात भाजपच्या कमकुवतपणाच्या तीन जागा ओळखल्याः देश – आग्नेय किनारपट्टीच्या काही प्रदेशांमध्ये भाजपला विरोध होतो; काल – निवडणूक वेळापत्रक दरवर्षी भाजपच्या वर्चस्वाची कसोटी घेते; आणि पात्र – भारताच्या सामाजिक उतरंडीच्या तळाशी असलेले काही घटक भाजपला मतदान करत असले तरी, त्याच्यावर विश्वास ठेवत नाहीत. या समस्यांना तोंड देण्यासाठी तो कोणती उपाययोजना करेल याची कल्पना करूया. मतदारसंघ पुनर्रचना, एक देश एक निवडणूक आणि मतदार याद्यांची सखोल आणि विशेष फेरतपासणी (एसआयआर) यांचा संयोग त्या उपायाशी आश्चर्यकारकपणे जुळतो. वरवर पाहता असंबंधित वाटणाऱ्या या चाली एका परिपूर्ण रचनेत बसतात.

मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे भाजपचे दोन उद्देश साध्य होतात. २०२६ च्या जनगणनेतील लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार लोकसभा जागांचे पुनर्वितरण केल्यास, ज्या प्रदेशांमध्ये भाजपची कामगिरी चांगली नाही, त्या प्रदेशांचा संसदीय प्रभाव कमी होईल आणि घटनादुरुस्तीवरील त्यांचा नकाराधिकार संपुष्टात येईल. एक अदृश्य हात अशी व्यवस्था करेल की, ज्या राज्यांमध्ये भाजप तुलनेने कमकुवत आहे (केरळ, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल, पंजाब) त्या सर्व राज्यांच्या जागा कमी होतील आणि ज्या राज्यांना सर्वाधिक जागांचा फायदा होईल (उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान) ती सर्व राज्ये भाजपचा बालेकिल्ला असतील. वरवर पाहता हे सर्व एका परिपूर्ण लोकशाही तत्त्वानुसार आणि संविधानानुसार केले जाईल. पुनर्रचनेमुळे 'जेरीमँडरिंग'ची (सत्ताधिकाऱ्यांच्या सोयीनुसार मतदारसंघाची पुनर्रचना) शक्यताही निर्माण होईल, म्हणजेच भाजपला सोयीस्कर ठरतील अशा प्रकारे मतदारसंघांच्या सीमा पुन्हा आखल्या जातील. हा अमेरिकन विषाणू आतापर्यंत भारतात अज्ञात होता, त्याची आसाम आणि जम्मू-काश्मीरच्या 'प्रयोगशाळे'त चाचणी करण्यात आली आहे आणि आता तो पूर्ण प्रमाणात अंमलबजावणीसाठी सज्ज आहे, ज्यामुळे डझनभर लोकसभा जागा सहजपणे भाजपच्या बाजूने झुकू शकतात.

'एक देश, एक निवडणूक' ही दुहेरी फायदा मिळवून देणारेच आहे. एकत्रित निवडणुका सत्ताधाऱ्यांना नेहमीच फायद्याच्या ठरतात. राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील निवडणुका एकत्र झाल्या तर प्रमुख राष्ट्रीय पक्षाला राज्य निवडणुकांत किंचित पण निर्णायक वाढ मिळते. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे पाच वर्षांत एकदाच निवडणुका झाल्या तर केंद्रातील सत्ताधारी पक्षासाठी या महासोहळ्याचे व्यवस्थापन तसेच नियंत्रण अधिक सोपे ठरते. निवडणुका आधीच सतत न होणारा लोकशाही सोहळा आहे; 'एक देश एक निवडणूक'मुळे हा सोहळा एका वेळेपुरता मर्यादित राहून त्याच्यावर नियंत्रण आणणे अधिक सोपे ठरेल.

एसआयआर प्रणाली भाजपसाठी गैरसोयीच्या असलेल्या व्यक्ती आणि समुदायांना मतदानाचा हक्क नाकारण्यासाठी मदतकारकच आहे. बिहारचे उदाहरण (एसआयआर-पूर्व यादीतून ४४ लाख नावांची निव्वळ घट) पाहिल्यास, देशभरातील एसआयआरमध्ये मतदार यादीतून पाच कोटींहून अधिक नावे वगळली जाण्याची शक्यता आहे. लोकशाहीच्या जागतिक इतिहासातील हा मतदानाचा हक्क हिरावून घेण्याचा सर्वात मोठा प्रकार असेल. विशिष्ट समूहांना लक्ष्य करून मतदार यादीतून त्यांची नावे वगळण्यात भाजपचा फायदा आहे. नावनोंदणीची जबाबदारी मतदारांवरच टाकल्यामुळे गरीब, स्थलांतरित, भटके इत्यादी सर्वात वंचित घटकांची नावे मोठ्या प्रमाणावर वगळली जाण्याची शक्यता आहे. या समूहांकडून भाजपला तुलनेत कमी मते मिळतात किंवा अजिबातच मिळत नाहीत. मजबूत संघटन आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांचा पाठिंबा यामुळे भाजपच्या निष्ठावंत मतदारांची परिस्थिती भाजपच्या विरोधकांच्या मतदारांपेक्षा अधिक चांगली आहे. निदान त्यांचे नाव निवडणूक यादीतून वगळले तर जाणार नाही.

याशिवाय, एसआयआरची रचना आणि त्याच्या अंमलबजावणीतील पक्षपातीपणा पाहता भाजप त्याला निवडणूकदृष्ट्या गैरसोयीच्या वाटणाऱ्या मुस्लीम तसेच इतर समुदायांना मताधिकारापासून वंचित ठेवेल असे वाटते.

या तिहेरी आघातामुळे भारतातील लोकशाही आणखी धोक्यात येईल का? 'इंटरनॅशनल आयडिया' या संस्थेने आधीच भारतात 'लोकशाहीचे अधःपतन' सुरू असल्याचे अधोरेखित केले आहे. तिच्या 'ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी' या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, गेल्या पाच वर्षांत भारताची 'विश्वासार्ह निवडणुकां'सह अनेक निर्देशकांवर घसरण झाली आहे. पुढील वर्षभरातदेखील 'इंटरनॅशनल आयडिया' ही संस्था विशेषतः तिच्या नियामक मंडळाच्या नवीन (फिरत्या) अध्यक्षांच्या नेतृत्वाखाली भारतावर लक्ष ठेवेल अशी आशा आहे. आणि हे नवे अध्यक्ष दुसरे तिसरे कुणी नाहीत, तर ते आहेत, भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार.

अन्वयार्थ

त्यांची ती द्वेषोक्ती... आमची ती अभिव्यक्ती?

तिरस्कार किंवा द्वेषमूलक (हेट स्पीच) भाषणांबद्दल शासनाची तरतूद असलेले विधेयक कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने विधिमंडळात सादर केल्यावर त्याची प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक होते. विविध राजकीय, धार्मिक, सामाजिक नेत्यांची तिरस्कारमूलक भाषणे ही सध्या शासकीय यंत्रणांसाठी डोकेदुखी ठरू लागली आहे. कोणाच्याच जिभेवर नियंत्रण राहिलेले नाही आणि त्याला आवर घालण्यात मर्यादा येतात. त्यातूनच द्वेषोक्ती किंवा तिरस्कारमूलक भाषणांच्या विरोधात कठोर शिक्षेची तरतूद असलेला कायदा करण्याच्या दृष्टीने कर्नाटक सरकारने पाऊल उचलले. राजकीय, धार्मिक नेतेमंडळींच्या चिथावणीखोर भाषणांमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणे, दंगे पेटण्याचे प्रकार नेहमीच घडतात. विशेषतः कर्नाटकात धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या राजकारणापायी वातावरण कलुषित झाल्याच्या घटना अलीकडच्या काळात घडल्या आहेत. 'कायदा आणि सुव्यवस्था तसेच शांतता राखण्यासाठीच' हा कायदा करण्यात येत असल्याचा दावा करीत उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी विधेयकाचे समर्थन केले. तिरस्कारमूलक किंवा प्रक्षोभक भाषणांना आळा घालण्यासाठी अशी कारवाई आवश्यक असली तरी प्रत्येक सरकारची द्वेषमूलक किंवा प्रक्षोभक भाषणाची व्याख्या आपापल्या सोयीनुसार असते याचे काय करायचे? त्यामुळेच या कायद्याला भाजपचा विरोध अपेक्षित असला तरी कर्नाटकातील नागरी संघटनांनी या कायद्याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी असे म्हणत प्रखर विरोध दर्शविला आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. केंद्रातील मोदी सरकारने देशात अघोषित आणीबाणी लादल्याचा आरोप काँग्रेसचे माध्यम विभागाचे प्रमुख तसेच खासदार जयराम रमेश यांनी केला होता. पण त्यांच्याच कर्नाटक सरकारने कोणते काय केले आहे?

तिरस्कारमूलक भाषण करताना पहिल्यांदा पकडल्यास एक ते सात वर्षे शिक्षा आणि ५० हजार रुपये दंड तर पुन्हा याच गुन्ह्यात पकडल्यास सात ते दहा वर्षे शिक्षा आणि एक लाख रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. हा गुन्हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असल्याची तरतूद आहे. केंद्रातील भाजप सरकारने निवडणूक आयोगापासून देशातील सर्व यंत्रणा वेठीस धरल्याचा आरोप काँग्रेस पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी करीत असतात. याच काँग्रेस पक्षाच्या सरकारने तिरस्कारमूलक भाषणांच्या विरोधात कायदा करणे हा तसा विरोधाभासच. गेल्या काही महिन्यांत कर्नाटकातील धार्मिक वातावरण बिघडविण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न होत असताना अशा कायद्याची आवश्यकता होती, असा दावा गृहमंत्र्यांनी केला. खरे तर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या सरकारचे हे अपयशच मानावे लागेल. कर्नाटकातील मेंगलुरू, उडपी, दक्षिण कन्नडा हा किनारपट्टीवरील भाग किंवा म्हैसुरू भागातील मंड्या ही सारी शहरे धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाची 'प्रयोगशाळा' म्हणून ओळखली जातात. हिजाबचा वाद याच भागात निर्माण झाला होता. हिंदू व मुस्लीम धार्मिक संघटनांच्या कार्यकर्त्यांचे हत्यासत्र याच भागातील. अडीच वर्षांपूर्वी सत्तेत आल्यावर काँग्रेस सरकारने ठोस उपाय योजून या भागातील परिस्थिती आटोक्यात राहण्यासाठी तसेच धार्मिक शक्ती डोके वर काढणार नाहीत यासाठी खबरदारी घ्यायला हवी होती. पण किनारपट्टी भागातील धार्मिक संघटनांच्या कार्यकर्त्यांचे हत्यासत्र सुरूच राहिले. मंड्यासारख्या कधीही धार्मिक वादाची पार्श्वभूमी नसलेल्या जिल्ह्यात धार्मिक तणाव वाढला. सरकारचे नियंत्रण नसल्यानेच ही परिस्थिती निर्माण झाली. सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार या दोघांचा निम्म्यापेक्षा अधिक वेळ मुख्यमंत्री कोण असावा या वादापायी गेला. धार्मिक ध्रुवीकरणातून निवडणुकीत यश मिळते हे लक्षात घेऊन अन्य पक्षीयांनी राजकीय पोळी भाजून घेतली. आता कायदा येत असला तरी वेळ कधीच निघून गेली होती. काँग्रेस नेते आपापसात भांडणात मशगूल राहिले.

खोट्या बातम्यांच्या (फेक न्यूज) विरोधात कायदा करण्याच्या प्रयत्नात कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारचे हात गेल्या पावसाळी अधिवेशनात चांगलेच पोळले होते. तेव्हाही नागरी संघटना आणि इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देणाऱ्या कंपन्यांनी आक्षेप घेतला होता. हा एक प्रकारे नियंत्रण (सेन्सॉरशिप) आणण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप झाला होता. कायदे मंडळातील सदस्यांच्या म्हणजेच आमदारांच्या समितीला खोटी माहिती काय आहे हे ठरविण्याचा अधिकार देण्याची योजना होता. या विधेयकावरून बरीच टीका झाल्यावर सिद्धरामय्या सरकारने ते विधेयक मंजूर केले नव्हते. आता तिरस्कारमूलक भाषणांवर आळा घालण्यासाठी कायदा करण्यात येणार आहे.

मोदी सरकार लोकशाहीचा गळा घोटत असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते केंद्रात करतात. याच काँग्रेस पक्षाच्या सरकारने द्वेषोक्तीच्या विरोधात कायदा करून कोणता आदर्श घालून दिला आहे? सत्ता मिळाली की सारे एकाच माळेचे मणी!

विश्लेषण

कोकणच्या हापूस आंब्यावर गुजरातचा दावा कसा?

दत्ता जाधव
dattatray.jadhav@indianexpress.com

> **कोकण हापूसला २०१८ मध्ये भौगोलिक मानांकन मिळाले. पण, त्यानंतर शिवनेरी आणि आता वलसाड हापूस नावाने मानांकन मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या आधी मलावी हापूसला विरोध करून मलावी आंबा, नामांतर करायला कोकणवासीयांनी भाग पाडले. पण वलसाड हापूसचा डाव हाणून पाडणे तितके सोपे नाही...**

भौगोलिक मानांकन म्हणजे काय?

भौगोलिक मानांकन (जीआय टॅग) म्हणजे एखाद्या विशिष्ट भौगोलिक ठिकाणीच, विशिष्ट भौगोलिक परिसरातच उत्पादित होणारा शेतीमाल किंवा वस्तूला दिले जाणारे एक नाव किंवा चिन्ह होय. हे नाव त्या उत्पादनाची अस्सल ओळख जपते. राज्यात कोकण हापूस, महाबळेश्वर स्ट्रॉबेरी, सांगलीची हळद या शेतीमालासह सोलापूरची चादर आणि कोल्हापुरी चप्पल या उत्पादनांना जागतिक ओळख मिळाली आहे.

ते का आणि कसे करायचे?

जागतिक व्यापार करारामध्ये १९९५ मध्ये प्रथमच कृषी विषयाचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे जागतिक बाजार सर्व शेतीमालांसाठी खुला झाला. जागतिक व्यापार कराराअंतर्गत झालेल्या करारांपैकी बौद्धिक संपत्ती हक्क हा करार महत्त्वाचा आहे. त्यानुसार बौद्धिक संपदा, आराखडा आणि व्यापार चिन्ह नोंदणी करता येते. या करारानुसार भौगोलिक क्षेत्राशी निगडित उत्पादित मालास संरक्षण देण्यासाठी संसदेने ३० डिसेंबर १९९९ रोजी वस्तूचे भौगोलिक चिन्हांकन (नोंदणी आणि संरक्षण) कायदा मंजूर केला. त्याची अंमलबजावणी १५ सप्टेंबर २००३ पासून सुरू झाली. या कायद्यांतर्गत शेती मालाकरिता भौगोलिक चिन्हांकन (जीआय) करण्याचे काम केंद्र सरकारकडून केले जाते.

भौगोलिक मानांकनामुळे फायदा होतो?

जागतिक बाजारपेठेमध्ये व्यापारचिन्ह जसे महत्त्वाचे आहे, तसेच भौगोलिक क्षेत्राशी निगडित शेतीमालाची गुणवत्ता, सातत्य व गुणधर्माबाबत भौगोलिक चिन्हांकन नोंदणीस विशेष महत्त्व आहे. भारतामध्ये बहुतांश शेतीमाल शेतकऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक उत्पादित केला जात असल्याने शेतीमालाची स्वतःची अशी खास गुणवत्ता आहे. काही शेतीमालांमधील गुणवत्ता वर्षानुवर्षे, पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली आहे. त्यामध्ये वर्षानुवर्षे फरक पडलेला नाही. शेतीमालाच्या गुणवत्तापूर्ण उत्पादनामध्ये विशिष्ट प्रदेशात सातत्य राखलेले आढळून येते. तेच उत्पादन इतर ठिकाणीही तशाच प्रकारच्या हवामानात किंवा जमिनीत घेतले जाते. परंतु, त्या शेतीमालास तशी खास गुणवत्ता येत नाही. कारण गुणवत्ता ही त्या - त्या प्रदेशाशी निगडित असते. उदाहरणार्थ स्ट्रॉबेरी देशात अनेक ठिकाणी होते. पण महाबळेश्वरात उत्पादित झालेल्या स्ट्रॉबेरीसारखी चव, स्वाद अन्य ठिकाणी उत्पादित झालेल्या स्ट्रॉबेरीला नसते. देशात आतापर्यंत अशा प्रकारचे भौगोलिक चिन्हांकन ३२२ हून जास्त शेती व फलोत्पादनांना मिळाले आहे. महाराष्ट्रात ४० हून जास्त उत्पादनांस भौगोलिक मानांकन अथवा चिन्हांकन मिळाले आहे.

हापूसच्या मानांकनासाठी स्पर्धा का?

हापूस आंबा म्हटले की, कोकण किनारपट्टीवर उत्पादित होणारा विशिष्ट चव, स्वाद, गोडी आणि वास असलेला आंबा. पण, याच कोकण हापूसवर आता गुजरातने दावा केला आहे. अलीकडे केशर आंब्याने बाजारपेठेत चांगले स्थान निर्माण केले आहे. तरीही हापूसच्या भौगोलिक मानांकनासाठी चढाओढ आहेच. २०१८ मध्ये कोकण हापूसला मानांकन मिळाल्यानंतर पहिल्यांदा शिवनेरी हापूस आंबा नावाने २०२२ मध्ये भौगोलिक मानांकनासाठी नारायणगाव कृषी विज्ञान केंद्राने अर्ज केला. त्यानंतर २०२३ मध्ये गांधीनगर आणि नवसारी विद्यापीठाने वलसाड हापूस नावाने भौगोलिक मानांकन मिळण्यासाठी अर्ज केला आहे. त्याबाबतची पहिली सुनावणी झाली आहे.

हापूसवर दावा का आणि विरोध का?

राज्यात सुमारे ४.५ लाख हेक्टरवर हापूसची लागवड आहे. त्यापैकी कोकणात १.८० लाख हेक्टरवर आहे. मुंबई, पुणे बाजारात कोकणातून येणाऱ्या एकूण आंब्यात हापूसचा वाटा ९५ टक्के, उर्वरित महाराष्ट्रातून दहा टक्के आणि गुजरातमधून ५० टक्के हापूस आणि ५० टक्के केसरसह अन्य आंबा येतो. देशातून एकूण आंबा निर्यातीत हापूसचा वाटा ५० टक्क्यांहून जास्त आहे. अमेरिका, ऑस्ट्रेलियासह युरोपात प्रक्रिया, नोंदणी करून निर्यात होणाऱ्या आंब्यांमध्ये हापूसचा वाटा ४० टक्क्यांपर्यंत आहे. तर आखाती देशांत निर्यात होणाऱ्या आंब्यात हापूसचा वाटा ९० टक्क्यांपर्यंत आहे. त्यामुळे आंब्याच्या हंगामात हापूस महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे हापूस या नावासह भौगोलिक मानांकन मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली येथे हापूसवर चांगले संशोधन झाले आहे. तिथे दर्जेदार रोपे तयार केली जातात. तिथूनच काही रोपे मलावी येथे गेली होती, त्यापासून तयार झालेल्या आंब्याला मलावी हापूस, असे नाव दिले गेले. शिवनेरी, जुन्नरसह राज्यात विविध ठिकाणी. गुजरातमधील वलसाड, नवसारी, कर्नाटकातील कारवार, धारवाड, केरळपर्यंत हापूसच्या रोपांची लागवड झाली आहे. त्यामुळे हापूस उत्पादन वाढले आहे. परिणामी प्रत्येकाने हापूसवर दावा सांगणे सुरू केले आहे. पण, शिवनेरी हापूस, वलसाड हापूस आणि भविष्यात कर्नाटक हापूस नावाने भौगोलिक मानांकन मिळाले तर कोकण हापूसची मागणी कमी होईल,या भीतीमुळे कोकणातील शेतकरी विरोध करीत आहेत.

अभिव्यक्ति

दैनिक भास्कर, नई दिल्ली, शुक्रवार, 12 दिसंबर, 2025

प्रेरणा

संघर्ष ने मुझे मनुष्य बनाया है। मुझमे आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ, जो पहले नहीं था।- **सुभाष चंद्र बोस**

संपादकीय

विदेशी कंपनियों का भारत में निवेश स्वागतयोग्य है

गूगल के बाद अब माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन सहित करीब दो दर्जन कंपनियों का भी भारत में भारी निवेश करने को तैयार होना शुभ संकेत है। विख्यात टेक कंपनियों के अलावा दुनिया की बड़ी निर्माता कंपनियां भी सेमी-कंडक्टर चिप, ऑटो उद्योग, ऊर्जा और वित्त सेवा के क्षेत्र में निवेश करने जा रही हैं। गूगल के आंध्र प्रदेश में निवेश की घोषणा दो हफ्ते पहले हुई और माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन की निवेश घोषणा ताजा है। टेक और चिप कंपनियों की भारत में रुचि का बड़ा कारण है ट्रम्प की मागा योजना, जिसके तहत अन्य देशों के इंजीनियरों की जगह अमेरिकी टेक युवाओं को नौकरी देने का दबाव है। अमेरिकी इंजीनियरों को रखने में कंपनियों को ज्यादा पगार देनी पड़ती है और ट्रम्प की अस्थिर नीतियों को भी झेलना पड़ता है। ट्रम्प के भारत-विरोधी रुख के कारण भारतीय टेक युवाओं का यूएस जाना भी मुश्किल हो गया है। भारत में इकाइयां लगाने से न केवल कम वेतन में अच्छे इंजीनियर मिलेंगे, बल्कि तैयार उपभोक्ता बाजार भी मिलेगा। अमेजन के विस्तार के पीछे भी यही बाजार है, जिसका भविष्य मध्यम वर्ग की क्रय-शक्ति बढ़ने से बेहतर रहेगा। फिलहाल अमेजन ने करीब 28 लाख लोगों को परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अपनी व्यावसायिक प्रक्रिया से जोड़ा है। ईवी कार निर्माता विन्फास्ट ने भी 4 अरब डॉलर निवेश से उपक्रम शुरू करने का मन बनाया है।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

आत्मविश्वास की तलाश हो तो ईश्वर पर भरोसा बढ़ाएं

आत्मविश्वास आता है ईश्वर पर अटूट विश्वास करने से। जिन्हें भी आत्मविश्वास की तलाश हो वो बाकी जो भी विधि अपनाएं पर सबसे सरल विधि है- ऊपर वाले पर भरोसा बढ़ाते जाना। आत्मविश्वास सबसे बड़ी दौलत है और आज अधिकांश लोग दौलतमंद होना चाहते हैं। जिन्हें रुपए-पैसे की मिल जाए वो सौभाग्यशाली, लेकिन वो भी और जिन्हें दौलत ना मिले वो भी- आत्मविश्वास की संपत्ति तो जरूर बढ़ाते जाएं। भारत की धरती पर एक सुविधा और है। यहां आत्मविश्वास के लिए कुछ ऐसे साधन हैं, जो दुनिया में कम पाए जाते हैं। और वो हैं हमारे देवस्थान। अयोध्या में राम मंदिर पर जो ध्वजारोहण हुआ, वो आत्मविश्वास का प्रतीक है। भारत के आर्थिक आंकड़ों में पर्यटन का जो अंशदान है, उसमें से लगभग आधा अब धार्मिक पर्यटन का हो रहा है। करोड़ों लोग अदृश्य आस्था के साथ देवस्थानों पर जा रहे हैं। बस उन्हें इतना परिपक्व होना है कि भीड़, हुड़दंग में से भी धक्का-मुक्की के बीच आत्मविश्वास का प्रसाद जरूर लेते आएं। •Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

मुद्दा • नहीं तो प्याज की कीमतें सरकार गिराती रहेंगी

खाने-पीने की चीजों के दामों पर सरकार का अंकुश जरूरी

फूड

नीरज कौशल
कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर
nk464@columbia.edu

महंगाई के मुद्दे ने दुनिया में कई चुनावों के नतीजे तय किए हैं। अमेरिका में कोविड के बाद महंगाई को काबू में न रख पाने की कीमत जो बाइडेन और डेमोक्रेट्स को व्हाइट हाउस खोकर चुकानी पड़ी थी। डोनाल्ड ट्रम्प ने कीमतें घटाने का वादा किया था, लेकिन उलटे उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिए, जिससे महंगाई और बढ़ी। उनका कोर वोटर इससे नाखुश है। ऐसे में कई विश्लेषकों का मानना है कि मिड-टर्म चुनावों में रिपब्लिकंस का प्रदर्शन कमजोर रह सकता है क्योंकि ट्रम्प प्रशासन महंगाई घटाने में नाकाम रहा है।

सच पूछो तो राजनेता महंगाई से डरते हैं। अमेरिका में अंडे की कीमतें- और भारत में प्याज के दाम- उनकी धड़कनें बढ़ा देते हैं। बहुतों का मानना है कि 1998 में प्याज की ऊंची कीमतों ने ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाई थी।

भारत में सब्जियों की कीमतों में उतार-चढ़ाव तो खासा बदनाम है। यहां कुछ ही महीनों- और कभी-कभी तो कुछ ही हफ्तों में- टमाटर या प्याज की कीमतें दस गुना तक बढ़ या घट जाती हैं। उदाहरण के तौर पर, दिल्ली में पिछले नवंबर में प्याज 100 रुपए किलो बिक रहा था और हाल में वह 13 रुपए किलो पर बिका। टमाटर पिछले अक्टूबर में 65 रुपए किलो था, अब 35 रुपए किलो है। हम अकसर बढ़ी हुई कीमतों पर ही ध्यान देते हैं, जबकि हालिया रुझान दिखाता है कि कीमतों का पेंडुलम दोनों दिशाओं में बराबर झूलता है। किसी भी व्यवसाय में आउटपुट-कीमतों में ऐसी अस्थिरता कारोबारी को हैरान-परेशान कर सकती है।

कीमतों में उतार-चढ़ाव कम करने के लिए सरकार क्या कर सकती है? दो सरल उपाय हैं : वैश्विक स्रोतों से खरीद और फूड प्रोसेसिंग। पाठकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि औद्योगीकृत देशों में फल-सब्जियों की कीमतें साल भर काफी स्थिर रहती हैं। इसका कारण यह है कि वे घरेलू फसल पर निर्भर नहीं रहते। वे वैश्विक सप्लाई चेन से जुड़े रहते हैं और जिस भी गोलार्ध में मौसम अनुकूल हो, वहां से आयात करते हैं। दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध की काउंटर-सीजनैलिटी (एक के ऑफ-सीजन के समय दूसरे का ऑन-सीजन) के कारण उन्हें साल भर आपूर्ति मिलती है।

यही कारण है कि अमेरिका में लोगों को सालभर ताजे टमाटर मिलते हैं। ऑफ-सीजन में वे चिली या मैक्सिको से टमाटरों का आयात कर लेते हैं। वास्तव में शायद ही ऐसा कोई मौसमी उत्पाद है, जो अमेरिकी ग्रॉसरी स्टोर्स में ऑफ-सीजन में भी उपलब्ध न होता हो। जब कैलिफोर्निया या फ्लोरिडा की आपूर्ति कमजोर पड़ती है तो मैक्सिको, कनाडा, चिली, ग्वाटेमाला या कोस्टा रीका उसकी भरपाई कर देते हैं। दक्षिणी गोलार्ध की सस्ती मजदूरी, कम परिवहन लागत और उनका विशाल कोल्ड-स्टोरेज नेटवर्क अमेरिकी सुपरमार्केट की शेल्फों पर साल भर स्थिर कीमतें बनाए रखते हैं।

लेकिन भारत में उपभोक्ताओं की रक्षा के नाम पर आयात-नियंत्रण और किसानों की रक्षा के नाम पर निर्यात-नियंत्रण ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि बड़े पैमाने पर फलों और सब्जियों के व्यापार तथा भंडारण के लिए आवश्यक वैल्यू चेन विकसित ही नहीं हो पाईं। नतीजा यह है कि खाने-पीने की चीजों की कीमतें लगातार ऊपर-नीचे होती रहती हैं।

फूड प्रोसेसिंग की बात करें। अधिकांश पश्चिमी देशों में प्याज और टमाटर का बड़ा हिस्सा प्रोसेस कर लिया जाता है- सूखे प्याज-टमाटर, कैन में स्टोर किए हुए स्लाइस या फिर प्याज-टमाटर की प्यूरी के रूप में।

भारत में सब्जियों की कीमतों में उतार-चढ़ाव खासा बदनाम है। इससे बचने के लिए सरकार क्या कर सकती है? दो सरल उपाय हैं : वैश्विक स्रोतों से खरीद और फूड प्रोसेसिंग। इससे ऑफ-सीजन में भी हमारे ग्रॉसरी स्टोर्स भरे रहेंगे।

2016 के आंकड़ों पर आधारित एक अध्ययन बताता है कि अमेरिका में 33 प्रतिशत टमाटर प्रोसेस होते हैं, चीन में 14 प्रतिशत, जबकि भारत में यह अनुपात सिर्फ 0.3 प्रतिशत ही है। एक अन्य अध्ययन का अनुमान है कि अमेरिका में फलों और सब्जियों का एक-तिहाई से अधिक हिस्सा प्रोसेस होता है; जबकि भारत में यह 5 प्रतिशत से भी कम है।

इस साल भारत में प्याज और आलू की भरपूर पैदावार ने महंगाई को नकारात्मक दायरे में पहुंचा दिया है। दुनिया बढ़ती कीमतों से चिंतित है, लेकिन भारतीय उपभोक्ता नहीं। बहरहाल, यह याद रखना जरूरी है कि ये हालात तेजी से उलट सकते हैं। कीमतें जब बहुत नीचे चली जाती हैं, तो किसान अगले साल वही फसल उगाने से कतराते हैं और इसी से कीमतों में उछाल की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। आपूर्ति और मांग के बीच यह विसंगति कीमतों में अस्थिरता को तंत्र की स्थायी विशेषता बना देती है। ऐसे में आयात कीमतों को स्थिर रखने में कारगर हो सकते हैं। भारत के लिए जरूरी है कि बाजार से नियंत्रण घटाए, विश्व-व्यापार बढ़ाए और भंडारण व प्रोसेसिंग पर गंभीरता से निवेश करे।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

दूरदृष्टि • अमेरिका भारत को हल्के में नहीं ले सकता

हमारे हितों की अनदेखी कर हमसे दोस्ती मुमकिन नहीं

कूटनीति

ब्रह्मा चेलानी
पॉलिसी फॉर सेंटर रिसर्च के प्रोफेसर एमेरिटस

अमेरिका की भारत-नीति दिन-ब-दिन अधिक विद्वेषपूर्ण होती जा रही है, लेकिन उसे यह मालूम होना चाहिए कि दीर्घकालिक अमेरिकी रणनीतिक हितों के लिए भारत से अधिक महत्वपूर्ण कोई और शक्ति नहीं है। क्योंकि जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति और सैन्य क्षमता- जिनमें परमाणु क्षमता भी शामिल है- के लिहाज से भारत एकमात्र ऐसा देश है, जो एशिया पर प्रभुत्व जमाने और अमेरिका के वर्चस्व को बेदखल करने की चीन की कोशिशों को चुनौती दे सकता है।

जॉर्ज डब्ल्यू. बुश के कार्यकाल से ही वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति-संतुलन बनाए रखने के लिए भारत के साथ साझेदारी को निर्णायक माना है। यह नीति कभी सिर्फ भाषणबाजी तक ही सीमित नहीं रही थी। पिछले एक दशक में तो अमेरिका-भारत सुरक्षा संबंध तेजी से गहराए थे- विशेषकर सैन्य इंटर-ऑपरेबिलिटी, खुफिया सहयोग और तकनीकी लेनदेन के स्तर पर।

वास्तव में, भारत-अमेरिका रिश्तों में बढ़त का एक हिस्सा तो ट्रम्प के पहले कार्यकाल में घटा था। चीन पर दबाव बढ़ाने और पाकिस्तान को दी जाने वाली सुरक्षा सहायता घटाने के साथ ही ट्रम्प ने भारत के साथ सहयोग को बढ़ाया, जो उनकी इंडो-पैसिफिक रणनीति के केंद्र में था। इसका असर भी स्पष्ट है : भारत आज किसी भी अन्य देश की तुलना में अमेरिका के साथ अधिक सैन्य अभ्यास करता है और अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन चुका है।

लेकिन इसी प्रक्रिया के बीच अमेरिका ने भारत को सतर्क रहने के कई कारण भी दिए। अफगानिस्तान से उसका अव्यवस्थित पलायन- जो बाइडेन के कार्यकाल में हुआ लेकिन जिसकी बुनियाद ट्रम्प द्वारा किए समझौते से पड़ी थी- ने अमेरिकी नेतृत्व की समझदारी और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि इसने अफगानिस्तान को फिर से तालिबान के हवाले कर दिया। चिंताएं 2022 में तब और बढ़ीं, जब बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान को आईएमएफ से बेलआउट दिलाने में मदद की और फिर उसके एफ-16 बेड़े के आधुनिकीकरण के लिए 45 करोड़ डॉलर की भी मंजूरी दे दी। ट्रम्प ने भी पाकिस्तान के प्रति इस झुकाव को और तेज ही किया है, जिसका एक उदाहरण उससे की गई क्रिप्टोकरेंसी डील है।

अमेरिका ने अकसर भारत के हितों की अनदेखी की है। इसके बावजूद रूस पर लगाए प्रतिबंधों को लागू कराने के मामले में वह भारत से पूरी निष्ठा की उम्मीद करता रहा। भारत इससे सहमत नहीं हुआ और उसने डिस्काउंटेड दरों पर रूसी तेल की खरीद बढ़ा दी। भारत को सुदूर यूरोप में चल रहे किसी संघर्ष के लिए अपने राष्ट्रीय हितों की बलि देने का कोई कारण नहीं दिखा, खासकर तब, जब रूस पर पश्चिमी दबाव का सबसे बड़ा लाभार्थी चीन था।

भारत इस समीकरण को पहले भी देख चुका है। 2019 में जब ट्रम्प ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए तो भारत अपने सबसे सस्ते और भरोसेमंद ऊर्जा स्रोतों में से एक से वंचित हो गया था। चीन ने इसका पूरा फायदा उठाया। उसने ईरानी कच्चा तेल भारी छूट पर खरीदा और वहां अपनी सुरक्षा मौजूदगी बढ़ाई। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद भी यही पैटर्न उभरा। पश्चिमी बाजारों से रूस को अलग कर देने के बाद उस पर लगाए प्रतिबंधों ने उसे चीन पर आर्थिक रूप से निर्भर बना दिया, जिससे चीन को रूस से आने वाले ऊर्जा-आपूर्ति मार्गों को मजबूत करने की क्षमता मिल गई। अब चीन जानता है कि ताइवान पर कार्रवाई करने पर भी रूसी ऊर्जा तक उसकी पहुंच नहीं घटेगी। इस बार भारत ने भी रूसी तेल पर उपलब्ध छूट का लाभ उठाया।

अमेरिका भारत को अपने लिए जरूरी बताता है, लेकिन उसके हितों की अनदेखी भी करता है। वह चाहता है कि भारत इंडो-पैसिफिक में उसकी रणनीति का आधार बने, लेकिन वो ऐसी नीतियां भी अपनाता है, जो हमें क्षति पहुंचाती हैं।

अमेरिका भारत को अपने लिए जरूरी बताता है, लेकिन उसके हितों की अनदेखी भी करता है। वह चाहता है कि भारत इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में उसकी रणनीति का आधार बने, लेकिन वो ऐसी नीतियां भी अपनाता है, जो भारत की आर्थिक क्षमता, क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता को सीधे नुकसान पहुंचाती हैं। यही कारण है कि आज भारत अमेरिका के प्रति अविश्वास से भर गया है और उसे रूस से संबंध मजबूत करने को मजबूर होना पड़ रहा है। अमेरिका हमारे साथ अच्छे रिश्ते चाहता है तो उसे हमें बराबरी का दर्जा देना होगा। (@प्रोजेक्ट सिंडिकेट)

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए **QR कोड** को स्कैन करें।

ब्रांड से सबक | ASHOK LEYLAND | अशोक लीलैंड, देश की प्रमुख कॉमर्शियल ऑटो कंपनी

2013 में 6,200 करोड़ का कर्ज, बिक्री घटी, आज देश की शीर्ष कॉमर्शियल ऑटो कंपनियों में अशोक लीलैंड

2013 का साल था। माइनिंग और इंफ्रा सेक्टर में मंदी का दौर चल रहा था। इसने देश की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों की बिक्री पर गहरा असर डाला। इसका असर वर्तमान में देश की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों में शामिल अशोक लीलैंड पर भी पड़ा। कंपनी की बिक्री करीब 42 प्रतिशत तक गिर गई। उस पर करीब 6,200 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया जो उस समय कंपनी की वैल्यू से भी ज्यादा था। लगातार हो रहे नुकसान से बचने के लिए उसे करीब 1200 कैजुअल वर्कर्स की छंटनी करनी पड़ी। कंपनी के तत्कालीन एमडी विनोद दासरी ने एक रिपोर्ट में कहा, 'यह हमारे लिए सबसे कठिन दौर था, लेकिन हमने वर्किंग कैपिटल 80% घटाकर 250 करोड़ तक ला दिया। कर्ज को आधे से ज्यादा तक कम किया है।' कंपनी के इस स्थिति में फंसने के कई कारण थे। अशोक लीलैंड ने बूम के दौरान बिना पुख्ता योजनाओं के तेजी से विस्तार शुरू कर दिए, जिसके लिए भारी कर्ज लिया। परिस्थितियां पलटते ही यह दांव उल्टा पड़ गया और कंपनी कर्ज के जाल में फंसने लगी। हालांकि नीतियों में बदलाव, लागत में कटौती जैसे बुनियादी सुधारों ने उसे न केवल वापस पटरी पर लौटाया बल्कि कॉमर्शियल वाहनों के निर्माण में आज देश की दूसरी बड़ी कंपनी बनाया। आज ब्रांड से सबक में पढ़ते हैं कहानी अशोक लीलैंड की।

वर्तमान स्थिति

दुनिया की चौथी बड़ी बस निर्माता कंपनी

अशोक लीलैंड आज भारत ही नहीं दुनिया की बड़ी कॉमर्शियल वाहन बनाने वाली कंपनियों में शामिल है। यह देश की दूसरी सबसे बड़ी कमर्शियल वाहन निर्माता कंपनी है। जबकि बस निर्माण में इसका दुनिया में चौथा स्थान है। 50 से अधिक देशों में इसका व्यापार है। मार्केट कैप करीब 93 हजार करोड़ रुपए है। कंपनी सैन्य बलों के लिए भी वाहन बनाती है। उत्तर प्रदेश में ईवी प्लांट लगाने जा रही है, जहां हर साल 5000 यूनिट उत्पादन क्षमता का लक्ष्य कंपनी ने रखा है।

सबक क्यों- कभी कंपनी पर उसकी वैल्यू से ज्यादा कर्ज हो गया था। आज 50 से अधिक देशों में कर रही व्यापार।

3,383 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 में

93 हजार करोड़ रुपए से अधिक का मार्केट कैप है कंपनी का वर्तमान में

2 नंबर पर है भारत में वाणिज्यिक वाहन निर्माण के मामले में

32 प्रतिशत हिस्सेदारी है देश के मध्यम एवं भारी कॉमर्शियल व्हीकल में

कॉमर्शियल ट्रक और बस बनाने से पहले अशोक लीलैंड देश में ब्रिटेन की अस्टिन कार असेंबल करती थी।

ऐसे संकट में फंसी अशोक लीलैंड

1. **इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग सेक्टर में मंदी-** 2011-14 में जीडीपी ग्रोथ घटने से इंफ्रा प्रोजेक्ट्स रुके। ओडिशा, कर्नाटक ने ट्रक डिमांड 45% तक घटा दी। कंपनी की मीडियम और हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स की सेल्स 42% तक प्रभावित हुई।
2. **भारी कर्ज, अधिक लागत-** कंपनी ने विस्तार के लिए करीब 6,160 करोड़ का कर्ज लिया। 2011-14 में सेल्स गिरी, लेकिन कंपनी के फिक्स्ड खर्च बने रहे। इससे प्रति यूनिट लागत बढ़ती गई।
3. **ग्लोबल मंदी से निर्यात में गिरावट :** यूरोपीय कर्ज और वैश्विक सुस्ती के चलते अशोक लीलैंड का निर्यात करीब 30 प्रतिशत तक गिर गया। इसके साथ ही सार्क बाजारों में भी मांग कमजोर पड़ गई।
4. **ओवर-कैपेसिटी-** 2010-12 में कंपनी ने हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर 2,500 करोड़ रु. झोंक दिए, लेकिन कई प्लांट का केवल 40% ही उपयोग हुआ।

इस तरह की वापसी

1. **कर्ज घटाया, बैलेंस सीट मजबूत की-** 2014 के बाद अशोक लीलैंड ने कर्ज को 6,200 करोड़ रुपए से घटाकर करीब 3,000 करोड़ किया। रोजमर्रा के खर्चों को 80 प्रतिशत तक घटाया, जिससे मैन्युफैक्चरिंग आत्मनिर्भर बनी।।
2. **एलसीवी, बस और हल्के वाहनों में विस्तार-** सिर्फ भारी बस/ट्रक पर निर्भरता कम करके हल्के वाणिज्यिक वाहन (एलसीवी), बसों और विभिन्न प्रकार के वाहन बनाने शुरू किए। लचीलापन बढ़ाया।
3. **ब्रांड की पुनर्स्थापना-** कंपनी ने भरोसेमंद, ट्रकों और बसों की अपनी पुरानी पहचान को मजबूत किया। मांग सुस्त होने के बाद जब इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश बढ़ा तो ग्राहकों ने सबसे पहले इसे चुना।
4. **इनोवेशन -** 2016 में कंपनी ने देश की शुरुआती इलेक्ट्रिक बसें और यूरो-6 ट्रक उतारे। ईवी पर फोकस बढ़ाया। बैटरी निर्माण में 5,000 करोड़ निवेश किया।

पंडित नेहरू के कहने पर कारों की असेंबलिंग शुरू की थी

शुरुआत : स्वतंत्रता सेनानी रघुनंदन सरन ने चेन्नई में रखी थी नींव

1948 में स्वतंत्रता सेनानी रघुनंदन सरन ने दिवंगत बेटे अशोक के नाम पर चेन्नई में अशोक मोटर्स की शुरुआत की थी। पंडित नेहरू के कहने पर ब्रिटिश ऑस्टिन कार की असेंबलिंग शुरू हुई। 1950 में ब्रिटेन के लीलैंड से साझेदारी कर कमेट ट्रक बनाया। 1955 में नाम पड़ा 'अशोक लीलैंड'। इसके बाद 1987 में हिंदुजा भाइयों ने कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी खरीदकर स्वामित्व पा लिया।

गिरावट : बूम के समय भारी निवेश, फिर मंदी से आया संकट

कंपनी ने पहले के बूम के समय भारी निवेश किया, प्लांटों का विस्तार किया, नए प्रोडक्ट पर आक्रामक तरीके से खर्च किया, जो बाद में मांग गिरने पर बोझ बन गया। कॉमर्शियल व्हीकल सेक्टर, खासकर मध्यम एवं भारी वाणिज्यिक वाहनों में 2012-14 के बीच तेज मंदी, डिस्काउंटिंग व वॉल्यूम गिरावट के कारण रेवेन्यू और मुनाफा दोनों ध्वस्त हुए।

ऐसे पड़ा नाम : अशोक नाम संस्थापक रघुनंदन सरन के बेटे अशोक से आया। ब्रिटिश लीलैंड के 40% स्टेक और जॉइंट वेंचर से अशोक लीलैंड बना।

सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी : कॉमर्शियल वाहनों में टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और आयशर मोटर्स इसके प्रमुख प्रतिद्वंद्वी हैं।

पीपुल भास्कर | अक्षय खन्ना | बॉलीवुड अभिनेता

अक्षय को 'द सीक्रेट' किताब, अकेलापन और खाना पसंद, कहते हैं लंच में ही डिनर के बारे में सोचने लगता हूं

साल 2012, एक फिल्म आई 'गली गली चोर है'। अक्षय खन्ना के लीड रोल वाली इस फिल्म में श्रिया सरन, अन्नू कपूर, सतीश कौशिक जैसे कलाकार थे। फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद करीब 4 साल तक अक्षय खन्ना फिल्मी दुनिया से पूरी तरह दूर हो गए। उनके करियर और स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की अफवाहें उड़ने लगीं, लेकिन 2019 में आई फिल्म 'सेक्शन 375' और 2022 में फिल्म 'दृश्यम' के साथ उन्होंने धमाकेदार वापसी की।

2016 में एक मीडिया संस्थान को दिए साक्षात्कार में अक्षय कहते हैं 'मैं घर बैठकर पागल नहीं हो रहा था, बस अच्छी स्क्रिप्ट का इंतजार कर रहा था' उनके बारे में फिल्म निर्देशक करण जौहर ने एक बार मजाक में कहा था कि अगर अक्षय खन्ना को किसी वीकेंड पर ऑस्कर अवॉर्ड भी मिल रहा होगा तो वह यह कहकर मना कर देंगे कि वह वीकेंड पर घर से नहीं निकलते। अक्षय खन्ना एक ऐसे स्टार हैं जो फिल्में भी कम करते हैं, लाइमलाइट और इंटरव्यूज से भी दूर भागते हैं। अपने साउथ बॉम्बे के घर में अकेले रहना उन्हें बेहद पसंद है। बॉलीवुड में हीरो बनने का सपना लेकर आए अक्षय को 19 साल की उम्र में ही बालों से जुड़ी बीमारी एलोपेसिया से जूझना पड़ा। उनके बाल तेजी से झड़ने लगे। इसके बारे में अक्षय ने एक साक्षात्कार मे कहा 'एक हीरो के लिए यह बिल्कुल वैसा ही है, जैसे किसी पियानिस्ट की उंगलियां कट जाएं।' वे लेखिका रॉन्डा बर्न की किताब 'द सीक्रेट' के बड़े प्रशंसक है। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था कि 'इसने मेरी जिंदगी बदल दी।'

चर्चा में क्यों- हाल ही में आई फिल्म 'धुरंधर' में उन्होंने रहमान डकैत का किरदार निभाया है। उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है।

अक्षय खन्ना एक ऐसे स्टार हैं जो लाइमलाइट और इंटरव्यूज से भी दूर भागते हैं।

जन्म : 28 मार्च 1975 (50 साल), मुंबई, महाराष्ट्र
शिक्षा : एच.आर. कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, मुंबई से स्नातक।
परिवार : बड़े भाई राहुल खन्ना, सौतेली मां- कविता खन्ना, सौतेले भाई-बहन- साक्षी और श्रद्धा खन्ना
सम्पत्ति : करीब 167 करोड़ रु.
(विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स)

शुरुआत
5 साल के थे जब पिता बन गए थे संन्यासी

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना के घर अक्षय का जन्म हुआ था, लेकिन उनका बचपन काफी कठिन रहा। अक्षय जब 5 साल के थे तभी विनोद खन्ना बॉलीवुड छोड़कर अमेरिका के ओरेगॉन में ओशो के शिष्य बन गए। वे 4 साल वहां रहे। इस दौरान मां गीतांजलि तलेयारखान ने उन्हें और उनके बड़े भाई राहुल की परवरिश की।

विवाह
खुद को 'बंधन' में रहने वाला शख्स नहीं मानते

अक्षय खुद को 'मैरिज मटीरियल' नहीं मानते। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा 'मैं कंट्रोल नहीं देना चाहता। शादी में जीवन साझा करना पड़ता है।' 90 के दशक में करिश्मा कपूर और फिर बाद में तारा शर्मा के साथ लिंकअप की खबरें आई थीं, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी। कुछ समय पहले उन्होंने कहा था कि अब नहीं लगता कि शादी हो सकती है।

करियर
दूसरी ही फिल्म में मिल गया फिल्म फेयर अवार्ड

अक्षय खन्ना ने 1997 में 'हिमालय पुत्र' से डेब्यू किया। फिल्म असफल रही, लेकिन उसी साल आई 'बॉर्डर' में लेफ्टिनेंट की भूमिका के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उन्होंने रोमैंटिक भूमिकाओं से लेकर कॉमेडी फिल्मों तक में अभिनय की छाप छोड़ी, लेकिन 'दृश्यम-2', 'छावा' और 'धुरंधर' जैसी फिल्मों में ग्रे शेड किरदारों ने असली पहचान दी।

रोचक : 'धुरंधर' की शूटिंग के दौरान ऑक्सीजन की कमी होने पर सिलेंडर का इस्तेमाल किया

खास : फराह खान ने ऑस्कर अवॉर्ड दिए जाने की मांग की है

- किसी भी तरह का सोशल मीडिया प्लेटफार्म इस्तेमाल नहीं करते।
- धुरंधर फिल्म की लद्दाख में शूटिंग के दौरान उन्होंने पर्याप्त ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर का इस्तेमाल किया।
- कोरियोग्राफर फराह खान ने 'धुरंधर' फिल्म के लिए उन्हें ऑस्कर दिए जाने की मांग की है।

उपलब्धि : बेस्ट डेब्यू, सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवॉर्ड

- 2007 में आई फिल्म 'गांधी, माई फादर' के लिए उन्हें प्रोड्यूसर गिल्ड में बेस्ट एक्टर के लिए नामित किया जा चुका है।
- 1998 में आई फिल्म 'बॉर्डर' और 2002 में आई 'दिल चाहता है' के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है।

तन्हाई पसंद : हाई प्रोफाइल सोशल लाइफ से दूर रहते हैं

- खुद को 'ऑडबॉल' कह चुके हैं। उन्हें हाई-प्रोफाइल सोशल लाइफ, पार्टीज और लगातार पब्लिक अटेंशन से दूर रहना सहज लगता है।
- अपने साउथ बॉम्बे के घर में अकेले रहना पसंद है। वे काफी फूडी हैं। कहते हैं लंच के दौरान ही मैं डिनर के बारे में सोचना शुरू कर देता हूं कि रात में क्या खाऊंगा।

सरला ने खेती में किए कई प्रयोग...

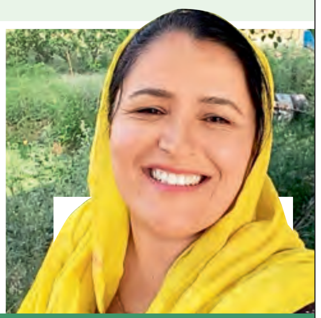

मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

हरियाणा के मेहमुदपुर गांव की सरला देवी ने अपने पति के लिए न केवल आयुर्वेदिक उपचार खोजा बल्कि महिलाओं और किसानों के लिए मोरिंगा उत्पादों के रूप में रोजगार का जरिया भी तलाशा। उच्च गुणवत्तायुक्त मोरिंगा फसल के लिए उन्होंने खेतों में कई प्रयोग किए। जिससे उन्हें देश-विदेश में पहचान मिली। आज उनके मोरिंगा उत्पाद यूएसए और यूएई में पसंद किए जा रहे हैं। वह बताती हैं कि शुरुआत में उन्होंने मोरिंगा की पत्तियों का उपयोग औषधी के रूप में किया। इसके बाद इसकी जड़ें और तने के भी स्वास्थ्य उत्पाद बनाने लगे। वह किसानों को निशुल्क बीज उपलब्ध करवाती हैं और खेती की ट्रेनिंग देती हैं।

दोस्त ने दी सलाह

वह बताती हैं कि पति दिल्ली में 11 वर्षों से कार्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे थे। इस दौरान उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं ने घेर लिया। बार-बार दवाएं खाने पर भी फायदा नहीं हो रहा था। ऐसे में एक दोस्त ने मोरिंगा की कुछ पत्तियां दी और इसके उपयोग की सलाह दी। उन्होंने इसे टेरेस गार्डन में लगाया और स्वास्थ्य के लिए उपयोग में लिया। पति को कमर दर्द, पाचन, हृदय संबंधित बीमारियों में इससे लाभ हुआ। इसके बाद 2017 में उन्होंने इसकी खेती करनी शुरू की।

मिट्टी को बनाया उपजाऊ

वह बताती हैं कि मोरिंगा के कई तरह के लाभ देखकर नौकरी छोड़कर वे पैतृक गांव में बस गए। लेकिन मिलावटी बीजों के कारण मोरिंगा के औषधीय गुण प्रभावित हुए। वहीं क्षेत्र की मिट्टी में पोषक तत्त्वों की काफी कमी पाई गई। इसके लिए उन्होंने कई लोगों से जानकारी एकत्रित की और मोरिंगा की पत्तियों को दो साल तक मल्चिंग प्रक्रिया अपनाई और जमीन को उपजाऊ बनाया। इसके बाद उन्होंने 2018 में मोरिंगा के उत्पाद बनाना शुरू किया। जिससे उन्हें सफलता मिली।

काम की बात

होममेड फेस पैक से पाएं निखार

सर्दियों में ठंडी हवाओं और कम आर्द्रता की वजह से त्वचा सूखी और बेजान हो जाती है। ऐसे में त्वचा को हाइड्रेट रखने और उसे मुलायम बनाने के लिए घरेलू सामग्री का उपयोग लाभदायक रहता है। होममेड फेस पैक से न केवल त्वचा को हाइड्रेट रखा जा सकता है बल्कि नरम और चमकदार भी बनाया जा सकता है। इसके लिए आप आलू, दही, नींबू, शहद और बादाम तेल जैसी प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग कर सकती हैं। आइए जानते हैं किस तरह से फेस पैक बनाएं...

कैसे बनाएं

- **दही और हल्दी का फेस पैक:** यह त्वचा की गहराई से सफाई के साथ संक्रमण से भी बचाता है। इसे बनाने के लिए एक चम्मच दही में एक चुटकी हल्दी मिलाएं और इसे चेहरे पर 15-20 मिनट तक लगाकर धो लें। यह पैक त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाता है।
- **शहद और बादाम तेल का फेस पैक-** शहद त्वचा को हाइड्रेट करता है जबकि बादाम तेल में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स स्किन को मुलायम बनाते हैं और उसे डैमेज होने से बचाते हैं। इस पैक को बनाने के लिए 1 चम्मच शहद और 5-6 बूंद बादाम तेल को अच्छे से मिला लें। इसे चेहरे पर 15-20 मिनट के लिए लगाकर धो लें।
- **आलू और नींबू का फेस पैक:** ब्लीचिंग गुणों से भरपूर इस फेस पैक को बनाने के लिए आधे आलू को कद्दूकस कर उसमें कुछ बूंद नींबू का रस मिला लें। इसे चेहरे पर लगाकर 15 मिनट तक छोड़ें और फिर धो लें।
- **ऑटमील और दूध का फेस पैक:** यह त्वचा को एक्सफोलिएट करने के साथ नमी प्रदान करती है। इसके लिए 2 चम्मच ऑटमील में 1 चम्मच दूध मिलाएं और इसे चेहरे पर हल्के हाथों से लगाकर कुछ देर तक मसाज करें। फिर इसे धो लें। यह पैक त्वचा को शुद्ध करता है।

ज्योति
ब्यूटी एक्सपर्ट
patrika.com

साइबर अलर्ट

ओपन वाई-फाई पर न खोलें पर्सनल अकांउट, हो सकता है हैक

क्या करें...

ओपन वाई-फाई पर हैकर्स वायरस या मैलवेयर डाल देते हैं, जिससे आपका अकाउंट खुलते ही हैक हो जाता है। इसके लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करें।

कई बार पब्लिक वाई-फाई बिना पासवर्ड के ओपन हो जाते हैं। ऐसे वाई-फाई का इस्तेमाल करते समय आपको अपने पर्सनल अकाउंट नहीं खोलने चाहिए, क्योंकि इस तरह के वाई-फाई पर हैकर्स अधिक सक्रिय रहते हैं। ऐसे वाई-फाई पर जब आप अपने पर्सनल अकाउंट का पासवर्ड डालते हैं तो वह हैक कर लिया जाता है। बिना पासवर्ड वाले नेटवर्क पर अनएन्क्रिप्टेड होता है, जिससे डाटा आसानी से चुराया जा सकता है।

अधिकार

गिफ्ट में मिली संपत्ति पर होता है मालिकाना हक

महिला का उपहार स्वरूप मिली संपत्ति पर एकतरफा मालिकाना हक होता है। चाहे वह संपत्ति (मकान हो या जमीन के रूप में) पति, सास, ससुर, पिता, भाई या किसी अन्य रिश्तेदार ने उसे गिफ्ट दी हो, वह पूरी तरह से स्त्रीधन की श्रेणी में मानी जाती है। जब तक महिला न चाहे तब तक उस संपत्ति को कोई खरीद या बेच नहीं सकता, न ही कोई उससे वापस ले सकता है। हालांकि इस संपत्ति का हस्तांतरण एक वैध गिफ्ट डीड के माध्यम से होना आवश्यक है। ऐसा होता है तो महिला कानून की सहायता ले सकती हैं। पति इस संपत्ति को पत्नी के भरण-पोषण के दावे में शामिल नहीं कर सकता।

किचन में कार्य करते समय खाना बनाने से लेकर उसकी साफ-सफाई तक में काफी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर आपके पास कुछ किचन सॉल्यूशन हों तो आपके नाम व अपनी फोटो सहित हमें वॉट्सएप नंबर ***9057531584*** पर भेजें। शी न्यूज पेज पर इन्हें प्रकाशित किया जाएगा। फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए यह क्यूआर कोड स्कैन करें।

पत्रिका शी न्यूज़
हमसे जुड़ें facebook.com/patrikaSheNews

शिक्षा विभाग के दावे फेल: 352 छात्राओं की पढ़ाई संकट में

झाडोली स्कूल में दो-दो कक्षाएं एक साथ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अधर में

पत्रिका ग्राउंड रिपोर्ट

सिरोही @ पत्रिका. शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षण व्यवस्थाओं के दावे कर रहा है, लेकिन जिले में कई स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं तो कई में भौतिक संसाधन पर्याप्त नहीं हैं। जिले के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय झाडोली में कक्षा-कक्ष की कमी, परिसर छोटा व अन्य मूलभूत सुविधाओं का टोटा है। इसके बाद भी शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह स्कूल पहली से बारहवीं तक संचालित हैं, लेकिन इसमें कमरे केवल आठ हैं। कक्षा-कक्षों की कमी होने से दो-दो कक्षाएं एक साथ संचालित करनी पड़ रही हैं। ऐसे में बालिकाओं की कैसी पढ़ाई होती होगी, इसका सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। एक साथ दो कक्षाएं संचालित होने से बालिकाओं की पढ़ाई प्रभावित होती है। इस गंभीर समस्या को लेकर ग्रामीणों ने भी कई बार शिक्षा विभाग व प्रशासन अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन अभी तक समस्या जस की तस बनी हुई है। वर्तमान में स्कूल में 352 बालिकाएं अध्ययनरत हैं।

स्कूल में एक साथ बैठकर पढ़ाई करतीं दो कक्षाओं की बालिकाएं।

स्कूल में एक भी व्याख्याता नहीं

स्कूल एक भी व्याख्याता नहीं है। साथ ही सैकण्ड ग्रेड के तीन पद रिक्त चल रहे हैं। स्कूल में कुल 13 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से केवल आठ कर्मचारी ही कार्यरत हैं। हालांकि गत दो साल से 10वीं बोर्ड का परिणाम शत-प्रतिशत रहा है, लेकिन शिक्षकों की कमी से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी खल रही है।

लैब, पुस्तकालय और खेल मैदान भी नहीं

स्कूल में ना तो कोई आईसीटी लैब है, ना ही पुस्तकालय कक्ष। खेलने के लिए मैदान भी नहीं है। स्कूल 2022 में क्रमोन्नत होने के बाद आज दिन तक कोई सुविधा इस स्कूल को नहीं मिली। स्कूल में कला वर्ग होने के कारण भूगोल विषय संचालित है, लेकिन प्रयोगशाला के लिए कक्ष ही नहीं है।

उच्च अधिकारियों को करवाया अवगत

स्कूल पहली से 12वीं तक संचालित हैं, जिसमें 352 बालिकाएं अध्ययनरत हैं। कक्षा-कक्षों की कमी होने से दो-दो कक्षाएं एक साथ संचालित करनी पड़ रही है। स्कूल अन्य जगह शिफ्ट करने के लिए उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया है, आदेश मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। **विद्या सिंघल,** प्रधानाचार्य, राबाउमावि झाडोली

स्कूल अन्य जगह शिफ्ट हो तो मिले राहत

बालिका स्कूल में कक्षाकक्षों की कमी से बालिकाओं को बैठने में परेशानी हो रही है। इस समस्या को लेकर हमने आगे भी अवगत कराया था, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ। इस स्कूल को नई झाडोली स्थित स्कूल भवन में शिफ्ट कर दिया जाए तो शिक्षकों व विद्यार्थियों को राहत मिल सकती है। वहां पर खेल मैदान है और पर्याप्त जगह होने से संचालन में सुविधा रहेगी।
जसवंत सिंह, सेवानिवृत शिक्षक, झाडोली

कलक्टर व सांसद को बताई समस्या

बालिका स्कूल में मूलभूत सुविधाओं को लेकर कुछ दिनों पहले झाडोली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जिला कलक्टर व सांसद को अवगत कराया था। स्कूल का परिसर काफी छोटा होने से बालिकाओं व शिक्षकों को बैठने की समस्या आ रही है।
परबत सिंह, उप प्रशासक, ग्राम पंचायत झाडोली

सैलानियों की सुविधा के लिए कवायद शुरू

स्वर्णनगरी में ऐतिहासिक सोनार दुर्ग के चारों तरफ दौड़ेंगी गोल्फ कार्ट

जैसलमेर स्थित ऐतिहासिक सोनार दुर्ग।

जैसलमेर @ पत्रिका. जैसलमेर के सोनार दुर्ग को ध्वनि प्रदूषण और यातायात की अव्यवस्थाओं में सुधार के बीच नगरपरिषद की तरफ से एक और नवाचार करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत सोनार दुर्ग के चारों तरफ यानी रिंग रोड में गोल्फ कार्ट चलाने की योजना बनाई गई है। जिस तरह से गड़ीसर में नगरपरिषद की तरफ से नौकायन का ठेका किया जाता है, उसी तर्ज पर गोल्फ कार्ट की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत आगामी 17 दिसम्बर को नगरपरिषद में दोपहर 2 से 4 बजे तक सार्वजनिक नीलामी करवाई जाएगी। जिसमें गोल्फ कार्ट का संचालन करने वाली फर्म या कोई संस्था, व्यक्ति आदि टेंडर प्रक्रिया में भाग ले सकता है। इसके लिए जहां 50 हजार रुपए धरोहर राशि परिषद में जमा करवानी होगी, वहीं न्यूनतम बोली 2 लाख रुपए रखी गई है।

आवाजाही के लिए बेहतर विकल्प

जैसलमेर का सोनार दुर्ग विश्व विरासत है। यहां सीजन के समय प्रतिदिन हजारों सैलानी भ्रमण के लिए पहुंच रहे हैं। उनकी सुविधा के लिए रिंग रोड पर गोल्फ कार्ट का संचालन किए जाने की योजना बनाई गई है। उम्मीद करते हैं कि ऐसे में दुर्ग के चारों तरफ रिंग रोड में आवाजाही के लिए गोल्फ कार्ट एक बेहतरीन विकल्प सिद्ध हो सकेगा।
- लजपालसिंह सोढ़ा, आयुक्त, नगरपरिषद जैसलमेर

सफल बोलीदाता को यह कार्य 3 साल के लिए दिया जाएगा और उसे 10 प्रतिशत शुल्क वृद्धि के साथ अंतिम तौर पर बोली गई राशि नगरपरिषद में जमा करवानी होगी।

मानवाधिकार की दिलाई शपथ

कार्यक्रम को संबोधित करते एएसपी आशाराम चौधरी।

नागौर @ पत्रिका. बीआर मिर्धा राजकीय महाविद्यालय में बुधवार को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर व्याख्यान, पोस्टर-स्लोगन व भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई।महाविद्यालय की मानवाधिकार प्रकोष्ठ समिति, राष्ट्रीय सेवा योजना और निर्वाचन साक्षरता क्लब के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत संयोजक डॉ. सुभाष यादव ने मानवाधिकार शपथ दिलवाकर की। मुख्य वक्ता विधि कॉलेज के प्राचार्य डॉ. हर्ष इनाणिया ने मानवाधिकारों के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। प्राचार्य डॉ. हरसुख राम छरंग ने मानवाधिकारों को सभ्य समाज की आधारशिला बताते हुए विद्यार्थियों से अधिकारों के साथ कर्तव्यों के पालना की अपील की।

10 किलोमीटर विहार कर गुड़ा रामसिंह पहुंचे तेरापंथ अधिशास्ता

चौरासी लाख जीव योनियों में मात्र मानव जीवन अतिमहत्वपूर्ण: आचार्य महाश्रमण

मारवाड़ जंक्शन @ पत्रिका. जैन श्वेताम्बर तेरापंथ धर्मसंघ के वर्तमान अधिशास्ता, शांतिदूत युगप्रधान आचार्यश्री महाश्रमण जाणुंदा से गुड़ा रामसिंह की ओर विहाररत हुए। मार्ग में विद्यार्थियों, महिलाओं एवं ग्रामीणों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए लगभग 10 किलोमीटर का विहार कर जब आचार्यश्री गुड़ा रामसिंह पहुंचे तो पूरा ग्राम भावविभोर होकर अपने आराध्य के स्वागत में उमड़ पड़ा। आचार्यश्री अपनी धवल तपस्वी सेना के साथ पारसमल गादिया के निवास पर पहुंचे। जहां श्रद्धालुओं ने विनम्रता पूर्वक स्वागत-निवेदन किया।

प्रवचन के पश्चात साध्वीप्रमुखा विश्रुतविभाजी ने भी श्रद्धालुओं को संबोधित किया। तेरापंथ सभा के अध्यक्ष गौतमचंद गादिया व माणकचंद गादिया ने आराध्य के स्वागत में अपनी श्रद्धाभिव्यक्ति प्रस्तुत की। तेरापंथ महिला मंडल ने स्वागत गीत की प्रस्तुत दी। बच्चों ने भी मनमोहक प्रस्तुति से सभी को आनंदित किया। संसारपक्ष के साधु मुनि प्रितकुमारजी सहित अभिनंदन गादिया, जेपी गादिया तथा इंदरचंद गादिया ने भावनाएं अभिव्यक्त कीं।

ज्ञान से खुलते हैं सन्मार्ग के द्वार: आचार्य ने कहा कि ज्ञान अपने आप में परम शक्ति है। विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय ज्ञान प्राप्ति के अनेक साधन उपलब्ध हैं। जहां भी अवसर मिले ज्ञान अर्जित करना चाहिए। साधु-साध्वियों की संगति, प्रवचन श्रवण से उत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है। आज के युग में तो यंत्रों के माध्यम से भी प्रवचन श्रवण सहज संभव है। उन्होंने सम्यक ज्ञान की प्राप्ति को जीवन उन्नयन का आधार बताया।

मारवाड़ जंक्शन. गुड़ा रामसिंह गांव में आशीर्वाद देते आचार्यश्री।

वैराग्य, अणुव्रत और साधना की ओर प्रेरणा

आचार्यश्री ने कहा कि जिस परिवार से साधु-साध्वियां दीक्षा ग्रहण करते हैं, वह परिवार अत्यन्त पुण्यशाली माना जाता है। यदि पूर्ण वैराग्य न भी आए तो भी धर्ममार्ग पर चलना जीवन का कल्याण कर देता है। अणुव्रत के छोटे-छोटे नियम भी जीवन को श्रेष्ठ दिशा प्रदान कर सकते हैं। आचार्यश्री ने गुड़ा रामसिंह की धार्मिक परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि यह स्थान प्राचीनकाल में चातुर्मास स्थल भी रहा है। आज यहां विशाल संख्या में धर्मप्रेमी जन एकत्र हुए हैं, सभी में यह धार्मिक भावना स्थिर बनी रहे।

छात्राओं ने सीखे आत्मरक्षा के गुर

डीडवाना @ पत्रिका. शहर स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में एक माह से संचालित रानी लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण केन्द्र के आत्मरक्षा शिविर का बुधवार को प्रमाण-पत्र वितरण समारोह के साथ समापन किया गया। एक माह के प्रशिक्षण शिविर में छात्राओं ने आत्मरक्षा के गुर सीखे। शिविर का संचालन प्रशिक्षक सुमन बेनीवाल, शर्मिला प्रजापत और निरमा ढ़ाका के मार्गदर्शन में किया गया। समापन कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, डीडवाना की प्राचार्य डॉ. मनीषा गोदारा रहीं। उन्होंने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मबल से छात्राओं के अन्दर आत्मविश्वास बढ़ता है, जो उनके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। उन्होंने प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाली सभी छात्राओं को प्रमाण-पत्र वितरित किए। डॉ. गोदारा ने भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने आत्मरक्षा से सम्बंधित अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर राजकीय कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. इरशाद अली खां, कार्यक्रम संयोजक सुमन गोदारा, सुनीता आदि मौजूद रहे।

हनुमान चालीसा हनुमान का शब्दावतार, रोज पाठ करें: पंडित विजय शंकर

मकराना @ पत्रिका. जूसरी रोड स्थित गेला मेला बालाजी मंदिर में बुधवार को महंत बनवारी शरण शास्त्री (जूसरी) के सानिध्य में एक शाम हनुमान के नाम का आयोजन किया गया। पंडित विजय शंकर मेहता ने हनुमान चालीसा को हनुमान का शब्दावतार बताते हुए कहा कि घर-परिवार में सुख-समृद्धि एवं शांति बनी रहे, इसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करने सहित बच्चों को संस्कारवान बनाना होगा। जीवन में चार मार्ग संसार, संपति, स्वास्थ्य तथा संतान के माध्यम से अशांति आती है। जिसमें से तीन कारणों का तो किसी प्रकार से सामना किया जा सकता है, लेकिन संतान के माध्यम से आने वाली अशांति का सामना कर पाना मुश्किल होता है।

जीवाणा में किसानों का हल्ला बोल, विद्युत समस्याओं के खिलाफ धरना

जालोर. जीवाणा@ पत्रिका. क्षेत्र में लगातार बढ़ रही बिजली समस्याओं, अनियमित कटौती और कम वॉल्टेज की मार से त्रस्त किसानों ने बुधवार को प्रदर्शन किया। किसान संघ जीवाणा की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में किसान जीवाणा बिजली घर के सामने एकत्र हुए और जोरदार नारेबाजी करते हुए सरकार के रवैये पर कड़ा विरोध जताया। किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम सूरजभान विश्नोई को विस्तृत ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। किसानों ने कहा कि रबी सीजन के बीच बिजली कटौती ने खेती को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। कई गांवों में रोजाना कई घंटों तक बिजली गुल रहती है, जिससे सिंचाई कार्य ठप हो जाता है।

कृषि बेरों पर बिजली के कम वोल्टेज के कारण पम्पसेट जल रहे हैं और किसान भारी आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं। किसान नेताओं ने बताया कि सरकार की उदासीनता के कारण कृषि कार्य बाधित हो रहे हैं, जबकि समय पर सिंचाई नहीं होने से फसलों की उत्पादकता पर सीधा असर पड़ रहा है। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि हालात नहीं सुधरे तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

जीवाणा. बिजली विभाग के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करते किसान।

जोधपुर डिस्कॉम: 2000 मेगावाट सौर क्षमता पार करने के बाद भी उपभोक्ता फाइलों के चक्कर में परेशान

पीपीए की उलझनों ने रोकी सौर ऊर्जा की रफ्तार

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जोधपुर. जोधपुर डिस्कॉम ने सौर ऊर्जा उत्पादन में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए 2000 मेगावाट से अधिक सौर क्षमता हासिल करने का तमगा लिया, जो प्रदेश में ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। दूसरी ओर, सौर ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़े पीपीए (पॉवर पर्चेज एग्रीमेन्ट) की प्रक्रियाएं अब भी उलझनों में फंसी हुई हैं। बड़ी संख्या में उपभोक्ता और उत्पादन इकाइयों के मालिक आज भी डिस्कॉम कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि उनके पीपीए संबंधित प्रकरण अधरझूल में पड़े हुए हैं।

फाइलें अटकी: आवेदकों का कहना है कि पीपीए जारी करने और संशोधित कराने से जुड़ी फाइलें महीनों से आगे नहीं बढ़ रही हैं। जोधपुर डिस्कॉम की डीएसएम सेल में पहुंचने वाले उपभोक्ताओं को अक्सर एक ही जवाब मिलता है- फाइल नहीं मिल रही है। यह स्थिति न केवल उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ा रही है, बल्कि सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने वाली प्रमुख योजनाओं की गति को भी प्रभावित कर रही है।

भुगतान अटका: उधर, परियोजना से जुड़े ईएमडी (अरनेस्ट मनी डिपोजिट) के भुगतान में भी कई मामले रुके पड़े हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोगों का भुगतान अटका हुआ है। इससे निवेशकों और किसानों दोनों में असंतोष बढ़ रहा है, क्योंकि भुगतान लंबित रहने से उनकी वित्तीय योजनाएं बाधित हो रही हैं।

शिकायतों पर कार्रवाई: बढ़ती शिकायतों को देखते हुए प्रबंधन स्तर पर कार्रवाई की शुरुआत की गई है। पहले इस पूरे मामलों की मॉनिटरिंग अतिरिक्त मुख्य अभियंता आरएन विश्नोई कर रहे थे, लेकिन प्रक्रियाओं में तेजी लाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विश्नोई को हटाकर यह जिम्मेदारी अब संभागीय मुख्य अभियंता (जोधपुर ज़ोन) पी.एस. चौधरी को सौंपी गई है।

एमडी ने दिए निर्देश : डिस्कॉम प्रबंध निदेशक डॉ. भंवरलाल ने भी स्थिति की गंभीरता को समझते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पीपीए और ईएमडी से जुड़े सभी प्रकरणों का पारदर्शिता के साथ निस्तारण किया जाए।

पीपीए क्या है

पीपीए, बिजली खरीद समझौता है, जो बिजली उत्पादक और खरीदार के बीच एक दीर्घकालिक अनुबंध है। इसका उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण सुरक्षित करने और बिजली की कीमतों में उतार-चढ़ाव के जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है।

इनका कहना है

पीपीए प्रकरणों को निस्तारण के लिए 40 कर्मचारियों की दो टीमें बनाई गई है। मॉनिटरिंग भी की जा रही है। प्रतिदिन करीब 70-80 फाइलें निस्तारित की जा रही है। 30 दिसंबर तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा।
- पी.एस.चौधरी, संभागीय मुख्य अभियंता, जोधपुर जोन, डिस्कॉम

आज का राशिफल शुक्रवार, 12 दिसंबर, 2025

पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद्

मेष — **मिश्रित प्रभाव वाला दिन रहेगा।** आवश्यक कार्य थोड़ी जल्दी निपटाने होंगे। पुराने अनुबंधों से जुड़े खर्च परेशान कर सकते हैं। भावनात्मक संबंधों में मुलाकात से आपसी समझ बेहतर होगी।

वृषभ — **विद्यार्थियों को शैक्षणिक गतिविधियों में जुटे रहना होगा।** अभिरुचियों के अनुसार व्यवस्थाएं मिलने से प्रसन्न रहेंगे। परिणाम भी बेहतर आएंगे। संबंधों से विशेष सहयोग मिलेगा।

मिथुन — **नियमों की पालना की तरफ विशेष ध्यान देना होगा।** उच्च अधिकारियों के साथ तनाव लेने से बचें। परिश्रम की अधिकता संबंधों के प्रति असंवेदनशील बन सकती है।

कर्क — **कार्यों की गति सहज रहेगी।** वार्तालाप में आपका पक्ष मजबूत होगा। ज्ञान से संबंधित प्रतिस्पर्धा में दूसरों से आगे रहेंगे। सार्वजनिक जीवन में मान सम्मान बढ़ेगा।

सिंह — **बातचीत में दिखाया गया धैर्य और संयम दिन की दिशा तय करेगा।** जल्दबाजी नुकसानदेह साबित हो सकती है। बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना होगा।

कन्या — **कार्यों के नतीजे बेहतर आएंगे।** नए प्रयोग सफल रहेंगे। ख्याति में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। व्यवसाय में आपकी नीतियों की प्रशंसा होगी। प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने से गौरव अनुभव करेंगे।

तुला — **निर्णय लेने से पहले सभी पक्षों को सुनना बेहतर रहेगा।** व्यर्थ के विवाद पीछा कर सकते हैं। भूमि व भवन संबंधी रखरखाव पर धन खर्च होने की संभावना है। स्वास्थ्य के मुद्दे पर सावधान रहें।

वृश्चिक — **संभावनाओं से भरा हुआ दिन है।** कार्य क्षमता और दक्षता दिखानी होगी। टीमवर्क से बड़े कार्य संभव है। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। राजनीतिक क्रियाकलापों में हिस्सा लेंगे।

धनु — **कार्य सही दिशा में आगे बढ़ेंगे।** पारिवारिक जीवन भी सामान्य तौर पर बेहतर रहेगा। उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत में भविष्य की योजनाओं में आपकी भूमिका सुनिश्चित हो सकती है।

मकर — **कार्यस्थल पर सभी के साथ समन्वय बेहतर रहेगा।** परिणाम आशा अनुरूप रह सकते हैं। ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करने से बचना होगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे।

कुंभ — **कार्यस्थल पर साथी कर्मियों का सहयोग मिलना मुश्किल रहेगा।** पारिवारिक जीवन में परिस्थितियों को संभालने में थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। धैर्य रखना होगा।

मीन — **साझेदारी व्यवसाय में आपसी सहयोग बढ़ेगा।** भावनात्मक संबंधों को स्थाई संबंधों में बदलने पर बातचीत आगे बढ़ सकती है। किसी पर भी अत्यधिक भरोसा करने से बचें।

ग्रह-नक्षत्र

शुभ वि. सं:	2082	हिजरी संवत :	1447	ऋतु:	हेमंत ऋतु
संवत्सर का नाम:	सिद्धार्थ	मु.मास:	जमादि उलसानी 21	मास:	पौष
शाके संवत:	1947	अयन:	दक्षिणायन	पक्ष:	कृष्ण

आज का दिन

शुक्रवार, 12 दिसंबर, 2025

सूर्योदयकालीन लग्न व ग्रह स्थिति

श्रेष्ठ चौघड़िया: आज चर, लाभ, अमृत के चौघड़िए सूर्योदय से 11.03 तक रहेंगे। शुभ का चौघड़िया 12.20 से 1.38 तक रहेगा। चर का चौघड़िया 4.13 से सूर्यास्त तक रहेगा।

तिथि: अष्टमी तिथि दिन 2.57 तक होगी, तदुपरांत नवमी तिथि होगी।

दिशाशूल: आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा।

राहु काल वेला: (मध्यमान से) दिन 10.30 से 12.00 तक रहेगा।

नक्षत्र: उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र अंतरात्रि 5.50 तक होगा, तदुपरांत हस्त नक्षत्र होगा।

योग: प्रीति योग दिन 11.12 तक रहेगा। तदुपरांत आयुष्मान योग रहेगा।

करण: कौलव करण दिन 2.57 तक रहेगा, तदुपरांत तैतिल करण रहेगा।

चंद्रमा: आज दिन 10.21 तक सिंह राशि में होगा, तदुपरांत कन्या राशि में प्रवेश होगा।

ग्रह का राशि/नक्षत्र परिवर्तन : शुक्र वृद्धत्त्व प्रारंभ दिन 8.00 पर।

आज जन्म लेने वाले बच्चे: आज दिन 10.21 तक जन्म लेने वाले बच्चों की राशि सिंह होगी, तदुपरांत कन्या राशि होगी। अंतरात्रि 5.50 तक जन्म लेने वाले बच्चों का उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र होगा। इसके बाद हस्त नक्षत्र होगा। इन बच्चों का रजत पाद होगा। इनके प्रथम नामाक्षर टे, टो, प, पी, पू पर रखे जा सकते हैं। राशि के स्वामी सूर्य है। इस राशि के बच्चे निडर, साहसी, दयालु, ऐश्वर्यशाली, शत्रुहंता होते हैं। ये अग्नि तत्त्व की राशि हैं, ये पराक्रमी व बुद्धिमान, उधमी, कर्मठ, निडर, स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं और बड़े काम से घबराते नहीं हैं। इनमें नैसर्गिक नेतृत्त्व क्षमता होती है। जातक कुशलनीति के अनुसार आचरण करने वाला, उच्चकांक्षी आदि होते हैं।

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। **–वाल्तेयर**

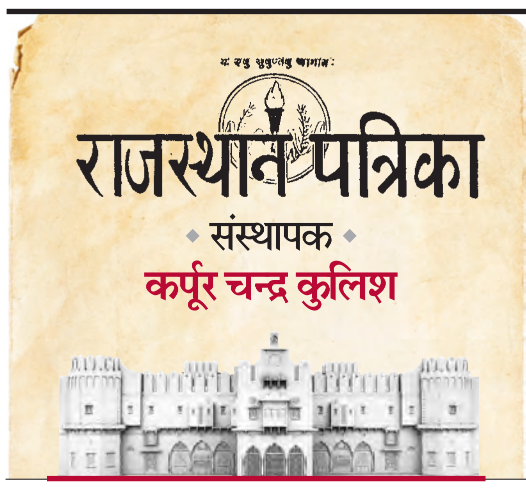

धार्मिक आधार पर भेदभाव की चिंताजनक तस्वीर

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के हालात को लेकर समय-समय पर उठने वाली चिंताएं नई नहीं हैं। हाल ही सामने आए आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पाक में अल्पसंख्यकों पर किस कदर अत्याचार हो रहे हैं और यह समस्या कितनी गहरी है। पाकिस्तान की संसदीय अल्पसंख्यक समिति ने खुद स्वीकार किया है कि वर्ष 1947 में वहां 1817 हिंदू मंदिर और गुरुद्वारे थे, जिनमें से अब मात्र 37 ही बचे हैं। 1285 हिंदू मंदिर और 532 गुरुद्वारे या तो ध्वस्त कर दिए गए, या बहुसंख्यकों द्वारा कब्जे में ले लिए गए, अथवा जानबूझकर खंडहर बना दिए गए।

आधुनिक दौर में धार्मिक आधार पर भेदभाव की ऐसी स्थिति किसी भी राष्ट्र के लिए चिंताजनक होनी चाहिए। अपने नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और अल्पसंख्यकों को विशेष सुरक्षा देने की प्रत्येक देश की जिम्मेदारी है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के जिन मुस्लिम देशों ने धर्मनिरपेक्षता की राह चुनी तो उनकी तरक्की की राह भी अपने आप खुलती रही। संयुक्त अरब अमीरात ने अबू धाबी में भव्य बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण मंदिर बनवाया। वहीं सऊदी अरब ने अपने हिंदू कर्मचारियों के लिए पूजा की जगह दी। इतना ही नहीं- ओमान, बहरीन, कुवैत, कतर हर जगह अल्पसंख्यकों को अपने आराधना स्थलों का निर्माण करने व पूजा-अर्चना की पूरी छूट है। इंडोनेशिया में सैकड़ों हिंदू-बौद्ध मंदिर संरक्षित हैं। यही कारण है कि हिंदू प्रोफेशनल्स और भारतीय पर्यटक इन देशों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बने हुए हैं। इसके ठीक विपरीत पाकिस्तान की उल्टी सोच ने उसे बर्बाद कर दिया है। धार्मिक कट्टरता की वजह से वहां से हिंदू-सिख पलायन करते रहे हैं और आज उनकी आबादी 1.6 प्रतिशत से भी कम रह गई। सवाल है कि जब कट्टर इस्लामिक देशों तक में अल्पसंख्यकों को सम्मान और सुरक्षा दी जा रही है, तो पाकिस्तान इसकी अनदेखी क्यों कर रहा है? किसी देश की प्रगति केवल आर्थिक सूचकांकों से नहीं, बल्कि उसके अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, सम्मान और समानता से मापी जाती है। धार्मिक स्थल केवल धर्म का प्रतीक नहीं, बल्कि समुदाय की स्मृति, संस्कृति और पहचान का आधार होते हैं। इनका अस्तित्व मिटता है, तब समुदाय का आत्मविश्वास और सुरक्षा-बोध भी क्षीण होता है। पाकिस्तान में बसे हिंदू और सिख परिवार पीढ़ियों से इसी मानसिक और सामाजिक दबाव को झेलते आए हैं।

यदि पाकिस्तान वास्तव में एक बहुलतावादी और आधुनिक राष्ट्र की श्रेणी में आना चाहता है, तो उसे कट्टरपंथ को प्रश्रय देने के बजाय अपने यहां अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा के लिए ईमानदार कदम उठाने होंगे। आज तो हालत यह है कि पाकिस्तान की छवि न केवल अल्पसंख्यकों, बल्कि इंसानियत के दुश्मन की बनी हुई है। जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान आईना देखे और सुधरे, वरना इतिहास उसे कभी माफ नहीं करेगा।

निवेश की होड़: यह केवल उद्योग की रणनीति नहीं है, बल्कि शक्ति संतुलन के नए समीकरण की शुरुआत है

ट्रंप के बावजूद भारत में 'एआइ निवेश' की बारिश

बालेन्दु शर्मा दाधीच
लेखक वरिष्ठ सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ हैं
@patrika.com

अगर अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप की तमन्नाओं से परे जाकर भी अमरीकी कंपनियां भारत पर इतना बड़ा दांव लगा रही हैं तो इसलिए कि वे भारत में छिपी संभावनाओं और यहां उभरते आइटी इकोसिस्टम को अनदेखा नहीं कर सकतीं।

ऐसा लगता है कि दुनिया की अग्रणी एआइ कंपनियों के बीच भारत में निवेश की होड़ है। वह भी ऐसे समय पर, जबकि डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन अपनी 'अमरीका फर्स्ट नीति' के तहत' अपने देश को ही सबसे सही जगह मानता है। माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन ने भारत में कुल मिलाकर 52.5 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है। अमेजन की ओर से 35 अरब डॉलर 2030 तक लगाए जाने हैं तो माइक्रोसॉफ्ट अगले चार वर्षों में 17.5 अरब डॉलर का निवेश करेगी। आपको शायद याद हो कि तीसरे आइटी दिग्गज गूगल ने पिछले अक्टूबर में 15 अरब डॉलर से विशाखापत्तनम में अपना एआइ डेटा हब कायम करने का वादा किया था। इसी हफ्ते माइक्रोप्रोसेसर बनाने वाली कंपनी इंटेल ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साझेदारी की घोषणा की है, जिसके तहत उसके उन्नत प्रोसेसरों की टेस्टिंग और पैकेजिंग भारत में होगी। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने 14 अरब डॉलर की सेमीकंडक्टर परियोजना का काम शुरू किया है। हैरत की बात यह है कि अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल तीनों ने ये घोषणाएं एक हफ्ते के भीतर की हैं। इन्हीं के साथ गूगल और कुछ दूसरी एआइ कंपनियों को भी जोड़कर देखें तो दिमाग में कुछ चमकता है।

यही कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत में 'कुछ सचमुच खास' हो रहा है जो सेवा-प्रधान आइटी इंडस्ट्री की हमारी पारंपरिक छवि से अलग है। हम महज बाजार की भूमिका में नहीं हैं बल्कि आइटी निवेश के केंद्र और एआइ हब का रूप ले रहे हैं। याद रहे, मौजूदा निवेश एआइ, क्लाउड, सेमीकंडक्टर उद्योग और एआइ-इन्फ्रास्ट्रक्चर में हो रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन की घोषणाएं अमरीका के बाहर किसी एक देश में किए गए अब तक के सबसे बड़े निवेशों में गिनी जा रही हैं। पिछली घोषणाओं को जोड़ लें तो भारत में अमेजन का कुल निवेश लगभग 75 अरब डॉलर तक जा पहुंचेगा। इससे वह देश का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बन जाएगा। इसी तरह, माइक्रोसॉफ्ट के 17.5 अरब डॉलर न केवल एशिया में उसका सबसे बड़ा निवेश हैं बल्कि दुनिया के स्तर पर भी शीर्ष दो-तीन में गिने जाएंगे। अगर अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप की तमन्नाओं से परे जाकर भी अमरीकी कंपनियां भारत पर इतना बड़ा दांव लगा रही हैं तो इसलिए कि वे भारत में छिपी संभावनाओं और यहां उभरते आइटी इकोसिस्टम को अनदेखा नहीं कर सकतीं। मिसाल के तौर पर इन तीन बातों पर गौर कीजिए-

हमारी पहली विशेषता है भारत के बाजार का आकार और उपभोक्ताओं की संख्या। यह देश इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। एक अरब से अधिक लोग मोबाइल या पीसी पर एआइ-सक्षम एप्लीकेशनों का उपयोग करते हैं। यह न केवल उत्पादों के परीक्षण के लिए, बल्कि उभरती एआइ सेवाओं के लिए भी एक आकर्षक अवसर है। एअरटेल के उपभोक्ताओं को मुफ्त में एआइ मॉडल की सुविधा मुहैया कराने वाली परप्लेक्सिटी इसका लाभ उठाकर दिखा चुकी है। आज अमरीका के बाद भारत में उसके सबसे ज्यादा उपभोक्ता हो गए हैं।

दूसरा कारण यह है कि भारत अमरीका और चीन के बाद एआइ कौशल का सबसे बड़ा केंद्र है। स्टैनफोर्ड एआइ रिपोर्ट कहती है कि 2016 से अब तक भारत में एआइ से संबंधित कौशल का दायरा 263% बढ़ा है। बेंगलूरु और हैदराबाद जैसे शहरों ने एक टेक इकोसिस्टम विकसित किया है जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी है। वहीं से माइक्रोसॉफ्ट का नया 'हाइपरस्केल क्लाउड रीजन' भी शुरू होने वाला है। एआइ कंपनी एंथ्रोपिक भी बेंगलूरु में दफ्तर खोल रही है।

भारत में निहित तीसरा आकर्षण है यहां से मिल रहे नीतिगत संकेत। सरकार 'सेमीकंडक्टर मिशन' और 'स्वदेशी (सॉवरेन) एआइ मॉडल' पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके मायने यह हैं कि भारत आयात-निर्भर तकनीकी उपभोक्ता नहीं बने रहना चाहता। वह आत्मनिर्भर एआइ अर्थव्यवस्था बनाना चाहता है। इधर डेटा सम्प्रभुता और डिजिटल इंडिया एक्ट जैसे नियामक ढांचे भी वैश्विक कंपनियों को यह भरोसा दे रहे हैं कि यहां वे लंबे समय के लिए, सुनियोजित ढंग से पैसा लगा सकती हैं। इस निवेश के वैश्विक निहितार्थ भी हैं। चीन के अनुभव से सबक ले चुके तकनीकी दिग्गज अब एआइ के प्रसार में 'भू-राजनीतिक विविधता' लाना चाहते हैं। यह केवल उद्योग की रणनीति नहीं है, बल्कि शक्ति-संतुलन के नए समीकरण की शुरुआत है। अमरीका और चीन के बाहर एक तीसरे तकनीकी ध्रुव का उदय भारत में हो सकता है। यह भी कह सकते हैं कि हो रहा है।

भारतीय आइटी उद्योग के लिए भी प्रतिद्वंद्विता से ज्यादा लाभ की स्थिति हो सकती है। जो कंपनियां अब तक वैश्विक आउटसोर्सिंग के लिए जानी जाती थीं, वे अब नवाचार और एआइ अनुसंधान में वैश्विक दिग्गजों की सहयोगी बन रही हैं। इस निवेश से उच्च कौशल वाली हजारों नौकरियों का सृजन होने के भी आसार हैं क्योंकि इन्हीं कंपनियों की बड़े पैमाने पर करोड़ों युवाओं को प्रशिक्षित करने की योजना है। विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारियों से भारतीय स्टार्टअप्स को भी पूंजी, प्रशिक्षण और वैश्विक बाजारों का सीधा अनुभव मिलेगा। लगता है, बेंगलुरु, हैदराबाद, गुरुग्राम और पुणे जैसे शहरों में सूचना प्रौद्योगिकी का जलवा जारी रहेगा। ये 'एआइ शहर' बनने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, यदि बाकी पक्ष भी सकारात्मक भूमिका निभाएं। ये हैं- सरकार, स्थानीय आइटी इंडस्ट्री और हमारी तकनीकी प्रतिभाएं। अगर केंद्र सरकार आइटी-एआइ उद्योग के अनुकूल नीतियां बनाए और राज्य सरकारें एक तत्पर सहयोगी की भूमिका निभाएं तो विदेशी एआइ कंपनियों के बीच भारत का आकर्षण बरकरार रह सकता है। विदेशी कंपनियां अपने दम पर धरती पर एआइ क्रांति नहीं रच सकती हैं यदि हम इस प्रक्रिया को गति नहीं देते और खुद भी उसी उत्साह के साथ भागीदारी नहीं करते।

प्रसंगवश

सीसीटीवी और गश्त के भरोसे एटीएम, जिम्मेदार बैंक प्रबंधन मौन

वारदात रोकने के लिए एटीएम में सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था भी होनी चाहिए

आमजन की सुविधा के लिए विभिन्न बैंकों की ओर से एटीएम स्थापित तो किए हैं लेकिन इनको एजेंसी के भरोसे छोड़ दिया गया है। एटीएम के निर्बाध संचालन के साथ उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी संबंधित बैंक प्रबंधन की है लेकिन इस जिम्मेदारी से अधिकांश जगह बैंक प्रबंधन मुंह फेर लेता है। नतीजा, एटीएम लूट की वारदात या किसी बुजुर्ग उपभोक्ता या महिला के एटीएम कार्ड को धोखे से बदलकर रुपए निकाल कर आरोपी गायब हो जाते हैं। राजस्थान में इस तरह के कई मामले सामने आते रहे हैं। हाल में एटीएम को कटर से काटकर नोट निकालने का मामला सामने आया है।

चित्तौड़गढ़ के उदयपुर मार्ग स्थित एटीएम को कटर से काटने की घटना ने उसकी सुरक्षा के मुद्दे पर सवाल उठाया है। पहले इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए बैंक प्रबंधन की ओर से रात्रिकालीन गार्ड की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन अब एटीएम की रखवाली सीसीटीवी कैमरे के भरोसे है। जबकि सीसीटीवी कैमरे सिर्फ घटना को रिकॉर्ड ही कर सकते हैं। वारदात को रोकने के लिए तो एटीएम में सुरक्षा गार्ड ही तैनात होने चाहिए। पिछली वारदातों में यह सामने आया है कि शातिर ऐसे एटीएम की तलाश में रहते हैं जहां सुरक्षा गार्ड नहीं हो और उस पर धावा बोल देते हैं। पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें रस्से से एटीएम को बांधकर जीप आदि से खींच कर एटीएम ही उखाड़ दिया गया।

ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जरूरी है कि पुलिस एवं प्रशासन पहले ऐसे बैंक के एटीएम को चिह्नित करे, जिनमें रात्रिकालीन गार्ड की व्यवस्था नहीं है। इनमें गार्ड की पुख्ता व्यवस्था करने के लिए संबंधित बैंक प्रबंधन को पाबंद किया जाए या फिर रात्रि में निर्धारित समय तक ही एटीएम खोलने की व्यवस्था हो। पुलिस की गश्त के भरोसे रहने से कैसे काम चलेगा। चित्तौड़गढ़ में भला हो गश्त के गार्ड का, जिसने लुटेरों को ललकारते हुए हल्ला कर दिया, जिससे एटीएम लूट की वारदात बच गई, नहीं तो ऐसी वारदातों में एक संख्या और जुड़ जाती।

- **चंद्रप्रकाश जोशी**
cp.joshi@in.patrika.com

बुक इनसाइट

रेंटल हाउस : एक चुटीला उपन्यास

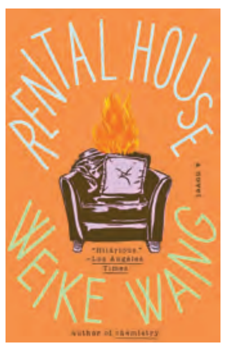

वेइके वांग का लिखा 'रेंटल हाउस' एक आधुनिक और चुटीला उपन्यास है, जो व्यक्तिगत और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में दिलचस्प प्रश्न उठाता है। इस किताब में वांग ने किराए के घर के एक साधारण से प्रतीत होने वाले स्थान को अपने पात्रों की भावनाओं, संघर्षों और संवेदनाओं की जटिलताओं से जोड़ा है। कहानी का केंद्र किराए पर रहने वाले व्यक्तियों और उनके साथ जुड़ी समस्याओं के इर्द-गिर्द घूमता है, जिनके जीवन में झंझट और अव्यवस्था बसी रहती है। कहानी की लेखिका ने इसे एक हास्यपूर्ण, लेकिन संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत किया है। किताब के पात्रों के बीच के रिश्ते और घटनाएं इतनी प्रभावशाली हैं कि वे पाठक को आकर्षित कर लेती हैं।

किराए के घर की स्थिति को वे एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करती हैं, जो समाज के उन संघर्षों को दिखाता है जिनसे आम इंसान गुजरता है जैसे पारिवारिक रिश्ते, निजी आकांक्षाएं और समर्पण की भावना। किताब का लेखन भी बेहद आकर्षक और शहरी भाषा में है, जो उसे आम पाठकों के लिए उपयुक्त बनाता है।

फैक्ट फ्रंट

विशाल टोकरी की तरह सर्कस ट्री

सर्कस ट्री किसी लकड़ी की मूर्ति या काट-छांट से बनाई गई आकृति नहीं है, बल्कि यह एक वास्तविक और जीवित पेड़ है, जिसे इंसान ने सालों की मेहनत और धैर्य से अनोखे आकार में बदल दिया है। सर्कस ट्री की शुरुआत 1940 के दशक में कैलिफोर्निया के एक किसान और कलाकार एक्सल एर्लैंडसन ने की थी। उन्होंने अपने खेत में साधारण साइकमोर पेड़ों को लगाकर उनकी टहनियों को मोड़ने, जोड़ने और ग्राफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की। इस तकनीक से पेड़ धीरे-धीरे अजीबोगरीब आकार में बदलने लगे। इनमें दिल के आकार, सर्पिल और यहां तक कि बास्केट जैसी आकृतियां बनाई गईं। सबसे प्रसिद्ध बास्केट ट्री है, जिसमें 6 अलग-अलग साइकमोर पेड़ों को इस तरह जोड़ा गया कि उनकी जड़ें अलग-अलग दिशाओं में फैली हुई हैं, लेकिन ऊपर से वे एक विशालकाय टोकरी जैसी दिखती हैं। ये पेड़ आज भी कैलिफोर्निया में स्थित 'ट्री सर्कस' पार्क में खड़े हैं। इन पेड़ों की उम्र 80-100 के बीच हो चुकी है।

जीवन प्रबंध विश्राम करना कोई अपराध नहीं है

वर्कलाइफ बैलेंस के लिए काम और आराम दोनों हैं आवश्यक

डॉ. गौरव बिस्सा
जीवन प्रबंध प्रशिक्षक
@patrika.com

इस समय लोकसभा में पेश किए गए विधेयक 'राइट टू डिस्कनेक्ट' की चर्चा है। इस विधेयक का लक्ष्य कर्मचारियों को कार्य का समय पूर्ण होने के बाद फोन कॉल्स, ईमेल आदि का जवाब देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होने से बचाना है। ऐसा करने से कर्मचारियों का तनाव कम होगा एवं वर्कलाइफ बैलेंस बेहतर होगा। विधेयक में तनाव के कारण मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के लिए डिजिटल डिटॉक्स केंद्र बनाने का सुझाव है।

आखिर ऐसे विधेयक की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसा प्रतीत होने लगा है कि मनुष्य, मनुष्य न होकर रोबोट सरीखा हो गया है। व्यक्ति सिर्फ धन, यश, और पद के लिए दौड़ लगा रहा है लेकिन दौड़ के अंत में कुछ हासिल नहीं हो रहा। जितना जरूरी काम है, उतना ही जरूरी है आराम। यदि आराम आवश्यक न होता तो इटली और फ्रांस 2017 में, पुर्तगाल 2021 में तथा ऑस्ट्रेलिया 2024 में 'राइट टू डिस्कनेक्ट' जैसा कानून क्यों लागू होता? मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान होना चाहिए लेकिन व्यक्ति को विविध तरह के आराम न मिलें तो मनोदशा बिगड़ने में देर नहीं लगती।

इस सन्दर्भ में जर्मनी से प्रेरणा लेनी चाहिए। जर्मनी में वर्कलाइफ बैलेंस तथा कार्य के साथ आराम करना एक परम्परा है जिसे 'फिएराबेंड' कहते हैं। जर्मनी में वर्कलाइफ बैलेंस बनाए रखने के लिए कानून भी बना हुआ है, जिसके तहत चौबीस घंटों में से ग्यारह घंटे आराम के लिए तय हैं। 'फिएराबेंड' शारीरिक और मानसिक शांति बनाए रखने की एक अचूक तकनीक है। बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में जितना महत्त्व श्रम और संकल्प का है, उतना ही महत्त्व विश्राम का भी है। विश्राम करना कोई अपराध नहीं है। 24 घंटे मस्तिष्क का प्रोसेसर चालू रखना व शरीर से आराम गायब करना गलत है।

मनुष्य को कुछ विशेष तरह के आरामों की आवश्यकता होती है। शारीरिक आराम के अंतर्गत शरीर को आराम देना, आठ घंटे सोना, मसाज करना, आदि आते हैं। दिमागी आराम का अर्थ है हर समय दिमाग दौड़ाने से या लगातार काम करने से बचना। अति सक्रिय मस्तिष्क ज्यादा चिंता देता है। सामाजिक आराम में व्यक्ति अनौपचारिक मित्र बंधुओं से मिलकर उनके साथ समय व्यतीत करता है। मित्रों से मन की बात कहना सामाजिक आराम है। भावनात्मक आराम का अर्थ है कि हर बात को दिल से लगाने की प्रवृत्ति से बचना और जो कार्य अच्छा न लगे, उस कार्य के लिए मना कर देना। तटस्थ आराम वो विशेष आराम है इसमें व्यक्ति साक्षी भाव से आनंदित रहता है। इस आराम में जो हो रहा है, उसी को दृष्टा भाव से देखकर आनंदित होना होता है जैसे पक्षियों का कलरव सुनना, पहाड़ की चोटी पर कुछ देर बैठना, बच्चों को खेलते हुए देखना आदि। कर्मठ होना परंपरा है लेकिन शरीर को इतना भी परेशान न किया जाए कि ब्रेकडाउन की नौबत आ जाए। आनंदित रहकर कार्य करना ही जीवन प्रबंध है।

एक ही पेड़ और फैलाव जंगल जैसा

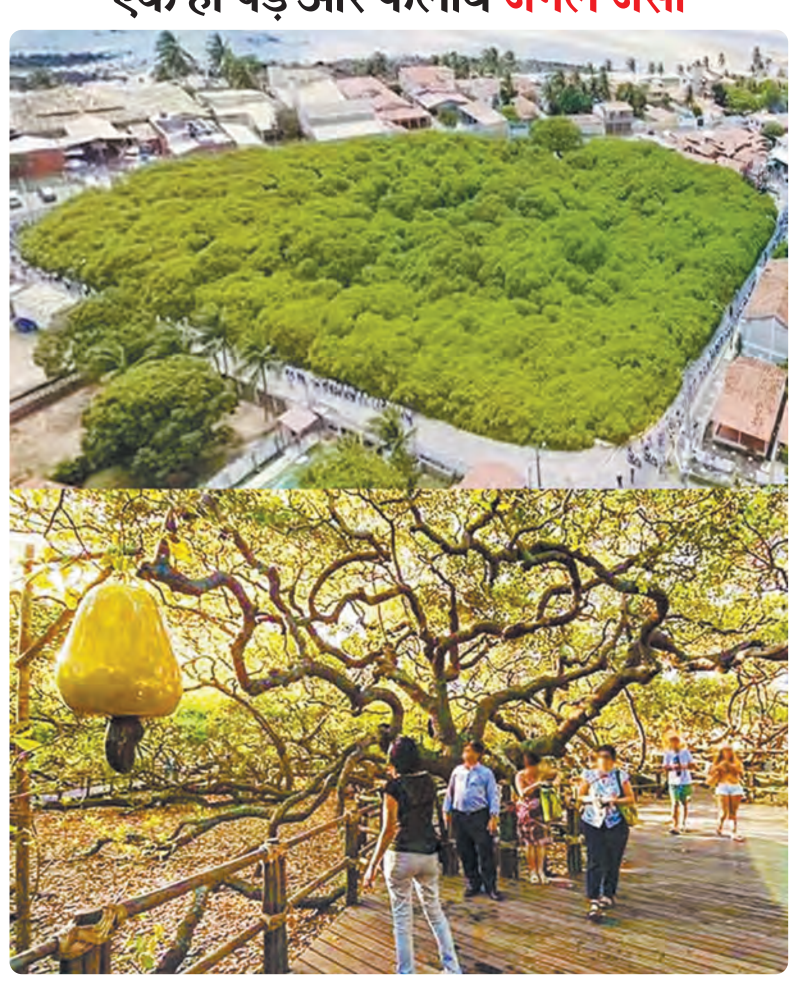

***ब्राजील** के पिरांगी में 'मायोर काजुएइरो दो मुंडो' दुनिया का सबसे बड़ा काजू का पेड़ है, जो अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है। लगभग 8,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला यह पेड़ एक पूरे जंगल जैसा दिखाई देता है, मानो कई पेड़ों का समूह हो। दुर्लभ आनुवंशिक गुण के कारण इसकी शाखाएं भूलभुलैया की तरह फैली हुई हैं।*

चिकित्सा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस आज

सभी के लिए सुलभ चिकित्सा सपना न होकर हकीकत बने

डॉ. शुभकाम आर्य
वरिष्ठ चिकित्सक
@patrika.com

स्वास्थ्य सेवा सबसे मूलभूत जरूरतों में से एक है। हाल के वर्षों में नए नवाचारों से स्वास्थ्य देखभाल में काफी सुधार हुआ है। गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की उपलब्धता के साथ हालांकि स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च भी महंगा हुआ है। यदि स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के बावजूद कोई नागरिक बीमारी के समय इलाज से वंचित रह जाता है, तो यह हमारी व्यवस्था की संवेदनशीलता पर प्रश्नचिह्न लगाता है। गरीब और निम्न आय वर्ग के लिए महंगे इलाज को वहन करना हमेशा एक बड़ी चुनौती रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सभी के लिए बिना वित्तीय कठिनाइयों के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने की आवश्यकता को प्रतिपादित किया। इसी आह्वान पर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस हर साल 12 दिसंबर को मनाया जाता है।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का अर्थ है कि हर व्यक्ति को, चाहे उसकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं मिलें और इलाज के खर्च से कोई आर्थिक संकट उत्पन्न न हो। आंकड़े बताते हैं कि विश्व में लगभग 450 करोड़ लोग यानी दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी अब भी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच से दूर है। चार में से एक व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अपनी जेब से भुगतान करने पर वित्तीय कठिनाई का सामना करता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार पिछले 20 वर्षों में लगभग 130 करोड़ लोग स्वास्थ्य खर्च के कारण गरीबी में चले गए। भारत में भी स्थिति चिंताजनक है। जो स्वास्थ्य खर्च सीधे लोगों की जेब से होता है, वह निर्धन वर्ग के लिए अब भी भारी बोझ है। भारत में केंद्र सरकार व राजस्थान जैसे राज्यों में आयुष्मान भारत (पहले चिरंजीवी योजना) जैसी निशुल्क सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं संचालित हैं। इन योजनाओं से सरकारी अस्पतालों के साथ प्राइवेट अस्पतालों को भी जोड़ा गया है। ये योजनाएं कई मायने में प्रभावशाली हैं, पर जमीनी स्तर पर अभी कई चुनौतियां बनी हुई हैं। कई निजी अस्पताल भुगतान में देरी और पैकेज दरों की असंतुष्टि के कारण इन योजनाओं से दूरी बनाए हुए हैं।

कई लोगों का यह भी तर्क है कि उपलब्ध सीमित संसाधनों का पूरा व वास्तविक फायदा पहले उन वंचितों व गरीबों को ही मिलना चाहिए, जो अपने खर्च से इलाज कराने में असमर्थ हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ज्यादा जरूरत सरकारी अस्पतालों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की है। सामान्य रोगों के उपचार के लिए भी जब दूरदराज के क्षेत्रों से बड़े अस्पतालों में रेफर न करना पड़े तभी यह सहज सुलभ चिकित्सा की ओर सबसे प्रभावी कदम होगा। मजबूत और लचीली स्वास्थ्य प्रणाली अपनाकर सभी लोगों को बिना आर्थिक संकट के स्वास्थ्य कवरेज के करीब लाना होगा। तभी हम कह सकेंगे कि 'सभी के लिए सुलभ चिकित्सा' अब केवल सपना नहीं, एक साकार होती हकीकत है।

आपकी बात

सर्विलांस टीम का गठन हो

मोबाइल और चेन स्नैचिंग की अधिकांश घटनाएं रेलवे स्टेशनों और अकेली महिलाओं के साथ व्यावसायिक इलाकों में होती हैं। ऐसे स्थानों पर सर्विलांस टीम का गठन करना चाहिए। लोगों को भी जागरूक होना चाहिए।

- **विनायक गोयल,** रतलाम

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की अन्य प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, 'मोबाइल व चेन स्नेचिंग के मामलों पर अंकुश के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?' ऑनलाइन भी देखें।

इसे स्कैन करें https://shorturl.at/vtm31

समसामयिक विषयों पर पाठकों के विचार आमंत्रित हैं। चुनिंदा विचार प्रकाशित किए जाएंगे।
ईमेल करें: edit@epatrika.com

एक्सचेंज ऑफर का जाल राइट टू रिपेयर को सिर्फ नीति नहीं, उपभोक्ता अधिकार की तरह देखा जाना चाहिए

कौन तय कर रहा है फोन की 'एक्सपायरी डेट'- आप या बाजार?

डॉ. मुकेश कुमार शर्मा
स्वतंत्र लेखक एवं शोधार्थी
@patrika.com

पिछले कुछ वर्षों में स्मार्टफोन बाजार की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि उपभोक्ता अपनी जरूरत से पहले ही फोन बदलने लगा है। कंपनियों के चमकदार एक्सचेंज ऑफर- 'पुराना दो, नया लो'–हमारे भीतर यह भ्रम पैदा करते हैं कि यह खर्च नहीं, बल्कि बचत है।

इस आकर्षण के पीछे एक ऐसी बाजार रणनीति काम कर रही है, जो धीरे-धीरे हमारी पसंद, हमारी जेब और हमारे निर्णय पर नियंत्रण स्थापित कर रही है। मरम्मत मुश्किल और महंगी होती जा रही है, अधिकृत सर्विस सेंटर कम महसूस होने लगे हैं और स्पेयर पार्ट्स इतने महंगे दिखते हैं कि उपभोक्ता चाहकर भी अपने पुराने फोन को ठीक नहीं करा पाता। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, जिसमें फोन बदलना विकल्प नहीं, बल्कि एक व्यापारिक अनिवार्यता बनता जा रहा है। दुनिया भी इसी दबाव से गुजर रही है। ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया ने लगभग 62 मिलियन टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा किया, जबकि उसका 22.3 प्रतिशत ही रीसाइकिल हो पाया। भारत की स्थिति कम गंभीर नहीं है। सीपीसीबी के अनुसार देश हर वर्ष 14-17 लाख टन ई-कचरा उत्पन्न कर रहा है। एक-दो वर्ष में फोन बदलना सिर्फ निजी निर्णय नहीं, बल्कि पृथ्वी पर अदृश्य बोझ भी है।

कंपनियों की बदलती उत्पाद रणनीति इस संकट की जड़ है। आधुनिक फोन इस तरह डिजाइन किए जा रहे हैं कि उनकी मरम्मत सहज न रहे- नॉन-रिमूवेबल बैटरी, बेहद नाजुक ग्लास बॉडी, महंगे स्पेयर पार्ट्स और सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद पुरानी डिवाइस का धीमा पड़ना उपभोक्ता को मरम्मत की बजाय अपग्रेड की ओर धकेल देते हैं। कई देशों में इसकी वजह से कंपनियों पर मुकदमे और जुर्माने भी लगे हैं, क्योंकि यह आरोप लगा कि उत्पादों की उम्र जानबूझकर कम रखी गई। सवाल यह है कि यदि तकनीक का उद्देश्य सुविधा बढ़ाना है तो मरम्मत को इतना कठिन और महंगा क्यों बनाया गया है? यह सवाल बाजार की नीयत पर सीधा प्रकाश डालता है।

यही रणनीति आगे बढ़कर एक्सचेंज ऑफर का रूप लेती है। व्यवहार-आर्थिकी बताती है कि ऑफर, आकर्षक कीमतें, ईएमआइ और सीमित समय जैसी बिक्री रणनीतियां उपभोक्ता के निर्णय को तुरंत प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि दुनिया भर में फोन बदलने का औसत चक्र 2-3 वर्ष पर आ गया है और युवाओं में यह अवधि और भी छोटी है। यह प्रवृत्ति वैश्विक स्तर पर भी अलग-अलग रूपों में दिखती है। एशिया में तकनीक की तेज रफ्तार और ऑनलाइन सेल्स ने युवाओं को सबसे छोटी अपग्रेड-संस्कृति में बांध दिया है। इसके विपरीत यूरोप मजबूत उपभोक्ता कानूनों और 'राइट टू रिपेयर' के जरिए कंपनियों को टिकाऊ और मरम्मत-अनुकूल डिजाइन अपनाने पर मजबूर कर रहा है।

अमरीका अपग्रेड संस्कृति का केंद्र है, जहां ट्रेड-इन, ईएमआइ और ब्रांड वफादारी ने फोन बदलने को जीवनशैली बना दिया है, भले पर्यावरणीय बोझ दूसरे देशों पर पड़े। ऑस्ट्रेलिया में कम आबादी लेकिन उच्च उपभोग ने प्रति व्यक्ति ई-कचरा तेजी से बढ़ाया है। उधर अफ्रीका में नया नहीं, बल्कि सेकेंड-हैंड स्मार्टफोन संस्कृति ज्यादा मजबूत है और स्थानीय रिपेयर नेटवर्क अब भी टिके हुए हैं। भारत ने 'राइट टू रिपेयर' की दिशा में कदम बढ़ाया है। एक रिपेयरएबिलिटी इंडेक्स पर भी विचार किया जा रहा है, जिसमें उत्पादों को उनकी मरम्मत की आसानी के आधार पर स्कोर दिया जाएगा। यदि यह लागू हो पाता है, तो कंपनियों को मजबूरन अधिक टिकाऊ और उपभोक्ता-हितैषी डिजाइन अपनाने होंगे। यह न केवल ई-कचरे को कम करेगा, बल्कि भारत की पुरानी रिपेयर संस्कृति को भी फिर से जीवन देगा।

अंततः सवाल सिर्फ इतना नहीं कि हमें नया फोन लेना चाहिए या नहीं। असली प्रश्न यह है कि हमारी जरूरतें कौन तय कर रहा है- हम स्वयं या बाजार की रणनीतियां? तकनीक हमें सक्षम बनाए, यह आदर्श स्थिति है लेकिन तकनीक हमें इतना निर्भर बना दे कि हम अपनी जरूरतों की पहचान न कर सकें, यह किसी भी समाज के लिए स्वस्थ संकेत नहीं। स्मार्टफोन बदलना हमारी अपनी पसंद होनी चाहिए, कंपनियों का दबाव नहीं। 'राइट टू रिपेयर' को सिर्फ नीति नहीं, बल्कि उपभोक्ता-अधिकार और सामाजिक आंदोलन की तरह देखा जाए।